



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सो.जी.-डी.एल.-अ.-०१०६२०२३-२४६२००
CG-DL-E-01062023-246200

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 2

PART II — Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं ८]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल ३, २०२३/चैत्र १३, १९४५ (शक)

No. ८]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 2023/CHAITRA 13, 1945 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

लोक सभा

बहु राज्य सहकारी सोसाइटी संबंधी संयुक्त समिति
(संशोधन) विधेयक, २०२२

(सत्रहवीं लोक सभा)

१५ मार्च, २०२३ को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

१५ मार्च, २०२३ को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, २०२३/फाल्गुन, १९४४ (शक)

LOK SABHA

**REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON
THE MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT)
BILL, 2022**

(SEVENTEENTH LOK SABHA)

Presented to Lok Sabha on 15th March, 2023

Laid in Rajya Sabha on 15th March, 2023

LOKSABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

MARCH, 2023/PHALGUNA 1944 (SAKA)

संक्षिप्ताक्षर

ए जी एम	- वार्षिक सामान्य अधिवेशन
बीआर अधिनियम	- बैंककारी विनियमन अधिनियम
सी ए आर ई	- क्रेडिट विश्वेषण और अनुसंधान
सी ई ए	- सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण
सी ई एफ	- सहकारी शिक्षा निधि
सी आई ओ	- सहकारी सूचना अधिकारी
सीआरएफआईसीएआरडी	- कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा संबंधी समिति
सी आर सी एस	- सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार
क्रिसिल	- क्रेडिट रेटिंग इंफार्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीआरआरडीएफ	- सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि
सी एस आर	- सहकारी सामाजिक उत्तरदायित्व
डीईएएफ	- जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष
डी एफ एस	- वित्तीय सेवा विभाग
डी आई सी जी सी	- जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम
आई सी ए आई	- इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
आई सी आर ए	- इनवेस्टमेंट इनफार्मेशन एण्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड
इफको	- इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड
जे पी सी	- संयुक्त संसदीय समिति
कृभको	- कृषक भारती सहकारी लिमिटेड
एमडी/सीईओ	- प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एम एस सी एस	- बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां
नाबार्ड	- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएएफसीएआरडी	- राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक संघ लिमिटेड
एन ए एफ सी यू बी	- नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड
नेफेड	- भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड
एनएएफएससीओबी	- राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय संघ
एन सी सी एफ	- भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ
एनसीडीसी	- राष्ट्रीय सहकारी विकास परिषद
एनसीयूआई	- भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ
एनपीए	- गैर निष्पादित आस्तियां
ओएनआईसीआरए	- ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया
पीएसयू	- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
आरबीआई	- भारतीय रिजर्व बैंक
आरबीआईआईओएस	- भारतीय रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना

आर सी एस	- सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार
आर ई	- विनियमित ईकाइयाँ
एस ए एफ	- पर्यवेक्षी कार्वाई ढांचा
एसएआरएफएईएसआई अधिनियम	- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम
एससी/एसटी	- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
यू सी बी	- शहरी सहकारी बैंक
डब्ल्यू टी डी	- पूर्णकालिक निदेशक

बहु राज्य सहकारी सोसाइटी संबंधी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी — सभापति

लोक सभा

2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
4. श्रीमती पूनमबेन माडम
5. श्री रामदास तडस
6. श्री अणासाहेब शंकर जोल्ले
7. डॉ निशिकांत दुवे
8. श्रीमती सुनीता दुग्गल
9. श्री बृजेन्द्र सिंह
10. श्रीमती जसकौर मीना
11. श्री राम कृपाल यादव
12. डॉ. ढालसिंह बिसेन
13. श्री कोडिकुम्हील सुरेश
14. श्री मनीष तिवारी
15. श्रीमती कनिमोद्धी करुणानिधि
16. श्री कल्याण बनर्जी
17. श्री लालू श्रीकृष्ण देवरायालू
18. श्री हेमन्त पाटिल
19. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
20. श्री चंद्र शेखर साहू
21. श्री गिरीश चन्द्र

राज्य सभा

22. श्री घनश्याम तिवाड़ी
23. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
24. श्री धनंजय भीमराव महादिक
25. श्री रामचंद्र जांगड़ा
26. ¹श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल
27. श्री सुखेन्दु शेखर राय
28. श्री एन.आर. इलांगो
29. श्री विक्रमजीत सिंह साहनी
30. श्री सुजीत कुमार
31. श्री एस. निरंजन रेड्डी

¹राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 256 के अंतर्गत राज्य सभा सचिवालय परिपत्र संख्या आरएस 50/2023 द्वारा दिनांक 10.02.2023 से 259वें सत्र के शेष भाग के लिए 10 फरवरी 2023 से निलंबित किया गया।

सचिवालय

1. श्री जे. एम. बैसाख	-	संयुक्त सचिव
2. श्री कल्याणसुंदरम	-	निदेशक
3. श्री सुमेश कुमार	-	उप सचिव
4. श्रीमती रचना सक्सेना	-	उप सचिव
5. श्री भरत लाल मीणा	-	उप निदेशक
6. श्रीमती सोनिया गुप्ता	-	समिति अधिकारी

प्राक्षयन

मैं, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति का सभापति, जिसे 'बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022' सौंपा गया था, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक के साथ इस प्रतिवेदन को, संलग्न कर रहा हूँ।

2. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 को 7 दिसंबर, 2022 को लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया था। श्री अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री द्वारा संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को विधेयक भेजे जाने संबंधी उल्लेख का प्रस्ताव लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था (देखिए परिशिष्ट-एक) और जिस पर 21 दिसंबर, 2022 को राज्य सभा सहमत हुई थी (देखिए परिशिष्ट-दो)।

3. संयुक्त समिति को संसद के बजट सत्र 2023 के दूसरे भाग के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन, सभा में प्रस्तुत करने का समय दिया गया।

4. संयुक्त समिति की 08 बैठकें हुईं। समिति ने विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों पर सहकारिता मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया था। सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के स्पष्टीकरण देने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि भी समिति की बैठकों के दौरान उपस्थित थे। संयुक्त समिति ने नावार्ड सहित सहकारी सोसाइटीयों और सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय स्तर के परिसंघों के विचारों को भी सुना। संयुक्त समिति ने कुछ प्रमुख बहुराज्य सहकारी समितियों के विचारों को भी सुना। तत्पश्चात, संयुक्त समिति ने विधेयक पर खंडवार विचार-विमर्श पूरा किया। प्रतिवेदन के साथ संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक को भी संलग्न किया गया है। बैठकों के विवरण परिशिष्ट-चार में दिए गए हैं।

5. संयुक्त समिति ने 12 हितधारकों के विचार/सुझाव सुने। मौखिक साक्ष्य के लिए संयुक्त समिति के समक्ष उपस्थित होने वाले साक्षियों की बैठकवार सूची संलग्न है (देखिए परिशिष्ट-पाँच)।

6. संयुक्त समिति ने 13 मार्च 2023 को हुई अपनी 08वीं बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया और सभापति को समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

7. श्री एन.आर. इलांगो से प्राप्त विमत नोट रिपोर्ट में संलग्न है (परिशिष्ट-सात देखें)।

8. संयुक्त समिति सहकारिता मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग), वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), भारतीय रिजर्व बैंक और नावार्ड के प्रतिनिधि, जो संयुक्त समिति के समक्ष उपस्थित हुए और विधेयक की जांच के संबंध में हुई बैठकों के दौरान संयुक्त समिति द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर अपने विचार रखे, को धन्यवाद देना चाहती है। संयुक्त समिति सहकारी सोसाइटीयों, सहकारी बैंकों और अन्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटीयों के राष्ट्रीय स्तर के संघों के प्रतिनिधियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करना चाहती है, जो संयुक्त समिति के समक्ष उपस्थित हुए और विधेयक के विभिन्न उपबंधों के बहुराज्य सहकारी सोसाइटीयों के क्षेत्र में प्रभाव के बारे में खुलकर अपने विचार प्रस्तुत किए। संयुक्त समिति लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा संयुक्त समिति की सभी बैठकों को सुचारू रूप से संचालित करने और संयुक्त समिति के प्रारूप प्रतिवेदन तैयार करने के लिए गए अथकर और समर्पित प्रयासों को भी स्वीकार करती है।

नई दिल्ली;

13 मार्च, 2023

22 फाल्गुन, 1944 (शक)

(चंद्र प्रकाश जोशी)

सभापति,

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन)

विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति

प्रतिवेदन

अध्याय-1

बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 और उसके संशोधन विधेयक 2022 का उद्भव और मुख्य विशेषताएं

1.1 सहकारिता किसी संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक रूप से एकजुट हुए व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है। सहकारिता स्व-सहायता, स्व-दायित्व, लोकतंत्र, समानता, समता और एकजुटता के मूल्यों पर आधारित है। इसके संस्थापकों से लेकर अब तक सहकारी सदस्य ईमानदारी, खुलेपन, सामाजिक दायित्व और दूसरों की देखभाल के नैतिक मूल्यों में विश्वास करते आए हैं।

भारत में सहकारी कानूनों का आरंभ और संक्षिप्त इतिहास

1.2 भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र से हुई थी और इसे मूलतः लोगों के अन्य संसाधनों को एकत्रित करने हेतु एक तंत्र के रूप में विकसित किया गया था, ताकि उन्हें विभिन्न स्तरों पर आर्थिक सहायता/लाभ प्रदान किया जा सके। सहकारी समितियों को संस्था के रूप में स्थापित करने का पहला प्रयास सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम, 1904 के अधिनियमन के साथ प्रारंभ हुआ था, तत्पश्चात् इसके दायरे में अधिक व्यापक सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 के द्वारा वृद्धि की गई। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अंतर्गत, सहकारी के विषय को तत्कालीन प्रांतों को हस्तांतरित कर दिया गया था, जिन्हें अपने स्वयं के सहकारी कानूनों को अधिनियमित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधीन, सहकारिता प्रांत का ही विषय बना रहा। वर्तमान में, भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के अधीन, सहकारिता राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सहकारी सोसाइटियों के संचालन को प्रशासित करने के लिए, जहां सदस्यता एक से अधिक प्रांतों से थी, भारत सरकार ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1942 का अधिनियमन किया, जिसे बाद में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 द्वारा भारत के संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत प्रतिस्थापित किया गया।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम (एमएससीएस अधिनियम), 2002

1.3 बिना किसी एक राज्य तक सीमित रहे, एक से अधिक राज्यों में सदस्यों के हितों की रक्षा करने, स्व-सहायता तथा पारस्परिक सहयोग के आधार पर जन-संस्थाओं के रूप में सहकारी सोसाइटियों के स्वैच्छिक गठन तथा लोकतांत्रिक कार्यकरण को सुविधाजनक बनाने और उन्हें अपने आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान को प्रोत्साहित करने में सक्षम बनाने हेतु एवं कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से सहकारी सोसाइटियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम, की आवश्यकता विभिन्न सहकारी सोसाइटियों, विभिन्न सहकारी सोसाइटियों के परिसंघों के साथ-साथ सरकार द्वारा भी महसूस की जा रही थी। इस संबंध में चौधरी ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति के प्रतिवेदन में एक आदर्श सहकारिता कानून का सुझाव दिया गया था। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर, विद्यमान बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के स्थान पर एक प्रस्तावित विधान, अर्थात् बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2000 प्रस्तावित किया गया, जिसे संसद में पुरःस्थापित किया गया। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक को 3 जुलाई, 2002 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और संविधिक रूप से यह बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के रूप में अधिनियमित किया गया।

संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011

1.4 संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 ने भारत के संविधान में भाग- नौ-ख को जोड़ा गया। यह भाग सहकारी सोसाइटियों के प्रावधानों से संबंधित है। सभी केंद्रीय और राज्य सहकारी अधिनियमों को इसके प्रारंभ से एक वर्ष के अंदर अर्थात् दिनांक 15.02.2013 तक संवैधानिक संशोधन के साथ संविधान के भाग IX-ख को रद्द कर दिया क्योंकि इसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के विशिष्ट उपबंध के अनुसार बहुमत में राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। तत्पश्चात्, भारत सरकार

ने माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध एक सिविल अपील दायर की, जिसमें दिनांक 20.07.2021 के अपने बहुमत के निर्णय में उल्लेख किया गया कि भारत के संविधान का भाग IX-ख केवल तभी तक प्रभावी है, जब तक इसका संबंध विभिन्न राज्यों और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों दोनों में यह बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों से संबंधित हो।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन की आवश्यकता

1.5 उपरोक्त घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, सहकारिता मंत्रालय, जो केंद्रीय स्तर पर "सहकारिता" विषय से संबंधित नोडल मंत्रालय है, ने उल्लेख किया कि मौजूदा विधान में व्याप कमियों को दूर करने और निम्नलिखित सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप, बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों में अभियासन को सुदृढ़ करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम को संविधान (सत्तानवे) (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुसार सुसंगत बनाने के लिए इसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है:—

स्वैच्छिक एवं खुली सदस्यता;

प्रजातांत्रिक रूप से सदस्य नियंत्रण ;

सदस्यों की आर्थिक भागीदारी;

स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता ;

शिक्षण, प्रशिक्षण एवं सूचना;

सहकारिताओं में सहकारिता ; और

समुदाय से जुड़े सरोकार ।

1.6 सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, कुछ बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों में पाए गए कमियों के कुछ मामलों का समाधान करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है। उदाहरण के लिए, कुछ बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों में वित्तीय गवन, चुनाव करने में विलम्ब और विवाद, लेखा परीक्षकों का पक्षपातपूर्ण चयन और भर्ती में पक्षपात, सदस्यों की सक्रिय भागीदारी में कमी आदि के बारे में शिकायतें मिली हैं। काफी समय से घटनाक्रम के परिणामस्वरूप भी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों में सहकारी कार्यों के संचालन को सुदृढ़ करने के लिए अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, विभिन्न सुधारों को सक्रिय रूप से लागू करने की आवश्यकता है, जैसे पंजीकरण प्रक्रिया को सुलम बनाकर 'व्यापार को सुगम बनाना' डिजिटल पंजीकरण की अनुमति देना, सदस्यता की प्रक्रिया को अधिक सार्थक और सक्रिय बनाना, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सूचना अधिकारी नियुक्त करना, सदस्यों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल नियुक्त करना आदि।

1.7 सहकारिता मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया कि निदेशकों की संख्या, उनसे संबंधित शर्तें, बोर्ड में सदस्यों की भागीदारी, निदेशक मंडल में कमजोर वर्गों का आरक्षण, चुनाव प्राधिकरण, कतिपय आधारों पर बोर्ड के अधिक्रमण और निलंबन, लेखा परीक्षा, आम निकाय की बैठकों का आयोजन, सूचना प्राप्त करने का अधिकार और विभिन्न अपराधों और शास्त्रियों से संबंधित उपबंधों जिन्हें पहले ही संविधान (सत्तानवे) (संशोधन) अधिनियम, 2011 के माध्यम से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के गठन करते हुए शामिल किया जा चुका है। इसलिए, इन उपबंधों को उपर्युक्त संशोधनों के माध्यम से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में शामिल किया जाना है। इनमें से अनेक सुधार पहले ही कई राज्य के कानूनों में शामिल किए जा चुके हैं। अनेक राज्यों में सहकारी निकायों के चुनाव करने के लिए चुनाव प्राधिकरण पहले ही स्थापित किया जा चुका है। विभिन्न राज्यों के कानूनों में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी संबंधी उपबंध भी शामिल किए गए हैं।

1.8 सहकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रुग्ण बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के पुनरुद्धार के लिए लाभकारी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों द्वारा किए गए योगदान से एक निधि बनाए जाने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा, बैंकिंग गतिविधि करने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों से संबंधित संवैधानिक उपबंधों को यह निर्दिष्ट करते हुए समाविष्ट करने की

आवश्यकता है कि समावेशन, विनियमन और समापन से संबंधित मामलों के संबंध में, बहुराज्य सहकारी सोसाइटियाँ, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी, बशर्ते कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी पर भी लागू होंगे।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022

1.9 बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 को 7 दिसंबर, 2022 को लोक सभा में पुरस्थापित किया गया। विधेयक का उद्देश्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के कुछ उपबंधों में संशोधन करना है। सहकारिता मंत्री ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 के साथ संलग्न 'उद्देश्यों और कारणों का कथन' में बताया कि विधेयक अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है, अर्थात्:—

- (i) मूल अधिनियम की धारा 41 में संशोधन करना ताकि एक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड की संरचना में सुधार किया जा सके;
- (ii) मूल अधिनियम की धारा 45 को प्रतिस्थापित करना ताकि "सहकारी चुनाव प्राधिकरण" के रूप में एक प्राधिकरण की स्थापना की जा सके जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन से अनधिक सदस्य होंगे जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। उक्त प्राधिकरण को सहकारी क्षेत्र में चुनावी सुधार लाने की दृष्टि से स्थापित करने का प्रस्ताव है;
- (iii) "रुग्ण बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों" के पुनरुद्धार के लिए "सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना" से संबंधित एक नई धारा 63क अंतर्विष्ट करने के लिए;
- (iv) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक वार्षिक कारोबार या जमा राशि वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के लिए "समवर्ती लेखापरीक्षा" से संबंधित एक नई धारा 70क अंतर्विष्ट करने के लिए;
- (v) "शिकायतों के निवारण" से संबंधित एक नया अध्याय 9क अंतर्विष्ट करने के लिए और इस उद्देश्य के लिए, केंद्र सरकार, सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों की जांच के लिए एक क्षेत्राधिकार के साथ एक या अधिक "सहकारी लोकपाल" नियुक्त कर सकती है;
- (vi) मूल अधिनियम की धारा 104 में संशोधन करना ताकि अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों पर मौद्रिक शास्ति बढ़ाई जा सके;
- (vii) ऐसी सोसाइटी के सदस्यों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के मामलों और प्रबंधन से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए "सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 106 को प्रतिस्थापित करने के लिए; और
- (viii) इलेक्ट्रॉनिक रूप में "आवेदन, दस्तावेज, रिटर्न, विवरण, खातों के विवरण की फाइलिंग" से संबंधित एक नई धारा 120क अंतर्विष्ट करने के लिए।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति

1.10 बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 को जांच और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए संसद द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया है। इस संबंध में प्रस्ताव 20 दिसंबर, 2022 को लोकसभा द्वारा स्वीकृत किया गया था और 21 दिसंबर, 2022 को राज्यसभा द्वारा उस पर सहमति दी गई थी। संयुक्त समिति में 31 सदस्य हैं जिनमें से 21 सदस्य लोक सभा से और 10 सदस्य राज्य सभा से हैं। श्री चंद्र प्रकाश जोशी, संसद सदस्य (लोक सभा)

इस समिति के सभापति हैं। समिति ने विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों पर सहकारिता मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक तथा विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। समिति ने सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय स्तर के संघों के विचारों को भी सुना। समिति ने कुछ प्रमुख बहुराज्य सहकारी समितियों के विचार भी सुने। निम्नलिखित अध्याय समिति द्वारा विधेयक की खंडवार जांच से संबंधित है।

अध्याय-दो

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 की खंड-वार जाँच

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 के खंड 1 में निम्नवत् वर्णित हैः—

“1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।”

मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) के पश्चात् एक व्यापक परंतुक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का अनुरोध

2.2 संशोधन विधेयक की जांच के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने समिति के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए हैं कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का प्रभाव बैंककारी विनियमन अधिनियम के कुछ उपबंधों पर पड़ेगा। इसके अलावा, यद्यपि बैंककारी विनियमन अधिनियम एक विशेष कानून है, तथापि इसकी अलग-अलग व्याख्याओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार, भविष्य में उत्पन्न होने वाले सभी संभावित विवादों की भविष्यवाणी करना संभव नहीं हो सकता है और इसलिए, नीचे दी गई धारा 2 के खंड (ख) के पश्चात् एक व्यापक परंतुक को अंतःस्थापित किया जा सकता हैः—

“परन्तु यह है कि सहकारी बैंक के मामले में, इस अधिनियम के उपबंध बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के उपबंधों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, निदेशों या अनुदेशों के अध्यधीन लागू होगा।”

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियां

2.3 सहकारिता मंत्रालय से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए उपर्युक्त सुझाव पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए कहा गया। अपने लिखित अनुरोध में, मंत्रालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं—

“प्रस्तावित उपबंध 120 खंड संविधान के अनुच्छेद 243 यज्ञ और अनुच्छेद 243 यठ के तीसरे परंतुक के अनुरूप है।

- अंतरमंत्रालयी परामर्श की प्रक्रिया के दौरान, वित्तीय सेवाएं विभाग ने दिनांक 04.10.2022 के अपने पत्र के माध्यम से बताया था कि प्रस्तावित संशोधित विधेयक व्यापक रूप से बैंककारी विनियमन अधिनियम के अनुरूप है और इसलिए वित्तीय सेवाएं विभाग संशोधन विधेयक का समर्थन करता है और उसका समर्थन करता है। इसके अलावा, वित्तीय सेवाएं विभाग बैंककारी विनियमन अधिनियम को संविधान के अनुरूप करने के लिए इसमें यथोचित संशोधन करेगा। सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) ने भी दिनांक 19.01.2023 को आयोजित हुई संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में यह बताया था।
- प्रचलित प्रथा के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न कानूनों, जैसे भारतीय कंपनी अधिनियम या विभिन्न सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के तहत निर्गमित संस्थानों को बैंकिंग लाइसेंस दिया जाता है। ऐसे सभी संस्थान, संबंधित अधिनियमों जिनके अधीन जो शामिल किए गए हैं, के साथ-साथ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित होते हैं। स्पष्टता लाने के लिए संशोधन विधेयक, धारा 120 खंड (का अंतःस्थापन) का प्रस्ताव करता है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के उपबंध, बहुराज्य सहकारी बैंक पर उनको शामिल करना, विनियमन और परिसमापन से संबंधित मामलों पर लागू होंगे, बशर्ते कि बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध भी लागू होंगे।”

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें

2.4 समिति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए प्रस्ताव और सहकारिता मंत्रालय के उत्तर पर चर्चा की। समिति में निष्कर्ष निकाला कि संशोधित अधिनियम की धारा 120ख में अंतःस्थापन और वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा दिए गए अश्वासन की बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में उपयुक्त संशोधन किए जाने में भारतीय रिजर्व बैंक की चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। अतः समिति ने निर्णय लिया कि मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) के पश्चात् व्यापक उपबंध के जोड़े जाने की आवश्यकता नहीं है।

खंड सं. 2

मूल अधिनियम में उपबंध

2.5 “धारा 3: परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “कार्यक्षेत्र” से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जहां से सदस्यों के रूप में व्यक्तियों को प्रवेश दिया गया है;”

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.6 “बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,—

खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

‘(कक) “प्राधिकरण” से धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण अभिप्रेत है;”

प्रस्तावित संशोधन के पीछे का तर्क

2.7 "संविधान के अनुच्छेद 243 यट (2) की तर्ज पर।

निर्वाचन सुधार

सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की परिभाषा का अंतःस्थापन"

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें

2.8 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया, जो संविधान के अनुच्छेद 243यट (2) के अनुरूप है।

मूल अधिनियम में उपबंध

2.9 “3(घ) “केन्द्रीय रजिस्ट्रार” से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सहकारी सोसाइटियों का केन्द्रीय रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उस धारा की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कोई अधिकारी भी है;”

2.10 विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

3(घ) को निम्नलिखित के द्वारा अंतःस्थापित किया जाएगा:

‘केन्द्रीय रजिस्ट्रार’ से संविधान के अनुच्छेद 243यज (घ) का खंड (घ) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सहकारी सोसाइटियों का केन्द्रीय रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उस धारा की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कोई अधिकारी भी है।”

प्रस्तावित संशोधन के पीछे का तर्क

- 2.11 “केन्द्रीय पंजीयक की परिभाषा में संशोधन ताकि इसे संविधान के अनुच्छेद 243ZH(f) के अनुरूप किया जा सके।”
- 2.12 केंद्रीय रजिस्ट्रार का अर्थ और संबंधित धारा में संशोधन करने की आवश्यकता के बारे में पूछे जाने पर, सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने विधेयक की खंडवार जांच के दौरान बताया: —

केन्द्रीय रजिस्ट्रार केवल एक होता है। धारा 4 (1) में कहा गया है कि “सरकार ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है।” इसमें कहा गया है कि “एक केंद्रीय रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकता है।” यह संविधान के अनुरूप है। फिर, धारा 4 (1) में कहा गया है कि “... और केन्द्रीय रजिस्ट्रार की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकेगी, जिन्हें वह ठीक समझे।” वे केन्द्रीय रजिस्ट्रार नहीं हैं।

परिभाषा में यह उपबंध संविधान से लिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रार की परिभाषा, अनुच्छेद 243 यजच में वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रार का अर्थ है- बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय रजिस्ट्रार। यह एक पहलू है। जो अधिनियम, जो इससे पहले था, उसके साथ-साथ जिस धारा को हम पढ़ रहे हैं, उसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति को-एक व्यक्ति को सहकारी सोसाइटियों का केन्द्रीय रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी और केन्द्रीय रजिस्ट्रार की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकेगी, जिन्हें वह ठीक समझे। मुद्दा यह है कि, जिसे भी केन्द्रीय रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है, वह केन्द्रीय रजिस्ट्रार नहीं बनता है। शेष इसका वैश्वासिक हिस्सा आता है, वैसे अन्य लेख, जिन्हें संदर्भित किया गया था...”

- 2.13 जब उनसे केन्द्रीय रजिस्ट्रार और “केन्द्रीय रजिस्ट्रार की शक्ति” का प्रयोग करने के लिए अधिकार प्राप्त किसी भी अधिकारी को शामिल करने के बीच विरोधाभास को स्पष्ट करने के लिए कहा गया तो, सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने आगे विस्तार से बताया कि: —

“... केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि प्रयोग की जा सकने वाली कोई भी शक्तियां, जो शायद किसी अन्य विधि का हिस्सा हैं, कि कंपनी का एक रजिस्ट्रार हो सकता है और केन्द्र सरकार किसी अन्य व्यक्ति को कंपनी रजिस्ट्रार की कतिपय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। इसी प्रकार, कार्य के भार या अनिवार्यता के आधार पर, जो वस्तुतः किसी विधि का हिस्सा है, जिसमें भी इसी प्रकार कहा गया है, और संविधान या धारा 4(1), 4(2) के साथ कोई विरोधाभास नहीं है कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली कोई शक्तिका आशय यह नहीं है कि वह व्यक्ति, जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार बन जाता है, और इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय रजिस्ट्रार की शक्ति का उपयोग कर सकता है, और इसे भी ‘बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण की शक्ति के अलावा’ कहते हुए सीमित कर दिया गया है, क्योंकि शायद यही प्राथमिक कार्य है, यह ऐसी सोसाइटी के संबंध में होगा। जहाँ 1,500 सोसाइटियां हैं। रजिस्ट्रार के पास कतिपय ऐसी शक्तियां होती हैं, जिन्हें केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित की जाने वाली आकस्मिकताओं के माध्यम से और ऐसे मामलों की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है कि केन्द्रीय रजिस्ट्रार की अधिसूचना की कौन-सी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार अधिसूचित किए गए व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, इसका प्रयोग किसी अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति केन्द्रीय रजिस्ट्रार बन जाता है...”

मूल अधिनियम में उपबंध

- 2.14 (च) “सहकारी बैंक” से ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो बैंककारी कारबार करती है;”

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

- 2.15 “(ख) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

“(चक) “सहकारी ऑम्बुडसमैन” से धारा 85क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सहकारी ऑम्बुडसमैन अभिप्रेत है;”

प्रस्तावित संशोधन के पीछे का तर्क

2.16 “धारा 85क के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला सहकारी ऑफिसमैन की परिभाषा का अंतःस्थापन किया गया है।”

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.17 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया, जो संविधान के अनुच्छेद 243यज (च) के अनुरूप है

मूल अधिनियम में उपबंध

2.18 “(झ) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या ऐसी सोसाइटियों के वर्ग के संबंध में सहकारी वर्ष से उस वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष और जहां ऐसी सोसाइटी या ऐसे वर्ग की सोसाइटियों के लेखाओं का, केन्द्रीय रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी से, किसी अन्य दिन को तुलनपत्र तैयार किया जाता है, वहां उस दिन को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;”

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.19 “खंड (झ) में, “सहकारी वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “सहकारी वर्ष या वित्तीय वर्ष” शब्द रखे जाएंगे:”

प्रस्तावित संशोधन के पीछे का तर्क

2.20 “सभी मामलों को कवर करने के लिए क्योंकि कुछ बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां ‘वित्तीय वर्ष’ और कुछ ‘सहकारी वर्ष’ शब्दों का प्रयोग कर रही हैं।”

समिति द्वारा जांच

2.21 सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों के बारे में जानकारी दिए जाने के दौरान, समिति ने सहकारी वर्ष और वित्तीय वर्ष की अलग-अलग परिभाषा के पीछे के तर्क के बारे में पूछा, जबकि दोनों की समाप्ति 31 मार्च को होती है। इस संबंध में, सहकारिता मंत्रालय ने अपने जानकारी पश्चात् उत्तरों में निम्नवत् बताया:—

“मौजूदा बहुराज्या सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 3(i) ‘सहकारी वर्ष’ को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ किसी वर्ष के मार्च महीने के 31वें दिन को समाप्ति वर्ष है और जब ऐसी सोसाइटी या ऐसी सोसाइटियों के वर्ग की लेखाकर्म को, केन्द्रीय पंजीयक के पूर्व अनुमोदन से, उस दिन वर्ष की समाप्ति पर जब किसी अन्यक दिन तुलन कर की जाती है।

संशोधन विधेयक के खंड 2 (उपधारा 3(i)) के द्वारा ‘वित्तीय वर्ष’ शब्दों को ‘सहकारी वर्ष’ के साथ अंतर्विष्ट किया जा रहा है ताकि किसी अस्पष्टहता को दूर किया जा सके और सभी दशाओं को शामिल किया जा सके क्योंकि कुछ बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों द्वारा ‘वित्तीय वर्ष’ और कुछ के द्वारा ‘सहकारी वर्ष’ का प्रयोग किया जाता है।”

हितधारकों द्वारा सुझाव

2.22 नावार्ड ने ‘सहकारी वर्ष’ या ‘वित्तीय वर्ष’ के स्थान पर शब्द ‘वित्तीय वर्ष’ का प्रयोग करने का सुझाव दिया है।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.23 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया। चूंकि सहकारी वर्ष और वित्त वर्ष एक ही समय अवधि अर्थात् प्रथम वर्ष के पहले अग्रैल से अगले वर्ष के इकतीस मार्च तक को दर्शाते हैं, अतः समिति ने महसूस किया कि विधेयक में सहकारी वर्ष और वित्त वर्ष दोनों का उल्लेख नहीं किया जा सकता। अतः समिति, सिफारिश करती है कि विधेयक में प्रस्तावित संशोधन को निम्नानुसार पढ़ा जाए:—

"खंड (i) में, "सहकारी वर्ष" शब्दों के स्थान पर "वित्त वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।"

मूल अधिनियम में उपबंध

2.24 "(ध)"अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;"

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.25 "खंड (ध) में, "आधिकारिक राजपत्र" शब्दों के पश्चात्, 'और "अधिसूचित" पद का इसके सजातीय अर्थों तथा व्याकरणिक रूपभेदों के साथ तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।"

प्रस्तावित संशोधन के पीछे का तर्क

2.26 "सभी संभावनाओं को कवर करने के लिए, अधिसूचना की परिभाषा को विस्तृत किया गया है।"

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.27 समिति ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 3

मूल अधिनियम में उपबंध

2.28 "धारा 7: पंजीकरण

(2) केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का निपटारा उसके द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(3) जहाँ केन्द्रीय रजिस्ट्रार किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को रजिस्टर करने से इंकार करता है वहां वह इंकार करने वाले ऐसे आदेश को इंकार करने के कारणों सहित, यथास्थिति, आवेदक या आवेदकों को, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चार मास भी अवधि के भीतर, संसूचित करेगा।

परंतु यह कि इंकार करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदकों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है।

परंतु यह और कि यदि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट चार मास की अवधि के भीतर निपटारा नहीं किया जाता या केन्द्रीय रजिस्ट्रार उस अवधि के भीतर इंकार का आदेश संसूचित करने में असमर्थ रहता है तो आवेदन रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया समझा जाएगा और केन्द्रीय रजिस्ट्रार इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।"

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.29 "(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय रजिस्ट्रार, किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा यदि समादर्त पूँजी का कुल मूल्य और तरलता सहित आरक्षितियों का उपबंध, बचत-उधार सोसाइटी के कारबार में लगी प्रस्तावित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट निवेश और अन्य विवेकपूर्ण संनियम ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार होंगे जो विनिर्दिष्ट किए जाएँ।"

परंतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ होने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के भीतर ऐसे मानकों को पूरा करेगी :

परंतु यह और कि यदि बहुराज्य प्रत्यय सोसाइटी की तरलता, निवेश, विवेकपूर्ण संनियम और अन्य मानदंड, उपर्युक्त उल्लिखित अवधि के भीतर ऐसे मानकों को पूरा नहीं करती है, तब केन्द्रीय रजिस्ट्रार को ऐसे निवेश जारी करने की शक्ति होगी जिन्हें वह ऐसी सोसाइटी के प्रति सुसंगत कार्रवाई करने के लिए समुचित समझता है :

परंतु यह और भी कि बहुराज्य सहकारी बैंक के मामले में, प्रदत्त पूँजी का कुल मूल्य और उपनियमों में उपबंधित तरलता मानकों के साथ आरक्षित के उपबंध ऐसे होंगे जैसा कि समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिकथित करे।

(3) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा उनके द्वारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा :

परन्तु केन्द्रीय रजिस्ट्रार, आवेदन में भूल, यदि कोई हो, के सुधार के लिए, आवेदक के अनुरोध पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं तीन मास की अवधि को ऐसी अतिरिक्त दो मास की अवधि से अनधिक अवधि तक विस्तार कर सकेगा।

(4) जहां केन्द्रीय रजिस्ट्रार बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को रजिस्टर करने से इंकार कर देता है, वहां वह ऐसे इंकार करने का कारण बताते हुए, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदक को सूचित करेगा :

परंतु इंकार का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो :

परंतु यह और कि यदि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का निपटारा उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है या केन्द्रीय रजिस्ट्रार उस अवधि के भीतर इंकार के आदेश को सूचित करने में असफल रहता है तो आवेदन रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया समझा जाएगा और केन्द्रीय रजिस्ट्रार इस अधिनियम तथा तद्वीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।”

प्रस्तावित संशोधन के पीछे का तर्क

शासन का सुदृढ़ीकरण और पारदर्शिता

2.30 श्रिफ्ट और क्रेडिट बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के लिए कोई वित्तीय मानक मौजूद नहीं थे जिससे उनके द्वारा कदाचार की संभावना बनी रहती थी। संशोधित उपबंध वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करेगा। पहले से मौजूद क्रेडिट सोसाइटियों को इन मानकों को पूरा करने के लिए 5 वर्ष का समय मिलेगा। बहुराज्य सहकारी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों का अनुपालन किया जाता रहेगा।

सुगम व्यापार

2.31 इससे त्वरित पंजीकरण प्रक्रिया और सुगम व्यापार सुनिश्चित होगा। पंजीकरण आवेदनों में हुई किसी भूल की दशा में, आवेदन रद्द करने के बजाए सुधार हेतु अतिरिक्त समय दिया जाएगा।”

समिति द्वारा जांच

2.32 सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा विधेयक में किए गए प्रस्तावों के बारे में जानकारी दिए जाने के दौरान समिति ने इंगित किया कि धारा 7 (2 और 3) के अंतर्गत विवेकपूर्ण मानदंडों के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस पर सहकारिता मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि मौजूदा अधिनियम में क्रेडिट बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के लिए विवेकपूर्ण मानदंड का कोई उपबंध नहीं है जिसकी वजह से कदाचार की संभावना रहती है। धारा 7 में संशोधन विवेकपूर्ण मानदंडों का उपबंध करता है, जो क्रेडिट और श्रिफ्ट के व्यवसाय में शामिल सभी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होंगे। इन्हें संबंधित नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। संशोधित उपबंध वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करेगा। बहुराज्य सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों का अनुपालन करना जारी रखेंगे।

2.33 विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों पर भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के दौरान, समिति ने विधेयक के खंड 3 में किए गए प्रस्ताव पर भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों के बारे में पूछा और यह भी पूछा कि वर्तमान में श्रिफ्ट और क्रेडिट में संलग्न/लगे बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां या बहुराज्य सहकारी बैंक किस तरह से विनियमित किए जाते हैं। इस संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में निम्नानुसार कहा है:—

“सभी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं हैं। बैंकिंग संबंधी कार्यकलाप कर रहे बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को ही बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के विभिन्न उपबंधों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेन्स दिया जाता है और विनियमित किया जाता है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अध्याय-पाँच के उपबंध बैंकिंग कारोबार कर रहे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी पर लागू होते हैं, जिसमें बैंकिंग का कारोबार भी करने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी शामिल है। इस प्रकार, बैंकिंग और बचत के क्षेत्र में लगी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के विनियमन की वर्तमान स्थिति बैंककारी विनियमन अधिनियम के अध्याय-पाँच के उपबंधों के अनुसार है और भारतीय रिजर्व बैंक को विनियामक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अध्याय-पाँच में किए गए सभी संशोधन, जिसमें 2020 में किए गए संशोधन भी शामिल है, बैंकिंग का कारोबार कर रही बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां पर भी लागू होते हैं। बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के बाद, बैंककारी विनियमन अधिनियम की प्रयोज्यता का विस्तार पूँजी और तरलता संबंधी उपबंधों के अलावा सहकारी बैंकों की शेयर धारिता, प्रबंधन, लेखापरीक्षा, समामेलन/पुनर्निर्माण और परिसमापन (समापन) जैसे क्षेत्रों में भी किया गया था। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन में किसी उपबंध के अभाव में, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 जैसे अन्य मौजूदा अधिशासी अधिनियमों में परिणामी संशोधनों की आवश्यकता है, प्रस्तावित संशोधनों से कुछ विरोधाभास उत्पन्न होते हैं।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 की प्रस्तावित धारा 7(2) के तहत, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की पूँजी और तरलता उपबंध बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अधिशासित होंगे, जबकि बहुराज्य सहकारी बैंकों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार शासित होंगे। एक सहकारी सोसाइटी जो अपने सदस्यों से संसाधनों को केवल उन सदस्यों के लाभ के लिए उपयोग करने के लिए एकत्र करती है के विपरीत, किसी सहकारी बैंक के धन का मुख्य और पर्याप्त स्रोत गैर-सदस्य सार्वजनिक जमा है। इसकारण, जमाकर्ता, जो सहकारी बैंक के अभिशासन का हिस्सा नहीं है के हितों की रक्षा करने के लिए, चालू संस्था के रूप में पूँजी की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक के पास अल्पकालिक देनदारियों को पूरा करने के लिए नकदी सहित पर्याप्त तरल आस्तियां हैं, पूँजी और तरलता से संबंधित विनियमों पर धारा 7(2) के तीसरे परंतुक के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्राधिकार पर उचित रूप से बल दिया गया है।

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 का उद्देश्य सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के 'दोहरे विनियमन' के मुद्दे को सहकारी सिद्धांतों के अनुरूपता या अनुरूपता के सिद्धांत का त्याग किए बिना निराकरण करना था। बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों के लिए एक अभिसरण लेकिन आनुपातिक और जोखिम-आधारित विनियामक दृष्टिकोण अपनाया था ताकि अन्य बैंकों की तुलना में अनुचित विनियामक मध्यस्थता मौजूद न हो क्योंकि यह सहकारी क्षेत्र और उनके जमाकर्ताओं के हित के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा, हमारा अनुभव बताता है कि अतीत में कई शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की विफलता का मुख्य कारण, अभिशासन या प्रबंधन से संबंधित मुद्दे हैं जो कि यूसीबी के विनियमन और पर्यवेक्षण के वर्तमान फोकस में से एक है। उक्त के मद्देनजर, यह महसूस किया गया है कि ऐसी सोसाइटियों द्वारा की जाने वाली बैंकिंग संबंधी गतिविधियों के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम सहित किसी भी अन्य कानून पर बैंककारी विनियमन अधिनियम को प्रधान रूप से जारी रखने की आवश्यकता है।”

हितधारकों के सुझाव

2.34 जहां तक विधेयक के उस खंड में प्रस्ताव का संबंध है, जिसमें पंजीकरण संबंधी मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) और (3) को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, नेफकॉब ने सुझाव दिया है कि इस अंतःस्थापन में अंतर्विष्ट कोई भी उपबंध उन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, जिन्हें बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त है, पर लागू नहीं होगा और उनपर बैंककारी विनियमन अधिनियम (बैंककारी विनियमन अधिनियम) के उपबंध और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश भी लागू होंगे। समिति को यह बताया गया है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ-साथ सहकारिता मंत्रालय के दोहरे विनियमन का सामना करना पड़ रहा है और यद्यपि, इसके खंड में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश का अनुपालन शामिल है, तथापि प्रस्तावित संशोधन विनियमन की रेखा को धुंधला कर सकते हैं। अतः, उन्होंने यूसीबी को इन उपबंधों से छूट

प्रदान करने का अनुरोध किया है, क्योंकि बैंककारी विनियमन अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम व्यक्त की गई इन चिंताओं का ध्यान रखता है।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियां

2.35 प्रस्तावित धारा 7 के तीसरे परंतुक में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बहुराज्य सहकारी बैंक के मामले में, उप-विधियों में प्रदान किए गए तरलता मानदंडों के साथ प्रदत्त पूंजी और रिजर्वों के उपबंध का कुल मूल्य ऐसा होगा, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

2.36 प्रचलित प्रथा के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम या विभिन्न सहकारी सोसाइटी अधिनियमों जैसे विभिन्न कानूनों के अधीन पंजीकृत संस्थानों को बैंकिंग लाइसेंस दिए जाते हैं। ऐसे सभी संस्थान, उन संबंधित अधिनियमों जिनके तहत उनका निगमन हुआ है और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित होते हैं। इस प्रकार की स्थिति में, ऐसी सभी संस्थाओं के लिए दोहरा विनियमन होता है। स्पष्टता हेतु, संशोधन विधेयक धारा 120ख (नया अंतःस्थापन) का प्रस्ताव करती है जिसके द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के उपबंध बहुराज्य सहकारी बैंक के निगमन, विनियमन और परिसमापन से संबंधित मामलों पर लागू होते हैं। तथापि, बहुराज्य सहकारी बैंकों की दशा में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध भी लागू होंगे। इसलिए, प्रस्तावित उपबंध संविधान के अनुसार हैं और इनमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

2.37 संशोधन विधेयक के खंड 3 और मूल अधिनियम की धारा 7 में प्रस्तावित संशोधन के औचित्य की व्याख्या करने के लिए कहे जाने पर, सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:—

“....हमने शासन को सुदृढ़ करने और पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा किया है। महोदय, पैरा 2(i) बहुराज्य सहकारी बैंकों के लिए नहीं है; यह उन सहकारी सोसाइटीयों के लिए है जो क्रेडिट और अन्य संबंधित कार्य कर रही हैं। यह आखिरी पैरा है जो बैंकों के लिए साफ तौर पर यही कहता है। क्रेडिट सोसायटीयों का विनियमन आरबीआई द्वारा नहीं की जाती है। उनके लिए, रजिस्ट्रार यह निर्धारित करेगा कि लिक्विडिटी मानदंड क्या होने चाहिए। चूँकि माननीय सदस्य ने एक और मुद्दा उठाया है और वह बार-बार उठाया जाएगा, मैं उस बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। संविधान के अनुसार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटीयों के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार या केंद्र सरकार को निगमन, विनियमन और विनियोग-अप का अधिकार दिया गया है। विनियमन के रूप में, पहले कंपनी का पंजीकरण होता है, फिर वह आरबीआई के मानदंडों को पूरा करती है और फिर उसे बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हो सकता है। इसी तरह, एक सहकारी सोसाइटी का पंजीकरण होगा, उसके उपविधि होंगे। इस अधिनियम में विनियम हैं कि बोर्ड के इतने सदस्य होने चाहिए, बोर्ड के सदस्यों की इतनी योग्यता होनी चाहिए। ये सभी विनियमों का हिस्सा हैं जिन्हें सहकारी सोसाइटी को पूरा करना होगा। एक बार यह सब हो जाने के बाद, सहकारी सोसाइटी आरबीआई के पास जाकर बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त कर सकती है। बैंकिंग लाइसेंस लेते ही बैंकिंग विनियमन अधिनियम के उपबंध भी लागू हो जाएंगे। यह इस अधिनियम की धारा 120ख में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसलिए, यह बहुत स्पष्ट है कि विनियमन हमेशा दोहरे होंगे, इस अर्थ में कि कितने निदेशक हैं, शेयरधारकों की बैठकें कैसे होती हैं, मतदान कैसे किया जाता है, आदि। जहां तक किसी सहकारी सोसाइटी के मूल रूप का संबंध है, यह उनके विनियमन का हिस्सा है। सहकारी सोसाइटी यदि बैंकिंग भी करना चाहती है, तो उसे अतिरिक्त रूप से बैंकिंग विनियमन अधिनियम का भी पालन करना होगा। यदि आपको याद हो, तो वित्त सचिव भी यहां आए थे और उन्होंने कहा था कि सरकार संविधान के मुताबिक बैंकिंग विनियमन अधिनियम में भी संशोधन कर रही है...’

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.38 समिति ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 4

मूल अधिनियम में उपबंध

“धारा 10: बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों की उपविधि:

2.39 (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी उपविधि निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के उपबंध कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) सोसाइटी का नाम, पता और कार्यक्षेत्र;”

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.40 “(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी उपविधि निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के उपबंध कर सकेगी, अर्थात् :

(क) नाम, पता (जिसके अंतर्गत ई-मेल पता भी है) ” और बहुराज्य सहकारी समिति का कार्यक्षेत्र;”

प्रस्तावित संशोधन के पीछे का तर्क

“सुगम व्यापार

2.41 बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के साथ तेज और प्रभावशाली संवाद हेतु पता के साथ इमेल का भी होना।”

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.42 समिति ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 5

मूल अधिनियम में उपबंध

2.43 “धारा 14: पते में परिवर्तन

प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कारबार का एक मुख्य स्थान होगा और विहित रीति से रजिस्ट्रीकृत पता होगा जिस पर सभी सूचनाएं और संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी।”

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.44 “धारा 14: पता

प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कारबार का एक मुख्य स्थान होगा और विहित रीति से इमेल पता सहित रजिस्ट्रीकृत पता होगा जिस पर सभी सूचनाएं और संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी।”

प्रस्तावित संशोधन के पीछे का तर्क

2.45 “सुगम व्यापार

बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के साथ तेज और प्रभावशाली संवाद हेतु पता के साथ इमेल का भी होना।”

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.46 समिति ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और प्रस्तावित संशोधन में पता के बाद “ ” के अंतर्वेशन का निर्णय लिया। अतः प्रस्तावित संशोधन निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—

"प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के पास व्यवसाय का मुख्य स्थान और एक पता होगा, जिसमें निर्धारित तरीके से पंजीकृत ई-मेल पता शामिल है, जिसके लिए सभी सूचना और संचार भेजे जा सकते हैं।"

खंड सं. 6

मूल अधिनियम में उपबंध

2.47 "धारा 17: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों और दायित्वों का समामेलन या अंतरण अथवा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का विभाजन

(9) जहां इस धारा के अधीन किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा पारित कोई संकल्प किन्हीं आस्तियों और दायित्वों के अंतरण के संबंध में है वहां वह संकल्प उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, और किसी हस्तांतरण पत्र के बिना अंतरिती में आस्तियों और दायित्वों के निहित होने का पर्याप्त हस्तांतरण पत्र होगा।"

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.48 "उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित का जाएगी :—

"(10) कोई सहकारी सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी के साधारण अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा मौजूदा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में विलय करने का विनिश्चय कर सकेगी:

परंतु ऐसा संकल्प संबंधित तत्समय प्रवृत्त राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के उपबंधों के अधीन होगा जिसके अधीन ऐसी सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत है।"

प्रस्तावित संशोधन के पीछे का तर्क

2.49 "मौजूदा अधिनियम में, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का दो या दो से अधिक राज्य सहकारी सोसाइटियों में विभाजन का उपबंध है। इसके अलावा, राज्य सहकारी समिति का बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में परिवर्तन का भी उपबंध है।

अब इस प्रस्तावित उपबंध से किसी राज्य सहकारी सोसाइटी का बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों में विलय हो सकेगा। तथापि, ऐसा विलय संबंधित राज्य सहकारी कानूनों और 2/3 सदस्यों द्वारा पारित संकल्प के अध्यधीन होगा।"

समिति द्वारा जांच

2.50 सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य सहकारी सोसाइटी के बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में विलय के नए उपबंध के संबंध में विधेयक के उपबंधों पर जानकारी दिए जाने के दौरान, जब समिति ने सुझाव दिया कि समान व्यावसायिक कार्य की शर्त होनी चाहिए, सहकारिता मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:—

"मौजूदा बहुराज्य सहकारी अधिनियम, 2002 की धारा 17 आस्तियों और देनदारियों का विलय या हस्तांतरण, या बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों का दो या दो से अधिक बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों या राज्य सहकारी सोसाइटियों में विभाजन से संबंधित है। इसके अलावा, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 22 के अधीन किसी राज्य सहकारी सोसाइटी को बहुराज्यी सहकारी सोसाइटी में परिवर्तित करने का उपबंध पहले से ही मौजूद है।

संबंधित राज्य सहकारी अधिनियमों और उसके सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा पारित संकल्प के अध्यधीन किसी राज्यी सहकारी सोसाइटी को मौजूदा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में विलय की अनुमति के लिए प्रस्तावित विधेयक में खंड 6 के माध्यम से मौजूदा धारा 17 में एक नई उपधारा 17(10) को शामिल करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इससे मौजूदा राज्य सहकारी सोसाइटियों को बहुराज्यी सहकारी सोसाइटी में विलय द्वारा अपनी व्यावहार्यता बढ़ाने एवं व्यापक उत्पादन द्वारा अधिक लाभ कमाने में मदद मिलेगी।

मौजूदा धारा 22 में और धारा 17 बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के विलय या विभाजन अथवा राज्य सोसाइटी को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में परिवर्तित होने के लिए समान व्यवसायिक कार्य करने की शर्त मौजूद नहीं है। विलय की अनुमति के लिए समान व्यावसायिक कार्य करने की शर्त रखने के माननीय संसद सदस्य के सुझाव को आगे जांच करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इससे लचीलापन और विविधीकरण में रुकावट आ सकती है।”

2.51 जब यह पूछा गया कि प्रस्तावित संशोधन (धारा 17 में) संघीय संरचना के विरुद्ध है, सहकारिता मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:—

“जी नहीं महोदय। मौजूदा बहुराज्य सहकारी अधिनियम, 2002 की धारा 17 आस्तियों और देनदारियों का विलय या हस्तांतरण, या बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों का दो या दो से अधिक बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों या राज्य सहकारी सोसाइटियों में विभाजन से संबंधित है। इसके अलावा, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 22 के अधीन किसी राज्य सहकारी सोसाइटी को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में परिवर्तित करने का उपबंध पहले से ही मौजूद है।

संबंधित राज्य सहकारी अधिनियमों और उसके सदस्यों की बहुमत द्वारा पारित संकल्प के 3/2 अध्यधीन, किसी राज्य सहकारी सोसाइटी को मौजूदा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में विलय की अनुमति के लिए प्रस्तावित विधेयक में खंड में एक नई उपधारा 17 के माध्यम से मौजूदा धारा (10)17 को शामिल करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इससे मौजूदा राज्य सहकारी सोसाइटी को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में विलय द्वारा अपनी व्यवहार्यता बढ़ाने एवं व्यापक उत्पादन द्वारा अधिक लाभ कमाने में मदद मिलेगी।

चूंकि, विलय राज्य सहकारी अधिनियमों के अध्यधीन ही होगा, इसलिए यह संघीय संरचना के उल्लंघन में नहीं है।”

2.52 भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने साक्षोपरांत उत्तर में बताया कि जहां तक बहुराज्य सहकारी बैंकों का संबंध है, प्रस्तावित संशोधनों का भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक प्रभावकारिता पर प्रभाव पड़ेगा और उन्होंने निम्नवत् प्रस्तुतीकरण को प्रभावों में से एक के रूप में रेखांकित किया है:—

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम में मौजूदा उपबंध दो अथवा दो से अधिक बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के बीच समामेलन को सक्षम बनाता है। धारा 17 के तहत उप-धारा (10) का प्रस्तावित अंतःस्थापन किसी भी सहकारी सोसाइटी को मौजूदा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में विलय करने में समर्थ बनाती है, वशर्ते कि ऐसा संकल्प उस समय के लिए लागू संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के उपबंधों के अधीन होगा जिसके तहत ऐसी सहकारी सोसाइटी पंजीकृत है। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी विनियमन अधिनियम 2020 के द्वारा संशोधित की धारा 44ए के अंतर्गत दो शहरी सहकारी बैंकों के बीच स्वैच्छिक समामेलन को उसके तहत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की जाने वाली धारा 45 के तहत अनिवार्य समामेलन के लिए योजना तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को शक्ति प्रदान करता है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (शहरी सहकारी बैंकों का समामेलन) निर्देश, 2020 जारी किए गए हैं जिसमें यूसीबी के स्वैच्छिक समामेलन के लिए नीति और प्रक्रिया शामिल है। धारा 44ए अपने आप में एक संहिता है और समामेलन के लिए सहकारी कानून (प्रस्तावित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक के अंतर्गत आवश्यक संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत भी नहीं है) के तहत किसी और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत, यूसीबी के लिए अनिवार्य समामेलन या पुनर्निर्माण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई योजना को मंजूरी देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। हालाँकि, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम की मौजूदा धारा 18 केंद्रीय रजिस्ट्रार को एक सहकारी बैंक के समामेलन अथवा पुनर्गठन की योजना तैयार करने का अधिकार देती है, जब बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 45(2) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिस्थगन का आदेश दिया गया हो। किसी सहकारी बैंक के स्वैच्छिक समामेलन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता के लिए किसी उपबंध की अनुपस्थिति परस्पर विरोधी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। यहां भी डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 2 (जीजी) का संदर्भ लिया जाए।

हितधारकों के सुझाव

2.53 एनएएफसीएआरडी ने एक मौजूदा सहकारी सोसाइटी को समान उद्देश्यों और कार्यों वाली मौजूदा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में विलय करने की अनुमति देने का सुझाव दिया है।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.54 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 7

मूल अधिनियम में उपबंध

2.55 “धारा 19: समनुषंगी संस्थाओं का संप्रवर्तन

(2) उपधारा (1) के अधीन संप्रवर्तित कोई समनुषंगी संस्था केवल तभी तक आस्तित्व में रहेगी जब तक कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का साधारण निकाय इसके आस्तित्व को आवश्यक समझता है। परंतु कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी किसी ऐसी समनुषंगी संस्था को संप्रवर्तित करते समय अपने कथित उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किए जा रहे कारबार या क्रियाकलाप के सारभूत भाग को अंतरित या समनुदेशित नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) कोई संस्था समनुषंगी संस्था समझी जाएगी यदि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी,—

- (i) ऐसी संस्था के प्रबंध तंत्र या निदेशक बोर्ड या शासी निकाय के सदस्यों को नियंत्रित करती है; या
- (ii) ऐसी संस्था के साधारण शेयरों के अभिहित मूल्य में आधे से अधिक धारित करती है; या
- (iii) यदि ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के एक या अधिक सदस्य, यथास्थिति, स्वयं या समनुषंगी संस्था के साथ या अपने संबंधियों सहित मिलकर, उस संस्था में साधारण शेयरों की बहुसंख्या धारण करते हैं;

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.56 “मूल अधिनियम की धारा 19 में, स्पष्टीकरण के खंड (क) में,—

- (i) उपखंड (ii) के अंत में आए “या” शब्द का लोप किया जाएगा ;
- (ii) उपखंड (iii) का लोप किया जाएगा।”

प्रस्तावित संशोधन के पीछे का तर्क

2.57 “शासन का सुदृढ़ीकरण और पारदर्शिता

इससे सहकारी सोसाइटीयों की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और कुछ सदस्यों द्वारा ऐसे समनुषंगी संस्थाओं में निवेश के फायदे, जहां सदस्य या उनके परिजनों द्वारा बहुमत शेयरों का धारण किया गया है, की घटनाओं में कमी आएगी।”

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.58 समिति ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 8

मूल अधिनियम में उपबंध

2.59 “धारा 22: सहकारी सोसाइटियों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में संपरिवर्तन

5(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार तदुपरि यह निदेश करते हुए आदेश करेगा कि सोसाइटी केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण की तारीख से उस राज्य में प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित विधि के अधीन सोसाइटी नहीं रह गई है।”

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.60 “मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (5) में, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ग) सहकारी सोसाइटी को, उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त ऐसी सहकारी सोसाइटी से संबंधित विधि के अधीन ऐसी सहकारी सोसाइटी को केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत संशोधन की प्रति सहित जारी किए गए और अग्रेषित किए गए प्रमाणपत्र की तारीख से विपंजीकृत किया गया समझा जाएगा।”

प्रस्तावित संशोधन के पीछे का तर्क

2.61 “सुगम व्यापार

इससे विलम्बता में कमी आएगी और सहकारी सोसाइटियों में सुगम व्यापार सुनिश्चित होगा। धारा 22 के तहत किसी मामले में विलय के लिए अनुमोदन राज्यों के सहकारी पंजीयों से परामर्श के पश्चात् दिया जाएगा।”

समिति द्वारा जांच

2.62 राज्य सहकारी सोसाइटी का बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में परिवर्तित होने पर राज्य सहकारी सोसाइटी के मानित विपंजीकरण की दशा में (धारा 22) – क्या होगा यदि राज्य समिति ने धोखाधड़ी किया हो।

विधेयक पर जानकारी दिए जाने के दौरान, समिति ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में परिवर्तित होने पर राज्य सहकारी सोसाइटी के मानित विपंजीकरण की स्थिति में राज्य समिति द्वारा धोखाधड़ी करने वाली राज्य सोसाइटी पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछा। उपर्युक्त के संबंध में सहकारिता मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में कहा, “बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की मौजूदा धारा 22 में, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में रूपांतरण के समय सहकारी सोसाइटियों के संबंधित राज्य रजिस्ट्रार (आरसीएस) से परामर्श किया जाता है और यदि सोसायटी के खिलाफ कोई शिकायत पाई जाती है, तो संबंधित आरसीएस को सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।”

हितधारकों का सुझाव

2.63 एनएएफसीएआरडी ने सहकारी सोसाइटियों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों में परिवर्तित करने के संबंध में, मूल अधिनियम की धारा 22 में निम्नानुसार 22(6) के रूप में एक अतिरिक्त खंड जोड़ने का अनुरोध किया है: –

“...राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के बहुराज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में परिवर्तित होने के पश्चात्राज्य सहकारी अधिनियम या राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम के उन उपबंधों का अनुपालन करता रहेगा, जो भूमि या अन्य संपत्तियों के पंजीकृत बंधक की सुरक्षा पर जारी किए गए ऋणों की वसूली के लिए लागू हो सकते हैं।”

कारण:— ऐसे उपबंध से दीर्घकालिक बंधक ऋणों की वसूली के लिए मूल अधिनियम में विशिष्ट उपबंधों के नहीं होने के कारण ऋण वसूली में संभावित बाधाओं को दूर किया जा सकेगा।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.64 समिति ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 9

मूल अधिनियम में उपबंध

2.65 “धारा 26: सोसाइटी का नाम मात्र का या सहयोगी सदस्य

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, यदि उसकी उपविधियों में इसके लिए उपबंध है, किसी व्यक्ति को नाममात्र के या सहयुक्त सदस्य के रूप में सम्मिलित कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई नाम मात्र का या सहयुक्त सदस्य ऐसी सोसाइटी के शेयरों में अभिदाय करने का हकदार नहीं होगा या उसके प्रबंध तंत्र में कोई हित नहीं रखेगा जिसके अंतर्गत मत देने, बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने या साधारण अधिवेशनों में भाग लेने का अधिकार आता है।”

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.66 “मूल अधिनियम की धारा 26 में,—

(i) परन्तुक में, ये शब्द कि “ऐसी सोसाइटी के शेयरों में अभिदाय करने का हकदार नहीं होगा” का लोप किया जाएगा;

(ii) परन्तुक के पश्चात्, इसमें निम्नलिखित नियम शामिल किए जाएँगे, अर्थातः—

जो हैं :—

“परन्तु ऐसा कोई नाम मात्र या सहयोगी सदस्य को गैर-वोटिंग शेयर जारी किए जा सकते हैं परन्तु उन्हें बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के प्रबंधन में कोई हित न हो जिसके अंतर्गत मत देने, बोर्ड के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने या साधारण सभा की बैठकों में भाग लेने का अधिकार होता है:

परंतु यह भी कि बहुराज्य सहकारी बैंक के मामले में, इस प्रकार के शेयरों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।”

प्रस्तावित संशोधन के पीछे का तर्क

2.67 “सहकारिता क्षेत्र द्वारा फण्ड जुटाने की समर्थता”

इससे एमएससीएस के पूंजी आधार में वृद्धि सुनिश्चित होगी और उनकी वृद्धि होगी। भा.रि. बैंक ने सहकारी बैंकों के लिए पहले से ही इसकी अनुमति दे दी है।”

समिति द्वारा जांच

2.68 विधेयक पर ब्रीफिंग के दौरान, समिति ने यह पाया कि पूंजी जुटाने के लिए नॉन-वोटिंग शेयरों के प्रावधान के मामले में जुटाई गई पूंजी से कदाचार को नियंत्रित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उपरोक्त विचार के संबंध में, सहकारिता मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:—

“धारा 26 के अंतर्गत विद्यमान बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में नाम मात्र या सहयोग सदस्यों को शेयरों को जारी करने की प्रतिबंध है। यह स्थिति बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के पूंजीगत अधम को प्रतिबंधित करती है

संशोधन विधेयक में, खंड 9 (धारा-26) के द्वारा बिना वोटिंग अधिकार, प्रबंधन में हित और निर्वाचित होने के अधिकार के बिना नाम मात्र/सहयुक्त सदस्यों को नॉन-वोटिंग शेयर जारी करने का प्रावधान प्रस्तावित है।

इससे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) अपना पूंजी आधार बढ़ाने में सक्षम होगी। आरबीआई ने दिनांक 08.03.2022 के अपने परिपत्र द्वारा सहकारी बैंकों के लिए पहले ही इसकी अनुमति दे दी है। एमएससीएस द्वारा वित्तीय कदाचार को रोकने के लिए वर्तमान अधिनियम के साथ-साथ संशोधन विधेयक में प्रस्तावित अन्य उपबंध भी हैं।"

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की टिप्पणियां

2.69 विधेयक में दिए गए प्रस्तावों पर आरबीआई के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के दौरान, समिति ने उपरोक्त प्रस्ताव पर आरबीआई की टिप्पणी मांगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक लिखित उत्तर में निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत कीं—

"संशोधन में यह प्रस्ताव है कि किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के नाम मात्र या सहयोगी सदस्यों को नॉन-वोटिंग शेर जारी किए जा सकते हैं, लेकिन उनके प्रबंधन में उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा, अर्थात् मत देने, बोर्ड के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने या सामान्य अधिवेशनों में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। संशोधन में आगे एक अन्य नियम प्रस्तावित किया गया है कि "परंतु यह भी कि बहुराज्य सहकारी बैंक के मामले में, इस प्रकार के शेर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।"

यह उल्लेख किया जा सकता है कि धारा 56 (एएसीएस) के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत, सहकारी बैंक द्वारा निर्देश जारी करने, शर्तों को निर्दिष्ट करने और ऐसे शेरों को जारी करने हेतु अनुमोदन देने संबंधी शक्ति आरबीआई के पास है। तदनुसार, आरबीआई ने दिनांक 8 मार्च, 2022 के परिपत्र डीओआर.सीएपी.आरईसी.92/09.18.201/2021-22 के माध्यम से "शेर पूंजी और प्रतिभूतियां जारी करना और उनका विनियमन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक" पर यूसीबी को दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नॉन-वोटिंग शेरों पर दिशानिर्देश शामिल हैं। आरबीआई ने 1 अप्रैल, 2022 को "मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्ति पर विवेकपूर्ण मानदंड - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)" जारी करने की शर्तों सहित वरीयता शेरों को जारी करने पर यूसीबी को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) (संशोधन) अधिनियम, 2022 ने इस पहलू पर बैंककारी विनियमन अधिनियम में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया है। धारा 26 में प्रस्तावित संशोधन स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि बहुराज्य सहकारी बैंक के मामले में, ऐसे शेर आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, विधेयक में एक नई धारा 105ए का प्रस्ताव किया गया है जिसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के उपबंध वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके विपरीत होंगे। इसलिए, जहां तक बैंकिंग गतिविधि करने वाले बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का संबंध है, विधेयक में यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट करने की आवश्यकता हो सकती है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम के प्रावधान प्रमुख रूप से बहुराज्य शहरी सहकारी बैंकों पर पूंजीगत साधनों के प्रकार पर लागू होंगे।"

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.70 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं.10

मूल अधिनियम में उपबंध

2.71 "धारा28: सम्यक संदाय किए जाने तक, सदस्यों द्वारा अधिकारों का प्रयोग न किया जाना

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य किसी सदस्य के अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने सदस्यता के संबंध में सोसाइटी को ऐसा संदाय न कर दिया हो या सोसाइटी में ऐसा हित न अर्जित कर लिया हो जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए।"

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.72 “बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य किसी सदस्य के अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को सभी संदाय कर दिया हो जिसमें सदस्यता के संबंध में सोसाइटी को संदाय कर दिया हो अथवा उत्पादों अथवा सेवाओं का लाभ लिया हो अथवा जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए, या सोसाइटी में ऐसा हित न अर्जित कर लिया हो जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए।”

प्रस्तावित संशोधनों के पीछे का तर्क

2.73 “संविधान के अनुच्छेद 243 यण(2) के अनुरूप यह सोसाइटी को सभी देय राशि का भुगतान सुनिश्चित करेगा और “ऐसे हित” शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा और सक्रिय सदस्यता को बढ़ावा देगा।”

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.74 समिति ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं.11

मूल अधिनियम में उपबंध

2.75 “धारा-29: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्य के लिए निर्हरता

कोई व्यक्ति, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि —

(ख) उसने लगातार दो वर्षों तक उपविधियों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम स्तर से कम की सेवाओं का उपयोग किया है; या”

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.76 “मूल अधिनियम की धारा 29 में, खंड (ख) हेतु, निम्नलिखित खंड के साथ परिवर्तित किया जाएगा, जो निम्नवत है:—

“(ख) वह लगातार दो वर्षों तक उपविधियों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम स्तर से कम के उत्पादों अथवा सेवाओं का उपयोग करने में असफल रहता है”

प्रस्तावित संशोधनों के पीछे का तर्क

2.77 “संविधान के अनुच्छेद 243 यण(2) के अनुरूप सक्रिय सदस्यता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसलिए ‘उत्पाद’ जैसे शब्द को ऐसे सदस्यों को निर्हर घोषित करने के लिए शामिल किया गया है, जो न्यूनतम सेवाओं/उत्पादों का उपयोग नहीं करते हैं।”

समिति द्वारा जांच

2.78 विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों पर सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा ब्रीफिंग के दौरान, एक सुझाव दिया गया कि सक्रिय सदस्यता संबंधी उपबंध को संशोधन विधेयक की धारा 29 में प्रस्तावित चुनाव लड़ने के लिए 5 में से 3 आम बैठकों में उपस्थिति में बदला जाना चाहिए। सहकारिता मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में इस संबंध में निम्नानुसार बताया:—

“सदस्यों के लिए निर्हरता से संबंधित अधिनियम की धारा 29 का मौजूदा उपबंध यह स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने एमएससीएस की लगातार तीन सामान्य अधिवेशनों में भाग नहीं लिया है और सामान्य अधिवेशनों में इस तरह की अनुपस्थिति को सदस्यों द्वारा क्षमा नहीं किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में निर्हर पाया जाता है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है।

संविधान का अनुच्छेद 243यण(2) सदस्यों द्वारा बैठक में भाग लेने की न्यूनतम आवश्यकता को शामिल करके सक्रिय सदस्यता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। इसलिए, चुनाव लड़ने के लिए पात्र होने के लिए कम से कम तीन लगातार सामान्य अधिवेशनों में भाग लेने के लिए धारा 45 (जे) में प्रस्तावित संशोधन धारा 29 के मौजूदा उपबंध के अनुसार है। इसलिए, यदि अनुपस्थिति को सामान्य निकाय द्वारा क्षमा कर दिया जाता है, तो वह सदस्य चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा।”

2.79 संक्षिप्त जानकारी दिए जाने के दौरान जब यह पूछा गया कि सदस्य के रूप में निर्हर हुए बिना किसी सदस्य को चुनाव से निर्हर कैसे ठहराया जा सकता है, तो सहकारिता मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित बताया:—

“मौजूदा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 की धारा 29 में, एमएससीएस का सदस्य होने पर निर्हरता का प्रावधान है, इसके अलावा, मौजूदा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 43 में, अलग से बोर्ड का सदस्य होने पर निर्हरता का उपबंध किया गया है।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का सदस्य होने पर निर्हरता की तुलना में बोर्ड के सदस्य होने पर निर्हरता बहुत अधिक विस्तृत और सख्त हैं क्योंकि बोर्ड के सदस्यों को एमएससीएस के समग्र प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।”

2.80 विधेयक के खंड 11, धारा 29 में प्रस्तावित 'उत्पादों या सेवाओं के न्यूनतम स्तर' के अर्थ के बारे में पूछे जाने पर, सचिव, सहकारिता मंत्रालय ने विधेयक की खंड दर खंड जांच के दौरान निम्नानुसार बताया:—

“...मूल अधिनियमका खंड 11, धारा 29 संविधान से परे चला जाता है। उत्पादों के अलावा, हम यह भी कह रहे हैं कि सदस्यों को न्यूनतम स्तर की सेवाएं भी लेनी चाहिए। यह अनुच्छेद 243जेडओ(2) से परे जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इफको ने अब सहकारी सोसाइटियों का एक बड़ा आधार बना लिया है। यह नैनो उर्वरक खरीदेगा। इसने अपने उपभोक्ता आधार पर उत्पादन शुरू कर दिया है। हर सोसाइटी में एजीएम, बोर्ड यह तय करेगा कि हर कोई कम से कम इतना तो खरीदे। इसी तरह उत्पाद आते हैं। और, इसी प्रकार सेवाएं भी। यह अनाज, भंडारण, सेवाएं हो सकती हैं। यह उत्पाद और सेवाएं दोनों हो सकते हैं। उन्हें नकली सदस्य नहीं होना चाहिए, जो केवल पूँजी लगाए और न तो उत्पादों का उपयोग करे और न ही सेवाओं का उपयोग करे। शायद, इसीलिए संविधान में स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि अगर आपको सदस्य बनना है, तो आपको एक सक्रिय सदस्य होना होगा और उसके लिए आपको उत्पादों और सेवाओं के स्तर को परिभाषित करना होगा...”

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.81 समिति ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं.12

मूल अधिनियम में उपबंध

2.82 “धारा 30: सदस्यों का निष्कासन

(2) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई ऐसा सदस्य, जिसे उपधारा (1) के अधीन निष्कासित किया गया है, ऐसे निष्कासन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक उस सोसाइटी के सदस्य के रूप में पुनः सम्मिलित किए जाने का पात्र नहीं होगा।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.83 “(2) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई ऐसा सदस्य, जिसे उपधारा (1) के अधीन निष्कासित किया गया है, ऐसे निष्कासन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक उस सोसाइटी के सदस्य के रूप में पुनः सम्मिलित किए जाने का पात्र नहीं होगा।

प्रस्तावित संशोधनों के पीछे का तर्क

2.84 “निगरानी तंत्र का सुदृष्टीकरण

यह प्रस्ताव दिया गया है क्योंकि एमएससीएस के हितों के विरुद्ध कार्य करने से सदस्यों को हतोत्साहित करने के लिए उनके पुनः सम्मिलित होने की प्रक्रिया को और अधिक कठोर बनाने की आवश्यकता है।”

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.85 समिति ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 13

मूल अधिनियम में उपबंध

2.86 “धारा 35: शेयरों का मोचन

(1) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ग) से खंड (छ) तक में निर्दिष्ट प्राधिकरणों में से किसी प्राधिकरण द्वारा किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में धारण किए गए शेयर ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों की उपविधियों के अनुसार, मोचनीय होंगे और उस दशा में, जहाँ उपविधियों में इसकी बाबत कोई उपबंध नहीं है, ऐसी रीति से मोचनीय होंगे, जो किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी और ऐसे प्राधिकरण के बीच तय की जाए।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शेयरों का मोचन शेयरों के अंकित मूल्य पर होगा”

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.87 “35. (1) धारा 25 की उप-धारा (1) के खंड (ग) और (घ) में बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों में धारित निर्दिष्ट प्राधिकरणों के शेयर,—

(क) ऐसे प्राधिकरणों के पूर्व अनुमोदन के बिना मोचन नहीं किया जाएगा; और

(ख) ऐसी रीति से मोचनीय होंगे, जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी एवं ऐसे प्राधिकरणों के बीच तय की जाए।

(2) धारा 25 की उप-धारा (1) के खंड (ड) से (छ) में निर्दिष्ट किसी भी प्राधिकरण द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में धारित शेयरों को इस तरह के बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के उप-नियमों के अनुसार और ऐसे मामले में, जहाँ उप-नियमों में कोई उपबंध नहीं है, वहाँ इस तरह से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी और ऐसे प्राधिकरणों के बीच तय अनुसार मोचन किया जाएगा।

उपधारा (1) एवं (2) में निर्दिष्ट शेयरों का मोचन शेयरों के अंकित मूल्य पर होगा”

प्रस्तावित संशोधनों के पीछे का तर्क

2.88 “सरकारी हितों की रक्षा और सरकारी इक्विटी के किसी भी एकतरफा आत्मसमर्पण को रोकने के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता को शामिल किया गया है।”

समिति द्वारा जांच

हितधारकों के सुझाव

2.89 खंड 13 की धारा 35 में प्रस्तावित संशोधन के मुद्दे पर, शेयर के मोचन के लिए ‘प्राधिकरण की स्वीकृति’ के बारे में उल्लेख किया गया है, समिति को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) और नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (एनएएफसीयूबी) से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इस तरह के उपबंध सोसाइटियों को आत्मनिर्भर बनने में

बाधा के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा, यह प्रस्ताव भी दिया गया है कि इसके बजाय, जिन सोसायटियों ने सरकार से निधि और निधि से इतर आधारित सहयोग प्राप्त किया है, उन्हें सरकार के शेयर के मोचन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसी फंड या सुविधाओं को वापस न कर दिया गया हो।

भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणियां

2.90 इस मुद्दे पर, भा.रि.बैंक ने यह भी उत्तर दिया है कि विधेयक का खंड 13 (मूल अधिनियम की धारा 35) जो ऐसे प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के साथ शेयर पूँजी के मोचन को निर्धारित करता है और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा और ऐसे प्राधिकरण द्वारा तय रूप में पूरी तरह से बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 12(1) के उपबंधों के अनुरूप नहीं हैं जिसके अनुसार, रिजर्व बैंक ऐसे मामलों में शर्तों को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत है। यह इस विषय पर यूसीबी को जारी किए गए मौजूदा निर्देशों को भी प्रभावित कर सकता है।

2.91 इसके अलावा, भा.रि.बैंक ने साक्ष्य के बाद के अपने उत्तर में कहा कि कुछ संशोधनों का बहुराज्य सहकारी बैंकों के संबंध में भा.रि.बैंक की नियामक प्रभावशीलता पर प्रभाव पड़ सकता है। शेयरों के मोचन के संबंध में, भा.रि.बैंक ने कहा है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 35में संशोधन यह निर्दिष्ट करता है कि सरकार द्वारा धारित शेयरों को ऐसे अधिकारियों की पूर्व स्वीकृति के बिना मोचन नहीं किया जाएगा; और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी और ऐसे प्राधिकरणों के बीच तय अनुसार मोचन किया जा सकता है। इसके अलावा, क्रमशः केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, किसी भी सरकारी निगम और किसी भी सरकारी कंपनी द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में धारित शेयर ऐसे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के उप-नियमों के अनुसार और यदि उप-नियमों में कोई प्रावधान शामिल न हो, तो इस तरह से जिस पर बहुराज्य सहकारी सोसाइटी और ऐसे प्राधिकरणों के बीच सहमति हो, उसके अनुसार, मोचन योग्य होंगे। सहकारी सोसाइटियों में विश्वास विकसित करने के लिए समान श्रेणी की शेयर पूँजी की निकासी की शर्तें आदर्श रूप से सरकारी और गैर-सरकारी निवेशकों दोनों के लिए एक समान होनी चाहिए या सरकारी निवेशकों के लिए संभवतः थोड़ी अधिक कठोर होनी चाहिए। बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 12(2)(ii)यह निर्दिष्ट करती है कि एक सहकारी बैंक अपनी शेयर पूँजी को वापस नहीं लेगा या कम नहीं करेगा, वशर्ते कि ऐसी सीमा और ऐसी शर्तों के अधीन जो भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में निर्दिष्ट करे। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 8 मार्च, 2022 को "शेयर पूँजी और प्रतिभूतियों के निर्गमन और विनियमन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों" पर परिपत्र के द्वारा किसी भी सदस्य द्वारा शेयरों का मोचन करने के कारण पूँजी में कमी से बचने के लिए, विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने और जमाकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सहकारी बैंकों की शेयर पूँजी की वापसी के लिए कुछ पूर्व शर्तें निर्दिष्ट की थीं। उपरोक्त को देखते हुए, बहुराज्य शहरी सहकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी की सीमा तक, प्रस्तावित संशोधनों का पूँजी की स्थिति पर, प्रभाव पड़ सकता है और पूँजी पर्याप्तता एवं संरक्षण पर नियामक शर्तों में संभावित रूप से हस्तक्षेप कर सकता है।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियां

2.92 धारा 35 में प्रस्तावित उपबंध सरकारी हितों की रक्षा और सरकारी इक्कीटी के एकत्रफा समर्पण को रोकने के लिए है, जैसा कि पिछले कुछ मामलों में हुआ है।

केवल राज्य या केंद्र सरकार के शेयरों के मोचन से पहले अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। साधारण शेयरों के मोचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है जो सरकार के पास नहीं हैं। •शेयरों का मोचन सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप अंकित मूल्य पर होगा।

यह प्रावधान बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आत्मनिर्भरता और भविष्य के विकास में बाधा नहीं बनेगा। इससे सरकार के हितों की रक्षा होगी।

भा.रि.बैंक द्वारा उठाए गए बिंदु के संबंध में, प्रस्तावित धारा 120व तक ही यह स्पष्ट करती है कि निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित मामलों के संबंध में, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के उपबंध बहुराज्य सहकारी बैंक पर लागू होते हैं: वशर्ते कि बहुराज्य सहकारी बैंक के बैंकिंग का कारोबार कर रहा हो के मामले में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध भी लागू होंगे।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.93 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 14

मूल अधिनियम में उपबंध

2.94 “धारा 39: साधारण निकाय का वार्षिक अधिवेशन

(1) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का बोर्ड, ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए और इसी वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अधिक से अधिक छह मास के भीतर, निम्नलिखित प्रयोजन के लिए विहित रीति से वार्षिक साधारण अधिवेशन बुलाएगा -

(ण) बोर्ड के सदस्य, यदि कोई हों, का निर्वाचन।”

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.95 “मूल अधिनियम की धारा 39 में, उप-धारा (1) में, खंड (ण) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: — “(त) लेखा परीक्षक की नियुक्ति।”

प्रस्तावित संशोधनों के पीछे का तर्क

2.96 “संविधान के अनुच्छेद 243यण(3) के अनुरूप।

‘एजीएम की कार्यसूची में लेखा परीक्षक की नियुक्ति को जोड़ा गया’

समिति द्वारा जांच

हितधारकों के सुझाव

2.97 नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज (एनएफसीयूबी) ने दिनांक 20 जनवरी, 2023 को समिति के समक्ष अपनी पावर प्वाइंट प्रस्तुति में कहा कि सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए, अब कुछ कड़े दिशानिर्देशों पर भा.रि.बैंक की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है। इस प्रकार यह किसी भी प्रकार के कदाचार को दूर करता है। परिणामस्वरूप, बोर्ड को सांविधिक या अन्य लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए ताकि भा.रि.बैंक के अनुमोदन के साथ व्यापार करने में आसानी हो। अन्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के लिए, यदि आवश्यक पाया गया, तो इसे यथावत रखा जा सकता है।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.98 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 15

मूल अधिनियम में उपबंध

2.99 “धारा 41:निदेशक बोर्ड

(3) बोर्ड में निदेशकों की संख्या उतनी होगी जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाए:

परंतु किसी भी दशा में निदेशकों की अधिकतम संख्या इक्कीस से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि बोर्ड, पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट इक्कीस निदेशकों के अतिरिक्त दो निदेशक सहयोजित कर सकेगा:

परंतु यह भी कि राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटियों के कृत्यकारी निदेशक भी बोर्ड के सदस्य होंगे और पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट निदेशकों की कुल संख्या की गणना ऐसे सदस्यों को छोड़कर की जाएगी।"

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.100 (3) "बोर्ड में निदेशकों की संख्या इक्कीस से अधिक नहीं होगी, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाए, जिसमें से बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी में ऐसे लोगों में से एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा और दो महिला सदस्य होंगी और ऐसे वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के सदस्य होंगे:

"परंतु बोर्ड, बैंक, प्रबंधन, सहकारी प्रबंधन और वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले या ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा अपनाए गए उद्देश्यों तथा किए गए क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले बोर्ड के सदस्यों को सहयोजित कर सकेगा:

परंतु यह और कि ऐसे सहयोजित किए गए सदस्यों की संख्या इस उपधारा में विनिर्दिष्ट इक्कीस निदेशकों के अतिरिक्त, ऐसे दो निदेशकों से अधिक नहीं होगी।

- (4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट सहयोजित निदेशकों को पदाधिकारियों के किसी निर्वाचन में मत डालने का अधिकार नहीं होगा या वे बोर्ड के पदाधिकारियों के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (5) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में कृत्यकारी निदेशक भी, इसकी उपविधियों के अनुसार बोर्ड के सदस्य होंगे और ऐसे निदेशक, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट निदेशकों की कुल संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिए विवर्जित किए जाएंगे।
- (6) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई निदेशक, निदेशक के रूप में, ऐसी सोसाइटी द्वारा या उसकी ओर से की गई या की जाने वाली किसी संविदा या ठहराव के संबंध में विचार-विमर्श या मतदान में उपस्थित नहीं होगा, यदि वह या उसका नातेदार प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी संविदा या ठहराव से संबंधित है या उसमें हितबद्ध है और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में किसी आसीन निदेशकों का संबंधी, सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी सहित यथा कर्मचारी के रूप में नहीं नियुक्त किया जाएगा।

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी शब्द के संदर्भ में "नातेदार" पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

- (क) पति या पत्नी;
- (ख) पिता (जिसके अंतर्गत सौतेला पिता भी है);
- (ग) माता (जिसके अंतर्गत सौतेली माता भी है);
- (घ) पुत्र (जिसके अंतर्गत सौतेला पुत्र भी है);
- (ङ) पुत्रवधू;
- (च) पुत्री (जिसके अंतर्गत सौतेली पुत्री भी है);
- (छ) दामाद;
- (ज) दादा;
- (झ) दादी;
- (ञ) नाना;
- (ट) नानी;

- (ठ) पौत्र;
- (ड) पौत्रवधु;
- (ढ) पौत्री;
- (ण) पौत्री का पति;
- (त) नाती;
- (थ) नाती की पत्नी;
- (द) नातिन;
- (ध) नातिन का पति;
- (न) भाई (जिसके अंतर्गत सौतेला भाई भी है);
- (प) भाई की पत्नी;
- (फ) बहन (जिसके अंतर्गत सौतेली बहन भी है);
- (व) जीजा; और
- (भ) अविभाजित हिंदू कुलंब।

(7) बोर्ड का ऐसा कोई निदेशक, जो उपधारा (6) के उपबंध का उल्लंघन करता है, बोर्ड का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उक्त उपधारा में निर्दिष्ट बोर्ड के ऐसे अधिवेशन की तारीख से अपना पद रिक्त कर दिया है जैसा कि उक्त उपधारा में निर्दिष्ट है और ऐसी कार्यवाही शून्य समझी जाएगी।”।

प्रस्तावित संशोधनों के पीछे का तर्क

2.101 “संविधान के अनुच्छेद 243यज (1) के अनुरूप

बोर्ड, बैठक और सदस्यता की संरचना में सुधार।

2.102 इससे सोसाइटी के बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। सहयोजित निदेशकों से संबंधित प्रस्तावित संशोधन सहकारी सोसाइटियों के प्रबंधन में वृत्तिदक्षता लाएगा।

शासन को सुदृढ़ करना और पारदर्शिता लाना

2.103 इससे भाई-भतीजावाद और कदाचार कम होगा।”

समिति द्वारा जांच

(एक) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी बोर्ड में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व

2.104 विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों के संबंध में सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी के दौरान यह सुझाव दिया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए बोर्ड में आरक्षण रोटेशन के आधार पर होना चाहिए। एक और सुझाव यह भी था कि महिलाओं के लिए और अधिक सीटें आरक्षित की जानी चाहिए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए न्यूनतम एक-एक सीट आरक्षित की जानी चाहिए। इस संबंध में, सहकारिता मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि मौजूदा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला सदस्यों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता हो। अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 243जेडजे के अनुरूप लाने के लिए धारा 41(3) में नया प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है जो अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला सदस्यों के लिए आरक्षण बहुराज्य सहकारी सोसाइटी पर लागू होगा जिसमें ऐसे ही व्यक्ति और ऐसे वर्ग या श्रेणी के सदस्य शामिल हैं। यह उपबंध बोर्ड में समाज के कमजोर वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए है।

2.105 इसके अलावा, एनएएफसीओबी (नेफस्कॉब) से एक सुझाव प्राप्त हुआ है कि बोर्ड में एक सदस्य अन्य पिछ़ड़ा वर्ग से होगा। समिति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदायों के एक सदस्य के स्थान पर एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को शामिल करने का सुझाव भी प्राप्त हुआ है। इन सुझावों पर विचार प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर, सहकारिता मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:—

“मौजूदा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और महिला सदस्यों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता हो। अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 243यज के अनुरूप लाने के लिए धारा 41(3) में नया उपबंध प्रस्तावित किया जा रहा है जो एमएससीएस बोर्ड एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और दो महिला सदस्यों के लिए आरक्षण प्रदान करता है।

(दो) बोर्ड में सहयोजित सदस्य

2.106 सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा विधेयक में निहित उपबंधों पर ब्रीफिंग के दौरान, समिति ने सुझाव दिया कि एमएससीएस के लिए विशेषज्ञों का एक दल होना चाहिए। इस संबंध में सहकारिता मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:—

“मौजूदा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 में, धारा 41 निदेशक बोर्ड में अधिकतम दो सहयोजित निदेशकों का उपबंध करती है। हालांकि, ऐसे सहयोजित निदेशकों के लिए अर्हता और अनुभव को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। संशोधन विधेयक में, उप-धारा 41(3) एक नई प्रविष्टि है जिसमें बोर्ड बैंकिंग, प्रबंधन, सहकारी प्रबंधन और वित्त या ऐसे एमएससीएस के लक्ष्यों और उनके द्वारा की गई गतिविधियों से संबंधित विशेषज्ञता के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोगों को बोर्ड के सदस्यों के रूप में सह-चयन कर सकता है। धारा 41(3) में प्रस्तावित नया उपबंध संविधान के अनुच्छेद 243यज के अनुरूप है।”

2.107 एनएएफसीयूबी (नेफकब) ने समिति के समक्ष अपनी प्रस्तुति में कहा है कि बैंकिंग, प्रबंधन, सहकारी प्रबंधन और वित्त आदि के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले बोर्ड के सदस्यों को सहयोजित करने का उपबंध किया जा रहा है और अपना यह विचार व्यक्त किया है कि “प्रौद्योगिकी” के क्षेत्र से भी सदस्यों को सहयोजित करने का उपबंध किया जाना चाहिए। इस संबंध में, सहकारिता मंत्रालय के विचार मांगे गए थे। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:—

“प्रस्तावित संशोधन संविधान के अनुच्छेद 243यज(3) के अनुरूप है। सूत्रीकरण में प्रयुक्त ‘किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता’ शब्द प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से भी सदस्यों को सहयोजित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन देता है।”

(तीन) मौजूदा निदेशक के रिश्तेदारों की भर्ती पर प्रतिबंध के दायरे में एमडी/सीईओ को शामिल करना

2.108 विधेयक पर ब्रीफिंग के दौरान, एक कर्मचारी के रूप में किसी मौजूदा निदेशक के रिश्तेदारों की भर्ती पर प्रतिबंध के बारे में धारा 41(6) के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंधों के दायरे में एमडी/सीईओ को शामिल करने की आवश्यकता के संबंध में समिति के प्रश्न के उत्तर में, सहकारिता मंत्रालय ने निम्नानुसार प्रतिक्रिया दी:—

“.....मौजूदा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में, धारा 41 निदेशक बोर्ड की संरचना से संबंधित है। बोर्ड के मौजूदा सदस्य के रिश्तेदारों की भर्ती पर इस धारा के अंतर्गत कोई रोक नहीं है। यह कर्मचारियों की भर्ती में भाई-भतीजावाद और पक्षपात की गुंजाइश बना देता है।

संशोधन विधेयक में, खंड 15 (उप-धारा 41(6)) जो एक नई प्रविष्टि है, बोर्ड के किसी मौजूदा निदेशक के रिश्तेदारों की भर्ती पर रोक लगाती है। कर्मचारियों की भर्ती में भाई-भतीजावाद और पक्षपात को रोकने के लिए यह संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी।

सीईओ/एमडी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 52 के अनुसार बोर्ड के सामान्य अधीक्षण, निर्देशों और नियंत्रण के अंतर्गत काम करता है। एमडी/सीईओ सहित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कर्मचारियों के रिश्तेदारों की भर्ती पर रोक लगाने से संबंधित सुझाव पर और जांच की आवश्यकता होगी ... ”

2.109 इसके अलावा, नेफकॉब ने समिति को अपने प्रस्तुतिकरण में कहा है कि निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिमों के संबंध में भा.रि.बैंक दिनांक 05.02.2021 के परिपत्र की तुलना में "रिश्तेदार" शब्द की परिभाषा को विस्तृत किया गया है। इसके अनुसार, रिश्तेदार की परिभाषा उपरोक्त भा.रि.बैंक परिपत्र के अनुसार रखी जानी चाहिए। नेफकॉब के इस सुझाव पर विचार प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर, सहकारिता मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर प्रस्तुत किया है:—

“नेफकॉब द्वारा उल्लिखित भा.रि.बैंक दिनांक 05.02.2021 के परिपत्र के अनुसार 'रिश्तेदारों' की परिभाषा विशेष रूप से यूसीबी द्वारा निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम देने के संबंध में है। हालांकि, मूल अधिनियम (विधेयक की धारा 15) की धारा 41 के अंतर्गत परिभाषित रिश्तेदार की परिभाषा सभी एमएससीएस में कर्मचारियों की भर्ती और इच्छुक पार्टी लेनदेन पर प्रतिबंध के संबंध में है। एमएससीएस में भाई-भतीजावाद और पक्षपात को रोकने के लिए रिश्तेदारों की इस व्यापक परिभाषा का प्रस्ताव दिया गया है।

2.110 यहां तक प्रस्तावित संशोधन का संबंध 4, नेफकॉब ने आगे समिति को उत्तर प्रस्तुत किया है कि कई खंड "निदेशक की नियुक्ति" और पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) जैसे शब्दों का उल्लेख करते हैं जो सहकारी बैंकों पर लागू होते हैं जहां बोर्ड के सदस्य नियुक्त नहीं होते हैं बल्कि निर्वाचित होते हैं। जब तक बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2020 के विभिन्न उपबंधों की प्रयोज्यता की समीक्षा नहीं की जाती है, एमएससीएस अधिनियम में प्रगतिशील संशोधनों के बावजूद, बहुराज्य सहकारी बैंकों को नुकसान होता रहेगा। इसका एक बेहतर समाधान यह हो सकता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 56 (एएसीएस) की तर्ज पर बहुराज्य सहकारी बैंकों के लिए एक अच्छी तरह से तैयार किए गए एक अलग अध्याय को इसमें शामिल किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहकारी चरित्र संरक्षित है और संविधान, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम और बैंककारी विनियमन अधिनियम के उपबंधों की प्रयोज्यता में कोई अस्पष्टता नहीं है। नेफकॉब के उपरोक्त सुझाव पर, सहकारिता मंत्रालय से विचार/टिप्पणियां मांगी गई थीं। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:—

“•बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 45 के मौजूदा प्रावधान के अनुसार निदेशक बोर्ड सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।

•विद्यमान प्रणाली के अनुसार, भा.रि.बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस विभिन्न कानूनों जैसे कि भारतीय कंपनी अधिनियम या विभिन्न सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के अंतर्गत गठित संस्थाओं को दिया जाता है। ऐसी सभी संस्थाएँ उन संबंधित अधिनियमों के साथ ही साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत भी शासित होती हैं जिनके अंतर्गत उन्हें शामिल किया गया है। इस तरह की सभी संस्थाओं के लिए दोहरा विनियमन मौजूद है। इसमें स्पष्टता लाने के लिए, संशोधन विधेयक धारा 120व (नई प्रविष्टि) में यह प्रस्ताव देता है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के उपबंध निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित मामलों के संबंध में किसी बहुराज्य सहकारी बैंक पर लागू होते हैं: परंतुकि बैंकिंग का कारोबार करने वाली किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध भी लागू होंगे।

•यह अनुच्छेद 243ज़ेडआई और संविधान के अनुच्छेद 243यठ के तीसरे परंतुकि अनुरूप है। इसलिए, इसमें एक अलग अध्याय शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।”

2.111 विधेयक पर ब्रीफिंग के दौरान, यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड में आकस्मिक रिक्तियों के मामले में सदस्यों को ही नामित किया जाना चाहिए। इस संबंध में, सहकारिता मंत्रालय ने अपने ब्रीफिंग पश्चात उत्तर में निम्नवत बताया:—

“मौजूदा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में नामांकन के माध्यम से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में आकस्मिक रिक्तियों को भरने का कोई उपबंध नहीं है।

आकस्मिक रिक्ति को नामांकन के माध्यम से भरना एक नया उपबंध है अर्थात् संशोधन विधेयक में 45(जे)(5) संविधान के अनुच्छेद 243यज(2) के अनुरूप है। यह आकस्मिक रिक्तियों के मामले में बार-बार चुनाव की आवश्यकता को रोकेगा।

फर्जी कार्यों से बचने के लिए नामांकन द्वारा आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए कुल निर्वाचित निदेशकों की एक तिहाई की सीमा रखी गई है।”

हितधारकों द्वारा सुझाव

2.112 नावार्ड ने नामांकन के आधार पर बोर्ड की कुल संख्या के 1/3 तक आकस्मिक रिक्तियों को भरने का सुझाव दिया है। उन्होंने इसकी समीक्षा करने और इसे कुल बोर्ड क्षमता के 1/4 या 1/5 तक सीमित करने की सलाह दी है।

2.113 वर्तमान निदेशक के किसी भी रिश्तेदार को कर्मचारी के रूप में भर्ती करने के प्रस्ताव के संबंध में नावार्ड ने कहा है कि ऐसे किसी उपबंध को लागू नहीं किया जाना चाहिए (ख) भर्ती प्रक्रिया (ग) मौजूदा कर्मचारियों के बारे में प्रकटीकरण जो बोर्ड के सदस्यों के रिश्तेदार हैं (धारा 120) के अनुसार यह मौजूदा निदेशकों के रिश्तेदारों को प्राप्त होने वाले अवसर से वंचित करने के बराबर है।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.114 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं.16

मूल अधिनियम में उपबंध

2.115 “धारा 43 : बोर्ड का सदस्य होने के लिए निरर्हता

(1) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य या राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी का सदस्य सोसाइटी का नामनिर्देशिती ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी या किसी अन्य ऐसी सहकारी सोसाइटी के जिससे ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संबद्ध है, बोर्ड के रूप में चुने जाने या सदस्य होने का पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा सदस्य:—

(क) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया या विकृतचित न्यायनिर्णीत किया गया है;

(ज) वह ऐसा व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध किसी डिक्री, विनिश्चय या आदेश के अधीन शोध्य कोई रकम इस अधिनियम के अधीन वसूली के लिए लंबित है।

43(2) कोई व्यक्ति बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पांच वर्ष की अवधि तक पात्र नहीं होगा यदि ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का बोर्ड:—

(क) धारा 45 के अधीन बोर्ड के निर्वाचन करवाने में;या

(ख)

(ग) वित्तीय विवरण तैयार करने और उसे वार्षिक साधारण अधिवेशन में प्रस्तुत करने में, असफल रहता है।"

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.116 “मूल अधिनियम की धारा 43 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (क) में “दिवालिया” शब्द के पश्चात् “या दिवालिया कंपनी के निदेशक रहें हो” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ख) खंड (ज) में, “इस अधिनियम के अधीन” शब्दों के पश्चात्, “या तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिनियम के अधीन” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ण) धारा 41 की उपधारा (7) के अधीन निरर्हित किया गया है ;”

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(1क) एक सदस्य जो किसी भी ऐसी बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी या सहकारी बैंक के बोर्ड का निदेशक रहा है, जिस के बोर्ड का अधिक्रमण कर दिया गया है, वह किसी अन्य बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी या सहकारी बैंक में इस तरह के अधिक्रमण की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए के बोर्ड के निदेशक के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं होगा:

परंतु यह कि इस उप-धारा के अंतर्गत किसी भी सदस्य को तब तक निरर्हित किया जाएगा जब तक कि केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे सदस्य को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है और निरर्हित की घोषणा केवल यह सुनिश्चित करने के बाद की जाएगी कि संबंधित सदस्य चूक के कृत्यों के लिए उत्तरदायी है जिसके आधार पर उसका अधिक्रमण किया जा सकता है।”;

(क) खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(क) इस अधिनियम के अंतर्गत यथा विहित रीति से चुनाव कराने के लिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण द्वारा वांछित जानकारी, दस्तावेज, कर्मियों, धन या व्यय या किसी अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए;”;

(ख) खंड (ग) में, अंत में आने वाले “साधारण अधिवेशन” शब्द के स्थान पर, “ साधारण अधिवेशन; या” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं;

(ग) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(घ) धारा 63 की उप-धारा (1) के खंड (ख) या धारा 63क के अंतर्गत स्थापित सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि में संदर्भित सहकारी शिक्षा निधि में योगदान करने के लिए; या

(ङ) निर्दिष्ट समय के भीतर धारा 120 में विहित वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए; या

(च) संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर, सोसाइटी की लेखापरीक्षा कराने के लिए:

परंतु यह कि इस उप-धारा के अंतर्गत कोई कार्रवाई करने से पहले, उसे केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।”

प्रस्तावित संशोधन का तर्क

2.117 बोर्ड की संरचना, बैठकें और सदस्यता में सुधार

शासन को सुदृढ़ करने हेतु निरर्हिता के लिए अतिरिक्त आधारों की आवश्यकता होती थी। तीसरे परंतुक के जोड़े जाने से बोर्ड के निदेशकों को निरर्हिता से बचने के लिए अधिनियम की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत बकाया किसी राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा।

इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी बहुराज्य सहकारी समिति के अधिक्रमण के लिए पूर्व में उत्तरदायी निदेशकों को किसी अन्य बहुराज्य सहकारी समिति में निदेशक बनने से पांच वर्षों के लिए निरर्ह किया जाएगा।

इससे निर्वाचित के संचालन में अनुशासन, सीईएफ/सीआरआरडीएफ (प्रस्तावित) आदि में अंशदान सुनिश्चित होगा।

समिति द्वारा जांच

2.118 सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा विधेयक के संबंध में किए गए प्रस्तावों पर जानकारी देने के दौरान, समिति ने पाया कि वार्षिक रिटर्न दाखिल न करना निदेशक की निरहता के कारणों में से एक नहीं होना चाहिए क्योंकि यह कर्मचारी या सोसाइटी की जिम्मेदारी है {धारा 43 (2)}। इस संबंध में, सहकारिता मंत्रालय ने अपनी जानकारी देने के बाद, उत्तर में निम्नवत बताया:—

“मौजूदा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में वार्षिक विवरणी दाखिल न करने पर निरहता का कोई प्रावधान नहीं है। इसके कारण अनुपालन में कठिनाई आती है और कई बहुराज्य सहकारी समितियां अपनी वार्षिक विवरणी जमा करने में विफल रहती हैं। नई धारा 43 (2) अंतःस्थापित की गई है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति, बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए 5 वर्ष तक अर्ह नहीं होगा, यदि ऐसी बहुराज्य सहकारी समितियों के बोर्ड द्वारा वार्षिक विवरणी जमा न कराई गई हो। निरहता से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। इससे सभी बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल करने का अनुपालन सुनिश्चित होगा, जिससे पारदर्शिता आएगी और केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा कार्यकरण की बेहतर निगरानी सुनिश्चित होगी। बहुराज्य सहकारी समिति के कार्यकलापों को चलाना समग्र रूप से बोर्ड की जिम्मेदारी है। सामूहिक रूप से बोर्ड और व्यक्तिगत रूप से निदेशकगण इसके लिए उत्तरदायी होते हैं।“

2.119 इसके अलावा संक्षिप्त जानकारी दिए जाने के दौरान, यह इंगित किया था कि बोर्ड के सदस्यों की निरहता की अवधि पर स्पष्टता होनी चाहिए। इस संबंध में सहकारिता मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

“संशोधन विधेयक में धारा 43(1क) का अंतःस्थापन बोर्ड के सदस्य की निरहता के अतिरिक्त आधार के रूप में किया जा रहा है। धारा 43(1क) के इस नए प्रस्तावित अन्तःस्थापन से ऐसी किसी बहुराज्य सहकारी समिति जहां निदेशक मण्डल का अधिक्रमण कर दिया है और संबंधित सदस्य को इस अधिक्रमण के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है तो वह ऐसे अधिक्रमण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अन्य बहुराज्य सहकारी समिति/बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा। सीआरसीएस द्वारा संबंधित सदस्य को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पूर्व में बहुराज्य सहकारी समितियों के अधिक्रमण के लिए उत्तरदायी निदेशक पांच वर्षों तक अन्य बहुराज्य सहकारी समितियों में निदेशक चुने जाने से निरर्ह रहें।“

हितधारकों द्वारा सुझाव

2.120 एनसीयूआई ने समिति के समक्ष अपनी पावर प्वाइंट प्रस्तुति में बताया कि प्रस्तावित खंड मनमाना है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है इसलिए इसका विलोपन किए जाने की आवश्यकता है अन्यथा 'अन्य' शब्द को 'जैसे' शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सकता है क्योंकि पांच साल सजा की अवधि उपयुक्त है। नेफेड और एनसीसीएफ ने यह भी सुझाव दिया है कि 'अन्य' शब्द को 'उस' शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जब इन सुझावों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो, सहकारिता मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:—

"प्रस्तावित खंड 16 (धारा 43 (1क)) के अनुसार, किसी भी सदस्य को तब तक निरर्ह घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे सदस्य को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है और निरहता की घोषणा केवल यह सुनिश्चित करने के बाद की जाएगी कि संबंधित सदस्य चूक के ऐसे कृत्यों के लिए उत्तरदायी है जिसके आधार पर उसका अधिक्रमण किया जा सकता है। इसलिए, यह उपर्युक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है। इसके अलावा, चूक के कृत्यों के लिए संबंधित

निदेशक का उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो जाने के बाद, उस व्यक्ति को किसी अन्य एमएससीएस/ बैंक में निदेशक पद पर नियुक्त होने से रोके जाने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उनके द्वारा चूक या धोखाधड़ी के ऐसे कृत्य कहीं और नहीं दोहराए जाएं।

एनएएफसीयूबी ने यह भी बताया कि ऐसी निरहता तब नहीं होनी चाहिए जब उक्त निदेशक द्वारा विमत्त टिप्पण दिया गया हो या ऐसी अस्पष्टता को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हों जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड का अधिक्रमण हुआ है। सहकारिता मंत्रालय को इस सुझाव पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया, "वास्तविकता यह है कि इस धारा के अंतर्गत निर्णय लेते समय यदि कोई भी निदेशक विमत्त टिप्पण देता है या उसके द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं, तो सुनवाई के दौरान उस पर उचित रूप से विचार किया जाएगा।"

2.121 विधेयक के खंड 16 (i) (ब) के अनुसार, (मूल अधिनियम की धारा 43 की उप धारा (1)) खंड (ज) में, "इस अधिनियम के अंतर्गत" शब्दों के पश्चात, "या तीसरी अनुसूची में विहित किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में, एनसीयूआई ने बताया कि यह उपबंध 97वें संविधान (संशोधन) अधिनियम 2011 की भावना और सहकारिता के सिद्धांतों के विरुद्ध है क्योंकि सहकारी समिति का एक अलग चरित्र है जो गरीब लोगों के लिए काम करती है। इसलिए, सहकारी अधिनियम की समानता किसी अन्य अधिनियम के नहीं की जा सकती। इसलिए, प्रस्तावित अतिरिक्त शब्द 'या तीसरी अनुसूची में विहित किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत' शब्दों को हटाने की आवश्यकता है। इस संबंध में, सहकारिता मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:—

"प्रस्तावित खंड 16 विधि का कड़ाई से अनुपालन करने और बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करके सहकारी समितियों में शासन सुदृढ़ करने में मदद करेगा।"

2.122 एनएएफसीयूबी ने कहा कि इस प्रकार से निरहता नहीं की जानी चाहिए यदि उक्त निदेशक ने विमत्त टिप्पण दिया है या ऐसी अस्पष्टता को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड का अधिक्रमण हुआ है।

2.123 इस तथ्य के बावजूद कि दिवाला कानून, दिवालिया कंपनी के निदेशक को दूसरी कंपनी में निदेशक बनने से नहीं रोकता है, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में निदेशक के पद से दिवालिया कंपनी के निदेशक को बाहर करने के प्रस्ताव के औचित्य के बारे में पूछे जाने पर, सचिव, सहकारिता मंत्रालय ने विधेयक की खंडवार जांच के दौरान निम्नानुसार बताया:—

".....हाँ, हम इस बारे में केवल इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कंपनियों के विपरीत, सहकारी समिति जिसमें बड़ी संख्या में सदस्य हैं, इसे बंद करना या इसका विलय करना इतना आसान नहीं है। अतः, यदि कोई व्यक्ति जिसका ट्रैक-रिकॉर्ड खराब है और यदि वह सहकारी सोसाइटी में प्रवेश करता है, तो यह सहकारी क्षेत्र के लिए हानिकारक होगा। अतः, अपात्रता को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया, अयोग्यता, आदि क्योंकि सहकारी क्षेत्र, विशेष रूप से अधिकांश मामलों में जिनके लिए सहकारी क्षेत्र का नाम खराब है, हमने सांछियकीय रूप से देखा है कि ऐसा होता है।"

2.124 सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने इस मुद्दे पर और विस्तार से बताया कि:—

"...दिवाला' शब्द और 'दिवालियापन संहिता' शब्द, ये सभी उन कंपनियों पर लागू होते हैं, जिन्हें कुछ प्रतिरक्षा मिली हुई है या जिन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जहां तक सहकारी ढांचे का संबंध है, इसे अलग-अलग प्रतिरक्षा और अलग-अलग विशेषाधिकार मिले हैं। अतः अलग प्रतिरक्षा और अलग-, सहकारिता क्षेत्र में हम ऐसे लोगों को रखना पसंद करेंगे, जिनके व्यवसाय में असफलता नहीं हुई है। अन्यथा, वे जमाकर्ताओं के 80,000 करोड़ रु या 20,000 करोड़ रु लेकर भाग जायेंगे। हमें ऐसे लोगों को क्यों रखेंगे?.."

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.125 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 17

मूल अधिनियम में उपबंध

2.126 "45. बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन—

- (1) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के लिए निर्वाचन कराने के कार्य का उत्तरदायित्व विद्यमान बोर्ड का होगा।
- (2) बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, गुरु मतदान द्वारा किया जाएगा।
- (3) बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्यों के साधारण अधिवेशन में किया जाएगा।
- (4) बोर्ड के निर्वाचित सदस्य, यदि ऐसी सोसाइटी की उपविधियाँ अनुज्ञात करें, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे।
- (5) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि होगी जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाएः।

परंतु यह कि निर्वाचित सदस्य इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों के उपबंधों के अधीन अपने उत्तरवर्तियों के निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किए जाने तक पद धारण किए रहेंगे और अपने पद का भार ग्रहण करते रहेंगे।

- (6) जहां बोर्ड, बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन करवाने में असफल रहता है वहां केन्द्रीय रजिस्ट्रार, निर्वाचन उस तारीख से जिसको ऐसे निर्वाचन होने थे, नब्बे दिन की अवधि के भीतर करवाएगा।
- (7) कोई भी व्यक्ति किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह उस सोसाइटी के साधारण निकाय का सदस्य न हो।
- (8) केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा निर्वाचन कराए जाने का व्यय उक्त बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा वहन किया जाएगा।
- (9) केन्द्रीय सरकार बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने के लिए या उनका विनियमन करने के लिए साधारणतया नियम बना सकेगी।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.127 "मूल अधिनियम की धारा 45 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:—

- *45 (1) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के नाम से ज्ञात प्राधिकरण का गठन करेगी, जो कि ऐसे व्यक्तियों, जो विहित किए जाएं, से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन में अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा।
- (2) प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।
 - (3) कोई व्यक्ति,—
 - (i) प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक उसने भारत सरकार के अपर सचिव या समतुल्य पंक्ति का पद धारण न किया हो;
 - (ii) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक उसने सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य पंक्ति का पद धारण न किया हो; और
 - (iii) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह ऐसी अर्हता और अनुभव, जो विहित किया जाए, पूरी नहीं करता हो।

(4) प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए या उनके द्वारा पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करेंगे और ये पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होंगे:

परंतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति के मामले में, वह पदेन सदस्य के रूप में माना जाएगा और यह सब एक बना रहेगा जब तक वह उस पद पर रहता है जिसके आधार पर वह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है।

(5) प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों, पदेन सदस्यों से भिन्न को संदेय वेतन और भते तथा उनकी सेवा के निवंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाए।

45क. प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्राधिकरण के कार्यकलापों के संचालन में साधारण अधीक्षण और निदेशन की शक्तियां प्राप्त होंगी तथा वह प्राधिकरण के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं।

45ख. (1) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकेगी, यदि, यथास्थिति, प्राधिकरण का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्यः—

(क) दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है;

(ख) ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है;

(ग) प्राधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है;

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे प्राधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; या

(च) अपनी पदावधि के दौरान, किसी समय किसी अन्य नियोजन में लगा हुआ है।

(2) प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से केंद्रीय सरकार के आदेश द्वारा सावित कदाचार या अधमता के आधार पर यदि केन्द्रीय सरकार उसके द्वारा इस निर्मित विहित प्रक्रिया के अनुसार हुई जांच पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य किसी ऐसे आधार पर हटाया जाना चाहिए, उसके पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(3) केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन जांच आरंभ की गई है या लंबित है, तब तक निलंबित नहीं कर सकेगी, जब तक केंद्रीय सरकार ने जांच की रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर कोई आदेश पारित न कर दिया हो।

45ग. (1) किसी व्यक्ति को प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे वह ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के अपने कार्य को करने में प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है।

(2) प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य पदग्रहण करने के पश्चात् तुरंत और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष उस सीमा की घोषणा करेगा जिस सीमा तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या वित्तीय या अन्यथा किसी सहकारी सोसाइटी में उसका हित है।

(3) उपधारा (2) के अधीन की गई ऐसी घोषणा प्राधिकरण द्वारा पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी।

45घ. पदेन सदस्यों से भिन्न, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य कम से कम तीस दिन की लिखित सूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और सरकार द्वारा ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार करने पर उसका पद रिक्त माना जाएगा:

परंतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को जब तक अपने पद को त्याग करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति नहीं दे दी जाती है ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक या जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है या जब तक उसकी पदावधि समाप्त नहीं हो जाती है, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपना पद धारण किए रहेगा।

45ड. यदि प्राधिकरण का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के पद की कोई आकस्मिक रिक्ति, चाहे वह उसकी मृत्यु, उसके त्यागपत्र या अन्यथा के कारण, होती है, तो ऐसी रिक्ति द्वारा 45 के उपबंधों के अनुसार, नई नियुक्ति करके नव्वे दिन की अवधि के भीतर भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति ऐसी शेष पदावधि के लिए वैसे ही पद धारण करेगा, जिसके लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य ने, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है, वह पद धारण किया हुआ होता।

45च. प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पद में न रहने पर, दो वर्ष की अवधि तक के लिए किसी सहकारी सोसाइटी में कोई नियोजन (जिसमें परामर्शी या अन्यथा भी है) स्वीकार नहीं करेगा:

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार में या किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (45) के अधीन यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी नियोजन पर लागू नहीं होगी।

45छ. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या कोई त्रुटि है;

(ख) प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण की कार्यवाही में ऐसी अनियमितता है जो मामले के किसी गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

45ज. (1) प्राधिकरण, ऐसे स्थानों पर और ऐसे समय पर अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत उसके अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएँ।

(2) प्राधिकरण का अध्यक्ष प्राधिकरण के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारणवश प्राधिकरण का अध्यक्ष, प्राधिकरण के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे सभी प्रश्न, जो प्राधिकरण के किसी अधिवेशन के समक्ष उत्पन्न होते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के मत के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मत के बराबर होने की दशा में, अध्यक्षता करने प्राधिकरण के अध्यक्ष या प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को निर्णयक मत का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

(4) उपधारा (1) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।

45झ. प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:

(i) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के निर्वाचनों का संचालन;

(ii) निर्वाचक नामावलियों के तैयार करने से संबंधित मामलों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और उनका नियंत्रण; और

(iii) ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किए जाएँ।

45झ. (1) कोई व्यक्ति बोर्ड के सदस्य या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के पदधारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक वह उस सोसाइटी के साधारण निकाय का सक्रिय सदस्य नहीं है।

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, 'सक्रिय सदस्य' पद से कोई ऐसा सदस्य अभिप्रेत होगा, जो:—

(i) सोसाइटी की सेवाओं या उत्पादों के न्यूनतम स्तर का उपभोग कर रहा है; या

जैसा कि धारा 29 में विनिर्दिष्ट है, कम से कम तीन लगातार सामान्य अधिवेशनों में उपस्थित हो रहा है।

(2) बोर्ड का कोई सदस्य या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का पदधारी ऐसा सदस्य या पदधारी नहीं रहेगा, यदि वह उस सोसाइटी के साधारण निकाय का सदस्य नहीं रह जाता है।

(3) बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, किया जाएगा।

(4) बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्यों के साधारण अधिवेशन में किया जाएगा और बोर्ड के निर्वाचित सदस्य यदि ऐसी सोसाइटी की उपविधियां अनुशास तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे:

परंतु यह कि बोर्ड, बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के एक तिहाई सदस्यों की आकस्मिक रिक्तियों को सदस्यों के उस वर्ग में से नामनिर्देशन द्वारा भर सकेगा जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई है, यदि बोर्ड की पदावधि उसकी मूल पदावधि में से आधे से कम है:

परंतु यह भी कि यदि बोर्ड की उसी पदावधि में ऐसी आकस्मिक रिक्तियों की संख्या निर्वाचित निदेशकों की एक-तिहाई से अधिक है तो उस दशा में ऐसी रिक्तियों को निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा।

(6) प्राधिकरण द्वारा निर्वाचन कराने के लिए व्यव बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा ऐसी रीति में जो विहित की जाए, वहन किया जाएगा।

(7) केंद्रीय सरकार बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन के संचालन के लिए शक्तियों का उपबंध करने और प्राधिकरण द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया के लिए नियम बना सकेगी।

(8) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक, निर्वाचन का समय के भीतर संचालन करने के लिए प्राधिकरण को विद्यमान बोर्ड की अवधि की समाप्ति से छह मास पूर्व सूचित करेगा।

(9) ऐसी सोसाइटी, जिसके संबंध में निर्वाचन कराया जा रहा है, प्राधिकरण को ऐसी अवसंरचना, कार्मिक, सूचना, दस्तावेज या अन्य सहायता उपलब्ध कराएगी, जिनकी वह अपेक्षा करे।

45ट. (1) प्राधिकरण, बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन संचालित करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर सकेगा और ऐसे कृत्यों का, जिनका प्राधिकरण द्वारा निदेश दिया जाए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निर्वहन कर सकेगा।

(2) केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण को ऐसे कर्मचारिवृंद और अधिकारी उपलब्ध कराएगी, जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(3) प्राधिकरण,—

(क) ऐसे संप्रेक्षकों की नियुक्ति कर सकेगा, जो वह निर्वाचनों का पर्यवेक्षण करने और ऐसे कृत्यों, जो विहित किए जाएं, का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे; और

(ख) सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों की उतनी संख्या में नियुक्ति कर सकेगा, जो वह रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता करने के लिए आवश्यक समझे।

45ठ. प्राधिकरण सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, बोर्ड को इसके सदस्यों सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक और अन्य कर्मचारिवृंद को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के लिए आवश्यक हो और बोर्ड, इसके सदस्य, सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक और कर्मचारिवृंद ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे।”

प्रस्तावित संशोधन का तर्क

2.128 “सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 243यट (2) के अनुरूप की गई है।

निर्वाचन सुधार

यह सुधार एमएससीएस के बोर्ड का निष्पक्ष, समयबद्ध और पेशेवर आयोजन सुनिश्चित करेगा।

सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है।

सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की नियुक्ति के नियम और शर्तें।

सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को हटाने की शक्तियाँ और आधार।

सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए।

निर्वाचन प्राधिकारी के त्यागपत्र और आकस्मिक रिक्तियों को भरने का उपबंध।

संविधान के अनुच्छेद 243यण (2) के अनुरूप सीईए के लिए कार्य संचालन नियम।

धारा 29 साधारण अधिवेशन से अनुपस्थिति को माफ करने का उपबंध करती है।

संविधान के अनुच्छेद 243यण (2) कि तर्ज पर धारा 45(ज)(5) के प्रथम परंतुक का प्रस्ताव बार-बार निर्वाचन कराने की आवश्यकता से बचने के लिए किया गया है।

बोर्ड की संरचना, बैठकों व सदस्यता में सुधार

सुगमता से निर्वाचन कराने के लिए

समिति द्वारा जांच

2.129 सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों पर ब्रीफिंग के दौरान, यह पाया गया कि निर्वाचन प्राधिकरण का होना लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के विपरीत है और इससे सहकारी समितियों की स्वायत्तता पर चोट पहुँचती है और जब इस प्राधिकरण के गठन का कारण पूछा तो इस संबंध में, सहकारिता मंत्रालय ने अपनी ब्रीफिंग के पश्चात उत्तर में निम्नवत स्पष्ट किया:—

"विद्यमान बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में निर्वाचन प्राधिकरण के गठन संबंधी कोई उपबंध नहीं है। तथापि, मौजूदा अधिनियम की धारा 45 में यह मौजूदा बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह निर्वाचन आयोजित कराए। संविधान का अनुच्छेद 243यट (2) निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना और इसके कार्यों का उपबंध करता है। संशोधन विधेयक में धारा 45 के प्रतिस्थापन के माध्यम से सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को स्थापित करने के लिए एक नया उपबंध किया जा रहा है। प्राधिकरण की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। धारा 45(3) के अनुसार, कोई व्यक्ति निम्नलिखित नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा:

- (i) प्राधिकरण का अध्यक्ष के रूप में, यदि वह भारत सरकार में अपर सचिव या समतुल्य पद पर न हो;
- (ii) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में, यदि उसने भारत सरकार में संयुक्त सचिव या समतुल्य पद पद पर न हो; और
- (iii) सदस्य के रूप में यदि वह विहित योग्यताओं और अनुभव को पूरा नहीं करता हो।

निर्वाचन प्राधिकरण होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से समय पर चुनाव कराने में मदद मिलेगी और एमएससीएस का लोकतांत्रिक कार्यकरण सुदृढ़ होगा।

2.130 जानकारी प्रदान करने के दौरान यह पूछा गया कि क्या निर्वाचन प्राधिकरण में व्यक्ति को अवैध रूप से नियुक्त करने के कार्य में सुधार की कार्रवाई करने संबंधी कोई उपबंध विद्यमान है। इस संबंध में, सहकारिता मंत्रालय ने निम्नवत बताया:—

"खंड 17 (धारा 45ब्द) यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण का कोई भी कृत्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति है या प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि हुई है या प्राधिकरण की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता से मामले की मेरिट प्रभावित नहीं होगी।"

यह एक मानक उपबंध है जो अन्य अधिनियमों में भी विद्यमान है। उदाहरण के लिए, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 93 में कहा गया है कि समुचित आयोग के गठन में केवल किसी रिक्ति या दोष होने के आधार पर ही समुचित आयोग के किसी भी कार्य या कार्यवाही पर सवाल नहीं उठाया जाएगा या उसे अमान्य नहीं ठहराया जाएगा।

इस मानक खंड का उपबंध यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा की गई वैध कार्रवाइयों पर प्राधिकरण के गठन और अन्य प्रक्रियात्मक मामलों में त्रुटि के आधार पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है।"

भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणियां

2.131 भा. रि. बैंक ने अपने अनुरोध में निदेशक मंडल की संरचना और बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में धारा 41 और 45 में उपबंधों के संबंध में आपत्ति जताई है। आरबीआई ने बताया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम में सहकारी बैंकों के ऐसे मामलों में भा. रि. बैंक की भूमिका निर्धारित है। इसके अलावा, भा. रि. बैंक ने बताया कि एमएससीएस अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन द्वारा ऐसे मामलों में भा. रि. बैंक/बैंकिंग विनियमन अधिनियम को कोई भूमिका नहीं सौंपी गई है। उन्होंने यह भी राय है कि संगत धाराओं में विशिष्ट परंतुक जोड़े जाए, ताकि बहुराज्य सहकारी बैंकों के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विनियम लागू हों। जब इन मुद्दों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:—

2.132 इसके अलावा भा. रि. बैंकने अपने साक्ष्योंपरांत उत्तर में बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243ज (2) में कहा गया है कि "बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल निर्वाचन की तारीख से पांच साल का होगा तथा पदाधिकारियों का कार्यकाल होगा बोर्ड की अवधि के साथ समाप्त होगा।" तदनुसार, उपर्युक्त संविधानिक उपबंध को प्रभावी करने के लिए एमएससीएस (संशोधन) विधेयक में धारा 45ज (5) का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 10क(2क)(i)के अनुसार, सहकारी बैंक के अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक के अलावा उसका कोई भी निदेशक, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, आठ साल से अधिक की अवधि के लिए लगातार पद धारण नहीं करेगा। इसलिए, यदि अनुच्छेद 243ज (2) और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक की धारा 45ज(2) बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होती है, तो इससे बीआर अधिनियम के उपबंधों से भिन्नता आएगी। इस मुद्दे को समाधान करने और बीआर अधिनियम के उपबंधों को भारत के संविधान के अनुरूप बनाए रखने के लिए आरबीआई ने सरकार से सहकारी बैंकों के लिए लगातार 8 वर्ष की अवधि को 10 वर्ष के रूप में संशोधित करने के क्रम में 2023-24 के केंद्रीय बजट में बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 10क(2क)(i) में संशोधन करने की सिफारिश की है।

2.133 भा. रि. बैंक के उपरोक्त निवेदन के संबंध में, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति के समक्ष बताया, "कार्यकाल के बारे में पूछा यह गया था कि क्या बैंकिंग विनियमन अधिनियम और संविधान में इसकी अलग-अलग अवधि बताई गई है। बीआर अधिनियम को संविधान के अनुरूप बदलने का प्रस्ताव और यह विधेयक मंत्रालय के विचाराधीन है। इसी तरह, बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि, जो छह महीने और पांच साल की है, को संविधान के अनुसार पांच साल करने का प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है। इसे संविधान के अनुरूप बनाया जाएगा और हम इस मामले में तुरंत कार्रवाई करेंगे।"

2.134 आरबीआई ने यह भी बताया कि विधेयक में कुछ ऐसे उपबंध हैं, यथा धारा 41, 45 और 51 जिनकी व्याख्या बोर्ड की संरचना या निदेशकों/सीईओ के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी किए गए मौजूदा अनुदेशों के अनुरूप अनिवार्यतः नहीं होने की सीमा तक संभावित रूप से अलग-अलग ढंग से की जा सकती है। उन्होंने आगे यह पाया कि बीआर अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अनुसार खंड 6, 16, 24, 28, 34 और 45 जैसे कुछ खंड भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के दायरे में आ रहे हैं, जिनके समक्ष कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में विधेयक में संशोधन के संबंध में अस्पष्ट निर्वाचन के परीक्षण का सामना करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। भा. रि. बैंक के उपरोक्त तर्क के संबंध में, सहकारिता मंत्रालय से पूछा गया था कि नोडल मंत्रालय ने इन अस्पष्टताओं को किस तरह से हल करने का प्रस्ताव किया है, इसके उत्तर में उन्होंने निम्नवत लिखित उत्तर दिया:—

- “• धारा 6, 16, 24, 28, 34 और 45 क्रमशः सहकारी समितियों के विलय, बोर्ड के सदस्य होने की निर्रहता, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि, समवर्ती लेखा परीक्षा, बकाया राशि की वसूली और अधिक्रमण से संबंधित हैं।

- बिल को अंतिम रूप देते समय भा. रि. बैंक और डीएफएस दोनों से परामर्श किया गया और परामर्श के आधार पर बिल में उचित बदलाव किए गए।
- अंतर-मंत्रालयी परामर्श प्रक्रिया के दौरान, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने अपने दिनांक 04.10.2022 के पत्र के माध्यम से बताया कि प्रस्तावित संशोधित विधेयक रूप से बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अनुरूप है और इस प्रकार से, डीएफएस संशोधन विधेयक से सहमत है और उसका समर्थन करता है। इसके अलावा, डीएफएस बीआर अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करेगा ताकि इसके उपबंध संविधान के अनुरूप हों। 19.01.2023 को आयोजित जेपीसी की बैठक में सचिव (डीएफएस) द्वारा भी यही कहा गया था।"

हितधारकों द्वारा सुझाव

2.135 एनएएफएससीओबी ने सुझाव दिया है कि धारा 45(1) के अंतर्गत विहित कार्यों के निर्वहन के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना के लिए प्रस्तावित संशोधन सहकारी चरित्र को न्यायोचित नहीं ठहराता है। संपूर्ण धारा 45 अस्वीकार्य है क्योंकि उपबंध सहकारी सिद्धांतों, नैतिकता, मूल्यों आदि के विरुद्ध हैं। मौजूदा उपबंध जारी रहना चाहिए। धारा 45 में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब इन मुद्दों पर टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:—

2.136 जब यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि ये प्रस्ताव किस प्रकार सहकारी सिद्धांतों, नैतिकता और मूल्यों के विरुद्ध नहीं हैं; मंत्रालय ने निम्नवत बताया:—

"संशोधन विधेयक में धारा 45 के प्रतिस्थापन के माध्यम से, संविधान के अनुच्छेद 243यट (2) के अनुसार, एक सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक नया उपबंध पुरःस्थापित किया जा रहा है। इससे निर्वाचन का समयबद्ध, नियमित और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित होगा और सहकारी समितियों का शासन सुदृढ़ होगा। इसलिए, यह सहकारी सिद्धांतों, नैतिकता और मूल्यों के विरुद्ध नहीं है।"

2.137 एनएएफसीएआरडी ने सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 45 में संशोधन के लिए सुझाव दिया है जो यह प्रस्ताव करता है कि खंड 45(j)(8) को, "बहु राज्य सहकारी समिति के मुख्य कार्यकारी प्राधिकरण समय के भीतर चुनाव कराने के लिए, मौजूदा बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति को छह महीने पहले सूचित करेगा" के रूप में बदला जाए।

उनके अनुसार अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से प्राधिकरण को सूचना देने के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा से मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकरण को सूचना दे सकते हैं।

एनएएफसीएआरडी ने प्रस्तावित 45(j)(9) के पश्चात मूल अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत 45(j)(10) के रूप में निम्नवत अतिरिक्त खंड जोड़ने का भी सुझाव दिया है:—

"सोसायटी से धारा 45 (ज) (8) के अंतर्गत वांछित सूचना प्राप्त होने पर, प्राधिकरण संबंधित सोसायटी के परामर्श से बोर्ड और पदाधिकारियों के निर्वाचन की तारीख नियत करेगा।"

इसके अनुसार, उपरोक्त उपबंध प्राधिकरण और सोसाइटी को समय पर निर्वाचन कराने के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि नियत करने में सुविधा प्रदान करेगा।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.138 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड 18

2.139 धारा 49. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य—

मूल अधिनियम में उपबंध

(1) बोर्ड ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों को करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्ति में निम्नलिखित शक्ति भी होगी, अर्थात्—

(क) सदस्यों को सम्मिलित करना;

(ख)... से (घ)

(ड) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनमानों, भर्तों और सेवा की अन्य शर्तों को, जिनके अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाइयां भी हैं, विनियमित करने के लिए उपबंध कराना;

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.140 मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (2) में—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(क) प्राधिकरण के निदेश के अनुसार बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों में से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या सभापति और उप सभापति का निर्वाचन करना:

परंतु निर्वाचन का प्रमाणपत्र बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक द्वारा बोर्ड द्वारा संकल्प पर सहमति होने के पश्चात् जारी किया जाएगा ;”;

(ii) खंड (ड) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु ऐसे कर्मचारियों की भर्ती, ऐसी प्रक्रिया के अधीन रहते हुए होगी, जो विहित की जाए।”।

प्रस्तावित संशोधन का तर्क

2.141 शासन व पारदर्शिता सुदृढ़ीकरण

इससे भर्ती में भाई-भतीजावाद रुकेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे मानकीकृत भर्ती नीति विनिर्दिष्ट करने में मदद मिलेगी।

समिति द्वारा जांच

2.142 सहकारी समितियों में नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने के क्रम में राष्ट्रव्यापी भर्ती बोर्ड की आवश्यकता के संबंध में समिति के एक प्रश्न पर सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों पर ब्रीफिंग के दौरान, मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:—

“...मौजूदा एमएससीएस अधिनियम, 2002, एमएससीएस के कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया विहित करने संबंधी उपबंध नहीं करता है। इससे मनमानापन और भाई-भतीजावाद होता है क्योंकि प्रत्येक एमएससीएस अपनी प्रक्रिया का अनुसरण करता है।

धारा 49 में प्रस्तावित उपबंध भाई-भतीजावाद को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया के निर्धारण का उपबंध करती है। इससे एक मानकीकृत भर्ती नीति बनाने में भी मदद मिलेगी।

एमएससीएस आर्थिक संस्थाएँ हैं और अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह हैं। भर्ती बोर्ड के गठन से उनके स्वायत्त कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, भर्ती के लिए केवल निर्धारित प्रक्रिया का प्रावधान शामिल किया गया है...”

हितधारकों द्वारा सुझाव

2.143 प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार बहुराज्य सहकारी समिति के बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों में से चेयरमैन, वाईस-चेयरमैन या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मूल अधिनियम की 49 की उपधारा (2) के अंतर्गत एक नया पैरा 'कक' शामिल करने हेतु संशोधन करने के संबंध में, एनसीयूआई ने कहा है कि प्रस्तावित उपबंध सोसाइटी के पदाधिकारियों के चुनाव में देरी करेगा, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि बोर्ड और सोसाइटी के पदाधिकारियों के चुनाव की पूरी प्रक्रिया चुनाव प्राधिकरण द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर के समग्र पर्यवेक्षण में चल रही है, इसलिए एमएससीएस अधिनियम और नियम 2002 के अनुसार मौजूदा उपबंधों को बनाए रखा जा सकता है। नेफेड ने यह भी सुझाव दिया है कि नए बोर्ड के गठन के तुरंत बाद सोसाइटी के पदाधिकारियों का चुनाव किया जाए। सहकारिता मंत्रालय को इन मुद्दों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:—

बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों के बीच में से बहुराज्य सहकारी समिति के सभापति, उपसभापति या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के तत्काल चुनाव पर कोई रोक नहीं है। बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन सहित संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के पर्यवेक्षण, निर्देशन व नियंत्रण में संपन्न होगा।

2.144 एनसीयूआई ने धारा 49 की उपधारा 2(ङ) के अंतर्वेशन के लिए प्रस्तावित संशोधन (विधेयक के खंड 18(ii)) विरोध भी किया है कि कर्मचारियों की भर्ती ऐसी प्रक्रिया के अधीन होगी जो निर्धारित की जा सकती है। एनसीयूआई के अनुसार, यह सोसाइटी के स्वतंत्र और स्वायत्त विशेषता को प्रभावित कर सकता है और मांग करता है कि कर्मचारियों की भर्ती सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बजाय ऐसी सोसाइटी के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित सेवा नियम के अनुसार होगी। एनएएफसीयूबी ने भी इसी तरह का अभिमत दिया, एनएएफईडी ने भी सुझाव दिया है कि खंड (ङ) को संशोधित किया जा सकता है, "बशर्ते कि ऐसे कर्मचारियों की भर्ती संगठन के भर्ती नियमों/सेवा नियमों में निर्धारित की जाएगी"। उपरोक्त सुझावों की ओर सहकारिता मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया गया और उस पर टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। मंत्रालय ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:—

धारा 49 में प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से धारा 49 (ii) में खंड (ङ) को अंतःस्थापित किया जाएगा, जिसके अनुसार कर्मियों की भर्ती ऐसी प्रक्रिया के अध्यधीन होगी जैसा कि विहित किया जाए। कर्मियों की भर्ती की शक्ति, बहुराज्य सहकारी समिति के बोर्ड के पास अंतर्विष्ट है। प्रस्तावित संशोधन से भर्ती में भाई-भतीजावाद पर लगाम लाने और पारदर्शिता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

2.145 एनएएफसीयूबी ने सुझाव दिया कि यह उन यूसीबी के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए जिनके पास आरबीआई से अनुज्ञा पत्र प्राप्त है और बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 35, 56 के अंतर्गत आरबीआई के निर्देश हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम बैंकिंग कंपनियों पर अन्य सभी अधिनियमों का स्थान लेता है। यह सम्मिलन परिवार्य विवाद का सृजन करेगा। इसलिए, गैर-प्रयोज्यता के लिए अनुरोध होगा। जब इन मुद्दों पर टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो सहकारिता मंत्रालय ने निम्नानुसार उल्लेख किया:—

'प्रचलित प्रथा के अनुसार, आरबीआई द्वारा विभिन्न कानूनों, जैसे भारतीय कंपनी अधिनियम या विभिन्न सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के तहत निगमित संस्थानों को बैंकिंग लाइसेंस दिया जाता है। ऐसे सभी संस्थान, संबंधित अधिनियमों जिनके अधीन उनका निगमन हुआ है के साथ-साथ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित होते हैं। तथापि, ऐसे सभी संस्थानों के लिए दोहरा विनियमन विद्यमान रहते हैं। स्पष्टता लाने के लिए संशोधन विधेयक, धारा 120 B (नई अंतर्विष्ट) का प्रस्ताव करता है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के प्रावधान, बहुराज्य सहकारी बैंक पर उनके निगमन, विनियमन और परिसमापन से संबंधित मामलों पर लागू होंगे, बशर्ते कि बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली बहुराज्य सहकारी समिति पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधान भी लागू होंगे।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.146 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं.19

मूल अधिनियम में उपबंध

2.147 धारा 50: बोर्ड के अधिवेशन

(1) मुख्य कार्यपालक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष वा सभापति की प्रेरणा पर बोर्ड के अधिवेशन बुलाएगा।

(2)

(3) सभापति, या किसी यदि वह बोर्ड के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अधिवेशन में उपस्थित बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया बोर्ड का कोई अन्य सदस्य अधिवेशन का सभापतित्व करेगा।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.148 “मूल अधिनियम की धारा 50 में,—

(क) उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“परंतु जहां ऐसा अध्यक्ष या सभापति मुख्य कार्यपालक को बोर्ड की तिमाही के भीतर बैठक आयोजित करने के लिए निदेश देने में असफल रहता है तो ऐसा मुख्य कार्यपालक बोर्ड के उप सभापति या उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की अध्यपेक्षा के आधार पर बैठक आयोजित करेगा:

परंतु यह और कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य कार्यपालक बोर्ड के कम से कम पचास प्रतिशत सदस्यों की अध्यपेक्षा के आधार पर बैठक आयोजित कर सकेगा।”

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(3) सभापति या अध्यक्ष, यदि किसी कारण से बोर्ड की बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं तो उपाध्यक्ष या उप सभापति और दोनों की अनुस्थिति में बोर्ड के उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से चुना गया बोर्ड का कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के निदेशक बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति इसके निर्वाचित निदेशकों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी।”

प्रस्तावित संशोधन के पीछे का तर्क

2.149 “बोर्ड की संरचना, बैठकों व सदस्यता में सुधार

यह पाया गया है कि कभी-कभी अध्यक्ष/सभापति बैठक बुलाने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं इससे बचने के लिए उपधारा (1) के अंतर्गत एक परंतुक जोड़ा जा रहा है।

आज की तिथि में कोई गणपूर्ति विहित नहीं किया गया है। इससे, बोर्ड में समावेशी व पारदर्शी निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

समिति द्वारा जाँच

2.150 विधेयक में किए गए उपबंध में ब्रीफिंग के दौरान, समिति ने पाया कि बोर्ड की बैठकों के लिए विहत गणपूर्ति प्रस्तावित 1/3 गणपूर्ति के स्थान पर कम से कम 50% होना चाहिए। इस संदर्भ में, सहकारिता मंत्रालय ने अपने ब्रीफिंग उपरांत उत्तर में निम्नवत् स्पष्ट किया:—

मौजूदा एमएससीएस अधिनियम, 2002 में बोर्ड की बैठकों के लिए कोई गणपूर्ति विनिर्दिष्ट नहीं है। इससे बोर्ड के कुछ ही सदस्यों द्वारा निर्णय लेने की संभावना बनती है।

बोर्ड के निर्णयों में अधिक सदस्यों की भागीदारी और बोर्ड की बैठकों के लिए गणपूर्ति के संबंध में एकरूपता लाने की आवश्यकता महसूस की गई।

बोर्ड की बैठकों के लिए न्यूनतम गणपूर्ति विहित करने के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 50 में उपधारा (4) में संशोधन अंतःस्थापित जा रहा है। इसे निर्वाचित निदेशकों के 1/3 पर रखा गया है क्योंकि एमएससीएस की बोर्ड बैठकों के लिए एक अधिक गणपूर्ति विहित होने पर बैठकें आयोजित करने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं।

हितधारकों द्वारा प्राप्त सुझाव

2.151 एनएएफसीएआरडी ने समिति के समक्ष उल्लेख किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पद्धति के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को भी बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति में माना जाएगा, वशर्ते बैठक के एजेण्डे में पदाधिकारियों का चुनाव सम्मिलित न हो। इस अनुच्छेद के जोड़े जाने से अपेक्षाकृत अधिक अच्छी सहभागिता के साथ व्यय एवं समय की दृष्टि से भी मितव्ययिता होगी, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर की सहकारिताओं के लिए जिनके सदस्य विभिन्न राज्यों में रहते हैं।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियाँ

2.152 मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि संशोधन विधेयक के खंड 19(4) के एमएससीएस के निदेशकों के बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति चयनित निदेशकों की कुल संख्या का एक तिहाई प्रस्तावित है। वास्तविक उपस्थिति के माध्यम से भागीदारी परस्पर वार्ता को बढ़ाएगी और एमएससीएस में लोकतंत्र को सुदृढ़ करेगी।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.153 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 20

मूल अधिनियम में उपबंध

2.154 धारा 51: मुख्य कार्यपालक

(1) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का एक मुख्य कार्यपालक होगा, चाहे वह किसी भी पदाभिधान से ज्ञात हो, जिसे बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का पूर्णकालिक कर्मचारी होगा।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.155 “मूल अधिनियम की धारा 51 में, उपधारा(1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“(1अ) कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, ऐसे मुख्य कार्यपालक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करेगी या उसके नियोजन को जारी नहीं रखेगी, जो,—

(क) इक्कीस वर्ष से कम आयु का है या जिसने सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

परंतु सत्तर वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति, बोर्ड के तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा उस दशा में नियुक्त किया जा सकेगा, जिस दशा में ऐसे प्रस्ताव के लिए सूचना से उपाबद्ध स्पष्टीकारक विवरण ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए औचित्य को उपदर्शित करेगा;

(ख) जो अननुमोचित दिवालिया है या किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है;

(ग) किसी न्यायालय द्वारा किसी भी समय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है और छह मास से अधिक की अवधि के लिए दंडादिष्ट किया गया है।”

(घ) बहुराजीय प्रत्यय सोसाइटियों की दशा में केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा यथा अवधारित 'ठीक और समुचित' के मानदंड को पूरा नहीं करता है; या गैर बहुराजीय प्रत्यय सोसाइटियों की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा शैक्षिक अहंताओं और सुसंगत अनुभव के निबंधनों में विहित किए जाने वाले मानदंड को पूरा नहीं करती है।'

संशोधन के पीछे औचित्य

2.156 अभिशासन और पारदर्शिता को सुदृढ़ करना

बोर्ड द्वारा सीईओ की नियुक्ति के लिए मानदंड आवश्यक हैं। आरबीआई द्वारा बैंकों के सीईओ की नियुक्ति के लिए 'फिट एंड प्रॉपर' मानदंड के अनुरूप बहुराज्य क्रेडिट सहकारी सोसाइटियों में सीईओ की नियुक्ति के लिए कड़े मानदंडों की आवश्यकता है।

समिति द्वारा जाँच

2.157 विधेयक में निहित उपबंधों पर ब्रीफिंग के दौरान, समिति ने सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों से पूछा कि क्या सीईओ की आयु 21 से 70 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। इस संबंध में, सहकारिता मंत्रालय ने अपने लिखित में निम्नवत् उत्तर प्रस्तुत किए:—

"मौजूदा अधिनियम की धारा 51 और धारा 52 मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों से संबंधित हैं। तथापि, मौजूदा अधिनियम में सीईओ की नियुक्ति की आयु-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं है। प्रस्तावित संशोधन के खंड 20 के माध्यम से धारा 51 में अंतःस्थापित नई उपधारा (1) द्वारा सीईओ की आयु सीमा निर्दिष्ट की गई है। आयु सीमा की शर्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196(3) के अनुरूप है।

आरबीआई का टिप्पणी

2.158 प्रस्तावित एमएससीएस अधिनियम के संशोधन की धारा 51(1ए) के तहत नया प्रावधान जोड़ा गया है जो मुख्य कार्यपालक की आयु 21 और 70 वर्ष के बीच निर्धारित करता है। इसके अलावा, 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को एक विशेष संकल्प द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 10, 10बी, 10बीबी, 35 ए, 35 बी, 36एए और 53 ए (धारा 56 के साथ पढ़ित) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित प्रबंध निदेशक (एमडी) और पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति, पुनः नियुक्ति, समाप्ति और हटाने से संबंधित कुछ निदेश आरबीआई के दिनांक 25 जून, 2021 के परिपत्र के माध्यम से जारी किए गए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुख्य कार्यपालक को संस्थान के प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए बैंकिंग, वित्त या प्रशासन का व्यापक अनुभव और ज्ञान होना आवश्यक है, उक्त परिपत्र के अनुसार मुख्य कार्यपालक के रूप में नियुक्त होने की न्यूनतम आयु, 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु 70 वर्ष है और विनियामकीय दिशानिर्देशों के तहत 70 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, अगर कोई सीईओ, बहु-राज्य क्रेडिट सोसाइटियों के मामले में केन्द्रीय रजिस्ट्रार और नॉन-क्रेडिट बहु-राज्य सोसाइटियों के मामले में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित "सटीक और उचित" मानदंड को पूरा नहीं करता है, अयोग्यता का भी प्रस्ताव है। तथापि, यूसीबी के लिए "उचित और उपयुक्त" मानदंड का निर्धारण आरबीआई द्वारा उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 3.4 (पात्रता) और 3.5 (औचत्य मानदंड) के अंतर्गत किया गया है। इसलिए, यूसीबी के सीईओ/एमडी की न्यूनतम और अधिकतम आयु, अयोग्यता और अध्यक्ष और एमडी/सीईओ बहु-राज्यीय यूसीबी के लिए "उपयुक्त और उचित" मानदंडों के संबंध में बीआर अधिनियम, 1949 के तहत आरबीआई द्वारा जारी लागू विनियमों की प्रधानता पर स्पष्टता लाना उचित होगा।

हितधारकों से प्राप्त सुझाव/टिप्पणियां

2.159 एनएफएससीओबी ने समिति के समक्ष अपने लिखित उक्त में उल्लेख किया कि सदस्य संचालित सहकारियों के कार्यों और संकल्पों का निष्पादन करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए 21 वर्ष का सीईओ बहुत अपरिपक्व है। उन्होंने आयु को 35 वर्ष करने का सुझाव दिया है।

2.160 नावार्ड ने सुझाव दिया है कि "बहुराज्य सहकारी बैंकों के सीईओ के लिए धारा 51 के अंतर्गत अतिरिक्त उपबंध शामिल किए जा सकते हैं, धारा 35 1.(ख) के उपबंधों के अनुसार मानदंड तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्य प्रासंगिक खंड लागू होंगे"

2.161 एनसीयूआई ने सुझाव दिया है कि उपयुक्त और उचित मानदंड के प्रस्तावित उपबंध बहुराज्य क्रेडिट सोसाइटियों के लिए ही लागू होंगे क्योंकि सहकारी व्यवसाय का स्वरूप निजी क्षेत्र से अलग है इसलिए, गैर-क्रेडिट सहकारी सोसाइटियों के लिए मानदंड तय करने के लिए भारत सरकार के बजाय ऐसी बहु राज्य सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड में निवेश किया जाना चाहिए।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियाँ

2.162 एनसीयूआई के उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के संबंध में, सहकारिता मंत्रालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:—

- सीईओ की नियुक्ति की शक्ति बोर्ड के पास ही निहित है। सीईओ की नियुक्ति की शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के प्रावधान का प्रस्ताव सभी बहुराज्य सहकारी समितियों के अभिशासन को सशक्त करने के लिए किया गया है। आरबीआई द्वारा बैंकों में सीईओ की नियुक्ति की 'फिट एंड प्रॉपर' शर्त के समान बहुराज्य क्रेडिट सहकारी समितियों के सीईओ की नियुक्ति के माप दंड को कड़ा करने की आवश्यकता है। गैर-क्रेडिट बहुराज्य सहकारी समितियों में सीईओ की नियुक्ति के लिए उनके व्यवसाय की प्रकृति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार यथोचित शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकती है।

"यह प्रावधान केवल न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा विनिर्दिष्ट करता है। संबंधित समिति का बोर्ड, सक्षम प्राधिकारी होने के नाते आवश्यकतानुसार इन आयु-सीमाओं के बीच सीईओ को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। यह प्रस्तावित आयु सीमा, कंपनी अधिनियम, 1923 की धारा 196(3) के अनुसार प्रबंध निदेशक के लिए निर्दिष्ट आयु सीमा के अनुरूप है।"

2.163 भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणियों के उत्तर में, अंतर-मंत्रालयी परामर्श की प्रक्रिया के दौरान, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने अपने दिनांक 04.10.2022 के पत्र के द्वारा सूचित किया कि प्रस्तावित संशोधित विधेयक व्यापक रूप से बैंककारी विनियमन अधिनियम के साथ संरेखित है और इसलिए, वित्तीय सेवाएं विभाग संशोधन विधेयक से सहमत है और इसका समर्थन करता है। इसके अलावा, डीएफएस बैंककारी विनियमन अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करेगा ताकि इसके उपबंध संविधान के अनुरूप हों। सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) ने दिनांक 19.01.2023 को आयोजित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में भी यही कहा था।

प्रचलित प्रथा के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस भारतीय कंपनी अधिनियम या विभिन्न सहकारी सोसाइटी अधिनियमों जैसे विभिन्न विधियों के अंतर्गत निगमित इकाईयों को दिया जाता है। ऐसी सभी इकाईयां संबंधित अधिनियमों के द्वारा, जिनके अंतर्गत उन्हें निगमित किया जाता है और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत भी प्रशासित होती हैं। इस प्रकार, ऐसी सभी इकाईयों के लिए दोहरे विनियमन विद्यमान हैं। स्पष्टता लाने के लिए, संशोधन विधेयक धारा 120 ख (नए अंतःस्थापन) में प्रस्तावित करता है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के उपबंध निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित मामलों के संबंध में एक बहुराज्य सहकारी बैंक पर लागू होते हैं: परंतु यह है कि बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के मामले में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधभी लागू होंगे।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.164 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 21

मूल अधिनियम में उपबंध

2.165 धारा 52: मुख्य कार्यपालक की शक्तियाँ और कृत्य

मुख्य कार्यपालक, बोर्ड के साधारण पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए नीचे विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कारवार का दिन प्रतिदिन का प्रबंध ;

(ख) से (i).....

(ज) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीस दिन के भीतर बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रारूप वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना;

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.166 “मूल अधिनियम की धारा 52 के खंड (ज) में, “तीस दिन” शब्दों के स्थान पर, “पैंतालीस दिन” शब्द रखे जाएंगे।”

संशोधन के पीछे का औचित्य

2.167 “प्रारूप वार्षिक रिपोर्ट व वित्तीय विवरणियां, आदि प्रस्तुत करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय देने का प्रावधान।”

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.168 समिति ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 22

मूल अधिनियम में उपबंध

2.169 धारा 53: बोर्ड की समितियां

(1) बोर्ड, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, ऐसी कार्यपालक समिति, अन्य समितियों या उपसमितियों का गठन कर सकेगा जो आवश्यक प्रतीत हों: परंतु कार्यपालक समिति से भिन्न अन्य समितियां या उपसमितियां तीन से अधिक नहीं होंगी।

प्रस्तावित विधेयक में संशोधन

2.170 मूल अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(1) बोर्ड, एक कार्यकारी समिति और ऐसी अन्य समितियों या उपसमितियों का गठन कर सकेगा, जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

परंतु बोर्ड,—

(क) उपविधियों के अनुसार एक संपरीक्षा और आचार समिति का गठन करेगा;

(ख) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण संबंधी समिति का गठन करेगा।”।

संशोधन के पीछे औचित्य

2.171 “अभिशासन और पारदर्शिता को सुदृढ़ करना

सदाचार, यौन उत्पीड़न की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए समितियों के गठन का कोई मौजूदा प्रावधान नहीं था। आंतरिक समितियों के माध्यम से मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और मिड-कोर्स करेक्शन से समितियों में बेहतर शासन सुनिश्चित होगा।

समिति के द्वारा जाँच

2.172 नोडल मंत्रालय के साथ ब्रीफिंग बैठक के दौरान, सदस्यों द्वारा वित्तीय सुरक्षा में एक और समिति को शामिल करने का सुझाव दिया गया। उक्त सुझाव पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में उल्लेख किया कि लेखापरीक्षा और आचार समिति वित्तीय सुरक्षा की अनुवीक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा, बोर्ड, जैसा उचित समझे, एक कार्यपालक समिति और अन्य समितियाँ तथा उपसमितियाँ गठित कर सकता है और ऐसी समितियों की संख्या तीन से अधिक नहीं होंगी।

हितधारकों से प्राप्त सुझावों

2.173 नाबार्ड ने अपने प्रस्तुतीकरण में कहा है कि हितधारकों की तरफ से संशोधित उपबंधों के लिए कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, इसने "कार्य स्थल पर" ... के बाद "उप-विधि के अनुसार" शामिल करने का सुझाव दिया है।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियां

2.174 एमएससीएस अधिनियम 2002 की वर्तमान धारा 53 में उपविधियों के अनुसार समितियों के कार्यकरण का प्रावधान है। अतः "कार्य स्थल पर" के पश्चात् 'उपविधियों के अनुसार' सुझाए गए शब्दों की विधेयक के खंड 22 में आवश्यकता नहीं है।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.175 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 23

मूल अधिनियम में उपबंध

2.176 धारा 63: शुद्ध लाभों का व्ययन

(1) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, किसी वर्ष में अपने शुद्ध लाभों में से—

(क);

(ख) एक प्रतिशत भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा अनुरक्षित सहकारी शिक्षा निधि में ऐसी रीति से जमा करेगी जो विहित की जाए;

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.177 "मूल अधिनियम की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली सहकारी शिक्षा निधि में शुद्ध लाभ का एक प्रतिशत प्रत्यय वार्षिक रूप से ऐसी रीति में जमा करेगी जो विहित की जाए और ऐसी निधि से प्राप्त आगम भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और ऐसे किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए उपयोग किए जाएंगे;"

संशोधन के पीछे औचित्य

2.178 "सहकारी क्षेत्र द्वारा पूँजी जुटाना। इससे उपयोग में लचीलापन, बेहतर अनुरक्षण व अनुपालन सुनिश्चित होगा।"

समिति द्वारा जाँच

हितधारकों द्वारा प्राप्त सुझाव

2.179 एनयूसीआई ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए:—

(i) 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग के सहयोग के कार्यकारी समूह की सिफारिश पर और 1981 में आरबीआई द्वारा गठित सीआरएएफआईसीएआरडी की समीक्षा करने के लिए समिति, सीईएफ के संग्रह और प्रबंधन के लिए एमएससीएस अधिनियम 2002 में पूर्ण धारा 63 पेश की गई थी, जिसे स्थापना के बाद से एनसीयूआई को सौंपा गया था, और उनके द्वारा अनुरक्षण तथा प्रबंधित किया गया। किसी भी एमएससीएस ने एनसीयूआई द्वारा निधि के अनुरक्षण पर आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है, जिसका लेखापरीक्षा नियमित रूप से किया जा रहा है।

(ii) इस निधि में भारत सरकार का कोई योगदान नहीं है, इसलिए इसे सहकारी स्वायत्तता, सहकारी सिद्धांतों और स्वतंत्रता के मूल्यों और सहकारी समितियों के बीच सहयोग की भावना से एनसीयूआई के साथ रहना चाहिए। सरकार की भूमिका सूत्रधार की होनी चाहिए न कि नियंत्रक की।

(iii) संबंधित राज्य सरकारें ऐसी निधियों पर नियंत्रण कर सकती हैं जो राज्य सहकारी संघों को कमज़ोर कर सकती हैं और शिक्षा और प्रशिक्षण की गतिविधियों को प्रभावित कर सकती हैं और नौकरशाही में देरी का कारण बन सकती हैं।

(iv) प्रस्तावित संशोधन को हटाया जा सकता है और एमएससीएस अधिनियम के अनुसार मौजूदा उपबंध को बनाए रखा जा सकता है।

2.180 अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में, उन्होंने उल्लेख किया कि एनसीयूआई निवेश पर ब्याज सहित निधि के लिए अलग बैंक खाता का रखरखाव करता है जिसे खाते में जमा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष गतिविधियों के लिए बजट सीईएफ समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है जो विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों, एमएससीएस, राज्य सहकारी संघों, वीएमएनसीओएम, एनसीसीटी, एनसीसीई, आरआईसीएम/आईसीएम के माध्यम से संचालित किया जाता है जिसके लिए एनसीयूआई द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, एनसीयूआई अब मंत्रालय के उद्देश्य के अनुरूप प्रमुख पहल कर रहा है जैसे डेटाबेस तैयार करना, विशेषरूप से डेयरी, क्रेडिट और मत्स्यपालन में नई सहकारी समितियों का गठन, संसाधन केंद्र स्थापित करने वाले उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग आदि। उपरोक्त के लिए सीईएफ से कुल 100 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है और इसके लिए भविष्य में भी नियमित धन की आवश्यकता होगी। इसलिए, सीईएफ के संग्रह और प्रबंधन से संबंधित मौजूदा उपबंध जारी रह सकते हैं।

2.181 निधि के उपयोग के संबंध में, एनसीयूआई ने उल्लेख किया कि वित्त वर्ष 2021-22 तक, कुल 356.85 करोड़ रुपये एकत्रित किए गए हैं, जिसमें से 228.145 करोड़ रुपये का उपयोग समय-समय पर सीईएफ समिति द्वारा उचित अनुमोदन के बाद और देय राशि का भुगतान करने के बाद किया गया है और खातों के रखरखाव में सावधानी बरतते हुए एकत्रित की गई निधि के लगभग 64% का उपयोग किया। निधि में अनुपयोगी के रूप में परिलक्षित होने वाली राशि वास्तव में एनसीयूआई द्वारा विवेकपूर्ण निवेश के परिणामस्वरूप वर्षों से संचित चक्रवृद्धि ब्याज है - जो सीईएफ का संरक्षक है। यह एक सतत निधि है इसलिए सहकारी क्षेत्र की आवश्यकतानुसार उपयोग करने के लिए वर्षों से संचित है। इसके अलावा, कोविड महामारी और उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा प्रतिबंधों के कारण, सभी सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण 2 वर्षों के लिए ऑनलाइन आयोजित किए गए थे और इसलिए निधि संचय से संबंधित थे। हर वर्ष वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा खातों की लेखापरीक्षा की जाती है और सीएजी हर 3-4 साल में लेखापरीक्षा करता है।

2.182 कृभको ने उल्लेख किया है कि एनसीयूआई कुशलतापूर्वक और संतोषजनक ढंग से निधि का प्रबंधन कर रहा है इसलिए, अधिनियम में मौजूदा उपबंध जारी रह सकते हैं। इसी तरह नेफेड ने भी एमएससीएस अधिनियम की धारा 63 के मौजूदा उपबंध को जारी रखने की वकालत की है।

2.183 एनएफएससीओबी ने उल्लेख किया है कि सहकारी समितियों के संसाधनों को सहकारी समितियों के पास जमा किया जाना चाहिए और उनका उपयोग किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा निधि का रखरखाव करने का प्रस्ताव दृढ़ता से न्यायोचित नहीं है। एनसीयूआई को हर तरह से निधि को बनाए रखने का अंतिम अधिकार होना चाहिए।

2.184 नाबाई ने हालांकि यह विचार व्यक्त किया है कि अधिनियम में संशोधन के माध्यम से निर्धारित उपबंधों से सहकारी क्षेत्र में आंतरिक संसाधनों के निर्माण में मदद मिलेगी और सरकार द्वारा बजट आवंटन पर निर्भरता कम होगी। यह सहकारी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की तरह है।

2.185 एनएफसीयूबी ने समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए कहा है कि एनसीयूआई उन्हें कुछ भी प्रदान नहीं कर रहा है और कुछ प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर के संघों को आवंटित किया जाना चाहिए जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

आरबीआई के टिप्पणियाँ/विचार

2.186 धारा 63(1)(बी) में संशोधन का प्रस्ताव है कि सहकारी शिक्षा निधि को केंद्र सरकार द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा और इसका उपयोग भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के माध्यम से सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। निधि में इस तरह का अनिवार्य अंशदान आरबीआई के बीआर अधिनियम/विनियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत उसके खर्चों पर लगाए गए सामान्य पर्यवेक्षी और विनियामक प्रतिबंधों में हस्तक्षेप कर सकता है। यदि निधि में कमी के प्रारंभिक संकेत हैं, तो यह बैंक के अभीष्ट हित में भी नहीं हो सकता है भले ही यह लाभदायक है और आरबीआई के पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत नहीं है। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि इस निधि के अलावा, अतिरिक्त ₹1 करोड़ या निवल लाभ का 1% (जो भी कम हो) पुनर्रचना निधि हेतु अंशदान करना आवश्यक है।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियाँ

2.187 हितधारकों के उपरोक्त सुझावों/विचारों को सहकारिता मंत्रालय के साथ उठाया गया और उनकी टिप्पणियां मांगी गईं। उत्तर में, सहकारिता मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:—

“प्रस्तावित उपबंध सहकारी शिक्षा निधि के उपयोग, बेहतर अनुपालन और उपयोग में अधिक लचीलापन सुनिश्चित करेगा। वर्तमान में, एनसीयूआई द्वारा बनाए जा रहे सहकारी शिक्षा निधि में लगभग 275 करोड़ रुपये का निधि अप्रयुक्त पड़ा हुआ है। चूंकि, यह योगदान केवल शुद्ध लाभ कमाने वाले एमएससीएस से एकत्र किया जाना है और वह भी एमएससीएस अधिनियम 2002 की मौजूदा धारा 63 के अनुसार केवल 1% की दर से, यह योगदान करने वाली समितियों पर बोझ नहीं होगा।”

2.188 आरबीआई की टिप्पणियों पर मंत्रालय ने उत्तर दिया कि अधिनियम की वर्तमान धारा 63 में पहले ही नेशनल कॉपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा रखे गए सहकारिता शिक्षा कोष में एक प्रतिशत उधार का प्रावधान है।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.189 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 24

नई अंतःस्थापना 63क से 63ग

प्रस्तावित विधेयक में संशोधन

2.190 “मूल अधिनियम की धारा 63 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

‘63क. (1) केन्द्रीय सरकार धारा 63ख में यथानिर्दिष्ट रूण बहु राज्यीय सरकारी सोसाइटियों के पुनरुद्धार के लिए और विकास प्रयोजनों के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्गठन और विकास निधि नामक एक निधि का ऐसी रीति में, जो उसके द्वारा अवधारित की जाए, गठन करेगी और ऐसी निधि में ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों द्वारा, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों से लाभ अर्जित कर रही है, एक करोड़ रुपए या ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के शुद्ध लाभ का एक प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हों, वार्षिक रूप से जमा करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक समिति का गठन करेगी, जो ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो वह निधि का प्रशासन करने के लिए ठीक समझे और निधि के संबंध में पृथक लेखों और अन्य सुसंगत अभिलेखों को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से ऐसे प्ररूप में रखेगी, जो विहित किया जाए।

(3) समिति, उन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए, जिनके लिए ऐसी निधि की स्थापना की गई है, निधि में से धन खर्च करेगी।

63ख. (1) यदि किसी समय केंद्रीय रजिस्ट्रार की यह राय है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी रुग्ण हो गई है, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी सोसाइटी को रुग्ण सोसाइटी घोषित कर सकेगा।

(2) जहां किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को उपधारा (1) के अधीन रुग्ण सहकारी सोसाइटी घोषित किया जाता है, वहां केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या अभिकरण सोसाइटी के सुधार और पुनर्गठन के लिए एक स्कीम तैयार कर सकेगी/सकेगा और उसे साधारण सभा में अनुमोदन के लिए सोसाइटी को सौंप सकेगी/सकेगा।

(3) केंद्रीय सरकार, साधारण सभा की सिफारिश पर और उपधारा (2) में निर्दिष्ट सुधार और पुनर्गठन संबंधी स्कीम को प्रभावी रूप देने के लिए, ऐसी सोसाइटी के बोर्ड का ऐसे व्यक्तियों के साथ पुनर्गठन कर सकेगी, जिसके पास सहकारिता, प्रबंध, वित्त, लेखांकन और ऐसी सोसाइटी से संबंधित ऐसे किसी अन्य क्षेत्र में, जिसकी साधारण सभा द्वारा सिफारिश की जाए, अनुभव हो:

परंतु रुग्ण सहकारी बैंक के संबंध में, सुधार या पुनर्गठन संबंधी कोई स्कीम रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से बनाई जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “रुग्ण सहकारी सोसाइटी” से ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, जिसकी किसी वित्तीय वर्ष के अंत में, उसकी समादत्त पूँजी, मुक्त आरक्षितियों और अधिशेषों के बराबर या उससे अधिक संचयित हानि है और उसने ऐसे वित्तीय वर्ष और ऐसे वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद के रूप में हानियां भी उठाई हैं।

63ग. (1) केंद्रीय सरकार, किसी ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा किए गए आवेदन पर, जिसने निरंतर पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए निधि में अभिदाय किया है, जो वह अवसंरचनात्मक अपेक्षा के लिए निधि में से सोसाइटी के लिए ऐसी वित्तीय सहायता मंजूर कर सकेगी, जो वह उचित समझे:

परंतु कुल अपेक्षा का कम से कम पचास प्रतिशत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा वहन किया जाएगा और निधि से वित्तीय सहायता ऐसी अपेक्षा के पचास प्रतिशत से अधिक की नहीं होगी।

(2) धारा 63क की उपधारा (2) के अधीन गठित समिति, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के उस सीमा तक और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह आवश्यक समझे, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समीक्षा करेगी और केंद्रीय सरकार को इसकी सिफारिश करेगी।

संशोधन के पीछे औचित्य

2.191 “सहकारी क्षेत्र द्वारा पूँजी जुटाना

रुग्ण सहकारी समितियों को सहारा देने के लिए यह एक नया उपबंध है जिससे उन्हें प्रगतिशील और लाभप्रद व्यावसायिक योजनाओं के माध्यम से व्यवहार्य बनाया जा सके।

बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा कुल आवश्यकताओं का 50% के अंशदान के प्रावधान से जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग सुनिश्चित होगा।

समिति के द्वारा जाँच

2.192 सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा विधेयक के उपबंधों पर ब्रीफिंग के दौरान समिति ने पाया कि निधि के प्रबंधन पर स्पष्टता की जरूरत है। यह भी बताया गया कि यह विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या सोसाइटी को लगातार 3 वर्षों तक या अन्यथा लाभ में होना चाहिए। इस संबंध में, मंत्रालय ने अपनी लिखित टिप्पणियों में निम्नवत् बताया है:—

मौजूदा एमएससीएस अधिनियम, 2002 में रुग्ण एमएससीएस के पुनरुद्धार या सहायता के लिए किसी निधि का उपबंध नहीं है। धारा-63 (क) की प्रस्तावित नया अंतःस्थापन पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि से संबंधित है जिसे केंद्र सरकार द्वारा बनाए रखा जाएगा। रुग्ण एमएससीएस के पुनरुद्धार और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

के लिए एमएससीएस द्वारा पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लाभ में शुद्ध लाभ का 1% या ₹ 1 करोड़, जो भी कम हो, के योगदान से इसे वित्त पोषित किया जाएगा। केंद्र सरकार इस निधि के प्रशासन के लिए एक समिति का गठन करेगी। केंद्र सरकार, एमएससीएस द्वारा किए गए एक आवेदन पर, जिसने लगातार पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए निधि में योगदान दिया है, ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, जैसा कि यह अवसंरचनात्मक अपेक्षा के लिए निधि से सोसाइटी के लिए उपयुक्त समानता हो वर्ते कि ऐसी आवश्यकता के 50% को एमएससीएस द्वारा ही पूरा किया जाएगा।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए, वाक्यांग "रुग्ण सहकारी समिति" का अर्थ एक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी है जो इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी है जिसकी किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में संचित हानि है इसकी कुल प्रदत्त पूँजी, मुक्त आरक्षित और अधिशेष राशि के बराबर संपदा उससे अधिक हो और इस तरह के वित्तीय वर्ष और ऐसे वित्तदर्जे के पिछले वर्ष में नकद हानियां भी हुई हो और वित्तीय वर्ष ऐसे वित्तीय वर्ष से ठीक पहले हुआ है।

प्रस्तावित उपबंध 'सहकारिताओं के बीच सहयोग' और 'समुदाय की चिंता' के सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप है।

आरबीआई की टिप्पणियाँ

2.193 नई धारा 63ए के अंतर्गत विधेयक एमएससीएस के मुनाफे में से एक निधि (सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं विकास निधि) स्थापित करने का प्रस्ताव करता है जो पिछले तीन वर्षों से लाभ अर्जित कर रहे हैं। इस निधि में वार्षिक योगदान ₹1 करोड़ या शुद्ध लाभ का 1%, जो भी कम हो, होगा। इस निधि का उपयोग केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा घोषित रुग्ण एमएससीएस को पुनर्जीवित करने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा पर, केंद्र सरकार द्वारा समाज के पुनर्वास अथवा पुनर्निर्माण की योजना तैयार की जाएगी और इसे अनुमोदन के लिए साधारण सभा को सौंप दिया जाएगा। सामान्य निकाय की सिफारिश पर, केंद्र सरकार द्वारा सोसायटी के बोर्ड का पुनर्गठन किया जा सकता है। हालाँकि, धारा 63बी(3) के परंतुक में कहा गया है कि बहु-राज्यीय सहकारी बैंक के लिए, पुनर्वास या पुनर्निर्माण की कोई भी योजना भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से की जाएगी। जैसा ऊपर उल्लिखित है, जब किसी सहकारी बैंक को बीआर अधिनियम की धारा 45 के तहत पुनर्वासित अथवा पुनर्निर्मित किया जाता है, तो केंद्र सरकार को अधिस्थगन की सिफारिश करने और केंद्र सरकार के अनुमोदन के लिए पुनर्निर्माण के लिए एक योजना तैयार करने की शक्ति भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त होती है। एमएससीएस अधिनियम की मौजूदा धारा 18 के अंतर्गत, बीआर अधिनियम की धारा 45 के तहत एक बार अधिस्थगन घोषित होने के बाद योजना तैयार करने की शक्ति केंद्रीय रजिस्ट्रार को सौंपी जाती है, जो इसे बीआर अधिनियम की धारा 45 के साथ ही असंगत बनाता है।

इसके अलावा आरबीआई ने निम्नवत अन्य विसंगतियां भी उजागर की हैं:

(क) यदि बीआर अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत किसी बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंक की समस्याओं का समाधान किया जाता है, तो यह आरबीआई और केंद्रीय रजिस्ट्रार दोनों के पुनर्वास अथवा पुनर्निर्माण के लिए एक योजना तैयार करने का एक उदाहरण हो सकता है। चूंकि धारा 45 को सहकारी बैंकों पर हाल ही में लागू किया गया है और यह खंड बीआर अधिनियम और एमएससीएस विधेयक की धारा 105 ए को प्रधानता देने वाला एक गैर-विरोधात्मक खंड है जो यह बताता है कि इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में, यह समझा जाता है कि बीआर अधिनियम की प्रधानता होगी। इसके लिए विधेयक में पर्याप्त स्पष्टता की आवश्यकता है।

(ख) यदि किसी बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंक को धारा 63बी(1) के तहत केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा रुग्ण घोषित किया जाता है, तो केंद्र सरकार को उसे फिर से सुदृढ़ करने या पुनर्रचना के लिए योजना बनानी होगी और इसे सोसाइटी के सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित करवाना होगा। बहु-राज्य सहकारी बैंकों के लिए, धारा 63बी(3) के प्रावधान में कहा गया है कि सुदृढ़ करने या पुनर्रचना के लिए योजना आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के साथ बनाई जाएगी। इसलिए, जब एक बहु-राज्य यूसीबी का समाधान हो रहा है, तो केंद्र सरकार की एक साथ दो अलग-अलग भूमिकाएं हो सकती हैं, अर्थात् एमएससीएस अधिनियम की धारा 63बी(1) के तहत एक योजना तैयार करने के लिए और दूसरा धारा 45 के तहत आरबीआई द्वारा तैयार की गई योजना को मंजूरी देने के लिए। यह विसंगतियों को जन्म दे सकता है और इससे कानूनी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।

(ग) 'रुग्ण' सहकारी सोसाइटी की परिभाषा लाभ के एकल मीट्रिक पर आधारित है। हालाँकि, आरबीआई द्वारा अपने पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ) के तहत किसी सहकारी बैंक पर की जाने वाली पर्यवेक्षी कार्रवाई अधिक व्यापक है और यह एनपीए सीमा के उल्लंघन, लाभप्रदता और प्रारंभिक कार्रवाई शुरू करने के लिए विनियामक पूँजी जैसे कई संकेतकों पर आधारित है। यह ध्यान में रखते हुए कि सहकारी बैंक सार्वजनिक जमाओं को स्वीकारते हैं, आरबीआई द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई बहु-आयामी है और यह प्रबंधन में बदलाव या एमएससीएस (संशोधन) विधेयक, 2022 के तहत निर्धारित निधि को सीमित करने तक नहीं है। तदनुसार, आरबीआई का मत है कि बैंक जमाकर्ताओं के हित में, एमएससीएस अधिनियम के सुदृढीकरण/पुनर्रचना प्रावधानों से सहकारी बैंकों को अलग करना आवश्यक होगा। यह उचित होगा कि यूसीबी के त्वरित और विशेष समाधान के लिए, संशोधित अधिनियम में एक प्रावधान शामिल हो कि सहकारी बैंक के सुदृढीकरण या पुनर्रचना के लिए कोई भी योजना बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम के प्रावधानों और समय-समय पर जारी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियां

2.194 भारतीय रिजर्व बैंक की उपर्युक्त आपत्तियों पर मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:—

"प्रचलित प्रथा के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस भारतीय कंपनी अधिनियम या विभिन्न सहकारी सोसाइटी अधिनियमों जैसे विभिन्न विधियों के अंतर्गत निगमित इकाईयों को दिया जाता है। ऐसी सभी इकाईयां संबंधित अधिनियमों के द्वारा, जिनके अंतर्गत उन्हें निगमित किया जाता है और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत भी प्रशासित होती हैं। इस प्रकार, ऐसी सभी इकाईयों के लिए दोहरे विनियमन विद्यमान हैं। स्पष्टता लाने के लिए, संशोधन विधेयक धारा 120 ख (नए अंतःस्थापन) में प्रस्तावित करता है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के उपबंध निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित मामलों के संबंध में एक बहुराज्य सहकारी बैंक पर लागू होते हैं: परंतु यह है कि बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के मामले में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधभी लागू होंगे।"

प्रस्तावित संशोधन विधेयक की धारा 63 (ख) (3) के परंतुक के अनुसार, एक रुग्ण बहुराज्य सहकारी बैंक के संबंध में, पुनर्वास या पुनर्निर्माण के लिए कोई भी योजना रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी। अतः, भारतीय रिजर्व बैंक का सुझाव स्वीकार नहीं किया जाता है।

हितधारकों द्वारा प्राप्त सुझाव

2.195 खंड 24 का अंतःस्थापन का समर्थन करते हुए, हितधारक संगठन नाबार्ड ने कहा कि उपबंध सहकारी क्षेत्र में आंतरिक संसाधनों के सृजन में मदद करेंगे और सरकार द्वारा बजट आवंटन पर निर्भरता कम करेंगे। यह सहकारी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की भाँति ही है। इसी प्रकार, एनसीडीसी ने वकालत की कि कई सहकारी सोसाइटियाँ जो वित्तीय संकट में हैं, लेकिन कुछ मौद्रिक राहत प्रदान करने पर लाभ में चल सकती हैं, इस निधि से लाभान्वित होंगी।

2.196 बहुराज्य सहकारी (एमएससी) बैंकों के संबंध में, एनएफसीयूबी ने विचार रखा कि निधि के योगदान का प्रबंधन हाल ही में बनाए गए अम्बेला संगठन द्वारा किया जाना चाहिए और यह केवल सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए है। भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी विचार रखा कि कम लाभ वाली कंपनियों सहित सभी सोसाइटियों को फंड में योगदान करना, उन पर अनावश्यक बोझ डालना होगा, जो पहले से ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य औद्योगिक घरानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और ऐसा करना सोसाइटियों के सदस्यों पर बोझ डालना होगा। उन्होंने कहा कि केवल कुछ रुग्ण सहकारी सोसाइटियाँ हैं और सहकारी सोसाइटियों को निधि में बड़ी राशि जमा करने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। तदनुसार उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि खंड 24 और खंड 16 में संबंधित उपबंध को हटा दिया जाना चाहिए।

2.197 एनसीयूआई ने बताया है कि यह लाभ कमाने वाली राज्य सहकारी सोसाइटी के लिए एक अतिरिक्त बोझ है और व्यवसाय के और विकास के लिए धन की आवश्यकता को बढ़ाव देगा। दूसरे, कंपनियों के संबंध में भी, कोई लाभ कमाने वाली कंपनी रुग्ण

उपकरणों के पुनरुद्धार के लिए योगदान नहीं दे रही है। तर्क की समानता पर, लाभ कमाने वाली सहकारी सोसाइटियों को बीमार एमएससीएस के कार्यकरण के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय ऐसे एमएससीएस को स्थिति से उबरने के लिए सभी आवश्यक नीतिगत सहायता, रियायतें/झूट प्रदान की जा सकती है। तथापि, रुग्ण बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के पुनरुद्धार के लिए केन्द्र सरकार स्वयं ऐसी निधि सृजित कर सकती है।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियाँ

2.198 विधेयक में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य, रुग्ण सहकारी सोसाइटियों का पुनरुद्धार करना और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना भी है। इससे रुग्ण सहकारी सोसाइटियों को सहायता मिलेगी, जिन्हें अभिनव और लाभदायक व्यवसाय विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से, व्यवहार्य बनाया जा सकता है। यह योगदान केवल उन एमएससीएस द्वारा शुद्ध लाभ के केवल 1 प्रतिशत या 1 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित है, जो पिछले 3 वित्तीय वर्षों से लाभ में हैं। इसलिए, इससे ऐसे सोसाइटियों पर बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत, यह 'सहकारी सोसाइटियों के बीच सहयोग' के सहकारी सिद्धांत के अनुसार, देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने में मदद करेगा। एमएससीएस को सरकारी सहायता के संबंध में, एमएससीएस अधिनियम 2002 में पहले से ही एक धारा 61 है। कंपनियों के मामले में भी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत व्यय करने का प्रावधान है।

2.199 एनएएफसीयूबी द्वारा संदर्भित अम्बेला संगठन केवल शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को कवर करेगा, जबकि यह समिति और फंड सभी क्षेत्रों में एमएससीएस के लिए होगा।

2.200 एमएससी द्वारा अवसंरचनात्मक आवश्यकता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित खण्ड 63ग में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि अवसंरचनात्मक आवश्यकता के लिए वित्तीय सहायता पचास प्रतिशत तक ही सीमित है और उन सोसाइटियों को जिन्होंने पांच वित्तीय वर्षों में निरंतर कार्यवाही के लिए निधि में योगदान दिया है। ये प्रतिबंध वित्तीय अनुशासन लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए हैं कि सहायता मांगने वाली सोसाइटियां व्यवहार्य हैं और आवश्यक भी हैं।

हितधारकों द्वारा आगे दिए गए सुझाव

2.201 विधेयक के खंड 24 (प्रस्तावित धारा 63क(2)) के अनुसार, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा एक सोसाइटी का गठन करेगी, जिसमें ऐसे सदस्य शामिल होंगे, जो निधि का प्रशासन करेंगे और निधि के संबंध में अलग-अलग खाते और अन्य संगत अभिलेख ऐसे रूप में रखेंगे जो केन्द्र सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से विनिर्दिष्ट किए जाएं। इस संबंध में, एनएएफसीओबी ने कहा है कि समिति संरचना को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। इसने यह भी राय व्यक्त की है कि वास्तव में विधेयक से यह अनुभूति होनी चाहिए कि एमएससी सोसाइटी सरकार के स्वामित्व वाली नहीं है, बल्कि सरकार समर्थित है। एमएससीएस अधिनियम, 2002 में संशोधन का मुख्य उद्देश्य इसे लोकतांत्रिक, गतिशील, व्यवहार्य, स्वायत्त और सरकार समर्थित बनाना सुनिश्चित करना है।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियाँ

2.202 मंत्रालय ने आगे बताया कि इस निधि को प्रशासित करने वाली सोसाइटी को केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करेगी जो इस निधि का उचित उपयोग और इसके प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। इस प्रस्तावित संशोधन द्वारा रुग्ण सहकारी सोसाइटियों की मदद की जाएगी और बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मौजूदा अधिनियम में भी सहकारी शिक्षा निधि के लिए समिति की संरचना का विवरण मौजूद नहीं है। अधिनियम में समिति की संरचना विनिर्दिष्ट करना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे लचीलेपन में कमी आएगी। मौजूदा सहकारी शिक्षा निधि के मामले में भी निधि के उपयोग के तरीके और समिति की संरचना अधिनियम में नहीं बल्कि नियमों में विनिर्दिष्ट हैं।

2.203 समिति द्वारा संशोधन विधेयक के खंडवार उपबंधों की जांच के दौरान धारा 63क (2) में निधि के प्रबंधन के लिए पदेन सदस्यों सहित प्रस्तावित सोसाइटी की संरचना में विधेयक में ही प्रदान किए जाने के मुद्दे पर, सचिव सूचित किया कि वे कैग के साथ परामर्श कर रहे हैं।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.204 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 25

मूल अधिनियम में उपबंध

2.205 धारा 64: निधियों का विनिधान

कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अपनी निधियों को—

(क) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में से किसी में; या

(ख) किसी सहायक संस्था या किसी अन्य संस्था के शेयरों, प्रतिभूतियों या आस्तियों में; या

(ग) किसी अन्य बैंक में; या

(घ) ऐसे अन्य ढंग से जो उपविधियों में विहित किया जाए।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.206 मूल अधिनियम की धारा 64 में,—

(i) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, सरकारी निगम, सरकारी कंपनियां, प्राधिकरणों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों या सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा सुनिश्चित की गई किसी अन्य प्रतिभूतियों में से किसी में;”;

(ii) खंड (घ) में “किसी अन्य संस्था” शब्दों के पश्चात “बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रूप में कारबार की उसी श्रेणी में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (ड) और (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ड) किसी अन्य अधिसूचित या राष्ट्रीयकृत बैंक में।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति,—

(i) “अनुसूचित बैंक” का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (ड) में है ; और

(ii) “राष्ट्रीयकृत बैंक” से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित तत्स्थानी नए बैंक अभिप्रेत है; या

(च) किसी अन्य रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए ।”।

संशोधन के पीछे तर्क

2.207 “शासन का सुदृढ़ीकरण और पारदर्शिता

स्वतंत्रता-पूर्व युग की कुछ प्रतिभूतियां भारतीय ट्रस्ट अधिनियम में शामिल हैं जिन्हें प्रतिस्थापित किया जाना है।

मौजूदा उपबंधों में (घ) में ‘कोई अन्य संस्था’ और (च) में ‘उपनियमों के अनुसार’ पद को शामिल करने से यह अस्पष्ट हो जाता है और कुछ बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया है। ‘किसी अन्य बैंक’ के स्थान पर अनुसूचित या राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश करने से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का निवेश सुरक्षित हो जाएगा।

समिति द्वारा जांच

2.208 विधेयक में किए गए प्रस्तावों पर सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा ब्रीफिंग के दौरान, समिति ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाने वाले अन्य तरीके से धन के निवेश (धारा 64) को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त अवलोकन के संबंध में, सहकारिता मंत्रालय ने अपना लिखित उत्तर निम्नवत प्रस्तुत किया है:—

‘मौजूदा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 64(च) किसी बहुराज्यी सहकारी सोसाइटी को अपनी निधियों को “ऐसी अन्यन रीति, जो उपविधियों में विनिर्दिष्टक की जाएं” में निवेश या जमा करने का उपबंध करती है। इससे संदिग्धी संस्थानों में और कपटपूर्ण निवेश करने के आसार बने रहते हैं। संशोधन विधेयक में खंड 25 (धारा 64) का प्रस्ताव किया जा रहा है जो धारा 64(च) में “ऐसे अन्या तरीके जो उपविधियों में विनिर्दिष्टख किए जाएं” शब्दों के बदले “ऐसी अन्यर रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे” रखा जाएगा। इससे दुरुपयोग और कपटपूर्ण निवेश की रोकथाम होगी। चूंकि, निवेश के भावी उभरते तरीके/माध्यम समय-समय पर बदलते रह सकते हैं, इसलिए केन्द्रीय सरकार को सहकारी सोसाइटियों, के समग्र हितों को ध्यानन में रखते हुए, ऐसी निवेशों की रीति को निर्धारित करने के लिए लचीलेपन की आवश्योकता है।’

हितधारकों द्वारा सुझाव

2.209 एनसीयूआई जैसे हितधारक संगठनों ने कहा है कि यह एक प्रतिबंधात्मक खंड होने के नाते नए उद्यमों के विविधीकरण और प्रचार और व्यवसाय के विस्तार में बाधा उत्पन्न करेगा, जिसके परिणामस्वरूप, सहकारी सोसाइटी का आर्थिक विकास प्रभावित होगा। एनसीयूआई ने कहा है कि विनिर्दिष्ट इकाइयों में निवेश करने से ऐसी एमएससीएस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिन्हें भारत या विदेश में संयुक्त उद्यम/एसपीवी के संवर्धन/सृजन द्वारा अपनी निधियों का निवेश करना आवश्यक है। संयुक्त उद्यम/एसपीवी के लिए इस तरह के सक्षम प्रावधान रखने से सहकारी क्षेत्र और भारत की अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा। एमएससीएस को निर्यात/आयात क्षेत्र में फलने-फूलने के लिए संयुक्त उद्यम/एसपीवी की भी आवश्यकता हो सकती है। इसलिए ‘किसी अन्य संस्था’ शब्द को बरकरार रखा जा सकता है।

2.210 इसके अलावा, उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि उन्होंने धारा 64 (च) में प्रस्तावित उपबंध बहुराज्यश सहकारी सोसाइटी की स्वायत्ता और स्वतंत्र कामकाज को समाप्त कर देता है जो 97 वें संविधान (संशोधन) अधिनियम 2011 की भावना के अनुरूप नहीं है।

2.211 इसी तर्ज पर कृभको द्वारा इस बात का समर्थन किया गया है कि व्यवसाय के एक ही क्षेत्र में धन का निवेश बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को विविध क्षेत्रों में विस्तार करने में प्रतिबंधित करेगा, जबकि सरकार का प्रयास सहकारी क्षेत्र के बहुमुखी विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने सुझाव दिया है कि उन्हें अपने उपनियमों द्वारा अनुमत किसी भी व्यवसाय में निवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

2.212 धारा 64 (च) में संशोधन पर कृभको ने कहा कि निवेश या जमा पर निर्णय एक वाणिज्यिक निर्णय है और इस निर्णय को उसी क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा लिया जाना सबसे अच्छा है। ऐसे निवेशों का ढंग और तरीका एमएससीएस के उप-नियमों में निर्दिष्ट किया जाएगा, जो किसी भी मामले में केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित और पंजीकृत हैं। उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया है कि धारा 19 और धारा 64 में विरोधाभास है।

2.213 बैंकों के संबंध में, एनएफएससीओबी ने बताया कि जटिलताओं से बचने के लिए अनुसूचित सहकारी बैंक को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए। सहकारी सोसाइटियों की निधियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा नहीं किया जाना चाहिए। इन संसाधनों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में उनके घाटे के लिए पूँजी के रूप में लगाया जाता है, लेकिन सहकारी बैंकों के संचित नुकसान को दूर करने के लिए पुनर्पूर्जीकरण नहीं किया जाता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि ‘सरकारी कंपनियों, प्राधिकरणों, पीएसयू या सरकारी गारंटी द्वारा सुनिश्चित किसी भी अन्य प्रतिभूतियों’ को हटा दिया जाना चाहिए।

2.214 इसी तर्ज पर नावार्ड ने बताया कि बोर्ड ने निवेश नीति अनुमोदित की है जिसका प्रारूप अन्य बातों के साथ-साथ विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, तैयार किया जाना चाहिए। इसकी समय-समय पर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियाँ

2.215 हितधारकों के उपर्युक्त सुझावों को सहकारिता मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया था। अपने उत्तर में मंत्रालय ने बताया, "बहुराज्यों सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की मौजूदा धारा 64 (ख) में, कुछ अनावश्यक और अप्रासंगिक प्रतिभूतियां जैसे यूनाइटेड किंगडम की प्रतिभूतियां आदि हैं। उन्हें भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार, शामिल किया गया था, जो स्वतंत्रता-पूर्व युग का अधिनियम था। इसलिए, इस उपबंध को केंद्र/राज्य सरकार के सुरक्षित और जोखिम मुक्त निवेशों के साथ प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। संशोधित उपबंधों में इस आवश्यकता का ध्यान रखा गया है। धारा 64(घ) में 'अन्यख कोई संस्थातन' एक खुला पद है जिसका दुरुपयोग कतिपय सोसाइटियों द्वारा संदेहास्परद निवेश करने के लिए किया गया है। प्रस्तावित संशोधन ऐसे निवेशों के प्रकार की रोकथाम में मदद करेगा। किसी अन्य बैंक में निवेश के लिए धारा 64(ङ) के मौजूदा उपबंध, को सहकारी सोसाइटियों के निवेशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित या राष्ट्रीय कृत बैंक द्वारा अंतःस्थापित किया जा रहा है। मौजूदा धारा 64(च) किसी बहुराज्य च सहकारी समिति को अपनी निधियों को "ऐसे अन्य तरीके जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट किए जाएं" में निवेश या जमा करने का उपबंध करती है। इसे "ऐसी अन्य रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी" पद द्वारा अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। चूंकि, निवेश के भावी उभरते तरीके/माध्यम समय-समय पर बदलते रह सकते हैं, इसलिए केन्द्रीय सरकार को सहकारी सोसाइटियों के समग्र हितों को ध्याजन में रखते हुए ऐसे निवेशों की रीति को निर्धारित करने के लिए लचीला रखने की आवश्य कता है। अतः, बदलाव का प्रस्ता व सदस्योंन की जमाराशियों के बचाव व सुरक्षा के हितों के लिए किया गया है। बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों द्वारा किए जाने वाले व्यसवसायों का विवरण उपविधियों में है और सोसाइटियों लोकतांत्रिक रूप से अपनी उपविधियां बना कर अपने व्यावसायिक कार्य का निर्णय स्वोयता से ले सकती हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि धारा 19 के अनुसार इसे सहायक संस्था को सोसाइटी के घोषित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी होना चाहिए जो उपनियमों में हैं।"

2.216 एनएफएससीओबी की टिप्पणी पर मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ उत्तर दिया है कि मौजूदा धारा 64(क) पहले से ही सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक में निवेश की अनुमति देती है। एमएससीएस उपरोक्त में से किसी में भी निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.217 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 26

मूल अधिनियम में उपबंध

2.218 धारा 67: उधार लेने पर निर्बन्धन

(1) कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी बाह्य स्रोतों से निक्षेप, उधार और अनुदान केवल उसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन प्राप्त करेगी, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाए:

परंतु किसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त निक्षेपों और उधारों की कुल रकम अभिदत्त शेयर पूँजी और संचित आरक्षितियों की राशि के दस गुणा से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि अभिदत्त शेयर पूँजी और संचित आरक्षितियों की कुल राशि संगणित करते समय संचित हानियों को उसमें से घटा दिया जाएगा।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.219 “मूल अधिनियम की धारा 67 में, उपधारा (1) के पहले पंरतुक में “दस गुणा” शब्दों के स्थान पर ‘‘ऐसे गुणकों से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाए’’ शब्द रखे जाएंगे।”

संशोधन के पीछे तर्क

2.220 “निगरानी तंत्र का सुदृढ़ीकरण

इससे क्रृण लेने और जमा में लचीलापन सुनिश्चित होगा।”

समिति द्वारा जांच

हितधारकों द्वारा प्राप्त सुझाव

2.221 समिति के समक्ष उपस्थित हितधारकों ने उपर्युक्त उपबंध पर आपत्ति व्यक्त की है जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार हैं:—

कृष्णको-एमएससीएस का बोर्ड उनकी क्रेडिट योग्यता, उधार लेने की क्षमता और क्रेडिट रेटिंग के आधार पर उनकी अधिकतम उधार सीमा निर्धारित कर सकता है। इस मामले का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया जाता है कि भारत की प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जैसे क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल), इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईसीआरए), क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च (केयर), ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया (ओएनआईसीआरए) आदि धन जुटाने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों की क्रृण योग्यता का आकलन कर सकता है। एमएससीएस उन कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है जिनके पास इस तरह के प्रतिबंध नहीं हैं और उधार उनके बोर्ड और शेयरधारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अधिकतम उधार को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा केवल समान अवसर के लिए निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

एनसीयूआई -सोसाइटी की स्वायत्तता और स्वतंत्र कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए, एमएससीएस अधिनियम 2002 की धारा 67 (1) के अंतर्गत मौजूदा उपबंध को बनाए रखा जा सकता है। केवल बोर्ड या समाज को सोसाइटी के वित्तीय स्वास्थ्य, क्रृण योग्यता आदि के बारे में पता है और केंद्र सरकार द्वारा इसका निर्धारण करना एक चिंता का विषय है।

एनएएफएससीओबी— यह प्रस्ताव अस्पष्ट और विवेकाधीन है और सहकारी सोसाइटियों के हित में नहीं है। मौजूदा उपबंध जारी रहना चाहिए।

नाबाई ने हालांकि कहा है कि अधिक लाभ उठाने से बचने के लिए नियामक उपाय आवश्यक हैं।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियाँ

2.222 विद्यमान धारा 67 बहुराज्य सहकारी सोसाइटी पर उधार लेना सीमित करती है जिसमें किसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त जमाराशियों व क्रृणों की कुल राशि उसकी शेयर पूँजी व संचित आरक्षित के दस गुना से अधिक नहीं होगा। इस सीमा को ‘दस गुना’ से बदलकर ‘केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले ऐसे गुणक’ करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इससे दस गुना की मौजूदा निश्चित सीमा के स्थान पर आवश्यकता व आर्थिक परिदृश्य पर निर्भर विभिन्न सीमाओं का लचीलापन प्राप्त होगा। इससे वित्तीय अनुशासन लाने में मदद मिलेगी।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.223 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं.27

धारा 70: संपरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

मूल अधिनियम में प्रावधान

2.224 (2) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन में एक या अधिक संपरीक्षक नियुक्त करेगी जो उस अधिवेशन की समाप्ति से आगामी वार्षिक अधिवेशन की समाप्ति तक पद धारण करेगा/करेंगे और नियुक्ति के सात दिन के भीतर इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक संपरीक्षक को उसकी प्रज्ञापना देगी:

परंतु ऐसा/ऐसे संपरीक्षक केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के पैनल से या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा तैयार किए गए संपरीक्षकों के पैनल से, यदि कोई हैं, नियुक्त किया जाएगा/किए जाएंगे।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.225 “मूल अधिनियम की धारा 70 में,—

उपधारा क (2) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

‘परंतु ऐसे संपरीक्षक या संपरीक्षा करने वाली फर्म केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल से नियुक्त किए जाएंगे:

परंतु यह और कि पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक के निक्षेपों वाले बहुराज्य सहकारी बैंकों, बहुराज्य प्रत्यय सहकारी सोसाइटियों और पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक की आवर्त वाली बहुराज्य गैर-पत्रय सोसाइटियों की दशा में, संपरीक्षक केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी सोसाइटियों की संपरीक्षा के लिए अनुमोदित संपरीक्षकों के एक पैनल से नियुक्त किया जाएगा’;

संशोधन के पीछे तर्क

2.226 “यह संविधान के अनुच्छेद 243यड (3) के अनुरूप है।

शासन का सुदृढ़ीकरण और पारदर्शिता

संशोधित उपबंध संपरीक्षकों की नियुक्ति में निष्पक्षता लाएगा।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.227 समिति ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

मूल अधिनियम में उपबंध

2.228 (3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक संपरीक्षक, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से अपनी नियुक्ति की प्रज्ञापना प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर केन्द्रीय रजिस्ट्रार को लिखित में सूचित करेगा कि उसने नियुक्ति स्वीकार कर ली है या स्वीकार करने से इंकार कर दिया है।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.229 उपधारा (ख) (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(3क) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त संपरीक्षक ऐसे वित्तीय वर्ष जिससे ऐसे लेखे संबंधित है, के समाप्त होने की तारीख से छह मास के भीतर बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा”;

संशोधन के पीछे तर्क

2.230 “यह संविधान के अनुच्छेद 243यड (4) के अनुरूप है।”

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.231 समिति ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

मूल अधिनियम में उपबंध

2.232 (7) (क) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संपरीक्षक के पद में किसी आकस्मिक रिक्ति को भर सकेगी किंतु जब तक ऐसी रिक्ति बनी रहती है तब तक शेष संपरीक्षक, यदि कोई हो कार्य करेगा/करेगे:

परंतु जहां ऐसी रिक्ति किसी संपरीक्षक के त्यागपत्र से कारित हुई हो वहां वह रिक्ति बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा केवल साधारण अधिवेशन में ही भरी जाएगी।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.233 (ग) उपधारा (7) के खंड (क) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु जहां ऐसी रिक्ति किसी संपरीक्षक के त्याग पत्र से या मृत्यु के कारण कारित हुई है, वहां वह रिक्ति बोर्ड द्वारा, संपरीक्षकों के ऐसे पैनल से जिससे ऐसे संपरीक्षक की नियुक्ति की गई थी, भरी जाएगी।”;

संशोधन के पीछे तर्क

2.234 “संपरीक्षकों के पैनल से नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुरूप करने के लिए है।”

मूल अधिनियम में उपबंध

2.235 (9) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के संपरीक्षकों का पारिश्रमिक—

बोर्ड या केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किसी संपरीक्षक की दशा में, यथास्थिति, बोर्ड या केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा नियत किया जाएगा; और खंड (क) के अधीन रहते हुए, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा साधारण अधिवेशन में या ऐसी रीति से नियत किया जाएगा जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा साधारण अधिवेशन में अवधारित की जाए।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा संपरीक्षकों के व्ययों के संबंध में सदत्त कोई राशि “पारिश्रमिक” पद में सम्मिलित की गई समझी जाएगी।”

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.236 उपधारा (9) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के आधार पर, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी :—

“(10) राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी के लेखा की संपरीक्षा रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।”

संशोधन के पीछे तर्क

2.237 “यह संविधान के अनुच्छेद 243यड (5) के अनुरूप है।

शासन का सुदृढ़ीकरण और पारदर्शिता

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की अनुसूची-2 में सूचीबद्ध राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटियों में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए”

समिति द्वारा जांच

2.238 विधेयक के उपबंधों पर सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी देते हुए, समिति ने कहा कि लेखा परीक्षकों की नियुक्ति (धारा 70) के संबंध में, लेखा परीक्षकों के पैनल के लिए 500 करोड़ रुपये की निर्धारित सीमा को केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा

अनुमोदित किए जाने के लिए घटाकर 100 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए। इस संबंध में, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नानुसार कहा:—

“बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की मौजूदा धारा 70 सभी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों में संपरीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है जिसमें केन्द्रीय पंजीयक द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के पैनल से या बहुराज्य सहकारी समिति द्वारा तैयार किए गए संपरीक्षकों के पैनल, यदि कोई है, से ऐसे संपरीक्षक या संपरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।”

संविधान का अनुच्छेद 243य-ड (3) सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पैनल से बहुराज्य सहकारी समिति द्वारा संपरीक्षक की नियुक्ति का उपबंध करता है।

“अतः, संशोधन विधेयक के खंड 27 (धारा 70) के माध्यम से, सभी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के लिए केन्द्रीय पंजीयक द्वारा अनुमोदित पैनल से संपरीक्षकों के नियुक्त करने का उपबंध किया गया है। तथापि, बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के लिए संपरीक्षकों की दो अलग-अलग पैनल होंगे- 500 करोड़ रुपए से अधिक की जमाराशि/टर्नओवर वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों व सहकारी बैंकों के लिए एक पैनल और शेष बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के लिए अलग पैनल।”

हितधारकों से प्राप्त सुझाव

2.239 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में एनएफएससीओबी ने सुझाव दिया कि मौजूदा उपबंध जारी रहना चाहिए। लेखा परीक्षक की नियुक्ति बहुराज्य सहकारी समिति द्वारा तैयार लेखा परीक्षकों के पैनल, यदि कोई हो, से की जा सकती है। यूसीबी के लिए एनएफएससीओबी ने कहा कि सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए, अब कुछ कड़े दिशानिर्देशों पर आरबीआई के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है। इस प्रकार यह किसी भी कदाचार को समाप्त करता है। नतीजतन, बोर्ड को वैधानिक या अन्य लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि आरबीआई के अनुमोदन से व्यापार करने में आसानी हो सके। अन्य एमएससीएस के लिए, आवश्यक पाए जाने पर इसे बनाए रखा जा सकता है।

2.240 नाफकार्ड का मानना था कि सामान्य निकाय तीन साल के निरंतर कार्यकाल के बाद कम से कम एक साल के ब्रेक के बिना किसी लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म को सोसाइटी के लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त नहीं करेगी। उपर्युक्त खंड लगातार वर्षों की संख्या पर एक सीमा तय करने की सुविधा प्रदान करेगा जिसके लिए लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म नियुक्त की जा सकती है।

2.241 नाबार्ड ने समिति के समक्ष अपनी प्रस्तुति में यह विचार रखा कि एमएससी बैंकों को लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति लेना आवश्यक है, जिसका विधेयक में उपबंध नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि धारा 70 के अंतर्गत, एक अतिरिक्त उपबंध शामिल किया जा सकता है क्योंकि एमएससी बैंकों के रूप में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 30 लागू होगी।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियाँ

2.242 धारा 70 का प्रस्तावित उपबंध संविधान के अनुच्छेद 243य-ड (3) के अनुसार है जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा सरकार अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण से अनुमोदित पैनल द्वारा संपरीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान करता है। (ii) और (iii) संशोधन विधेयक का खंड 27 (धारा 70) सभी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के लिए केन्द्रीय पंजीयक द्वारा अनुमोदित पैनल से संपरीक्षकों की नियुक्ति विनिर्दिष्ट करता है। तथापि, बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के लिए दो पृथक पैनल होंगे- एक पैनल टर्नओवर वाली बहुराज्य सहकारी/करोड़ रुपए की जमाराशियों 500 बहुराज्य सहकारी समिति बैंकों व सोसाइटियों के लिए और दूसरा पैनल शेष बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के लिए। बड़ी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के लिए अलग पैनल का प्रस्ताव इसलिए किया जा रहा है कि उन्हें ज्यादा अनुभवी संपरीक्षकों और उनकी बड़ी टीम की आवश्यकता होगी।

2.243 मंत्रालय ने आगे बताया कि लेखा परीक्षा के मानक तैयार करते समय एनएफसीएआरडी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.244 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 28

नया 70क: अंतःस्थापन

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.245 “मूल अधिनियम की धारा 70 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

7170 क. बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों की दशा में,—

- (i) जिनकी वार्षिक आवर्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की गई रकम से अधिक है; या
- (ii) जिनका निक्षेप केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित की गई रकम से अधिक है,

समवर्ती संपरीक्षा केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के एक पैनल से नियुक्त किए गए किसी संपरीक्षक द्वारा की जाएगी।”

संशोधन के पीछे तर्क

2.246 “शासन का सुदृढीकरण और पारदर्शिता

बड़ी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के लिए समवर्ती लेखापरीक्षा से समिति में धोखाधड़ी या अनियमितताओं का जल्दी पता लग सकेगा और तदनुसार त्वरित सुधारात्मक उपाए किए जा सकेंगे।”

समिति द्वारा जांच

भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणियाँ

2.247 भारतीय रिजर्व बैंक ने उल्लेख किया है कि उन्होंने अपनी किसी भी विनियमित संस्था (आरई) में समवर्ती लेखा परीक्षा का कार्य करने के लिए लेखा परीक्षा फर्मों के किसी पैनल को निर्धारित/अनुमोदित नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक प्रतिक्रिया में निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणालियों पर मास्टर परिपत्र के आरबीआई के दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य है कि जमा या टर्नओवर मानदंडों के बावजूद सभी यूसीबी के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली अनिवार्य है, जबकि प्रारूप विधेयक में कहा गया है कि निर्धारित राशि से अधिक राशि वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता है। इसलिए, यूसीबी की समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली पर आरबीआई के दिशानिर्देशों और एमएससीएस विधेयक में प्रासंगिक खंड के बीच टकराव हो सकता है।

हितधारकों द्वारा सुझाव

2.248 एनएफएससीओबी ने समिति के समक्ष अपने लिखित व्यापार में बताया कि चूंकि सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दायरे में आते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लेखा परीक्षा, आरबीआईए, सांविधिक लेखा परीक्षा के व्यापक दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं, इसलिए इसे विशिष्ट उपबंध के माध्यम से छूट दी जानी चाहिए।

2.249 एनसीडीसी ने विचार रखा कि गंभीर त्रुटियों और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने और सदस्यों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी नियंत्रण के लिए मजबूत तंत्र स्थापित किया जाएगा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार बैंकिंग कंपनियों के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा के उपबंध भी प्रदान किए गए हैं।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियां

2.250 मंत्रालय ने समिति को अवगत कराया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, बैंककारी विनियमन अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करेगा ताकि इसके उपबंध संविधान के अनुरूप हों। सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) ने 19.01.2023 को आयोजित संयुक्त समिति की बैठक में भी यही कहा था। उन्होंने यह भी बताया कि प्रचलित प्रथा के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस भारतीय कंपनी अधिनियम या विभिन्न सहकारी सोसाइटी अधिनियमों जैसे विभिन्न विधियों के अंतर्गत निगमित इकाईयों को दिया जाता है। ऐसी सभी इकाईयां संबंधित अधिनियमों के द्वारा, जिनके अंतर्गत उन्हें निगमित किया जाता है और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत भी प्रशासित होती हैं। इस प्रकार, ऐसी सभी इकाईयों के लिए दोहरे विनियमन विद्यमान हैं। स्पष्टता लाने के लिए, संशोधन विधेयक धारा 120 ख (नए अंतःस्थापन) में प्रस्तावित करता है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के उपबंध निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित मामलों के संबंध में एक बहुराज्य सहकारी बैंक पर लागू होते हैं: परंतु यह है कि बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के मामले में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध भी लागू होंगे।

तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यूसीबी के समवर्ती लेखापरीक्षा पर व्यक्त की गई चिंता को मानदंड को विहित करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.251 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 29

मूल अधिनियम में उपबंध

2.252 धारा 73: संपरीक्षकों की शक्तियां और कर्तव्य

(5) जहां उपधारा (3) के खंड (क) और खंड (ख) या उपधारा (4) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी विषय पर उत्तर नकारात्मक है या किसी विश्लेषण के साथ है वहां संपरीक्षक की रिपोर्ट में उत्तर के लिए कारण कथित किए जाएंगे।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.253 “मूल अधिनियम की धारा 73 में, उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(6) यथास्थिति, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का वर्ग ऐसी संपरीक्षा और लेखांकन मानकों को अपनाएंगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं:

परंतु ऐसे संपरीक्षा और लेखांकन मानक अधिकथित किए जाने तक, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए संपरीक्षा मानकों को लेखा और संपरीक्षा मानक समझा जाएगा :

परंतु यह और कि बहुराज्य सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक द्वारा अधिकथित लेखा और संपरीक्षा मानकों को, यदि कोई हों, अपनाएंगे।”

संशोधन के पीछे तर्क

2.254 “यह संविधान के अनुच्छेद 243 य ड (2) के अनुरूप है।

“शासन का सुदृढ़ीकरण और पारदर्शिता

संपरीक्षण और लेखाकर्म के मानकों को विनिर्दिष्ट करने का कोई मौजूदा उपबंध नहीं है। इससे लेखाकर्म और संपरीक्षण में मानकीकरण और एकरूपता सुनिश्चित होगी और पारदर्शिता व वित्तीय अनुशासन आएगा।”

समिति द्वारा जांच

2.255 विधेयक के उपबंधों पर सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी देते हुए, समिति ने कहा कि लेखा परीक्षा मानक सभी एमएससीएस के लिए एक समान होने चाहिए (एमएससीएस बैंकों सहित) और हर तीन साल में लेखा परीक्षकों में बदलाव होना चाहिए। इस संबंध में सहकारिता मंत्रालय ने अपने पोस्ट ब्रीफिंग जवाब में निम्नानुसार कहा है:—

“मौजूदा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा संपरीक्षकों की शक्तियों और 73क कर्तव्यों से संबंधित है। मौजूदा उपबंध में संपरीक्षण के मानक विशिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं हैं।

संशोधन विधेयक में खंड (धारा 73(6)) के माध्यम से संपरीक्षण के मानकों को निर्धारित करने का प्रावधान शामिल किया जा रहा है जो संविधान के अनुच्छेद 243 य ड (2) के अनुरूप है। इससे लेखाकर्म और संपरीक्षण में मानकीकरण और सार्वभौमिकता सुनिश्चित होने के साथ-साथ पारदर्शिता व वित्तीय अनुशासन भी आएगी। सहकारी बैंकों, जिनसे आरबीआई द्वारा निर्धारित मानकों की अनुपालना करने की अपेक्षा होती है, को छोड़कर सभी बहुराज्यन सहकारी सोसाइटीयों के लिए संपरीक्षण के मानक एक समान होंगे। माननीय संसद सदस्य के सुझाव को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी अधिनियम, आदि के दिशानिर्देशों के अनुसार विमर्श करने की आवश्यकता होगी।”

हितधारकों द्वारा सुझाव

2.256 एनएएफसीयूबीने कहा कि आईसीएआई लेखा मानकों का नियामक और इसका निर्माता है। बिना किसी विकल्प के आधार पर आईसीएआई द्वारा निर्धारित मानकों को अनिवार्य माना जाना चाहिए। नतीजतन, यह उपबंध देश की आर्थिक जरूरतों के लिए एक स्पष्टरिखा पर है और इसे हटाने की आवश्यकता है।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियाँ

2.257 मौजूदा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 73 संपरीक्षकों की शक्तियां व कर्तव्यों से संबंधित हैं। मौजूदा अधिनियम में संपरीक्षण के मानकों का विशेष उल्लेख नहीं है। संशोधन विधेयक में धारा 73(6) द्वारा संपरीक्षण के मानकों को विनिर्दिष्ट करने का एक उपबंध लाया जा रहा है जो संविधान के अनुच्छेद 243 य ड (2) के अनुरूप है। इससे लेखाकर्म व संपरीक्षण में मानकीकरण व एकरूपता तथा पारदर्शिता व वित्तीय अनुशासन भी सुनिश्चित होगा। संपरीक्षण के मानक सभी बहुराज्यक सहकारी सोसाइटीयों के लिए एक समान होंगे सिवाए सहकारी बैंकों के लिए जिन्हें आरबीआई द्वारा स्थापित मानकों का अनुपालन करने की आवश्यकता होगी।

जबतक कि संपरीक्षण व लेखाकर्म के ऐसे मानक विनिर्दिष्ट नहीं होते हैं, तब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा के अधीन स्थापित इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा 3 विनिर्दिष्ट संपरीक्षण व लेखाकर्म मानकों को ही संपरीक्षण व लेखाकर्म के मानक माने जाएंगे।

चूंकि, सहकारी सोसाइटीयां सहकारी सिद्धांतों के द्वारा शासित होती हैं और जिन्हें कंपनियों के रूप में कार्य करना जरूरी नहीं होता है, यदि आवश्यकता पड़े तो संपरीक्षण के मानकों को तदनुरूप बनाया जा सकता है।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.258 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 30

मूल अधिनियम में उपबंध

2.259 धारा 78: केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा जांच

(1) केन्द्रीय रजिस्ट्रार, किसी ऐसी परिसंघीय सहकारी समिति जिससे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी सहबद्ध है या लेनदार है या बोर्ड के कम-से-कम एक-तिहाई सदस्यों या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या के कम-से-कम एक बटा पाँच सदस्यों के अनुरोध पर, जांच कर सकेगा या इस निमित्त लिखित आदेश द्वारा अपने द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के गठन, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति की जांच करने का निदेश देगा:

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई जांच तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संबद्ध बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना न दे दी गई हो।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.260 “मूल अधिनियम की धारा 78 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(1क) यदि केन्द्रीय रजिस्ट्रार का उसके पास उपलब्ध या सरकारी अभिकरण द्वारा उसे प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कारबार किसी कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, तो वह बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को उसके विरुद्ध किए गए अभिकथनों के बारे में जानकारी देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे आदेश में अन्तर्विष्ट सोसाइटी के बोर्ड के पृष्ठांकन के साथ मामलों के संबंध में लिखित में कोई जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगा:

परंतु यदि केन्द्रीय रजिस्ट्रार का सोसाइटी के स्पष्टीकरण से समाधान नहीं होता है तो वह स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत कार्यालय या अभिकरण के माध्यम से सोसाइटी के गठन, कार्यप्रणाली और वित्तीय स्थिति की जांच करेगा।

(1ख) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय रजिस्ट्रार, चाहे तो स्वप्रेरणा से या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या अभिकरण के माध्यम से, ऐसी अवधि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए में एक बार, किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के गठन, कार्यप्रणाली और वित्तीय स्थिति की जांच करेगा।“

संशोधन के पीछे तर्क

2.261 “निगरानी तंत्र का सुदृढ़ीकरण

सीआरसीएस की मौजूदा शक्ति अत्यंत सीमित है। यह उपबंध सीआरसीएस को सशक्त करेगा कि यदि उसे सूचना मिलती है कि बहुराज्य सहकारी समिति द्वारा कपटपूर्ण तरीके से या गैरकानूनी प्रयोजन के लिए व्यवसाय चलाया जा रहा है तो वह उसकी जांच कर सकेगा।”

हितधारकों से प्राप्त सुझावों का सार

2.262 उपर्युक्त के संबंध में, एनएएफएससीओबी ने प्रस्ताव दिया कि केन्द्रीय रजिस्ट्रार को सरकारी एजेंसी द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रार के पास अपना तंत्र होना चाहिए।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियाँ

2.263 प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय रजिस्ट्रार को न केवल सरकारी एजेंसी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बल्कि उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर भी कार्य करने का अधिकार देता है।

विधेयक की खंडवार जांच के दौरान कपटपूर्ण व्यवसाय आदि के बारे में केंद्रीय रजिस्ट्रार को जानकारी प्रस्तुत करने वाली सरकारी एजेंसी के प्रकार के संबंध में समिति के प्रश्न पर, सचिव, सहकारिता मंत्रालय ने उत्तर दिया कि यह सेवी हो सकता है; यह एसएफआईओ, आयकर, ईडी, इनमें से कोई भी हो सकता है। यह कोई भी एजेंसी हो सकती है।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.264 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं.31

नया: अंतःस्थापन 85क.

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.265 “मूल अधिनियम के अध्याय 9 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“अध्याय 9क शिकायतों का समाधान”

85क. (1) केंद्रीय सरकार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों के संबंध में, उनके निषेपों, सोसाइटी के कार्यकरण के साम्यापूर्ण फायदों या संबंधित सदस्य के वैयक्तिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी अन्य मुद्दे के संबंध में, उसके द्वारा की गई शिकायतों के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता वाले एक या अधिक सहकारी ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति ऐसी रीति में कर सकेगी, जो विहित की जाए।

(2) सहकारी ऑम्बुड्समैन, शिकायत की प्राप्ति पर, शिकायत की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर जांच और अधिनिर्णयन की प्रक्रिया पूर्ण करेगा और जांच के दौरान सोसाइटी को आवश्यक निदेश जारी कर सकेगा और सोसाइटी ऐसे निदेशों के जारी करने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

(3) ओम्बुड्समैन के किसी निदेश द्वारा व्यथित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी केन्द्रीय रजिस्ट्रार के समक्ष एक माह की अवधि के भीतर, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अपील फाइल कर सकेगी जो अपील का पैतालींस दिनों की अवधि के भीतर विनिश्चय करेगा और केन्द्रीय रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम और आवद्धकर होगा:

परंतु केन्द्रीय रजिस्ट्रार एक मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि सोसाइटी समय पर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण द्वारा निवारित हुई थी।

(4) ओम्बुड्समैन, सहकारी सोसाइटियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) सहकारी ओम्बुड्समैन, उपधारा (1) के अधीन जांच करते समय, निम्नलिखित के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं,—

(क) व्यक्तियों को समन करने और उनकी उपस्थिति का लागू कराने;

(ख) शपथ पर उनकी परीक्षा करने;

(ग) लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों के प्रकटीकरण और उन्हें प्रस्तुत करने ; और

(घ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।”

प्रस्तावित संशोधन के लिए तर्क

2.266 "शासन का सुदृढ़ीकरण और पारदर्शिता

यह नव प्रस्तावित पद सदस्यों की शिकायतों का समाधान करेगा और उनकी शिकायतों का समयबद्ध, त्वरित और निष्पक्ष समाधान के माध्यम से वित्तीय व प्रचलनात्मक अनुशासन लाएगा।

समिति द्वारा जांच

2.267 सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा विधेयक पर जानकारी देते हुए समिति ने ओम्बुड्समैन की नियुक्ति के तरीके और उसकी योग्यता के बारे में पूछताछ की। समिति ने आगे यह उल्लेख किया कि ओम्बुड्समैन (धारा 85) का नाम बदला जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। अपीलीय प्राधिकारी के लिए यह बाध्यकारी होनी चाहिए कि वह एक निर्धारित समयावधि के अंदर अपील का निपटारा करे। उपर्युक्त के संबंध में सहकारिता मंत्रालय ने निम्नानुसार कहा है:—

“मौजूदा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में ‘ऑम्बुड्समैन’ का कोई प्रावधान नहीं है।

संशोधन विधेयक में ‘सहकारी ऑम्बुड्समैन’ की नियुक्ति एक नई अंतर्विष्टि है। ‘सहकारी ऑम्बुड्समैन’ की परिभाषा खंड (2)(iii)(एफए) में है। केन्द्रीय सरकार, बहुराज्यस-सहकारी समिति के किसी सदस्यव-द्वारा की गई शिकायतों की जांच-पड़ताल के लिए एक या अधिक सहकारी ‘ऑम्बुड्समैन नियुक्त करेगी। सहकारी ऑम्बुड्समैन 3 महीने के भीतर जांच पड़ताल की प्रक्रिया समाप्त करके अपना निर्णय देगा। ऑम्बुड्समैन के निदेशों से असंतुष्ट कोई बहुराज्य सहकारी समिति एक महीने के भीतर केन्द्रीय पंजीयक के समक्ष अपना अपील दर्ज कर सकती है जो पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर उक्त अपील का निर्णय करेगा और केन्द्रीय पंजीयक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

निर्धारित किए जाने वाले नियमों में केन्द्रीय सरकार द्वारा ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति का का तरीका और योग्यताओं का विस्तृत विवरण दिया जाएगा।”

आरबीआई की टिप्पणियाँ/सुझाव

2.268 रिजर्व बैंक ने नवंबर 2021 में एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस), 2021 शुरू की थी। इसका उद्देश्य आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों को एक केंद्रीकृत प्रणाली के साथ अपनी शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाकर शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को आसान बनाना है। योजना का उद्देश्य आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित और लागत प्रभावी तरीके से समाधान करना है। आरबी-आईओएस 2021 के दायरे में, अन्य संस्थाओं के अलावा अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और गैर अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक शामिल हैं, जिनका जमा राशि आकार 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक है और जिसमें एमएससीबी भी शामिल हैं। वर्तमान में आरबी-आईओएस 2021 के तहत कवर नहीं की गई आरबीआई की विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों को भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कक्ष (सीपीईसी) द्वारा देखा जाएगा। इसके अलावा, आरबी-आई ओएएस 2021 आरबीआई के सभी आरई को चरणबद्ध तरीके से अपने दायरे में लेने का प्रयास करता है।

बहिष्करण सूची में सूचीबद्ध शिकायतों का छोड़कर, बैंकिंग में “सेवा में कमी” से संबंधित सभी शिकायतें, आरबी-आईओएस 2021 के तहत कवर की जाएंगी। शिकायतकर्ता आरबीआई के शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपनी शिकायतें 24 X 7 ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में एक केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) स्थापित किया गया हैं, जिसमें बहुभाषी सुविधा सहित एक संपर्क केंद्र के साथ-साथ आरबीआई (आरबीआई-लोकपाल और सीपीईसी के कार्यालयों के लिए) द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं के ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त होती हैं। आरबी-आईओएस 2021 ने आरबीआई लोकपाल तंत्र के अधिकार क्षेत्र को तटस्थ बनाकर ‘एक राष्ट्र एक लोकपाल दृष्टिकोण अपनाया है।

इस प्रकार, उन्होंने इस बात से अवगत कराया कि बीआर अधिनियम की धारा 35क के तहत तैयार किए गए बहु-राज्यीय सहकारी यूसीबी के ग्राहकों के लिए इसी उद्देश्य हेतु एकीकृत लोकपाल योजना और अन्य तंत्र भी इसी प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इसके अलावा, आरबीआई ने अपने सदस्य यूसीबी को सहायता प्रदान करने के लिए यूसीबी क्षेत्र के लिए यूओ के गठन हेतु जून, 2019 में नेफकॉब को विनियामक अनुमोदन प्रदान किया है।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियाँ

2.269 भारतीय रिजर्व बैंक के उपर्युक्त बयान के संबंध में, मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा पद्धति के अनुसार, आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस विभिन्न कानूनों जैसे कि भारतीय कंपनी अधिनियम अथवा विभिन्न सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के अंतर्गत शामिल इकाइयों को दिया जाता है। ऐसी सभी इकाइयाँ संबंधित अधिनियमों जिनके अंतर्गत उन्हें शामिल किया जाता है के साथ साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के द्वारा भी शासित होती हैं। इस प्रकार ऐसी सभी संस्थाओं के लिए दोहरे विनियमन मौजूद हैं। स्पष्टता लाने के लिए, संशोधन विधेयक धारा 120 ख (नया अंतःस्थापन) में प्रस्ताव करता है कि एमएससीएस अधिनियम 2002 के उपबंध निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित मामलों के संबंध में एक बहुराज्य सहकारी बैंक पर लागू होते हैं: बशर्ते कि बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के मामले में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध भी लागू होंगे।

तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यूसीबी के समवर्ती लेखा परीक्षा पर व्यक्त की गई चिंता को मानदंड निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

हितधारकों द्वारा सुझाव

2.270 एनसीडीसी ने माना है कि यह सहकारी समिति के सदस्यों के लिए एक आसान, सस्ता और प्रभावी विवाद निवारण तंत्र प्रदान करेगा और इसके कामकाज में दक्षता में सुधार करेगा और शिकायतों के निपटान में भी तेजी लाएगा। एनएफएससीओबी ने सिफारिश की है कि लोकपाल की नियुक्ति के मानदंड स्पष्ट रूप से बताए जाने चाहिए। सहकारी लोकपालों को सहकारी समितियों से, अधिमानतः राष्ट्रीय स्तर के एमएससीएस से सेवानिवृत्त को लिया जाना चाहिए ताकि मुद्दों की बेहतर समझ हो और बिना किसी पूर्वाग्रह के निर्णय दे।

2.271 यूसीबी के लिए नेफकॉब ने तर्क दिया कि चूंकि सहकारी बैंक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकिंग लोकपाल योजना के दायरे में आते हैं, इसलिए अलग से "सहकारी लोकपाल" की कोई आवश्यकता नहीं है। बैंकिंग लोकपाल के अलावा यूसीबीएस केंद्र सरकार/आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना का भी भाग है।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियाँ

2.272 धारा 85क के तहत लोकपाल की नियुक्ति के मानदंड नियमों में निर्धारित किए जाएंगे और सहकारी समितियों से व्यक्तियों का चयन करने के लिए एनएफएससीओबी के सुझाव को नियमों को तैयार करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

एनएफसीयूबी के सुझाव पर लोकपाल की नियुक्ति के लिए नियम तैयार करते समय और लोकपाल द्वारा शिकायतों को संबोधित करने के तरीके पर विचार किया जाएगा।

2.273 मंत्रालय ने आगे बताया कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का बोर्ड पहले से ही सदस्यों की शिकायत निवारण के लिए जिम्मेदार है। तथापि, असंतुष्ट सदस्यों को शिकायत निवारण के लिए पहले सोसाइटी से संपर्क करने और उसके बाद ही लोकपाल से संपर्क करने के सुझाव पर नियम बनाते समय विचार किया जाएगा।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.274 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 32

मूल अधिनियम में उपबंध

2.275 धारा 86: बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों का परिसमापन

(1) यदि धारा 70 के अधीन संपरीक्षा किए जाने या धारा 77 के अधीन या विशेष संपरीक्षा किए जाने या धारा 78 के अधीन कोई जांच किए जाने या धारा 79 के अधीन कोई निरीक्षण किए जाने के पश्चात्, केन्द्रीय रजिस्ट्रार की राय है कि सोसाइटी का

परिसमापन किया जाना चाहिए, तो वह सोसाइटी को अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा उसका परिसमापन किए जाने का निदेश दे सकेगा।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.276 मूल अधिनियम की धारा 86 में,—

(क) उपधारा (1) में “धारा 79” शब्द और अंकों के पश्चात्, “या धारा 108” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

संशोधन के लिए तर्क

2.277 “धारा 108, अर्थात् निरीक्षण संबंधी प्रक्रिया को भी परिसमापन आरंभ करने के आधार के रूप में शामिल किया गया है।”

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.278 समिति ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

मूल अधिनियम में उपबंध

2.279 (2) केन्द्रीय रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से और किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसका परिसमापन करने का निदेश देने वाला आदेश कर सकेगा—

(क) जहां सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की यह एक शर्त है कि सोसाइटी में कम से कम पचास सदस्य होने चाहिए और सदस्यों की संख्या घटकर पचास से कम हो गई है; या

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.280 (ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(क) यथास्थिति, सदस्यों की संख्या या सोसाइटियों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या, धारा 6 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट सदस्यों या सोसाइटियों या व्यक्तियों की संख्या से किसी भी समय कम हो गई है :

परंतु बहुराज्य सोसाइटी को सदस्यों या सोसाइटियों या व्यक्तियों की संख्या को अपेक्षित संख्या में प्रत्यावर्त्तन करने के लिए छह मास का समय दिया जाएगा ;”;

संशोधन के लिए तर्क

2.281 निगरानी तंत्र का सुदृढ़ीकरण

यह बहुराज्य सहकारी समितियों को अपेक्षित सदस्यों की संख्या बनाए रखने का अवसर देगा।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.282 समिति ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

मूल अधिनियम में उपबंध

2.283 (ख) जहां बहुराज्य सहकारी सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार इस निमित्त अनुज्ञात करे, अपना कार्य आरम्भ नहीं किया है।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.284 "(ii) खंड (ख) में "सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार कृत्य करना बन्द कर दिया है ;" शब्दों के स्थान पर, "सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार कृत्य करना बन्द कर दिया है ; या" शब्द रखे जाएँगे ;

(iii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) जहां केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकरण तथ्यों के दुर्व्यपदेशन, मिथ्या या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करके, तात्त्विक तथ्यों को छिपाकर या कपट जिसके परिणामस्वरूप सहकारिता की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा से प्राप्त किया गया था।"

संशोधन के लिए तर्क

2.285 "इससे ऐसी समितियों की छंटायी सुनिश्चित होगी जो गलत सूचना व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत होना चाहती है।"

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.286 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

मूल अधिनियम में उपबंध

2.287 (5) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी बैंक का परिसमापन, रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.288 "(iv) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बहुराज्य सहकारी बैंक के परिसमापन की दशा में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध भी लागू होंगे।"

संशोधन के लिए तर्क

2.289 "बहुराज्य सहकारी बैंकों की दशा में बैंककारी विनियमन अधिनियम का भी लागू होना सुनिश्चित करना।"

मूल अधिनियम में उपबंध

2.290 (6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय रजिस्ट्रार, किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का परिसमापन करने का आदेश करेगा यदि सोसाइटी साधारण अधिवेशन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करके उस सोसाइटी का परिसमापन करने का विनिश्चय करती है।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.291 "(v) उपधारा (6) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

परंतु परिसमापन के पूर्व, सोसाइटी से बकाया ऋण वाले संस्थागत उधारदाताओं से अनापत्ति, लिखित रूप में अपेक्षित होगी।

स्पष्टीकरण—इस परंतुक के प्रयोजन के लिए "संस्थागत उधारदाताओं" अभिव्यक्ति के अंतर्गत बैंक, बचत और ऋण संगम, न्यास कंपनी, बीमा कंपनी, भू-संपदा विनिधान न्यास, पेंशन निधि और वैसी ही चीजें भी हैं।"

संशोधन के लिए तर्क

2.292 " परिसमापन की दशा में यह सुनिश्चित करना कि संस्थागत ऋणदाताओं के हित सुरक्षित हों।"

आरबीआई की टिप्पणियाँ/विचार

2.293 समिति के समक्ष अपने निवेदन में आरबीआई ने उल्लेख किया कि नए प्रावधान में कहा गया है कि "इस धारा में निहित कोई बात के बावजूद, बहु-राज्य सहकारी बैंकों को बंद करने के मामले में बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधान भी लागू होंगे"। इस खंड के लिए आरबीआई के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यह जमाकर्ताओं के हित और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, डीआईसीजीसी कवरेज केवल पात्र सहकारी बैंकों के लिए उपलब्ध है जैसा कि डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 2(जीजी) में परिभाषित किया गया है। डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 2(जीजी) (i) में प्रावधान है कि बैंक के समापन आदेश, या समझौता या व्यवस्था या समामेलन या पुनर्निर्माण की योजना को मंजूरी देने वाला आदेश केवल रिज़र्व बैंक की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के साथ ही किया जा सकता है। इसलिए, यदि एमएससीएस अधिनियम, 2002 की प्रस्तावित धारा 86(5) को लागू किया जाता है, तो बहु-राज्य सहकारी बैंक डीआईसीजीसी अधिनियम के तहत प्रदान किए गए जमा बीमा कवर को खो सकते हैं।

समिति द्वारा जांच

2.294 खंड संख्या 32 के अनुसार, सहकारी बैंक को बंद करने के मामले में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध भी लागू होंगे। मूल अधिनियम के अनुसार रिज़र्व बैंक की लिखित मंजूरी के बिना किसी भी सहकारी बैंक को बंद नहीं किया जा सकता था। इस संबंध में, सहकारिता मंत्रालय से एमएससीएस बैंकों पर दोहरे विनियमों के लागू करने के औचित्य के बारे में पूछा गया था, जबकि उन्हें विशेष रूप से आरबीआई के अधिकार क्षेत्र के तहत शामिल किया जाना चाहिए।

सहकारिता मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नानुसार बताया:—

2.295 प्रचलित प्रथा के अनुसार, आरबीआई द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम या विभिन्न सहकारी समिति अधिनियमों जैसे विभिन्न कानूनों के अधीन पंजीकृत संस्थानों को बैंकिंग लाइसेंस दिए जाते हैं। ऐसे सभी संस्थान, उन संबंधित अधिनियमों जिनके तहत उनका निगमन हुआ है और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित होते हैं। स्पष्टता हेतु संशोधन विधेयक धारा 120ख (नई अंतर्विधि) का प्रस्ताव करती है जिसके द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के प्रावधान बहुराज्य सहकारी बैंक के निगमन, विनियमन और परिसमापन से संबंधित मामलों पर लागू होते हैं। तथापि, बहुराज्य सहकारी बैंकों की दशा में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधान भी लागू होंगे। यह संविधान के अनुच्छेद 243ZI और अनुच्छेद 243ZL के तीसरे परंतुक के अनुरूप है।

2.296 अंतरमंत्रालयी परामर्श की प्रक्रिया के दौरान विधायी सेवा विभाग ने दिनांक 04.10.2022 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि प्रस्तावित संशोधित विधेयक व्यापक रूप से बैंककारी विनियमन अधिनियम के अनुरूप है और इसीलिए वित्तीय सेवा विभाग संशोधन विधेयक से सहमत है और उसका समर्थन करता है इसके अलावा वित्तीय सेवा विभाग बैंककारी विनियमन अधिनियम को संविधान के अनुरूप करने के लिए इसमें यथोचित संशोधन करेगा सचिव (वित्तीय सेवा विभाग) ने भी दिनांक 19.01.2023 को आयोजित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में यही कथन किया था।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.297 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 33

मूल अधिनियम में उपबंध

2.298 धारा 94: विनिश्चयों, आदि का निष्पादन

धारा 39 या धारा 40 या धारा 83 या धारा 99 या धारा 101 के अधीन किया गया प्रत्येक विनिश्चय या आदेश, यदि क्रियान्वित न किया गया हो तो,—

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.299 "मूल अधिनियम की धारा 94 के आरंभिक पैरा में, "धारा 83 या" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "धारा 84 या" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।"

संशोधन के लिए तर्क

2.300 "मध्यस्थ के निर्णयों को कार्यान्वित कराने के लिए तंत्र स्थापित करना।"

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.301 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 34

मूल अधिनियम में उपबंध

धारा 98: सरकार को शोध्य राशियों की वसूली

2.302 (2) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को शोध्य और उपधारा के अधीन वसूलीय राशियाँ प्रथमतः सोसाइटी की संपत्ति से और द्वितीयतः सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों या मृत सदस्यों की संपदाओं से, उनके दायित्व की सीमा के अधीन रहते हुए वसूल की जा सकेंगी :

परंतु भूतपूर्व सदस्यों का और मृत सदस्यों की संपदा का दायित्व सभी दशाओं में धारा 37 के उपबंधों के अधीन होगा।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.303 मूल अधिनियम की धारा 98 में, उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3) केन्द्रीय रजिस्ट्रार को व्यतिक्रमी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के बैंक लेखाओं को कुर्की कर निम्नलिखित शोध्यों की वसूली करने की शक्ति भी होगी—

- (क) धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सहकारी शिक्षा निधि; या
- (ख) धारा 63क के अधीन गठित सहकारी पुनर्वास, पुनर्गठन और विकास निधि; और
- (ग) निर्वाचनों के संचालन के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा उपगत व्यय।"

संशोधन के लिए तर्क

2.304 सहकारी क्षेत्र द्वारा पूंजी जुटाना में सक्षमता

"सीईएफ और प्रस्तावित पुनर्वास निधि के बकाए की वसूली सुनिश्चित करने के लिए।"

समिति द्वारा जांच

आरबीआई की टिप्पणियां

2.305 धारा 98 में प्रस्तावित संशोधन सहकारी शिक्षा निधि, सहकारी सुदृढीकरण, पुनर्रचना और विकास निधि और सहकारी चुनाव प्राधिकरण द्वारा किए गए खर्चों की वसूली के लिए चूककर्ता एमएससीएस के बैंक खातों को कुर्की करने के लिए केंद्रीय रजिस्टर को शक्ति प्रदान करता है। यह उल्लेखनीय है कि मौजूदा प्रावधानों (धारा 94) के अनुसार, कुर्की द्वारा किसी भी राशि की वसूली के लिए या किसी आदेश को पारित करने के लिए इस अधिनियम के तहत किसी भी शक्ति का प्रयोग करते समय केंद्रीय रजिस्ट्रार को सिविल कोर्ट माना जाता है। प्रस्तावित संशोधन के साथ, उक्त निधियों में गैर-अंशदान को एक अपराध बना दिया गया है जिससे चूककर्ता एमएससीएस के बैंक खातों को कुर्की के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है। यह उन स्थितियों में विरोधात्मक हो सकता है, जैसे कि जहां जमाओं में कमी के प्रारंभिक संकेत हैं या जमा वीमा प्रीमियम में चूक हुई है या जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) हस्तांतरण नहीं हुआ है या आरबीआई द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि बहु-राज्य यूसीबी के बैंक खातों की कोई भी कुर्की भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियां

2.306 सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि में योगदान उन बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों द्वारा किया जाएगा, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों से लगातार लाभ में हैं, और यह ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के निवल लाभ के एक करोड़ रुपये या एक प्रतिशत, जो भी कम हो, तक सीमित होगा। सहकारी शिक्षा निधि (सीईएफ) में योगदान अधिनियम की विद्यमान धारा 63 में पहले से ही है, जिसमें निवल लाभ का एक प्रतिशत भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (एनसीयूआई) को क्रेडिट देने का उपबंध है। चूंकि उपर्युक्त निधियों में योगदान आयकर/जीएसटी की तरह एक सांविधिक अनुपालन है, इसलिए अनुपालन और वसूली किसी अन्य प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना की जानी चाहिए।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.307 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 35

नई: अंतःस्थापना 98क

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.308 मूल अधिनियम की धारा 98 के पश्चात, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“98क. केंद्रीय रजिस्ट्रार, किसी पक्षकार से आवेदन की प्राप्ति पर, धारा 94 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करेगा:

परंतु केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या परिसमापक द्वारा जारी किए गए वसूली प्रमाणपत्र के विरुद्ध कोई पुनर्विलोकन का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक आवेदक संबंधित सोसाइटी को वसूलीय शोध्य की रकम का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर देता है:

परंतु यह और कि पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि वह विनिश्चय या आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के पश्चात् किया जाता है:

परंतु यह भी कि केंद्रीय रजिस्ट्रार, ऐसा कोई आवेदन ऐसी अवधि के पश्चात् तब ग्रहण कर सकेगा, जब आवेदक उसका यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर आवेदन नहीं करने का पर्याप्त कारण था।”।

संशोधन के लिए तर्क

2.309 "बकाए के वसूली के निर्णय की समीक्षा के लिए अवसर प्रदान करना।"

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.310 समिति ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 36

मूल अधिनियम में उपबंध

2.311 धारा 103: राज्यों के पुनर्गठन के ठीक पूर्व कार्य कर रही सहकारी सोसाइटियां

(1) जहां राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) के भाग 2 के उपबंधों या राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति के आधार पर, कोई सहकारी सोसाइटी जिसके उद्देश्य, उस दिन के ठीक पूर्व, जिसको पुनर्गठन हुआ था, एक राज्य तक सीमित थे, उस दिन से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी बन जाती है, वहां वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी समझी जाएगी और ऐसी सोसाइटी की उपविधियां जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक वे परिवर्तित या विखंडित न कर दी जाएँ।

विशेषक में प्रस्तावित संशोधन

2.312 "मूल अधिनियम की धारा 103 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परंतु सभी उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा उक्त बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को उनके उद्देश्यों, सेवाओं और सदस्यों को ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संबंधित राज्यों तक परिरूद्ध करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों में विभाजित या पुनर्गठन करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की दशा में, ऐसी सोसाइटी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नहीं समझी जाएगी:

परंतु यह और कि पहले परंतुक में वर्णित से भिन्न समझी गई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगी और केंद्रीय रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी।"

संशोधन के लिए तर्क

2.313 "उत्तराधिकारी राज्यों को मानित बहुराज्य सहकारी समितियों को 3 वर्षों के अवधि के भीतर राज्य समितियों में पुनर्गठित करने का विकल्प।"

हितधारकों द्वारा सुझाव

2.314 नाबार्ड का मत था कि उत्तराधिकारी राज्यों में एमएससीएस के रूप में अच्छी कार्यरत सहकारी समितियों को जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए प्रावधान की आवश्यकता है। यह राज्यों के पुनर्गठन के बाद समाजों के अनुचित विभाजन से बचेगा।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.315 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 37: धारा 104 में संशोधन

मूल अधिनियम में उपबंध

2.316 धारा 104: अपराध और शास्तियां

(1) कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर कोई मिथ्या विवरणी देगा या मिथ्या जानकारी देगा या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए किसी समन, अध्येक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश की, कोई व्यक्ति जानबूझकर या किसी युक्तियुक्त हेतुक के बिना अवज्ञा करेगा या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उससे अपेक्षित कोई जानकारी जानबूझकर नहीं देगा, तो वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, और जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) कोई नियोजक, जो पर्यास कारण के बिना, किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को धारा 60 के अधीन उसके द्वारा कटौती की गई रकम का उस तारीख से, जिसको ऐसी कटौती की गई है, चौदह दिन की अवधि के भीतर संदाय करने में असफल रहेगा, ऐसी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती है, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(3) कोई अधिकारी या अभिरक्षक जो किसी ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से, जिसका वह अधिकारी या अभिरक्षक है, संबंधित बहियों, लेखाओं, दस्तावेजों, अभिलेखों, नकद प्रतिभूति और अन्य संपत्ति की अभिरक्षा, धारा 54 या धारा 70 या धारा 78 या धारा 79 या धारा 89 के अधीन हकदार किसी व्यक्ति को देने में जानबूझकर असफल रहेगा, जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और चालू रहने वाले भंग की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा भंग, ऐसे प्रथम भंग के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् चालू रहता है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(4) जो कोई धारा 38 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रतिनिधियों के निर्वाचन या बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन से पूर्व; उसके दौरान या पश्चात,—

.....
(ज) किसी व्यक्ति को किसी दान की प्रस्थापना करेगा या परितोषण की प्रस्थापना करने का वचन देगा, जिसका प्रत्यक्षतः या परोक्षतः यह उद्देश्य हो कि—

.....
(iii) किसी सदस्य के लिए इस बात के लिए कि वह मत देने या मत देने से विरत रहे, ईनाम के रूप में हो, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.317 मूल अधिनियम की धारा 104 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) “मिथ्या विवरणी देगा” शब्दों के पश्चात्, “या विवरणियां फाइल करने में असफल रहेगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) “दो हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) “दस हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, “पांच हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) में,—

(i) “धारा 89 के अधीन हकदार किसी व्यक्ति को” शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा 120 के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति को” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) “दो हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) “पांच हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(5) जहां कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी,—

(क) जिससे निरीक्षण, जांच या अन्वेषण के दौरान स्पष्टीकरण देना या कथन करना अपेक्षित है, संपत्ति, आस्तियों या सोसाइटी के क्रियाकलापों से संबंधित किसी दस्तावेज को नष्ट करती है, विद्विपित करती है या मिथ्या बनाती है या उसे छुपाती है अथवा उससे छेड़छाड़ करती है या अनाधिकृत रूप से उसे हटाती है अथवा उसे नष्ट करवाती है, विद्विपित करवाती है या मिथ्या बनवाती है या उसे छुपवाती है या उससे छेड़छाड़ करवाती है या अनाधिकृत रूप से उसे हटवाती है; या

(ख) धारा 64 अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियों के उपबंधों के उल्लंघन में कोई विनिधान करती है; या

(ग) सोसाइटी की आस्तियों और संपत्ति में अवैध अभिलाभ करती है; या

(घ) जमाकर्ता को अवैध हानि करती है,

तो बहुराज्य सोसाइटी का निदेशक बोर्ड या उत्तरदायी अधिकारी, ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होंगे, जो एक मास से कम नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम न होगा, किंतु एक लाख रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होंगे।”।

(6) जहां बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के निदेशक बोर्ड या अधिकारी ऐसी सोसाइटी से संबंधित मामलों का संव्यवहार करते समय कोई विधिविरुद्ध अभिलाभ प्राप्त करते हैं या व्यक्तिगत विधिविरुद्ध अभिलाभ के लिए सोसाइटी की किसी आस्ति का उपयोग करते हैं, ऐसे निदेशक या संबंधित अधिकारी ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होंगे, जो एक मास से कम नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक हो सकेगी या जुमाने से जो पांच हजार रुपए से कम न होगा, किंतु एक लाख रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होंगे और ऐसे विधिविरुद्ध अभिलाभ के आगम, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, उनसे वसूल और निष्क्रेपित किए जाएंगे।

संशोधन के लिए तर्क

निगरानी तंत्र का सुदृढ़ीकरण

2.318 इससे सदस्यों व बोर्ड के निदेशकों में अनुशासन सुनिश्चित होगा। जुर्माने की राशि को काफी पहले वर्ष 2002 में निर्धारित किया गया था जिसमें संशोधन की आवश्यकता थी। विवरणी जमा करवाने के लिए प्रावधान की आवश्यकता थी क्योंकि कई बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा समय पर विवरणी दाखिल नहीं किया जा रहा था। निर्वाचन कदाचार के लिए उपहारों, वायदे व पारितोषण की प्राप्ति को अपराध में शामिल किया गया। चुनाव लड़ने से 3 वर्ष की आयोग्यता निर्वाचन अपराध करने में निवारक होगी। गलत तरीके से समिति/निवेशकों को हानि पहुंचाने, गलत तरीके से व्यक्तिगत लाभ लेने, उपविधियों/अधिनियम के उल्लंघन में निवेश करने के लिए दंड के प्रावधान की आवश्यकता थी।

समिति द्वारा जांच

हितधारकों द्वारा सुझाव

2.319 एनसीडीसी ने उल्लेख किया है कि 20 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन जुर्माने में कोई संशोधन नहीं किया गया है। प्रस्तावित परिवर्तन मुद्रासंस्थिति के अनुरूप किया गया है। इससे समिति में समय पर रिटर्न दाखिल करने का अनुशासन आएगा।

2.320 खंडवार विचार-विमर्श बैठक के दौरान, समिति ने चिंता जताई कि जब हम गैर-अपराधीकरण की ओर बढ़ रहे हैं तो हम शास्ति के बजाय जुर्माना शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं। इस संबंध में सहकारिता मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया, "असत्य जानकारी प्रस्तुत करने" शब्दों के पश्चात् 'रिटर्न दाखिल करने में विफल' शब्द हैं। ये आपराधिक कृत्य हैं।"

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.321 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित परिवर्तनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं.38

मूल अधिनियम में उपबंध

2.322 धारा 105: अपराधों का संज्ञान

(1) किसी महानगर मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से नीचे का कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(2) धारा 104 के अधीन अपराधों के लिए कोई अभियोजन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य या केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में लिखित रूप में फाइल किए गए परिवाद पर के सिवाय, संस्थित नहीं किया जाएगा।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.323 मूल अधिनियम की धारा 105 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"105क. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त, न कि उसके अल्पीकरण में। वास्तव में, यह केवल बीआर अधिनियम के लिए ही नहीं बल्कि अन्य सभी अधिनियमों के लिए है।"

संशोधन के लिए तर्क

2.324 अन्य अधिनियमों के लागू होने की स्पष्टता। इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य अधिनियम के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में। वास्तव में, यह केवल बीआर अधिनियम के लिए ही नहीं बल्कि अन्य सभी अधिनियमों के लिए है।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.325 समिति ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं.39

मूल अधिनियम में उपबंध

2.326 धारा 106: उपविधियों आदि की प्रति का निरीक्षण के लिए खुला रहना

प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, नियमों और उसकी उपविधियों की एक प्रति और अपने सदस्यों की एक सूची भी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत पते पर, सभी युक्तियुक्त समयों पर, निःशुल्क निरीक्षण के लिए खुली रखेगी।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.327 मूल अधिनियम की धारा 106 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"106. (1) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी के सदस्यों को, सोसाइटी के मामलों और प्रबंधन से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए, एक सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति करेगी और ऐसी सूचना सोसाइटी द्वारा इसकी उपविधियों में विनिर्दिष्ट प्रकटन मानदंडों के अधीन आने वाली सूचना तक सीमित होगी।"

(2) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए, ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, आवेदन करेगा।

(3) सहकारी सूचना अधिकारी, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या तो सूचना प्रदान करेगा या अस्वीकार करने के कारण विनिर्दिष्ट करते हुए उसे अस्वीकार करेगा।

(4) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य जिसका आवेदन नामंजूर कर दिया गया सहकारी ऑम्बुड्समैन को ऐसी नामंजूरी की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम और बाध्य होगा।

106क. प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी मुख्य कार्यपालक, नियमों और इसकी उपविधियों की एक प्रति तथा इसके सदस्यों की एक सूची, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत पते पर सभी सुसंगत समयों पर, किसी प्रभार के बिना, निरीक्षण के लिए रखेगी।”।

प्रस्तावित संशोधन के लिए तर्क

2.328 यह संविधान के अनुच्छेद 243ZO(1) के अनुरूप है।

शासन का सुदृढ़ीकरण और पारदर्शिता

सदस्यों को सूचना प्रदान करने के लिए और अधिक व्यवस्थित प्रणाली की आवश्यकता है। इससे शासन में पारदर्शिता आएगी व जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

समिति द्वारा जांच

हितधारकों द्वारा सुझाव

2.329 एनएफएससीओबी के अनुसार प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी एक सहकारी सूचना अधिकारी (सीआईओ) को नियुक्त करेगी या एमएससीएस में किसी अधिकारी को सीआईओ के रूप में कार्य करने के लिए नियमित करेगी ताकि सोसाइटी के सदस्यों को सोसाइटी के मामलों और प्रबंधन से संबंधित जानकारी प्रदान की जा सके। यह सूचना, सोसायटी द्वारा अपने उप-नियमों में निर्दिष्ट प्रकटीकरण मानदंडों के अंतर्गत आने वाली सूचना तक ही सीमित होगी।

2.330 एनएफएससीयूबी ने सुझाव दिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एमएससीएस पर लागू नहीं होगा, बर्ते कि भारत सरकार या उस मामले के लिए किसी सरकारी कंपनी/संगठन या किसी राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषण या निवेश के माध्यम से समाज में उनकी इक्किटी हिस्सेदारी या पर्याप्त हित न हो।

2.331 एनसीडीसी के अनुसार, इससे समिति के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। सूचना तक पहुंच सहकारी समितियों को जवाबदेह बनाने में मदद करेगी एवं अन्य उद्देश्यों में भी सहायक होगी जो समिति के सदस्यों के समग्र हितों की सेवा करेगी।

मंत्रालय की टिप्पणियाँ

2.332 (क) और (ख) बहुराज्य सहकारी में ‘सूचना अधिकारी’ की नियुक्ति का प्रस्तावित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243ZO(1) के अनुरूप है। यह बहुराज्य सहकारी समितियों पर निर्भर करता है कि वे ऐसे सूचना अधिकारी को अपने मौजूदा कर्मियों में से नामित करें या फिर इस प्रयोजन के लिए किसी पृथक अधिकारी को नियुक्त करें। इसके अलावा सूचना अधिकारी, समिति के सदस्यों को समिति के कारोबार और प्रबंधन से संबंधित सूचना प्रदान करेगा और ऐसी सूचनाएं समिति द्वारा अपनी उपविधियों में विनिर्दिष्ट प्रकटन मानकों के अधीन सीमित होंगी। इससे सहकारी समितियों के कार्यकरण में पारदर्शिता आएगी।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.333 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित परिवर्तनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 40

मूल अधिनियम में उपबंध

2.334 धारा 108: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की लेखा बहियों इत्यादि का निरीक्षण

(1) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की लेखा बहियां और अन्य बहियां तथा कागज-पत्र निम्नलिखित द्वारा निरीक्षण के लिए कारबार के समय के दौरान खुले रहेंगे—

(i) केन्द्रीय रजिस्ट्रार, या

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.335 मूल अधिनियम की धारा 108 की उपधारा (1) के खंड(i) में, “केन्द्रीय रजिस्ट्रार” शब्दों के पश्चात्, “या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति जो सहायक आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो या समतुल्य” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

प्रस्तावित संशोधन के लिए तर्क

2.336 सीआरसीएस कार्यालय द्वारा निरीक्षण को सुगम बनाना

समिति द्वारा जांच

2.337 विधेयक की खंडवार जांच के दौरान, हितधारकों पर उस विधि के अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बारे में एक अवलोकन किया गया था और यह सुझाव दिया गया था कि किसी चरण पर अनुपालन की लागत का भुगतान किया जाए। इस संबंध में, सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया—

“यह समवर्ती लेखापरीक्षा के मामले में होना चाहिए। जहां समवर्ती लेखापरीक्षा की आवश्यकता है, मान लीजिए कि भारत सरकार 10,000 करोड़ रुपये या 5,000 करोड़ रुपये का कर लगाती है, 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी को समवर्ती लेखापरीक्षा करानी होगी। समवर्ती लेखापरीक्षा महंगी है। अतः उसे देखकर प्रयास करना होगा। लेकिन हमें समवर्ती लेखापरीक्षा के मामले में अनुपालन की लागत का पता लगाना होगा”

नोडल मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि सदस्यों को खाता बहियों और एमएससीएस की अन्य पुस्तकों के निरीक्षण से बाहर करने का सुझाव स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि यह पारदर्शिता के सिद्धांत के विरुद्ध है।

हितधारकों द्वारा सुझाव

2.338 एनएएफएससीओबी ने सुझाव दिया कि “केन्द्रीय रजिस्ट्रार या उसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर राज्य स्तर पर) इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति जो (नहीं सहायक आयुक्त के रैंक से नीचे का न हो या समतुल्य शब्द अंतःस्थापित किये जाएंगे

2.239 इस संबंध में, नेफकब ने कहा है कि यह उपबंध, सूचना साझा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित गोपनीयता और प्रकटीकरण मानदंडों का पालन करने में विफल रहता है। हालांकि किसी भी विनियामक प्राधिकरण के साथ किसी भी जानकारी को साझा करने पर कोई आपत्ति नहीं है, सदस्यों के लिए यह खुला प्रावधान आरबीआई गोपनीयता और प्रकटीकरण मानदंडों का उल्लंघन करता है। इसमें धारा 108 की उपधारा 1 के खंड (iii) को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है, “बशर्ते बैंक का कोई भी सदस्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी रजिस्टर या रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकेगा, जब तक कि वह अपने स्वयं के व्यावसायिक लेनदेन से संबंधित है।”

2.340 केन्द्रीय भंडार ने सुझाव दिया है कि मूल अधिनियम यानी एमएससीएस अधिनियम, 2002 में धारा 108 (1) (iii) एक सोसाइटी के सदस्यों को वैसी ही शक्ति प्रदान करती है जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार / केंद्र सरकार में निहित हैं और मौजूदा सोसाइटियों में कई सदस्य निहित स्वार्थ के लिए इस उपबंध का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रत्येक सदस्य को, यदि वे मांग करें तो, सोसाइटी की प्रत्येक पुस्तकों और कागजों का निरीक्षण करने या उनकी प्रति रखने के लिए पहुँच प्रदान करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यदि

केंद्रीय रजिस्ट्रार या उनके/सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास समान शक्तियाँ निहित हैं, तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जब कोई सदस्य किसी भी समाज में रखी गई प्रत्येक पुस्तक और कागज की प्रति का निरीक्षण करना या उसकी प्रति माँगना चाहे और यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो बड़े कार्यशील/कार्यात्मक सोसाइटी एकाएक रुक जाएगी।

अतः, मूल अधिनियम से धारा 108(1)(iii)को हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई सदस्य ऐसी जानकारी के आधार पर केंद्रीय रजिस्ट्रार को कोई विश्वसनीय जानकारी/शिकायत प्रस्तुत करता है, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी से संबंधित जानकारी मांग सकता है और एमएससीएस अधिनियम, 2002 के अनुसार उपयुक्त और आवश्यक कार्रवाईकर सकता है।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियां

2.341 एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 108 के मौजूदा उपबंध के अनुसार, प्रत्येक बहुराज्य सहकारी समिति की खाताबही और अन्य पुस्तकों और दस्तावेज़ केंद्रीय रजिस्ट्रार, या सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा व्यावसायिक घंटों के दौरान निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे, जिसे इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अथवा बहुराज्य सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है। प्रस्तावित संशोधन में केन्द्रीय रजिस्ट्रार के अतिरिक्त उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति जो सहायक आयुक्त के पद से नीचे का न हो, को निरीक्षण के लिये अधिकृत किया गया है।

2.342 जुर्माना शब्द के संबंध में समिति की आशंकाओं को देखते हुए, सहकारिता मंत्रालय ने निम्नवत् उत्तर दिया:—

“यह समवर्ती लेखापरीक्षा के मामले में होना चाहिए। जहां समवर्ती लेखापरीक्षा की आवश्यकता है, मान लीजिए कि भारत सरकार 10,000 करोड़ रुपये या 5,000 करोड़ रुपये का कर लगाती है, 5,000 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाली बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी को समवर्ती लेखापरीक्षा करानी होगी। समवर्ती लेखापरीक्षा महंगी है। अतः उसे देखकर प्रयास करना होगा। लेकिन हमें समवर्ती लेखापरीक्षा के मामले में अनुपालन की लागत का पता लगाना होगा”

2.343 नोडल मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि सदस्यों को खाता बहियों और एमएससीएस की अन्य पुस्तकों के निरीक्षण से बाहर करने का सुझाव स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि यह पारदर्शिता के सिद्धांत के विरुद्ध है।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.344 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं.41

मूल अधिनियम में उपबंध

2.345 धारा 116: दूसरी अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति

- (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी के रूप में अभिहित किया जाना चाहिए या दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी का उक्त अनुसूची से लोप किया जाना चाहिए, तो वह अधिसूचना द्वारा उक्त अनुसूची को संशोधित कर सकेगी जिससे कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को उस अनुसूची में सम्मिलित किया जा सके या ऐसी राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी को अलग किया जा सके और तदुपरि उक्त अनुसूची को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई प्रत्येक अधिसूचना की प्रतिलिपि उसके बनाए जाने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.346 मूल अधिनियम की धारा 116 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“अनुसूचियों को संशोधन करने की शक्ति”;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(1क) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची और तीसरी अनुसूची को संशोधित कर सकती है और तत्पश्चात् ऐसी अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी: परंतु पहली अनुसूची की दशा में, ऐसी अधिसूचना का उपयोग केवल सूची में सहकारी सिद्धांतों को जोड़ने के लिए किया जाएगा”;

(iii) उपधारा (2) में, “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, “उपधारा (1) और उपधारा (1क)” शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

प्रस्तावित संशोधन के लिए तर्क

2.347 प्रस्तावित तीसरी अनुसूची को संशोधित करने और प्रथम अनुसूची में सहकारी सिद्धांतों को जोड़ने की शक्ति शामिल करने के लिए।

समिति द्वारा जांच

हितधारकों द्वारा सुझाव

2.348 विधेयक के खंड 41 के अनुसार, जिसका उद्देश्य विधेयक की धारा 116 में संशोधन करना है, यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची और तीसरी अनुसूची में संशोधन कर सकती है और उसके बाद ऐसी अनुसूचियों को तदनुसार संशोधित माना जाएगा। इस संबंध में एनएएफसीयूबी ने कहा है कि इस अनुसूची में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा स्वीकृत सहकारी सिद्धांत शामिल हैं और भारत सरकार इसके लिए एक हस्ताक्षरकर्ता है। अतः, इसमें संशोधन करने के लिए सरकार को अधिकार देने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरे, एक प्रावधान किया जाना चाहिए कि सभी पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समितियां डिफॉल्ट रूप से अपने क्षेत्रीय महासंघों और राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/संघ राज्यक्षेत्र सहकारी संघों की सदस्य मानी जाएंगी। एनएएफसीयूबी ने यह भी सुझाव दिया है कि तीसरी अनुसूची में इनसाँल्वेंसी एक्ट, सरफेसी एक्ट, इनकम टैक्स और नेगोशिएशन इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट जैसे अधिनियमों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियां

2.349 (i) सहकारी सिद्धांतों वाली पहली अनुसूची में संशोधन के संबंध में धारा 116 में प्रस्तावित संशोधन केवल सहकारी सिद्धांतों की सूची में जोड़ने तक सीमित है और कोई भी अतिरिक्त परिवर्धन राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(ii) नेफकव के सुझाव के संबंध में कि यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि सभी पंजीकृत बहुराज्यीय सहकारी समितियों को डिफॉल्ट रूप से उनके क्षेत्रीय संघों और राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/संघ राज्य क्षेत्र सहकारी संघों का सदस्य माना जाएगा। यह 'स्वैच्छिक सदस्यता' के सहकारी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। राष्ट्रीय महासंघों को सभी सहकारी समितियों में अपनी सदस्यता बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रयास करने चाहिए।

(iii) तीसरी अनुसूची में शामिल अधिनियमों की सूची पर्याप्त है।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.350 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 42

मूल अधिनियम में उपबंध

2.351 धारा 120: विवरणियों को दाखिल किया जाना

प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी प्रत्येक वर्ष लेखावर्ष के बंद होने के छह मास के भीतर केन्द्रीय रजिस्ट्रार के समक्ष निम्नलिखित विवरणियाँ फाइल करेगी—

- (क) क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट;
- (ख) लेखाओं के संपरीक्षित विवरण;
- (च) अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई जानकारी।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.352 मूल अधिनियम की धारा में 120,—

- (i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—
“(क) क्रियाकलापों, जिनमें बोर्ड के ऐसे विनिश्चय जिन पर सर्वसम्मति नहीं बनी थी, के ब्यौरे भी हैं, की वार्षिक रिपोर्ट ;”;
- (ii) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—
“(च) ऐसे कर्मचारियों के बारे में प्रकटन जो बोर्ड के सदस्यों के नातेदार हैं ;
- (छ) निदेशक मंडल द्वारा किसी संबंधित पक्षकार संव्यवहारों की घोषणा;
- (ज) इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना...”

प्रस्तावित संशोधन के लिए तर्क

2.353 अभिशासन का सुदृढीकरण और पारदर्शिता

इससे पारदर्शिता में वृद्धि होगी और विवादास्पद निर्णयों पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी।

- (च) भर्तियों में भाई-भतीजावाद की रोकथाम व पारदर्शिता बढ़ाने के लिए।
- (छ) बहुराज्य सहकारी समिति के बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए।

समिति द्वारा जांच

2.354 सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों पर संक्षिप्त जानकारी के दौरान, समिति ने सहकारिता मंत्रालय से बोर्ड के उन निर्णयों पर टिप्पणियों देने को कहा, जो एकमत से नहीं लिए गए हैं और यह भी पूछा कि क्या वार्षिक प्रतिवेदन में असहमत सदस्यों के नाम शामिल होंगे (धारा 120)। क्या कोई विमत टिप्पण होगा? सर्वसम्मति से निर्णय क्यों नहीं लिया गया? उस पर एक संक्षिप्त टिप्पण अनिवार्य किया जा सकता है। इस संबंध में, सहकारिता मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में निम्नानुसार बताया:—

"समिति के प्रश्न के उत्तर में नोडल मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा बहुराज्यत सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में सर्वसम्मति से नहीं लिए गए बोर्ड के निर्णयों के संबंध में जानकारी प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 120(i)(क) का प्रतिस्थापन, जिसे संशोधन विधेयक में प्रस्तावित किया जा रहा है, के माध्यम से सभी सहकारी समितियों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी और उसके साथ उन सभी निर्णयों का पूर्ण विवरण देना होगा जिन्हें सर्वसम्मति से नहीं लिया गया था। इससे बहुराज्य सहकारी समितियों के कार्यकरण की पारदर्शिता में सुधार होगा।"

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.355 समिति ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 43: नई धाराओं 120क और 120ख का अन्तःस्थापन

मूल अधिनियम में उपबंध

2.356 नई अन्तःस्थापना

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.357 मूल अधिनियम की धारा 120 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"120क. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार, ऐसी तिथि से, जो विहित की जाए, यह अपेक्षा कर सकेगी कि—

(क) ऐसे आवेदन, तुलनपत्र, विवरणी या कोई अन्य विशिष्टियाँ और दस्तावेज, जिनका इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल या परिदत्त किया जाना अपेक्षित हो, इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल अधिप्रमाणित किए जाएंगे;

(ख) ऐसा दस्तावेज, सूचना, कोई संसूचना या सूचना, जिसका इस अधिनियम के अधीन तामील या परिदान किया जाना अपेक्षित हो, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में तामील या परिदत्त और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित किया जाएगा;

(ग) ऐसे आवेदन, तुलनपत्र, विवरणियाँ, रजिस्टर, उपविधियाँ या इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल की गई कोई अन्य विशिष्टियाँ या दस्तावेज और विवरणियाँ केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में रखी जाएंगी, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत या अधिप्रमाणित की जाएंगी;

(घ) इलैक्ट्रानिक रूप में रखी गई उपविधियों, तुलनपत्रों, विवरणियों या किन्हीं अन्य विशिष्टियों अथवा दस्तावेजों का, जो इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन निरीक्षण के लिए अन्यथा उपलब्ध हों, ऐसा निरीक्षण किसी व्यक्ति द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप के माध्यम से किया जा सकेगा; और

(ङ) इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय ऐसी फीसों, प्रभारों या अन्य राशियों को इलैक्ट्रानिक रूप के माध्यम से संदत्त किया जाएगा।

(2) केंद्रीय रजिस्ट्रार,—

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा;

(ख) उपविधियों के संशोधन को रजिस्टर करेगा;

(ग) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में परिवर्तन को रजिस्टर करेगा;

(घ) किसी दस्तावेज को रजिस्टर करेगा;

(ङ) किसी प्रमाणपत्र को जारी करेगा;

(च) सूचना को जारी करेगा; और

(छ) ऐसी संसूचना को प्राप्त करेगा,

जिनका इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या जारी या अभिलिखित या प्राप्त किया जाना अपेक्षित हो अथवा इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन कर्तव्यों का पालन या कृत्यों का निर्वहन या शक्तियों का प्रयोग करेगा अथवा ऐसा कोई कार्य करेगा, जिसको केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप में या ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पालन या निर्वहन या प्रयोग किया जाना या करना इस अधिनियम के अधीन निर्देशित किया गया है।

120ख. इस अधिनियम के उपबंध, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के निगमन, विनियमन और परिसमापन से संबंधित विषयों के संबंध में लागू होंगे:

परंतु बैंककारी कारबार करने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की दशा में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध भी लागू होंगे।

प्रस्तावित संशोधन के लिए तर्क

2.358 120क: व्यापार में सुगमता

यह एक नया जोड़ा गया उपबंध है। पेपरलेस/डिजिटल कार्यालय समय की मांग है। अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्ट/दस्तावेजों की ई-फाइलिंग सधम की जाएगी। इससे व्यापार में सुगमता को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त सीआरसीएस कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

120ख: संविधान के अनुच्छेद 243यज और 243यठ (तीसरा परंतुक) के अनुरूप और यह बीआर अधिनियम और वर्तमान अधिनियम के बीच अधिकार क्षेत्र के मुद्दों को स्पष्ट करेगा।

समिति द्वारा जांच

आरबीआई की टिप्पणियां

2.359 भारतीय रिजर्व बैंक ने धारा 120ख के अन्तःस्थापन के संबंध में कहा है कि धारा 120ख के इस प्रस्तावित अन्तःस्थापन से आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों की विधिक प्रवर्तनीयता के बारे में अनिश्चितता हो सकती है। रिजर्व बैंक का मत है कि "भी" शब्द बैंकिंग व्यवसाय करने वाली बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए बीआर अधिनियम के प्रावधानों को प्रधानता प्रदान नहीं करेगा। आरबीआई का यह मत है कि प्रस्तावित संशोधित धारा 120ख केवल एक सीमित सीमा तक चिंताओं को संबोधित करती है और इसे बीआर अधिनियम को प्रधानता देने और बहु-राज्य सहकारी बैंकों के मामले में आरबीआई को अधिभावी अधिकार प्रदान करने वाले अभेद्य खंड के रूप में नहीं माना जा सकता है। यद्यपि बीआर अधिनियम की धारा 56 में गैर-वाधा खंड के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि इन दोनों अधिनियमों के उपबंधों के बीच किसी भी तरह के विरोध के मामले में, बीआर अधिनियम के प्रावधान प्रबल होंगे, एमएससीएस अधिनियम पर बीआर अधिनियम की प्रधानता के संबंध में व्यक्त प्रावधान के अभाव में इस संबंध में आगे कानूनी मुद्दों की संभावना उत्पन्न होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः, संभावित विरोध से बचने के लिए प्रस्तावित धारा 120बी के परंतुक से 'भी' शब्द को हटाने या सुझाव के अनुसार धारा 2 में व्यापक प्रावधान जोड़ने का सुझाव दिया गया है।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियां

2.360 प्रस्तावित उपबंध 120ख संविधान के अनुच्छेद 243यज और अनुच्छेद 243यठ के तीसरे परंतुक के अनुरूप है। प्रचलित पद्धति के अनुसार, आरबीआई द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम या विभिन्न सहकारी समिति अधिनियमों जैसे विभिन्न कानूनों के अधीन पंजीकृत संस्थानों को बैंकिंग लाइसेंस दिए जाते हैं। ऐसे सभी संस्थान, उन संबंधित अधिनियमों जिनके तहत उनका निगमन

हुआ है और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अभिशासित होते हैं। इस प्रकार के सभी निकायों हेतु द्विविनियामक प्रणाली है। स्पष्टता हेतु संशोधन, विधेयक धारा 120ख (नया अंतःस्थापन) का प्रस्ताव करता है जिसके द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के प्रावधान बहुराज्य सहकारी बैंक के निगमन, विनियमन और परिसमापन से संबंधित मामलों पर लागू होते हैं। तथापि, बहुराज्य सहकारी बैंकों की दशा में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधान भी लागू होंगे।

2.361 यह पूछे जाने पर कि विधि के अंतर्गत आरबीआई के दिशानिर्देशों की प्रवर्तनीयता के बारे में संभावित विवाद और अस्पष्टता से वे कैसे बचना चाहते हैं, सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि अंतर-मंत्रालयी परामर्श की प्रक्रिया के दौरान, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने अपने दिनांक 04.10.2022 के पत्र द्वारा सूचित किया कि प्रस्तावित संशोधित विधेयक काफी हद तक बीआर अधिनियम के साथ संरेखित है और इस प्रकार, डीएफएस संशोधन विधेयक से सहमत है और इसका समर्थन करता है और डीएफएस, बीआर अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करेगा ताकि इसके प्रावधान संविधान के अनुरूप हों। 19.01.2023 को आयोजित जेपीसी की बैठक में सचिव (डीएफएस) ने भी यही बताया था।

2.362 सहकारी बैंकों के दोहरे विनियमन के संबंध में उठाए गए प्रश्न के उत्तर में नोडल मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि—

"प्रचलित पद्धति के अनुसार, आरबीआई द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम या विभिन्न सहकारी समिति अधिनियमों जैसे विभिन्न कानूनों के अधीन पंजीकृत संस्थानों को बैंकिंग लाइसेंस दिए जाते हैं। ऐसे सभी संस्थान, उन संबंधित अधिनियमों जिनके तहत उनका निगमन हुआ है और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित होते हैं। इस प्रकार के सभी निकायों हेतु द्विविनियामक प्रणाली है। स्पष्टता हेतु संशोधन, विधेयक धारा 120ख (नया अंतःस्थापन) का प्रस्ताव करता है जिसके द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के प्रावधान बहुराज्य सहकारी बैंक के निगमन, विनियमन और परिसमापन से संबंधित मामलों पर लागू होते हैं। तथापि, बहुराज्य सहकारी बैंकों की दशा में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधान भी लागू होंगे।"

हितधारकों द्वारा सुझाव

2.363 एनसीडीसी: यह विवरणिका दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाएगा और डिजिटल गवर्नेंस के साथ-साथ कागज रहित कार्यालयों को बढ़ावा देगा।

2.364 नावार्ड के अनुसार, यह विभिन्न राज्यों में राज्य सहकारी समिति अधिनियम और बीआर अधिनियम (एएसीएस), 1949 के उपबंधों के अनुरूप है।

धारा 120(1) - उन सभी स्थानों पर जहां प्रमाणीकरण की आवश्यकता है, 'डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा' जोड़ा जा सकता है।

धारा 120(ज) - वर्ष के दौरान पाई गई धोखाधड़ी/अनियमितताओं का विवरण जोड़ा जा सकता है।

2.365 विधेयक की खंडवार जांच के दौरान समिति ने नोट किया कि बैंकिंग का कारोबार करने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के मामले में बैंकिंग विनियमन अधिनियम के उपबंध भी लागू होंगे। अतः, एक टिप्पणी थी कि जो भी उच्च मानक हैं, उन्हें लागू किया जाना चाहिए। इस संबंध में, सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने कहा कि आरबीआई के नियम इस अधिनियम के नियमों के अतिरिक्त होंगे। लेकिन उदाहरण के लिए आरबीआई, बीआर अधिनियम के माध्यम से किसी भी बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी की मूल संरचना साथ को नहीं बदल सकता है। अतः दोनों को साथ-साथ लागू करना होगा। ये दोनों पंक्तियां संविधान में विशेष रूप से लिखे गए अनुच्छेद 243यज्ञ और 243यठ से आई हैं।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.366 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 44

मूल अधिनियम में उपबंध

2.367 धारा 121: कुछ अधिनियमों का लागू न होना

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) के उपबंध बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों पर लागू नहीं होंगे।
- (2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां या रजिस्ट्रीकृत समझी गई बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969(1969 का 54) में परिभाषित एकाधिकारिक तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार में भाग नहीं लेंगी।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.368 मूल अधिनियम की धारा 121 में,—

- (i) उपधारा (1) में, “कंपनी अधिनियम, 1956 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969”शब्दों और अंकों के स्थान पर, “कंपनी अधिनियम, 2013 और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002”शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ii) उपधारा (2) में, “एकाधिकार तथा अवरोधन व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में परिभाषित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार” शब्दों और अंकों के पश्चात्, “प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में निर्दिष्ट एकाधिकार क्रियाकलाप” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

प्रस्तावित संशोधन के लिए तर्क

2.369 संबंधित अधिनियमों में संशोधन के कारण परिवर्तन

समिति द्वारा जांच

हितधारकों से प्राप्त सुझाव

2.370 एनएएफसीयूबी ने सुझाव दिया है कि तीसरी अनुसूची में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, आयकर अधिनियम और परक्राम्य लिखित अधिनियम जैसे अधिनियमों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियां

2.371.दिवाला अधिनियम, सरफेसी अधिनियम, आयकर और परक्राम्य लिखित अधिनियम को तीसरी अनुसूची में सम्मिलित करने के संबंध में नेफकब के सुझाव के महेनजर, सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि तीसरी अनुसूची में शामिल अधिनियमों की सूची पर्याप्त है।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

3.372 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 45

मूल अधिनियम में उपबंध

2.373 धारा 123: विनिर्दिष्ट बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का अधिक्रमण

यदि केन्द्रीय सरकार की राय में, किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का बोर्ड इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में बार-बार व्यतिक्रम कर रहा है या उनकी उपेक्षा करता है या उसने कोई ऐसा कार्य किया है जो सोसाइटी के या उसके सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है या उसने धारा के अधीन उसे दिए गए किन्हीं नियमों का अनुपालन 122 करने में लोप किया है या असफल रहा है या बोर्ड के गठन में अथवा कृत्य करने में गत्यावरोध आ गया है, तो केन्द्रीय सरकार, बोर्ड को अपने आक्षेपों का, यदि कोई हों, कथन करने का अवसर देने के पश्चात् और आक्षेपों पर, यदि प्राप्त हों, विचार करने पर लिखित आदेश द्वारा, बोर्ड को हटा सकेगी और एक या अधिक प्रशासकों को, जिनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे सोसाइटी के सदस्य हों, सोसाइटी के कार्यकलापों का छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए और जो केन्द्रीय सरकार के विवेक पर समय-समय पर बढ़ाई जा सकेगी किन्तु जिसकी कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु सहकारी बैंक के मामले में, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर “दो वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों।

स्पष्टीकरण- धारा 122 और 123 के प्रयोजनार्थ, “विनिर्दिष्ट, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी” से ऐसी कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसमें समादत्त शेयर पूँजी या कुल शेयरों के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित हों।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.374 मूल अधिनियम की धारा 123 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) “या उसने कोई ऐसा कार्य किया है” से आरंभ होने वाले और “जिसकी कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी”, से अंत होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“या उसने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके अंतर्गत कपट, मिथ्या दुर्विनियोग और उसी तरह के कार्य शामिल हैं जो सोसाइटी के या उसके सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है या उसने धारा 122 के अधीन लोक हित में उसे दिए गए किन्हीं निदेशों का अनुपालन करने में लोप किया है या असफल रहा है या बोर्ड के गठन या कृत्य करने में गत्यावरोध आ गया है या सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्वाचनों को संचालित करने में असफल रहा है तो केन्द्रीय सरकार, बोर्ड को अपने आक्षेपों का, यदि कोई हो, कथन करने का अवसर देने के पश्चात् और आक्षेपों पर, यदि प्राप्त हो, विचार करने पर लिखित आदेश द्वारा, बोर्ड को अतिथित या निलंबित कर सकेगी और ऐसे एक या अधिक प्रशासकों को नियुक्त कर सकेगी जिनको ऐसी अवधि के लिए जो छह मास से अनधिक होगी, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंधन करने के लिए सोसाइटी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है”;

(ख) विद्यमान परन्तु के पश्चात् निम्नलिखित परन्तु अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि निर्वाचन कराने में असफलता के आधार पर किसी अधिक्रमण या निलंबन के लिए विनिश्चय करते समय, ऐसी कार्रवाई केवल तभी की जाएगी यदि बोर्ड ने धारा 45 के उपबंधों के अनुसार सीमा के भीतर सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को निर्वाचन कराने की अध्येत्यक्षा न दी हो या आवश्यक सहायता प्रदान न की हो।”

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा। अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—धारा 122 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट बहुराज्य सहकारी सोसाइटी” पद से कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसमें सरकारी शेयरधारिता है या सरकार द्वारा लिया गया कोई ऋण या दी गई वित्तीय सहायता अथवा कोई प्रतिभूति है।’।

प्रस्तावित संशोधन के पीछे तर्क

2.375 यह संविधान के अनुच्छेद 243ZL(1) के अनुरूप है।

निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाना

धोखाधड़ी और गवन के मामले में कार्रवाई की भी आवश्यकता है। 97वां संविधान संशोधन अधिक्रमण व निलंबन, दोनों का प्रावधान करता है और निर्वाचन कराने में विफलता को अतिरिक्त आधार के रूप में शामिल करता है। विनिर्दिष्ट सोसाइटियों की परिभाषा को संविधान के अनुच्छेद 243 यठ के अनुरूप बनाया जाएगा।

समिति द्वारा जांच

2.376 सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों पर संक्षिप्त जानकारी के दौरान, समिति ने पाया कि निर्दिष्ट सोसाइटी की परिभाषा में बदलाव पर चर्चा की आवश्यकता है। इस संबंध में, सहकारिता मंत्रालय ने अपने संक्षिप्त जानकारी पश्चात् उत्तरों में निम्नवत् बताया है: -

"वर्तमान बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में धारा 122 धारा व धारा 123 के तहत दी गई व्याख्या में यह कथित है कि प्रयोजन के लिए "विनिर्दिष्ट बहुराज्य सहकारी समिति" से अभिप्रेत ऐसी बहुराज्य सहकारी समिति है जिसकी चुकता शेयर पूँजी या कुल शेयरों के न्यूनतम इक्यावन प्रतिशत, का धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया हो। धारा 123 के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों के अवक्रमण पर कार्रवाई केवल 122 के तहत तथा धारा 122 विनिर्दिष्ट बहुराज्य सहकारी समितियों की दशा में की जा सकती है जिनकी संख्या बहुत कम है। 'विनिर्दिष्ट समितियों' की परिभाषा को बदलने की आवश्यकता है ताकि इसे संविधान के अनुच्छेद 243यठ(1) के अनुरूप किया जा सके। तदनुसार, संशोधन विधेयक में विनिर्दिष्ट समिति की परिभाषा को विस्तारित करके उन बहुराज्य सहकारी समितियों को शामिल किया गया है जिनमें सरकारी शेयरधारिता क्रृष्ण या वित्तीय सहायता या सरकार की कोई गारंटी है।"

हितधारकों द्वारा सुझाव

2.377 एनएएफएससीओबी ने कहा है कि विनिर्दिष्ट बहु-राज्य सहकारी समिति के बोर्ड के अधिक्रमण (1) निर्दिष्ट बहु-राज्य सहकारी समिति के बोर्ड के अधिक्रमण में केंद्रीय रजिस्ट्रार और भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका और जिम्मेदारी का उल्लेख किया जा सकता है।

2.378 भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) ने अपने प्रस्तुतिकरण में कहा है कि विनिर्दिष्ट बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के अधिक्रमण के मानदंड धारा 123 उप धारा (1), (2), (3), (4), (5) और (6) में भली भांति परिभाषित हैं। विनिर्दिष्ट एमएससीएस की व्याख्या/परिभाषा में परिवर्तन अधिक्रमण का मानदंड नहीं हो सकता। जहां सरकार किसी भी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में बहुसंख्यक हिस्सेदारी रखती है वहां वह धारा 123 उपधारा (1), (2), (3), (4), (5) और (6) के अंतर्गत निर्धारित उचित कार्रवाई कर सकती है। मौजूदा स्पष्टीकरण जारी रह सकता है क्योंकि संशोधित स्पष्टीकरण सरकार को दूरगामी शक्ति देता है जो सहकारी सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त सोसाइटी के लिए इसकी योजना के लिए सरकार द्वारा दी गई गारंटी को सोसाइटी के लिए गारंटी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। सरकार को केवल एक सूत्रधार की भूमिका निभानी चाहिए। अतः, मौजूदा एमएससीएस अधिनियम 2002 की धारा 123 के अंतर्गत स्पष्टीकरण को बनाए रखा जा सकता है।

2.379 कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको) ने अपने निवेदन में निम्नानुसार कहा है:—

"सात सिद्धांत हैं जो सहकारी समितियों के समग्र कामकाज को नियंत्रित करते हैं। चौथा सहकारी सिद्धांत नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:—

स्वायत्तता और स्वतंत्रता : सोसाइटियां स्वायत्त, स्वयं सहायता संगठन हैं जो उनके सदस्यों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यदि सहकारी सोसाइटियां सरकार सहित अन्य संगठनों के साथ समझौता करती हैं या बाहरी स्रोतों से पूँजी जुटाती हैं, तो वे

ऐसा उन शर्तों पर करती हैं जो सदस्यों द्वारा उनके लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी स्वायत्तता के रखरखाव को सुनिश्चित करती हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 43ख में भी सहकारी समितियों के स्वायत्त कामकाज और स्वतंत्रता की परिकल्पना की गई है और निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:—

"43ख. राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।"

अनुच्छेद 243 यठ (1) (भारत के संविधान का अध्याय IXख) के 97वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल दूसरे परंतुक में, सहकारी समितियों के स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण पर भी जोर दिया गया है।

इसके अनुरूप, 97 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया अनुच्छेद 243 यठझ (भारत के संविधान का भाग IXख), जिसमें कहा गया है कि "इस भाग के उपबंधों के अधीन, एक राज्य का विधानमंडल स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य आर्थिक भागीदारी और स्वायत्त कामकाज के सिद्धांतों के आधार पर सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और परिसमापन के संबंध में प्रावधान कर सकता है।"

इसके अलावा, अनुच्छेद 243 यठ (1) के दूसरे परंतुक में निम्नानुसार है:

"बशर्ते आगे कि ऐसी किसी भी सहकारी समिति के बोर्ड को अधिक्रमित नहीं किया जाएगा या निलंबन के तहत नहीं रखा जाएगा जहां कोई सरकारी शेयरधारिता या क्रृष्ण या वित्तीय सहायता या सरकार द्वारा कोई गारंटी नहीं है"

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि 97वें संविधान संशोधन में यह परिकल्पना की गई है कि यदि सरकार के पास कोई शेयरधारिता या क्रृष्ण या वित्तीय सहायता या कोई गारंटी नहीं दी गई है, तो वह ऐसी सहकारी समितियों के बोर्ड का अधिक्रमण नहीं करेगी। यहां तक कि ऐसे मामले में जहां सरकार के पास कोई शेयरधारिता है या कोई क्रृष्ण या वित्तीय सहायता या कोई गारंटी प्रदान की गई है, भौतिकता की अवधारणा को देखा जाना चाहिए। यही कारण था कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002 के मामले में धारा 123 के स्पष्टीकरण भाग में शेयरधारिता की मात्रा निर्धारित की गई थी जो इस प्रकार है:—

"स्पष्टीकरण:— धारा 122 व धारा 123 के प्रयोजन के लिए "विनिर्दिष्ट बहुराज्य सहकारी समिति" से अभिप्रेत ऐसी बहुराज्य सहकारी समिति है जिसकी चुकता शेयर पूँजी या कुल शेयरों के न्यूनतम इक्यावन प्रतिशत, का धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया हो।"

संविधान के अनुच्छेद 43ख, 97वें संवैधानिक संशोधन और स्वायत्तता और स्वतंत्रता के चौथे सहकारी सिद्धांत की भावना को ध्यान में रखते हुए, हम प्रस्तुत करते हैं कि एमएससीएस अधिनियम 2002 की धारा 122 और 123 की व्याख्या में विनिर्दिष्ट सरकारी शेयरधारिता की मात्रा को बरकरार रखा जा सकता है।

2.380 नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) ने अपने उत्तर में बताया कि, "प्रस्ताव में संशोधन करते समय सरकार की शेयरधारिता या क्रृष्ण या वित्तीय सहायता या सरकार द्वारा किसी भी गारंटी जैसे विभिन्न तत्वों के उद्देश्य को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है।"

2.381 एनसीडीसी ने अपनी टिप्पणियों में कहा है कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243यठ (97वें संशोधन, 2012 द्वारा जोड़े गए भाग IXख में निहित) को प्रभावी करने के लिए शामिल किया गया है। विनिर्दिष्ट सहकारी समितियों की परिभाषा में यह परिवर्तन किसी भी धोखाधड़ी या गंभीर कदाचार पाए जाने की स्थिति में बेहतर निगरानी और नियंत्रण में मदद करेगा।

2.382 मूल अधिनियम की धारा 123 में संशोधन का प्रस्ताव करने वाले विधेयक के खंड 45 के संबंध में, एनएफएससीओबी ने कहा है कि एक विनिर्दिष्ट बहु राज्य सहकारी समिति के बोर्ड के अधिक्रमण में केंद्रीय रजिस्ट्रार और आरबीआई की भूमिका और कर्तव्य को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

सहकारिता मंत्रालय की टिप्पणियां

2.383 विनिर्दिष्ट समितियों की प्रस्तावित परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 243यठ(1) (दूसरा परंतुक) के अनुरूप है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 243यन के अनुसार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के ऐसे प्रावधान जो संविधान के भाग IX ख के अनुरूप नहीं हैं, वे उनके संशोधन अथवा निरसन अथवा संविधान अधिनियम, (संशोधन) (सतानंवा) 2011 के प्रवृत्त होने के एक वर्ष की अवधि की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक लागू रहेंगे। मौजूदा प्रस्ताव बहुराज्य सहकारी समितियों के शासन को सशक्त करेगा और धोखाधड़ी व कुप्रबंधन का भी निवारण करेगा।

2.384 धारा 123 में प्रस्तावित संशोधन संविधान के अनुच्छेद 243ZL(1) के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, स्पष्टता लाने के लिए संशोधन विधेयक, धारा 120 ख (नया अंतःस्थापन) का प्रस्ताव करता है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के प्रावधान, बहुराज्य सहकारी बैंक पर उनके निगमन, विनियमन और परिसमापन से संबंधित मामलों पर लागू होंगे, बशर्ते कि बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली बहुराज्य सहकारी समिति पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधान भी लागू होंगे।

नोडल मंत्रालय की प्रतिक्रिया:

- सहकारी समितियां जिनके उद्देश्य एक राज्य में सीमित होते हैं, उनका शासन संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के अनुसार राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अधीन होता है।
- संविधान के अनुच्छेद 243यज(घ) के अनुसार बहुराज्य सहकारी समिति एक ऐसी सहकारी समिति है जिसका उद्देश्य किसी एक राज्य में सीमित नहीं है। बहुराज्य सहकारी समिति संविधान की संघ सूची-। की प्रविष्टि 44 और भाग IXख के अनुसार अभिशासित होती है।
- बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 को संघ सूची की उक्त प्रविष्टि के अंतर्गत संसद द्वारा पारित किया गया था।
- मौजूदा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 को निरस्त कर अधिनियमित किया गया था।

2.385 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों पर अनुच्छेद 243यठ और अनुच्छेद 43ख में वर्णित सहकारिता सिद्धांत के उल्लंघन के संबंध में प्रश्न के उत्तर में, नोडल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संशोधन विधेयक मौजूदा कानून में खामियों को दूर करने के लिए और निम्नलिखित सहकारी सिद्धांतों के अनुसार एमएससीएस में अभिशासन को सुदृढ़ करने के लिए, 97वें संवैधानिक संशोधन के अनुरूप है यथा:-

- (क) स्वैच्छिक और खुली सदस्यता;
- (ख) लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण;
- (ग) सदस्यों की आर्थिक प्रतिभागिता;
- (घ) स्वायत्ता और स्वतंत्रता;
- (ङ) शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना;
- (च) सहकारी समितियों के बीच सहयोग; और
- (छ) समुदाय के प्रति लगाव।

यह सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप बहुराज्य सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक कार्यकरण व सदस्यों की प्रतिभागिता को सशक्त करेगा। यह बहुराज्य सहकारी समितियों के कार्यकरण में पाई गई कदाचार की घटनाओं का समाधान करने में मदद करेगा और पारदर्शिता, सक्रिय सदस्यता, सुगम व्यापार, आदि संबंधी मामलों में सुधार भी लाएगा।

जहां तक एमएससीएस की कार्यात्मक स्वायत्तता को छीनने की बात है, मंत्रालय ने बताया कि संशोधन विधेयक स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य-आर्थिक प्रतिभागिता और स्वायत्त कार्यकरण के सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप है। इसके फलस्वरूप अधिक सक्रिय सदस्य प्रतिभागिता, पारदर्शी और जवाबदेह शासन तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित होंगे। इससे बहुराज्य सहकारी समितियों की कार्यशील स्वायत्ता प्रभावित नहीं होती है। यह सुगम व्यापार संबंधी सुधारों को लाकर बहुराज्य सहकारी समितियों के कार्यकरण को सुगम बनाएगा।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.386 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड सं. 46

मूल अधिनियम में उपबंध

2.387 धारा 124: नियम बनाने की शक्ति

विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (2), इन नियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

धारा 6 के अधीन किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्ररूप, उस आवेदन में दी जाने वाली विशिष्टियाँ और उसे देने में अनुपालन की जाने वाली शर्तें, तथा ऐसे आवेदनों के विषय में प्रक्रिया;

इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.388 मूल अधिनियम की धारा 124 में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(कक) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांत;”;

(ii) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(जक) वह रीति जिसमें बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का बोर्ड धारा 43 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निर्वाचन संचालित करने के लिए सूचना, दस्तावेज, कार्मिक, निधियाँ या व्ययों या सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा चाही गई कोई अन्य सहायता प्रदान की जाएगी ;”;

(iii) खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“(ट) धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की संरचना;

(टक) धारा 45 की उपधारा (3) के खंड (iii) के अधीन प्राधिकरण के सदस्य की नियुक्ति के लिए अहंता और अनुभव; (टख) धारा 45 उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्राधिकरण के सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें;

(टग) धारा 45क के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य;

(टघ) धारा 45ख की उपधारा (2) के अधीन जांच की प्रक्रिया;

(टड) धारा 45ज की उपधारा (1) के अधीन इसकी बैठकों में कारबार के संबंध में प्राधिकरण द्वारा पालन किए जाने वाला समय, स्थान और प्रक्रिया;

(टच) धारा 45झ के खंड (3) के अधीन प्राधिकरण के अन्य कृत्य;

(टछ) धारा 45ज की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन की रीति;

(टज) धारा 45 (ज) की उपधारा (6) के अधीन प्राधिकरण द्वारा निर्वाचन करने के लिए व्यय वहन करने की रीति;

(टझ) धारा 45ट की उपधारा (1) और उपधारा (3) के खंड (क) अधीन रिटर्निंग आफिसरों और पर्यवेक्षकों द्वारा कृत्य के निर्वहन की रीति;

(टज) धारा 45ट की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन पर्यवेक्षकों के अन्य कृत्य;" ;

(iv) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(डक) धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (ड) के परंतुक के अधीन कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रक्रिया” ;

(v) खंड (ण) का लोप किया जाएगा ;

(vi) खंड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(थक) धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निधि के अनुरक्षण की रीति”;

(vii) खंड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(धक) धारा 85क की उपधारा (1) के अधीन सहकारी ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति की ओर ऐसे ऑम्बुड्समैन को शिकायत प्रस्तुत करने की रीति;

(धख) धारा 85क की उपधारा (3) के अधीन ऑम्बुड्समैन के निदेशों के विरुद्ध सोसाइटी द्वारा अपील फाइल करने की रीति;

(धग) धारा 85क की उपधारा (5) के खंड (घ) के अधीन अन्य मामले” ;”;

(viii) खंड (ब) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(बक) धारा 104 की उपधारा (6) के अधीन विधिविरुद्ध अभिलाभ की वसूली और उनके आगमों के निष्क्रेपों की रीति;

(बख) धारा 106 की उपधारा (2) के अधीन सूचना प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी फीस से आवेदन करने की रीति ;”;

(ix) खंड (भ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(भक) धारा 120क की उपधारा (1) के अधीन इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप में आवेदन, दस्तावेज और इसी प्रकार की चीजें फाइल करने से संबंधित मामलों की बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियों की रीति ;

(भख) धारा 120 (क) की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप में उसमें उल्लिखित मामलों की बाबत कार्यों के निर्वहन या शक्तियों के प्रयोग की रीति ;”;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(3) धारा 116 के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम तथा जारी की गई कोई अधिसूचना, बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाएं कि धारा 116 के अधीन बनाया गया नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तथा जारी की गई कोई अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो यथास्थिति, वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा ; किंतु धारा 116 के अधीन बनाए गए उस नियम या जारी की गई किसी अधिसूचना के परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।”

प्रस्तावित संशोधन के पीछे तर्क

2.389 सभी संबंधित धाराओं को शामिल करने हेतु नियम बनाने की शक्तियां

उपधारा के अंतर्गत संसद में अधिसूचना रखने का प्रावधान । **116 धारा : हेतु (3)** यह उपबंध पहले से ही है। यह केवल स्थान का परिवर्तन है।

समिति द्वारा जांच

हितधारकों से प्राप्त सुझावों का सार

2.390 एनएएफएससीओबी ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है। निम्नलिखित मामलों को छोड़कर: (जक) से (टज) और (डक), (थक), (भक), (भख) आदि। बहुत अधिक और असीमित शक्तियों वाली कोई भी एंजेंसी अपने कार्यनिष्पादन में विफल हो सकती है।

2.391 ड्राफ्ट कैबिनेट नोट दिनांक **05/07/2022** के अनुबंध II पर नाबार्ड की प्रतिक्रिया

धारा 124(2)(कक) - '.. प्रदत्त पूंजी' के बाद और 'आरक्षण के साथ...' से पहले 'का प्रावधान' शब्द हटाए जा सकते हैं।

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

2.392 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड 47: धारा 125 का संशोधन

मूल प्रतिवेदन में उपबंध

2.393 धारा 125: कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.394 “(1क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 के द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों : परंतु ऐसा कोई आदेश, इस धारा के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।”।

प्रस्तावित संशोधन के लिए तर्क

3.395 कठिनाइयों को दूर करने के लिए दो वर्ष के समय के लिए सामान्य खंड

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें

3.396 समिति ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

खंड 48: तीसरी अनुसूची का अन्तःस्थापन

मूल प्रतिवेदन में उपबंध

2.397 नई अंतःस्थापना

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन

2.398 मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“तीसरी अनुसूची

[धारा 43 की उपधारा (1) का खंड (ज) देखिए]

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	अधिनियम संख्यांक
(1)	भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899;	1899 का 2
(2)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934;	1934 का 2
(3)	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944;	1944 का 1
(4)	उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951;	1951 का 65
(5)	खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954;	1954 का 37
(6)	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955;	1955 का 10
(7)	प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956;	1956 का 42
(8)	धन-कर अधिनियम, 1957;	1957 का 27
(9)	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962;	1962 का 52
(10)	इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978;	1978 का 43
(11)	रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985;	1986 का 1
(12)	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992;	1992 का 15
(13)	विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992;	1992 का 22
(14)	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999;	1999 का 42
(15)	प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002;	2003 का 12

(16)	धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002;	2003 का 15
(17)	कंपनी अधिनियम, 2013	2013 का 18।”।

प्रस्तावित संशोधन के लिए तर्क

2.399 तीसरी अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के लिए देय राशि के भुगतान में किसी भी चूक से निदेशक मंडल की अयोग्यता हो जाएगी।

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें

2.400 समिति ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क/उत्तर सहित खंड में किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और खंड के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

नई दिल्ली;

13 मार्च, 2023

22 फाल्गुन, 1944 (शक)

(चंद्र प्रकाश जोशी)

सभापति,

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन)

विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति

परिशिष्ट-एक

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव

मंगलवार, दिसंबर, 20, 2022/ अग्रहायण 29, 1944 (शक)

श्री अमित शाह ने प्रस्ताव किया:—

“कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में और संशोधन करने वाला विधेयक सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें इस सभा से निम्नवत 21 सदस्य हों, अर्थात:—

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022

1. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
4. श्रीमती पूनमबेन माडम
5. श्री रामदास तडस
6. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
7. डॉ. निशिकांत दुबे
8. सुश्री सुनीता दुग्गल
9. श्री बृजेन्द्र सिंह
10. श्रीमती जसकौर मीना
11. श्री रामकृपाल यादव
12. डॉ. ढालसिंह बिसेन
13. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
14. श्री मनीश तिवारी
15. श्रीमती कनिमोद्धी करुणानिधि
16. श्री कल्याण बनर्जी
17. श्री लालू श्रीकृष्ण देवरायालू
18. श्री हेमन्त पाटिल
19. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
20. साहू, श्री चंद्र शेखर
21. श्री गिरीश चन्द्र

और राज्य सभा से 10 सदस्य ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी।

कि समिति इस सभा को बजट सत्र, 2023 के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समिति के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें;

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें; और

कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से किसी एक को इसके सभापति के रूप में नियुक्त करेंगे।”

सौंपने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

परिशिष्ट-दो**विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए राज्य सभा में प्रस्ताव**

सोमवार, दिसम्बर 21, 2022

राज्यसभा से संदेशः

“कि 21 दिसंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा लोकसभा की इस सिफारिश से सहमत है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक (संशोधन), 2022 पर सभाओं की संयुक्त समिति के साथ जुड़ने के लिए राज्यसभा से 10 सदस्यों को नामित करे और राज्यसभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम भी बताए, जिन्हें उक्त समिति के लिए चुना गया हैः—

1. श्री घनश्याम तिवाड़ी
2. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
3. श्री धनंजय भीमराव महादिक
4. श्री रामचंद्र जांगड़ा
5. श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल
6. श्री सुखेन्दु शेखर राय
7. श्री एन. आर. इलांगो
8. श्री विक्रमजीत सिंह साहनी
9. श्री सुजीत कुमार
10. श्री एस निरंजन रेण्टी”

परिशिष्ट-तीन

सरकारी एजेंसियों और विशेषज्ञों/हितधारकों/संगठनों की सूची
जिन्होंने ज्ञापन प्रस्तुत किया

क्रम सं. सरकारी एजेंसियों और विशेषज्ञों/हितधारकों/संगठनों/व्यक्तियों का नाम

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
- नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स (एन ए एफ एस सी ओ बी)
- नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (एन ए एफ सी यू बी)
- भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई)
- इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको)
- कृषक भारती को ऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको)
- भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड)
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नावार्ड)
- राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक संघ लिमिटेड (एनएएफसीएआरडी)
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)
- भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एन सी सी एफ)
- केंद्रीय भंडार
- सहकार भारती
- सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसायटी
- पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च

परिशिष्ट-चार**बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक (संशोधन), 2022 पर संयुक्त समिति की बैठकों का विवरण**

बैठकों की संख्या	बैठकों की तिथि	बैठक की कार्यसूची और साक्षियों की उपस्थित
1	05.01.2023	बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पर सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी दी गई। (उपस्थित: सहकारिता मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय- विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग)
2	19.01.2023	बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पर भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य। (उपस्थित: सहकारिता मंत्रालय)
3	20.01.2023	बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पर निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों के विचार जानने के लिए: नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स (एन ए एफ एस सी ओ बी); तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (एन ए एफ सी यू बी) (उपस्थित: सहकारिता मंत्रालय)
4	20.01.2023	बहुराज्य सोसाइटी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 पर निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों के विचार जानने के लिए : <ol style="list-style-type: none"> 1. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई); 2. इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको); 3. कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको); तथा 4. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) (उपस्थित: सहकारिता मंत्रालय)
5	13.02.2023	बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पर निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों के विचार जानने के लिए: <ol style="list-style-type: none"> 1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नावाड़ी) 2. राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक संघ लिमिटेड (एनएएफसीएआरडी) 3. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) 4. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एन सी सी एफ) (उपस्थित: सहकारिता मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय- विधायी विभाग)
6	20.02.2023	बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पर खंडवार विचार (उपस्थित: सहकारिता मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय- विधायी विभाग)
7	27.02.2023	बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पर खंडवार विचार (उपस्थित: सहकारिता मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय- विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग)
8	13.03.2023	बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।

परिशिष्ट-पाँच

समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले साक्षियों की सूची
आधिकारिक साक्षियों की सूची

क्रम सं.	संगठनों के नाम	मौखिक साक्ष्य की तिथि
1	सहकारिता मंत्रालय	05.01.2023
2	विधि एवं न्याय मंत्रालय-विधि कार्य विभाग	
3	विधि एवं न्याय मंत्रालय - विधायी विभाग	
4	भारतीय रिजर्व बैंक	19.01.2023
5	सहकारिता मंत्रालय	
6	वित्त मंत्रालय -वित्तीय सेवाएं विभाग	
7	सहकारिता मंत्रालय	20.01.2023
8	सहकारिता मंत्रालय	13.02.2023
9	विधि एवं न्याय मंत्रालय - विधायी विभाग	
10	सहकारिता मंत्रालय	20.02.2023
11	विधि एवं न्याय मंत्रालय - विधायी विभाग	
12	सहकारिता मंत्रालय	27.02.2023
13	विधि एवं न्याय मंत्रालय - विधि कार्य विभाग	
14	विधि एवं न्याय मंत्रालय - विधायी विभाग	

साक्षियों की सूची

क्रम सं.	संगठनों के नाम	मौखिक साक्ष्य की तिथि
1	नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स (एन ए एफ एस सी ओ बी)	20.01.2023
2	नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (एन ए एफ सी यू बी)	
3	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई)	
4	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको)	
5	कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको)	
6	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड)	
7	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नावाड़)	13.02.2023
8	राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक संघ लिमिटेड (एनएफसीएआरडी)	
9	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)	
10	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एन सी सी एफ)	

परिशिष्ट- छ**बहुराज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति का कार्यवाही सारांश**

संयुक्त समिति की पहली बैठक गुरुवार, 5 जनवरी, 2023 को 1100 बजे से 1400 बजे तक समिति कक्ष डी, संसदीय सौंध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी - सभापति

लोकसभा

2. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
3. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
4. श्री रामदास चन्द्रभानजी तडस
5. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
6. डॉ. निशिकांत दुबे
7. श्रीमती सुनीता दुग्गल
8. श्री वृजेन्द्र सिंह
9. श्रीमती जसकौर मीना
10. श्री राम कृपाल यादव
11. डॉ. ढाल सिंह विसेन
12. श्री मनीष तिवारी
13. श्री कल्याण बनर्जी
14. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
15. श्री हेमत श्रीराम पाटिल
16. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
17. श्री चंद्र शेखर साहू

राज्यसभा

18. श्री धनंजय भीमराव महादिक
19. श्री राम चन्द्र जांगड़ा
20. श्री एन. आर. इलांगो
21. श्री सुजीत कुमार

सचिवालय

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--------------|
| 1. | श्री जे. एम. वैसाख | - | संयुक्त सचिव |
| 2. | श्री सी. कल्याणसुंदरम | - | निदेशक |
| 3. | श्री सुमेश कुमार | - | उप सचिव |
| 4. | सुश्री रचना सक्सेना | - | उप सचिव |

सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री ज्ञानेश कुमार, सचिव,
2. श्री विजय कुमार, अपर सचिव,
3. श्री कपिल मीना, उप सचिव,
4. श्री अमित सच्चदेव, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

5. डॉ. नितिन चन्द्र, सचिव, विधि कार्य विभाग
6. श्री आर. एस. वर्मा, अपर सचिव, विधि कार्य विभाग
7. श्री के. विस्वाल, अपर सचिव, विधायी विभाग
8. श्री आर. श्रीनिवास, अपर विधायी परामर्शदाता, विधायी विभाग

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने संयुक्त समिति की पहली बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने बहुराज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022, की संक्षिप्त पृष्ठभूमि देते हुए, सदस्यों को बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया।
3. तत्पश्चात्, सभापति ने बहुराज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समिति को जानकारी देने के लिए सहकारिता मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। इसके बाद, उन्होंने मंत्रालय के प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता से संबंधित लोकसभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55(1) और निदेश 58 की ओर आकृष्ट कराया।
4. तत्पश्चात् सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित पहलुओं को कवर करते हुए, एक पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन दी:—
 (i) बहुराज्य सहकारी समितियों और बहुराज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 पर संक्षिप्त स्पष्टीकरण; (ii) बहुराज्य सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2002 में संशोधनों की आवश्यकता विशेषकर सहकारी समितियों पर संवैधानिक उपबंधों के साथ अधिनियम को संरेखित करने के सन्दर्भ में; (iii) चुनाव सुधारों से संबंधित बड़े संशोधन, बोर्ड संरचना में सुधार, सदस्यता और बैठकें, प्रशासन और पारदर्शिता निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना और विधेयक में प्रस्तावित दूसरे अन्य संशोधन।
5. तत्पश्चात् सदस्यों ने विधेयक में प्रस्तावित किए जा रहे विभिन्न संशोधनों पर स्पष्टीकरण मांगे। मोटे तौर पर, ये सहकारी संघवाद में राज्य और केंद्र की शक्तियों को परिभाषित करने, निधि प्रबंधन में पारदर्शिता सुधार और ऑडिट के मानकों को परिभाषित करने, सहकारी बैंकों के लिए नियामक तंत्र, बोर्ड के सदस्यों के चुनाव में अपात्रता के आधार, अनियत रिक्ति को भरने, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षण, सदस्यों की नियुक्ति और सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के कार्य, सीईओ की पात्रता आयु, सहकारिता की कार्यात्मक स्वायत्तता, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि आदि के प्रबंधन के तरीके से संबंधित थे।
6. कुछेक सदस्यों द्वारा यह भी इंगित किया गया कि मंत्रालय को संशोधनों के पीछे के तत्त्व ज्ञान को स्पष्ट करना चाहिए और अपनी अगली बैठक में खंड दर खंड प्रस्तुति देनी चाहिए। इसके बाद सभापति ने मंत्रालय को बैठक के दौरान उठाए गए सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर देने का निर्देश दिया।

तत्पश्चात् मंत्रालय के प्रतिनिधि चले गए।

7. तत्पश्चात् समिति ने अगली बैठक की तिथि और आरबीआई और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता सहित जांच की भावी दिशा पर संक्षेप में विचार-विमर्श किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

समिति की कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति का कार्यवाही सारांश

संयुक्त समिति की दूसरी बैठक गुरुवार, 19 जनवरी, 2023 को 1500 बजे से 1630 बजे तक समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी - सभापति

लोक सभा

2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री रामदास चन्द्रभानजी तडस
4. श्री अण्णा साहेब शंकर जोल्ले
5. डॉ. निशिकांत दुबे
6. श्री वृजेन्द्र सिंह
7. श्रीमती जसकौर मीना
8. श्री राम कृपाल यादव
9. डॉ. ढाल सिंह विसेन
10. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
11. श्री मनीश तिवारी
12. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
13. श्री हेमन्त पाटिल
14. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी

राज्य सभा

15. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
16. श्री धनंजय भीमराव महादिक
17. श्री निरंजन रेण्डी सिरगापूर

सचिवालय

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. श्री जे. एम. बैसाख | संयुक्त सचिव |
| 2. श्री सी. कल्याण सुंदरम | निदेशक |
| 3. श्री सुमेश कुमार | उप सचिव |
| 4. सुश्री रचना सक्सेना | उप सचिव |
| 5. श्री भरत लाल मीणा | उप निदेशक |

सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि

1	श्री ज्ञानेश कुमार	सचिव
2	श्री विजय कुमार	अपर सचिव
3	श्री कपिल मीणा	उप सचिव
4	श्री कुमार राम कृष्ण	उप सचिव

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्रतिनिधि

1	श्री जयंत कुमार दास	कार्यकारी निदेशक
2	श्री जोसेफ राज	विधिक सलाहकार

वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधि

1	श्री विवेक जोशी	सचिव
2	श्री एम.पी. तंगिराला	अपर सचिव
3	श्री प्रशांत कुमार गोयल	निदेशक

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने संयुक्त समिति की दूसरी बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने सदस्यों को बैठक की कार्यसूची के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और हितधारियों को मौखिक साक्ष्य के लिए बुलाया गया।

3. इसके बाद, सभापति ने सहकारिता मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) के प्रतिनिधियों को बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समिति को जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निदेशों के निदेश 55 (1) और 58 की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया।

4. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्रतिनिधि ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करते हुए विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को स्पष्ट किया:—

- (i) शहरी सहकारी बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की अनुप्रयोजनीयता।
- (ii) शेयर पूँजी का प्रतिदाय।
- (iii) बोर्ड की संरचना/निदेशकों के लिए उपर्युक्त और उचित मानदंड।
- (iv) उपभोक्ता शिकायत और निपटान; और
- (v) अन्य खंड जो विशिष्ट परिस्थितियों में स्पष्ट व्याख्या की परीक्षा पर खरे उत्तर सकते हैं।

5. तत्पश्चात्, सदस्यों ने विधेयक में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों पर स्पष्टीकरण मांगा और भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्तीय सेवा विभाग के प्रश्नों का भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधियों ने संक्षिप्त उत्तर दिया। इसके बाद, सभापति ने नोडल मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक को सदस्यों द्वारा बैठक के दौरान उठाए गए सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर उपलब्ध करने का निदेश दिया।

तत्पश्चात्, एनएएफएससीओबी तथा एनएएफसीयूबी के प्रतिनिधि साक्ष्य देकर गए।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाहियों की प्रति का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति का कार्यवाही सारांश

संयुक्त समिति की तीसरी बैठक शुक्रवार, 20 जनवरी, 2023 को 1100 बजे से 1300 बजे तक समिति कमरा संख्या '1' , संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी - सभापति

लोक सभा

2. श्री रामदास चन्द्रभानजी तडस
3. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
4. डॉ. निशिकांत दुबे
5. श्रीमती सुनीता दुग्गल
6. श्री बृजेन्द्र सिंह
7. श्रीमती जसकौर मीना
8. डॉ. ढाल सिंह बिसेन
9. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
10. श्री श्रीकृष्ण देवरायालू लावू
11. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी

राज्य सभा

12. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
13. श्री धनंजय भीमराव महादिक
14. श्री निरंजन रेण्टी सिरगापूर

सचिवालय

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. श्री जे. एम. बैसाख | संयुक्त सचिव |
| 2. श्री सी. कल्याण सुंदरम | निदेशक |
| 3. श्री सुमेश कुमार | उप सचिव |
| 4. सुश्री रचना सक्सेना | उप सचिव |
| 5. श्री भरत लाल मीणा | उप निदेशक |

सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि

1	श्री ज्ञानेश कुमार	सचिव
2	श्री विजय कुमार	अपर सचिव
3	श्री कपिल मीणा	उप सचिव

नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के प्रतिनिधि (एनएएफएससीओबी)

1	श्री कोंडुरु रविंदर राव	अध्यक्ष
2	श्री भीम सुब्रमण्यम	प्रबंध निदेशक

नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (एनएएफसीयूबी)

1	श्री ज्योतिन्द्र मेहता	अध्यक्ष
2	श्री उदय जोशी	निदेशक
3	श्री ओ.पी. शर्मा	निदेशक
4	श्री अतुल खिरवाडकर	विशेषज्ञ
5	श्री योगेश शर्मा	सीई आई /सी

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने संयुक्त समिति की तीसरी बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने सदस्यों को बैठक की कार्यसूची के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी।

3. तत्पश्चात, माननीय सभापति ने नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स (एनएएफएससीओबी) और नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (एनएएफसीयूबी) के प्रतिनिधियों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रावधानों पर उनके विचार सुनने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद, उन्होंने प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता से संबंधित लोकसभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55(1) और निदेश 58 की ओर आकृष्ट कराया।

4. इसके बाद क्रेडिट सोसाइटीयों के प्रतिनिधियों ने समिति को विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के विभिन्न प्रावधानों पर अपने विचारों से अवगत कराया, जिसमें धारा 45 के अंतर्गत सहकारी चुनाव प्राधिकरण, शुद्ध लाभ का निपटान और उधार पर प्रतिबंध, सहकारी लोकपाल की नियुक्ति, धारा 123 के अंतर्गत बोर्ड की अतिवृद्धि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के प्रतिशत में वृद्धि आदि शामिल हैं। तत्पश्चात् सदस्यों ने एनएएफएससीओबी और एनएएफसीयूबीके प्रतिनिधियों से विधेयक में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों/सुझावों पर स्पष्टीकरण मांगा। तदुपरांत सभापति ने उन्हें बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर एक सप्ताह के भीतर देने का निदेश दिया।

तत्पश्चात् एनएएफएससीओबी तथा एनएएफसीयूबी के प्रतिनिधि साक्ष्य देकर चले गए।

5. तत्पश्चात् समिति ने अगली बैठक जारी रखने का फैसला किया, जो 1400 बजे शुरू होने वाली थी।

समिति की कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति का कार्यवाही सारांश

संयुक्त समिति की चौथी बैठक शुक्रवार, 20 जनवरी, 2023 को 1300 बजे से 1400 बजे तक समिति कमरा संख्या '1', संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी - सभापति
लोकसभा

2. श्री रामदास तडस
3. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
4. डॉ. निशिकांत दुबे
5. सुश्री सुनीता दुगगल
6. श्री बृजेन्द्र सिंह
7. श्रीमती जसकौर मीना
8. डॉ. ढालसिंह विसेन
9. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
10. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
11. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी

राज्यसभा

12. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
13. श्री धनंजय भीमराव महादिक
14. श्री एस. निरंजन रेड्डी

सचिवालय

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. श्री जे. एम. बैसाख | संयुक्त सचिव |
| 2. श्री सी. कल्याण सुंदरम | निदेशक |
| 3. श्री सुमेश कुमार | उपसचिव |
| 4. सुश्री रचना सक्सेना | उपसचिव |
| 5. श्री भरत लाल मीणा | उपनिदेशक |

सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि

1	श्री ज्ञानेश कुमार	सचिव
2	श्री विजय कुमार	अपर सचिव
3	श्री कपिल मीणा	उप सचिव

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई)

1	श्री वेद प्रकाश सेतिया	कार्यपालक निदेशक
2	श्री रितेश डे	निदेशक

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको)

1	डॉ. यू.एस अवस्थी	प्रबंध निदेशक और सीईओ
2	श्री संतोष कुमार शुक्ला	संयुक्त महाप्रबंधक (सहकारिता विकास)

कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको)

1	श्री रंजन चौधरी	प्रबंध निदेशक
2	श्री सुंदर सिंह यादव	निदेशक (एचआर)
3	श्री एल.पी. गुडविन	डीजीएम (एम)

नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन (नेफेड)

श्री राजबीर सिंह पवार	प्रबंध निदेशक
-----------------------	---------------

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में समिति के सभी सदस्यों और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई), इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको), कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको), और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन(नेफेड) के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इसके बाद, उन्होंने साक्षियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता से संबंधित लोकसभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55(1) और निदेश 58 की ओर आकृष्ट कराया।

3. तत्पश्चात् एनसीयूआई, इफको, कृभको और नेफेड के प्रतिनिधियों ने समिति को निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित संशोधनों के विभिन्न उपबंधों पर अपनी चिंताओं/विचारों/सुझावों के बारे में जानकारी दी :—(i)बोर्ड का सदस्य होने के लिए अयोग्यता, (ii) बोर्ड की शक्तियाँ और कार्य (iii) सहकारी शिक्षा कोष से संबंधित धारा 63ख (iv) धारा 64 के अंतर्गत निधि का निवेश (v) उधारों पर प्रतिबंध, और (vi) निर्दिष्ट बहुराज्य सहकारी सोसाइटी बोर्ड का अधिक्रमण।

4. तत्पश्चात्, सदस्यों ने उपरोक्त संगठनों के प्रतिनिधियों से विधेयक में प्रस्तावित किए जा रहे विभिन्न संशोधनों पर स्पष्टीकरण मांगा और प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में अपने सुझाव भी रखे। इसके बाद सभापति ने उपरोक्त संगठनों के प्रतिनिधियों को बैठक के दौरान उठाए गए सभी बिंदुओं पर एक समाह के भीतर लिखित उत्तर देने का निदेश दिया।

तत्पश्चात् सहकारी सोसाइटी के प्रतिनिधि चले गए।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

समिति की कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति का कार्यवाही सारांश

संयुक्त समिति की पांचवीं बैठक शुक्रवार, 13 फरवरी, 2023 को 1500 बजे से 1630 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी - सभापति

लोक सभा

2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
4. श्री रामदास तडस
5. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
6. डॉ. निशिकांत दुबे
7. श्रीमती सुनीता दुग्गल
8. श्री वृजेन्द्र सिंह
9. श्रीमती जसकौर मीना
10. श्री राम कृपाल यादव
11. डॉ. ढालसिंह बिसेन
12. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
13. श्री मनीष तिवारी
14. श्री कल्याण बनर्जी
15. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
16. श्री हेमंत पाटिल
17. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी

राज्य सभा

18. श्री घनश्याम तिवाड़ी
19. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
20. श्री धनंजय भीमराव महादिक
21. श्री एस. निरंजन रेण्टी

सचिवालय

1.	श्री जे. एम. बैसाख	संयुक्त सचिव
2.	श्री सी. कल्याण सुंदरम	निदेशक
3.	श्री सुमेश कुमार	उप सचिव
4.	सुश्री रचना सक्सेना	उप सचिव
5.	श्री भरत लाल मीणा	उप निदेशक

सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि

1	श्री ज्ञानेश कुमार	सचिव
2	श्री विजय कुमार	अपर सचिव
3	श्री कपिल मीणा	उप सचिव
4	श्री जितेन्द्र नागर	उपायुक्त
5	श्रीमती निशा सागर	सहायक आयुक्त
6	श्री अमित सचदेव	वरिष्ठ तकनीकी सहायक

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि (विधायी विभाग)

1	श्री के. विस्वाल	विशेष सचिव
2	श्री आर. श्रीनिवास	अपर विधायी काउंसल

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नावार्ड)

1	श्री के. एस. रघुपति	मुख्य महाप्रबंधक
2	श्री वी. के. पहवा	उप-महाप्रबंधक

नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक फेडरेशन लिमिटेड (एनएएफसीएआरडी)

1	श्री डोलर कोटेचा	चेयरमैन
2	श्री के. के. रविन्द्रन	प्रबंध निदेशक

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)

1	श्री आर. के. मंगला	निदेशक (पी एवं सी)
---	--------------------	--------------------

भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ)

1	श्री विशाल सिंह	चेयरमैन
2	श्री विनीत माथुर	प्रबंध निदेशक

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नावार्ड), नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक फेडरेशन लिमिटेड (एनएएफसीएआरडी), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात सभापति ने प्रतिनिधियों से अपना परिचय देने के लिए कहा तथा समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में मंत्रालय के प्रतिनिधियों और गूगल के प्रतिनिधियों का ध्यान लोकसभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55 एवं 58 की ओर ध्यान आकर्षित किया।

4. साक्षियों के परिचय के बाद नावार्ड के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण दिया। फिर एनएएफसीएआरडी, एनसीडीसी और एनसीसीएफ के प्रतिनिधियों को प्रस्तावित संशोधनों के विभिन्न उपबंधों पर उनकी चिंताओं/विचारों/सुझावों के बारे में समिति को जानकारी देने के लिए कहा गया। अपनी प्रस्तुति और मौखिक साक्ष्य में, उन्होंने विधेयक के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य बातों पर प्रकाश डाला:—

(एक) बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम और विधेयक के उपबंधों की अधिव्यासि (दो) धारा 35(1) के अंतर्गत बहुराज्य सहकारी बैंक के शेरयों का मोचन (तीन) निदेशक बोर्ड की योग्यता, ज्ञान आदि (चार) बोर्ड का सदस्य होने के लिए निर्हरता, (पांच) धारा 45 के अंतर्गत सहकारी चुनाव प्राधिकरण (छः) सीईओ के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु (सात) एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति (आठ) धारा 120 के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करना (नौ) निर्दिष्ट बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड का अधिक्रमण (दस) "सहकारी वर्ष" की परिभाषा (ग्यारह) एक सहकारी सोसाइटी का बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में रूपांतरण (वारह) रुग्ण सहकारी सोसाइटियों के लिए निधि (तेरह) धारा 49 के अंतर्गत बोर्ड की शक्ति और कार्य।

5. विचार-विमर्श के दौरान, सभापति और सदस्यों ने विधेयक में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों पर कई प्रश्न उठाए और प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद सभापति ने प्रतिनिधियों को बैठक के दौरान उठाए गए सभी प्रश्नों का एक समाह के भीतर लिखित उत्तर देने का निदेश दिया।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

समिति की कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

**बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी
संयुक्त समिति का कार्यवाही सारांश**

संयुक्त समिति की छठीं बैठक सोमवार, 20 फरवरी, 2023 को 1000 बजे से 1600 बजे तक समिति कमरा संघ्या 'सी', संसदीय सौधविस्तार, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी - सभापति

लोक सभा

2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
4. डॉ. निशिकांत दुबे
5. सुश्री सुनीता दुग्गल
6. श्री वृजेन्द्र सिंह
7. डॉ. ढाल सिंह विसेन
8. श्री कोडिकुम्हील सुरेश
9. श्री मनीष तिवारी
10. श्री कल्याण बनर्जी
11. श्री लावू श्रीकृष्ण देवरायालू
12. श्री गिरिश चन्द्र

राज्य सभा

13. श्री घनश्याम तिवारी
14. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
15. श्री एस. निरंजन रेण्डी

सचिवालय

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. श्री जे. एम. बैसाख | संयुक्त सचिव |
| 2. श्री सी. कल्याण सुंदरम | निदेशक |
| 3. श्री सुमेश कुमार | उप सचिव |
| 4. सुश्री रचना सक्सेना | उप सचिव |
| 5. श्री भरत लाल मीना | उप निदेशक |

सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि

1	श्री ज्ञानेश कुमार	सचिव
2	श्री विजय कुमार	अपर सचिव
3	श्री कपिल मीना	उप सचिव
4	श्री सत्य प्रकाश कुमार	अवर सचिव
5	श्रीमती निशा सागर	सहायक आयुक्त
6	श्री अमित सचदेव	वरिष्ठ तकनीकी सहायक

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि (विधायी विभाग)

1	श्री के. विस्वाल	विशेष सचिव
2	श्री आर. श्रीनिवास	अपर विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों और सहकारिता मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों का बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 के खंडवार विचार के लिए बुलाई गई बैठक में स्वागत किया। इसके बाद, सभापति ने समिति और अधिकारियों का ध्यान समिति की कार्यवाहियों की गोपनीयता से संबंधित लोकसभा अध्यक्ष के निदेश 55 और 58 की ओर आकृष्ट कराया।

3. प्रतिनिधियों द्वारा परिचय दिए जाने के पश्चात्, समिति ने विधेयक की खंडवार जांच की और सहकारिता मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों के साथ सभी खंडों पर विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श के दौरान, उन्होंने विधेयक के खंडों पर सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दिया। अगली बैठक के दौरान विस्तृत जांच के लिए, समिति ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तरों/स्पष्टीकरणों के आधार पर विधेयक के खंडों को पारित किया था, जिसमें उन खंडों को शामिल किया गया था जिन पर सहकारिता मंत्रालय ने समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर सहमति व्यक्त की थी और छह खंडों यथा (i) परिभाषाओं के बारे में खंड 2, (ii) सदस्यों के निष्कासन के संबंध में खंड 12, (iii) खंड 16 जो बोर्ड के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बताता है, (iv) खंड 17 बोर्ड के सदस्यों के चुनाव से संबंधित है, (v) बोर्ड की शक्तियों और कार्यों पर खंड 18 और (vi) मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति पर खंड 20, को अलग रखा था।

4. अंत में सभापति ने सदस्यों और मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

समिति की कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक, (संशोधन) 2022 संबंधी
संयुक्त समिति का कार्यवाही सारांश

संयुक्त समिति की 7वीं बैठक सोमवार, 27 फरवरी, 2023 को 1500 बजे से 1630 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

उपस्थित

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी - सभापति

लोक सभा

2. श्री जगदम्बिका पाल
3. डॉ निशिकांत दुबे
4. सुश्री सुनीता दुग्गल
5. श्री बृजेन्द्र सिंह
6. श्रीमती जसकौर मीना
7. डॉ. ढाव सिंह बिसेन
8. श्री मनीष तिवारी
9. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
10. श्री लालू श्रीकृष्णा देवरायालू
11. श्री हेमन्त पाटिल
12. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
13. श्री गिरिश चन्द्र

राज्य सभा

14. श्री घनश्याम तिवारी
15. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
16. श्री एस निरंजन रेड़ी

सचिवालय

- | | | |
|----|-----------------------|--------------|
| 1. | श्री जे. एम. बैसाख | संयुक्त सचिव |
| 2. | श्री सी कल्याण सुंदरम | निदेशक |
| 3. | श्री सुमेश कुमार | उप सचिव |
| 4. | सुश्री रचना सक्सेना | उप सचिव |
| 5. | श्री भरत लाल मीना | उप निदेशक |

सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि

1	श्री ज्ञानेश कुमार	सचिव
2	श्री विजय कुमार	अपर सचिव
3	श्री कपिल मीणा	उप सचिव
4	श्री जितेंदर नागर	उपायुक्त
5	श्री सत्यप्रकाश कुमार	अवर सचिव
6	श्रीमती निशासागर	सहायक आयुक्त

विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि (विधायी विभाग)

1	श्री के. विस्वाल	विशेष सचिव
2	श्री आर श्रीनिवास	अपर विधायी वकील

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि (विधि विभाग)

श्री आर.एस. वर्मा	अपर सचिव
-------------------	----------

2. सर्वप्रथम, सभापति ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पर खंडवार विचार करने हेतु बुलाई गई बैठक में सहकारिता मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय के सदस्यों (विधायी विभाग) और प्रतिनिधियों का स्वागत किया। तत्पश्चात्, सभापति ने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के निदेश 55 और 58 की ओर समिति और अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया।
3. तत्पश्चात्, समिति ने छह खंडों पर खंडवार विचार किया, अर्थात् (i) खंड 2, परिभाषाओं के संबंध में (ii) खंड 12, सदस्यों के निष्कासन के संबंध में, (iii) खंड 17 बोर्ड के सदस्यों के चुनाव से संबंधित, (iv) खंड 18 बोर्ड की शक्तियों और कार्यों के संबंध में, और (v) खंड 20, मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति के संबंध में तथा (vi) खंड 24 रूग्ण, बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के पुनरुद्धार के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना। इसके अतिरिक्त, दो सदस्यों ने कुछ खंडों से संबंधित विधेयक पर अपने संशोधन भी प्रस्तुत किए।
4. समिति ने इन खंडों पर गहन विचार-विमर्श किया और मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दिया और प्रस्तावित संशोधनों पर स्पष्टीकरण दिया। तत्पश्चात् समिति खंडों के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने के लिए सहमत हुई और विधेयक पर खंडवार चर्चा का समापन किया। तत्पश्चात् सभापति ने मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही के शब्दशः रिकॉर्ड की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

**बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति का
कार्यवाही सारांश**

संयुक्त समिति की 8वीं बैठक सोमवार, 13 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1515 बजे तक समिति कमरा सं. '4', संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

उपस्थित

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी-सभापति

लोक सभा

2. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
3. डॉ निशिकांत दुबे
4. सुश्री सुनीता दुग्गल
5. श्री बृजेन्द्र सिंह
6. श्रीमती जसकौर मीना
7. डॉ ढालसिंह बिसेन
8. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
9. श्री मनीष तिवारी
10. श्री कल्याण बनर्जी
11. श्री हेमन्त पाटिल
12. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
13. श्री चंद्र शेखर साहू
14. श्री गिरीश चन्द्र

राज्य सभा

15. श्री घनश्याम तिवाड़ी
16. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
17. श्री धनंजय भीमराव महादिक
18. श्री एन. आर. इलांगो

सचिवालय

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. श्री जे.एम. बैसाख | - | संयुक्त सचिव |
| 2. श्री सी. कल्याण सुंदरम | - | निदेशक |
| 3. श्री सुमेश कुमार | - | उप सचिव |
| 4. सुश्री रचना सक्सेना | - | उप सचिव |
| 5. श्री भरत लाल मीना | - | उप निदेशक |

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने हेतु बुलाई गई बैठक में संयुक्त समिति के सदस्यों का स्वागत किया। समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया। समिति ने माननीय सभापति को लोक सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और राज्य सभा के पटल पर प्रतिवेदन रखने हेतु भी प्राधिकृत किया।

3. एक सदस्य विमत टिप्पण भी देना चाहता था। सभापति ने इस संबंध में निर्णय लिया कि यदि कोई सदस्य विमत टिप्पण देना चाहता है, तो वह इसे उसी दिन के सांय तक अर्थात् 13.03.23 तक प्रस्तुति कर सकता है।

4. सभापति ने अपने समापन भाषण में संयुक्त समिति के सभी सदस्यों को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया, जिससे समिति ने अल्प-काल में एक व्यापक और महत्वपूर्ण विधान संबंधी प्रतिवेदन की जांच की और उसे अंतिम रूप दिया। तत्पश्चात्, सभापति ने लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा समिति को प्रदान की गई अथक सहायता की प्रशंसा की।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

APPENDIX-VII

N. R. ELANGO
MEMBER OF PARLIAMENT
(RAJYA SABHA)
TAMIL NADU

To

The Chairman,
Joint Committee,
Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022,
Lok Sabha, New Delhi – 110 001

Sir,

SUB: Dissent note – to the draft report

REF: mail from LAFEAS – JCMC018/8/2023 – JCMC

Vanakkam,

I express my sincere thanks to you and the members of the committee for having deliberated the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022 at length. Though I could participate only in the few of the meetings of the committee, the deliberations were done in a democratic manner. The manner in which you have conducted the proceedings of the committee reemphasize the need for constituting such committees with respect to all important bills introduced in the parliament.

Though I concur with most of the draft report, I find myself not able to agree with the report on certain clauses. Hence, I propose the following descent note and request you to place the same on record.

Thank you

N.R.ELANGO
MEMBER OF PARLIAMENT
RAJYA SABHA
IC NO. 4881

NOTE:

1. Dissent note is annexed.
2. I may be permitted to submit the physical copy tomorrow.

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति के प्रारूप प्रतिवेदन पर
श्री एन.आर. इलांगो द्वारा प्रस्तुत किया गया विमत टिप्पण

वर्ष 2012 में संविधान के भाग नौ खं में सतानवेवां संविधान संशोधन को पुरःस्थापित करते समय, यह देखा गया था कि, "राज्य सहकारी सोसाइटियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करेगा"।

- जबकि 2022 का विधेयक संख्या क 215, विभिन्न तरीकों से, इनको कम करता है, विशेषकर कर्मचारी सहकारी सोसाइटियां जैसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को, जिनका गठन केवल सदस्यों के एक वर्ग विशेष के लिए हुआ है।
 - बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत, 21 राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटियां हैं, जिनका गठन या तो उपर्युक्त अधिनियम या संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तपोषण भी किया जाता है।
 - जबकि कर्मचारी सहकारी सोसाइटियां, जिनका गठन और प्रबंधन कर्मचारियों द्वारा उनके स्वयं के अंशदान, श्रिफ्ट जमा, उधार आदि की अपनी निधियों से किया जाता है और जिसमें राज्य/केंद्र सरकार द्वारा कोई वित्तपोषण या सब्सिडी या अनुदान या ऋण गारंटी नहीं दी जाती है और जिनमें राज्य/केंद्र सरकार की कोई शेयर होल्डिंग नहीं होती है, इसलिए ऐसी सोसाइटियों को निम्नलिखित उपबंधों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाना चाहिए, जिन्हें उपर्युक्त विधेयक द्वारा संशोधित करने की मांग की गई है। वे मुख्य रूप से निम्नवत् हैं:
- एक. "सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी" की प्रयोज्यता और अधिकार क्षेत्र।
दो. प्रस्तावित "सहकारी लोकपाल" के अंतर्गत शिकायतों का निवारण।
तीन. धारा 49(2) (ड) (बोर्ड की शक्तियां और कत्य) के अंतर्गत मुख्य कार्यकारी सहित इसके कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में, दिशा-निर्देशों/प्रतिबंधों को लागू करने की मांग की गई है।

विमत टिप्पण-एक

खंड सं.	उपबंध	सुझाए गए संशोधन
17	धारा 45 (1) से धारा 45 (3)	सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी से संबंधित उपर्युक्त उपबंध उन कर्मचारी सहकारी सोसाइटियों के संबंध में लागू नहीं होंगे, जिनमें राज्य/केंद्र सरकार द्वारा कोई वित्तपोषण नहीं किया जाता है या उनकी कोई शेयर होलिंडिंग नहीं है या उनके द्वारा कोई सब्सिडी या मूलधन/ब्याज राहत या छूट प्राप्त नहीं की जाती है।

सुझाव के आधार:

- मूल अधिनियम के अनुसार, सोसाइटी के उत्तराधिकारी बोर्ड का निर्वाचन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 की धारा 45 के अंतर्गत शामिल होता है।
- जबकि प्रस्तावित संशोधन में, मूल अधिनियम की संपूर्ण धारा 45 को धारा 45 (1) से धारा 45 (3) में प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जो सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी पर विचार करती है।
- जब संविधान में **स्वायत्त कार्यकरण** की व्यवस्था की गई है, तो "सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी" की आवश्यकता और वह भी, कर्मचारी सहकारी सोसाइटियों जैसे पूरी तरह से स्वतंत्र वित्तीय संस्थानों के मामले में, अनुचित है और ऐसी कर्मचारी सहकारी सोसाइटियों को मूल अधिनियम की धारा 45 में प्रस्तावित संशोधन से बाहर रखा जाना चाहिए।
- कंपनियों के निदेशक मंडल के लिए निर्वाचन, शेयरधारकों द्वारा स्वयं उनकी आम सभा की बैठक में किया जाता है। इसी प्रकार, कर्मचारी सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों को भी स्वायत्त कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- इसके अलावा, कुछेक हजार सदस्यता वाली विभिन्न बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियां विद्यमान हैं, तथापि यदि सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को प्रस्तावित तरीके से पुरःस्थापित किया जाता है तो यह ऐसी सहकारी सोसाइटियों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा, जो पूर्णतः अनुचित है।
- इसके अलावा, यदि केंद्र अथवा राज्य सरकार के पास कोई शेयर नहीं है या वह कोई सब्सिडी या मूलधन/ब्याज राहत या छूट प्राप्त नहीं करती है या कोई क्रेडिट गारंटी नहीं देती है, तो ऐसी कर्मचारी सहकारी सोसाइटियों को प्रस्तावित "सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी" के दायरे में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 45 की उप-धारा 6 के अंतर्गत पहले से ही एक स्पष्ट अधिदेश है, जहां वर्तमान बोर्ड अपने अनुवर्ती बोर्ड के लिए चुनाव कराने में विफल रहता है, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार, उस तिथि से जब से चुनाव होने थे, 90 दिन के भीतर चुनाव कराएगा और ऐसे बोर्ड सदस्य, एमएससीएस अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा 2 के खंड (क) के अंतर्गत अयोग्यता के पात्र होंगे।
- अतः सहकारी सोसाइटियां जो इन सरकारों द्वारा वित्तपोषित नहीं हैं जैसे कि कर्मचारी सहकारी सोसाइटियों, को धारा 45 में प्रस्तावित संशोधन के दायरे से पूरी तरह से बाहर रखा जाना चाहिए।

विमत टिप्पण - दो

खण्ड सं.	उपबंध	प्रस्तावित संशोधन
18	धारा 49, उपधारा 2 खण्ड (ङः)	बोर्ड की शक्तियों और कार्यों से संबंधित उपरोक्त उपबंध, कर्मचारी सहकारी सोसाइटी के मामले में लागू नहीं होंगे, जहां राज्य/केंद्र सरकार द्वारा कोई वित्तपोषण या शेयरधारिता या सम्बिंदी या मूल/व्याज छूट या माफ़ी नहीं है।

• **सुझावों हेतु कारण:**

- मूल अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा 2 के खंड (ङ) के लिए एक परंतुक शामिल करने का प्रस्ताव है, यथा "परन्तु कि ऐसे कर्मचारियों की भर्ती ऐसी प्रक्रिया के अधीन होगी जैसाकि विहित की गई है।"
- जब राज्य या केंद्र सरकार की कोई शेयरधारिता नहीं होती है, कोई सम्बिंदी नहीं देती है, कोई मूल/व्याज छूट नहीं देती है, कोई ऋण गारंटी नहीं देती है, तो ऐसी परिस्थितियों में, आवश्यक संख्या में कर्मियों की भर्ती के साथ-साथ ऐसे कर्मियों की योग्यता भी नियोक्ता अर्थात् सहकारी सोसाइटी, के विवेक पर छोड़ दी जानी चाहिए जो संचालन के क्षेत्र, शाखाओं की संख्या आदि को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं की निधियों से कार्यकरण करती है।
- इस तरह के परंतुक, जिसे प्रत्यायोजित विधान द्वारा पेश करने की मांग की गई है यथा, "जैसाकि विहित किया जा सकता है", अनपेक्षित है और बोर्ड की शक्तियों और कार्यों के संबंध में धारा 49 की उप-धारा 2 के खंड (ङ) के परंतुक के प्रस्तावित अन्तःस्थापन को हटा दिया जाना चाहिए।

विमत टिप्पण-III

खंड संख्या	उपबंध	सुन्नाए गए संशोधन
31	धारा 85क (उप-धारा 1 से उप-धारा 5)	सहकारी लोकपाल से संबंधित उपर्युक्त उपबंध, कर्मचारी सहकारी सोसाइटी के मामले में लागू नहीं होगा, जहां, राज्य/केंद्र सरकार द्वारा कोई वित्तपोषण या शेयरधारिता या सञ्चिस्डी या मूलधन/ब्याज राहत या छूट नहीं है।

सुन्नाव हेतु कारण :

- मूल अधिनियम में अध्याय IXक "शिकायतों का निवारण" शीर्षक के अंतर्गत एक नया अध्याय अंतःस्थापित किए की मांग की गई है।
- प्रस्तावित संशोधन के उद्देश्यों में यह कहा गया है कि "शिकायतों के निवारण" के लिए "सहकारी लोकपाल" को लाया गया है।
- जबकि, पहले से ही मूल अधिनियम की धारा 84 के संदर्भ में, "विवाद" को सुपरिभाषित परिभाषा है, और "विवाद" के पक्षकार जैसे कि, सोसाइटी का सवियान प्रबंधन या व्यवसाय से संबंधित, सदस्यों के बीच, सदस्य और सोसाइटी के बीच, बोर्ड और किसी सदस्य के बीच और इस प्रकार के "विवाद" को, माध्यस्थम् के लिए भेजा जाएगा।
- इस प्रकार के विवादों का निपटान या विनिर्णय केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त माध्यस्थम् द्वारा किया जाता है और इस प्रकार की माध्यस्थम् की कार्यवाही माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के तहत कवर किया जाता है।
- इस तरह, वित्तीय विवादों सहित कोई भी विवाद पहले से ही मूल अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए हैं।
- इसके अलावा, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम में संशोधन के साथ, वर्ष 2015 में, सदस्यों और सोसाइटी के बीच विवादों के त्वरित निवारण संबंधी व्यवस्था पहले से ही मौजूद है।
- बैंकिंग थ्रेट में, केवल बैंक द्वारा ग्राहकों को प्रदत्त सेवाएं प्रदान किए जाने से जुड़ी शिकायतों के संबंध में तथा ऋणों और अग्रिमों के मामले में, केवल उस सीमा तक जहां तक वे ब्याज दर, समय सीमा पर आरबीआई के आदेशों और आरबीआई के उच्च निदेशों का पालन न किए जाने के संबंध तक "लोकपाल" की भूमिका सीमित है इसमें बैंक द्वारा ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली शामिल नहीं है।
- इसके अलावा, "सहकारी लोकपाल" का प्रावधान न केवल भ्रम पैदा करेगा और जटिल बनाएगा, बल्कि मूल अधिनियम की धारा 84 में अंतर्विष्ट मौजूदा और प्रभावी विवाद निवारण उपबंध को भी शिथिल बनाएगा।
- इस प्रकार, "सहकारी लोकपाल" के प्रस्ताव को विखंडित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह कर्मचारी सहकारी सोसाइटियों के संबंध में मूल अधिनियम की धारा 84 के उपबंधों को शिथिल करेगा।

अनुबंध-एक

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022

संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार

[अधोरेखांकित शब्द संयुक्त समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को और तारंकन (*** लोपों को उपदर्शित करते हैं]

2022 का विधेयक संख्यांक 215-सी

[दि मल्टी-स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटीज (अमेंडमेंट) विल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

**बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन)
विधेयक, 2023**

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002

का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

2002 का 39

2. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,—

धारा 3 का संशोधन।

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(क) “प्राधिकरण” से धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण अभिप्रेत है ;’;

(ii) खंड (घ) में, “धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन” शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंकों के स्थान पर “धारा 4 की उपधारा (1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243 यज के खंड (च) के अनुसार” शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंकों को रखा जाएगा ;

(iii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(च) “सहकारी ऑम्बुड्समैन” से धारा 85क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सहकारी ऑम्बुड्समैन अभिप्रेत है ;’;

(iv) (****) खंड (झ) “(***) का लोप किया जाएगा ;

(v) खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(ट) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या ऐसी सोसाइटियों के वर्ग के संबंध में “वित्तीय वर्ष” से 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष और जहां ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग के लेखों का केन्द्रीय रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी के साथ किसी अन्य दिन को तुलन किया जाता है, उस दिन को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ;’;

(vi) खंड (ध) में, “अभिप्रेत है” शब्दों के पश्चात्, “और ‘अधिसूचित’ पद का इसके सजातीय अर्थों तथा व्याकरणिक रूपभेदों के साथ तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 7 का संशोधन।

“(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय रजिस्ट्रार, किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा यदि समादत्त पूंजी का कुल मूल्य और तरलता सहित आरक्षितियों का उपबंध, बचत-उधार समिति के कारबार में लगी प्रस्तावित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट निवेश और अन्य विवेकपूर्ण संनियम ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार होंगे जो विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ होने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के भीतर ऐसे मानकों को पूरा करेगी :

परंतु यह और कि यदि बहुराज्य प्रत्यय सोसाइटी की तरलता, निवेश, विवेकपूर्ण संनियम और अन्य मानदंड, उपरोक्त उल्लिखित अवधि के भीतर ऐसे मानकों को पूरा नहीं करती है, तब केन्द्रीय रजिस्ट्रार को ऐसे निदेश जारी करने की शक्ति होगी जिन्हें वह ऐसी सोसाइटी के प्रति सुसंगत कार्रवाई करने के लिए समुचित समझता है :

परंतु यह और भी कि बहुराज्य सहकारी बैंक के मामले में, प्रदत्त पूंजी का कुल मूल्य और उपनियमों में उपबंधित तरलता मानकों के साथ आरक्षित के उपबंध ऐसे होंगे जैसा कि समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारित करे ।

(3) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा उनके द्वारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा :

परन्तु केन्द्रीय रजिस्ट्रार, आवेदन में भूल, यदि कोई हो, के सुधार के लिए, आवेदक के अनुरोध पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं तीन मास की अवधि को ऐसी अतिरिक्त दो मास की अवधि से अनधिक अवधि तक विस्तार कर सकेगा।

(4) जहाँ केन्द्रीय रजिस्ट्रार बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को रजिस्टर करने से इंकार कर देता है, वहाँ वह ऐसे इंकार करने का कारण बताते हुए, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदक को संसूचित करेगा :

परंतु इंकार का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो :

परंतु यह और कि यदि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का निपटारा उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है या केन्द्रीय रजिस्ट्रार उस अवधि के भीतर इंकार के आदेश को सूचित करने में असफल रहता है तो आवेदन रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया समझा जाएगा और केन्द्रीय रजिस्ट्रार इस अधिनियम तथा तदीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।”।

धारा 10 का
संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (क) में, “पता” शब्द के स्थान पर, “पता (*** जिसके अंतर्गत ई-मेल पता भी है (***))” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

धारा 14 का
संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

- (i) पार्श्व टिप्पण “पते में परिवर्तन” शब्दों के स्थान पर “पता” शब्द रखा जाएगा ;
- (ii) शब्द “पता” के स्थान पर “पता, जिसमें ई-मेल पता भी शामिल है” शब्दों को रखा जाएगा।

धारा 17 का
संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित का जाएगी :—

“(10) कोई सहकारी समिति, ऐसी सोसाइटी के साधारण अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा मौजूदा बहुराज्य सहकारी समिति में विलय करने का विनिश्चय कर सकेगी:

परंतु ऐसा संकल्प संबंधित तत्समय प्रवृत्त राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के उपबंधों के अधीन होगा जिसके अधीन ऐसी सहकारी समिति रजिस्ट्रीकृत है।”।

धारा 19 का
संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 19 में, स्पष्टीकरण के खंड (क) में,—

- (i) उपखंड (ii) के अंत में आए “या” शब्द का लोप किया जाएगा ;
- (ii) उपखंड (iii) का लोप किया जाएगा।

धारा 22 का
संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (5) में, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) सहकारी सोसाइटी को, उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त ऐसी सहकारी सोसाइटी से संबंधित विधि के अधीन ऐसी सहकारी सोसाइटी को केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत संशोधन की प्रति सहित जारी किए गए और अग्रेषित किए गए प्रमाणपत्र की तारीख से विपंजीकृत किया गया समझा जाएगा।”।

धारा 26 का
संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 26 में,—

(i) परंतुक में “ऐसी सोसाइटी के शेरयों में अभिदाय करने का हकदार नहीं होगा या” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) परंतुके पश्चात्, निम्नलिखित परंतुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि अभिहित या सहयुक्त सदस्य को ऐसे गैर-मतदान शेयर जारी किए जा सकते हैं जो उसे बहुराज्य सहकारी समिति के प्रबंधन में कोई हित जिसमें मताधिकार, बोर्ड के निदेशक के रूप में निवाचित होना या साधारण निकाय अधिवेशनों में भाग लेना भी है, प्रदान नहीं कर सकेगा :

परंतु यह और भी कि बहुराज्य सहकारी बैंक के मामले में, ऐसे शेयर समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार जारी किए जाएंगे ।”।

10. मूल अधिनियम की धारा 28 में, “जब तक कि उसने सदस्यता के संबंध में सोसाइटी को ऐसा संदाय न किया हो, या” शब्दों के स्थान पर, “जब तक कि उसने सदस्यता के संबंध में संदाय सहित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को सभी बकायों का संदाय न कर दिया हो या उत्पाद या सेवाओं, जो उपनियमों में यथाविनिर्दिष्ट है के ऐसे न्यूनतम स्तर का उपभोग न कर लिया हो, या” शब्द रखे जाएंगे ।

11. मूल अधिनियम की धारा 29 के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) वह दो निरंतर वर्षों के लिए उपविधियों में यथाविनिर्दिष्ट उत्पादों या सेवाओं के न्यूनतम स्तर का उपयोग करने में असफल रहता है ; या”।

12. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) में, “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “तीन वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ।

13. मूल अधिनियम की धारा 35 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“35. (1) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) में निर्दिष्ट प्राधिकरणों के ऐसे शेयर, जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों में धारित किए गए हैं,—

(क) ऐसे प्राधिकरणों के पूर्व अनुमोदन के बिना मोचित नहीं किए जाएंगे ;

(ख) ऐसी रीति में मोचित किए जा सकेंगे, जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी तथा ऐसे प्राधिकरणों के बीच तय किया जाए ।

(2) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ङ) से खंड (छ) तक में निर्दिष्ट किन्हीं प्राधिकरणों द्वारा, किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में धारण किए गए शेयर ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार मोचित किए जाएंगे और उस दशा में, जहां उपविधियों में इसकी बाबत कोई उपबंध नहीं है, ऐसी रीति में मोचित होंगे, जो किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी और ऐसे प्राधिकरणों के बीच तय किया जाए ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट शेयरों का मोचन शेयर के अंकित मूल्य पर होगा ।”।

14. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में, खंड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(त) संपरीक्षक की नियुक्ति ।”।

15. मूल अधिनियम की धारा 41 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 28 का संशोधन ।

धारा 29 का संशोधन ।

धारा 30 का संशोधन ।

धारा 35 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

शेयरों का मोचन ।

धारा 39 का संशोधन ।

धारा 41 का संशोधन ।

(3) बोर्ड, इंडिया से अनधिक निदेशकों की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा, जिनमें व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के व्यष्टियों और सदस्यों से मिलकर बनी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा और दो महिलाएं होंगी :

परंतु बोर्ड, बैंक के प्रबंधन, सहकारी प्रबंधन और वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले या ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा अपनाए गए उद्देश्यों तथा किए गए क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले बोर्ड के सदस्यों को सहयोजित कर सकेगा:

परंतु यह और कि ऐसे सहयोजित किए गए सदस्यों की संख्या इस उपधारा में विनिर्दिष्ट इंडिया निदेशकों के अतिरिक्त, ऐसे दो निदेशकों से अधिक नहीं होगी।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट सहयोजित निदेशकों को पदाधिकारियों के किसी निर्वाचन में मत डालने का अधिकार नहीं होगा या वे बोर्ड के पदाधिकारियों के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(5) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में कृत्यकारी निदेशक भी, इसकी उपविधियों के अनुसार बोर्ड के सदस्य होंगे और ऐसे निदेशक, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट निदेशकों की कुल संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिए विवर्जित किए जाएंगे।

(6) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई निदेशक, निदेशक के रूप में, ऐसी सोसाइटी द्वारा या उसकी ओर से की गई या की जाने वाली किसी संविदा या ठहराव के संबंध में विचार-विमर्श या मतदान में उपस्थित नहीं होगा, यदि वह या उसका नातेदार प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी संविदा या ठहराव से संबंधित है या उसमें हितबद्ध है और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में किसी आसीन निदेशकों का संबंधी, सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी सहित यथा कर्मचारी के रूप में नहीं नियुक्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यष्टि के संदर्भ में “नातेदार” पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

- (क) पति या पत्नी ;
- (ख) पिता (जिसके अंतर्गत सौतेला पिता भी है) ;
- (ग) माता (जिसके अंतर्गत सौतेली माता भी है) ;
- (घ) पुत्र (जिसके अंतर्गत सौतेला पुत्र भी है) ;
- (ङ) पुत्रवधू ;
- (च) पुत्री (जिसके अंतर्गत सौतेली पुत्री भी है) ;
- (छ) दामाद ;
- (ज) दादा ;
- (झ) दादी ;
- (ञ) नाना ;
- (ट) नानी ;
- (ठ) पौत्र ;
- (ঢ) পৌত্রবধু ;
- (ঢ) পৌত্রী ;

- (ण) पौत्री का पति ;
- (त) नाती ;
- (थ) नाती की पत्नी ;
- (द) नातिन ;
- (ध) नातिन का पति ;
- (न) भाई (जिसके अंतर्गत सौतेला भाई भी है) ;
- (प) भाई की पत्नी ;
- (फ) बहन (जिसके अंतर्गत सौतेली बहन भी है) ;
- (ब) जीजा ; और
- (भ) हिंदू अविभक्त कुटुंब ।

(7) बोर्ड का ऐसा कोई निदेशक, जो उपधारा (6) के उपर्युक्त काउन्टर काउन्टर का उल्लंघन करता है, बोर्ड का सदस्य होने के लिए निरहित होगा और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उक्त उपधारा में निर्दिष्ट बोर्ड के ऐसे अधिवेशन की तारीख से अपना पद रिक्त कर दिया है जैसा कि उक्त उपधारा में निर्दिष्ट है और ऐसी कार्यवाही शून्य समझी जाएगी।’।

16. मूल अधिनियम की धारा 43 में,—

धारा 43 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (क) में “दिवालिया” शब्द के पश्चात् “या दिवालिया कंपनी के निदेशक रहें हो” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ख) खंड (ज) में, “इस अधिनियम के अधीन” शब्दों के पश्चात्, “या तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिनियम के अधीन” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ण) धारा 41 की उपधारा (7) के अधीन निरहित किया गया है ;”;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1क) ऐसा कोई सदस्य, जो किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या सहकारी बैंक के बोर्ड का निदेशक रहा है, जहां ऐसा बोर्ड अधिक्रान्त हो गया है, किसी अन्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या सहकारी बैंक के बोर्ड के निदेशक के रूप में ऐसे अधिक्रमण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु कोई भी सदस्य इस उपधारा के अधीन अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे सदस्य को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है और अयोग्यता की घोषणा अभिनिश्चय के पश्चात् केवल तभी की जाएगी जब संबंधित सदस्य ऐसे अधिक्रमण के परिणामस्वरूप कार्य या लोप के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं ।”;

(iii) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन ऐसी रीति से जो विहित की जाए, निर्वाचन करवाने के लिए यथा अपेक्षित सूचना, दस्तावेज, कार्मिक, निधियां या खर्चों या कोई अन्य सहायता उपलब्ध करने में ;”;

(ख) खंड (ग) में, “साधारण अधिवेशन” शब्दों के स्थान पर, “साधारण अधिवेशन ; या” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(घ) धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सहकारी शिक्षा निधि या धारा 63क के अधीन स्थापित सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि में अभिदाय करने में ; या

(ङ) धारा 120 के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर वार्षिक विवरणी फाइल करने में ; या

(च) उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे लेखा संबंधित है, की समाप्ति के छह मास के भीतर सोसाइटी की संपरीक्षा कराने में :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व, उसे केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।”।

17. मूल अधिनियम की धारा 45 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 45 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना ।

“45. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के नाम से जात प्राधिकरण का गठन करेगी, जो कि ऐसे व्यक्तियों, जो विहित किए जाएं, से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा ।

(2) प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

(3) कोई व्यक्ति,—

(i) प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक उसने भारत सरकार के अपर सचिव या समतुल्य पंक्ति का पद धारण न किया हो ;

(ii) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक उसने भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य पंक्ति का पद धारण न किया हो ; और

(iii) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह ऐसी अर्हता और अनुभव, जो विहित किया जाए, पूरी नहीं करता हो ।

(4) प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए या उनके द्वारा पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त

कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करेंगे और वे पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होंगे :

परंतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति के मामले में, वह पदेन सदस्य के रूप में माना जाएगा और वह तब तक बना रहेगा जब तक वह उस पद पर रहता है जिसके आधार पर वह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है।

(5) प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों, पदेन सदस्यों से भिन्न, को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निवधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

45क. प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्राधिकरण के कार्यकलापों के संचालन में साधारण अधीक्षण और निदेशन की शक्तियां प्राप्त होंगी तथा वह प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं।

45ख. (1) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकेगी, यदि, यथास्थिति, प्राधिकरण का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य,—

अध्यक्ष की शक्ति ।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हटाया जाना और उनका निलंबन ।

(क) दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है ;

(ख) ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ;

(ग) प्राधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ;

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे प्राधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; या

(च) अपनी पदावधि के दौरान किसी समय किसी अन्य नियोजन में लगा हुआ है।

(2) प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को, उसके पद से केंद्रीय सरकार के आदेश द्वारा सावित कदाचार या अक्षमता के आधार पर यदि केन्द्रीय सरकार उसके द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार हुई जांच पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य किसी ऐसे आधार पर हटाया जाना चाहिए, उसके पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(3) केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन जांच आरंभ की गई है या लंबित है, तब तक निलंबित नहीं कर सकेगी, जब तक केंद्रीय सरकार ने जांच की रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर कोई आदेश पारित न कर दिया हो ।

45ग. (1) किसी व्यक्ति को प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे वह ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के अपने कार्य को करने में प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है ।

(2) प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य पदग्रहण करने के पश्चात् तुरंत और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष, उस सीमा की घोषणा करेगा जिस सीमा तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या वित्तीय या अन्यथा किसी सहकारी सोसाइटी में उसका हित है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन की गई ऐसी घोषणा प्राधिकरण द्वारा पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी।

सदस्यों का
त्यागपत्र

45व. पदेन सदस्यों से भिन्न, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, कम से कम तीस दिन की लिखित सूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और सरकार द्वारा ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार करने पर, उसका पद रिक्त माना जाएगा :

परंतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को जब तक अपने पद को त्याग करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति नहीं दे दी जाती है ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक या जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है या जब तक उसकी पदावधि समाप्त नहीं हो जाती है, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपना पद धारण किए रहेगा ।

आकस्मिक
रिक्ति का भरा
जाना ।

45ड. यदि प्राधिकरण का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के पद की कोई आकस्मिक रिक्ति, चाहे वह उसकी मृत्यु, उसके त्यागपत्र या अन्यथा के कारण, होती है, तो ऐसी रिक्ति धारा 45 के उपर्यांतों के अनुसार नई नियुक्ति करके नब्बे दिन की अवधि के भीतर भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति ऐसी शेष पदावधि के लिए वैसे ही पद धारण करेगा, जिसके लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य ने, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है, वह पद धारण किया हुआ होता ।

पुनःनियोजन
का निर्बन्धन ।

45च. प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य पद में न रहने पर, दो वर्ष की अवधि तक के लिए किसी सहकारी सोसाइटी में कोई नियोजन (जिसमें परामर्शी या अन्यथा भी है) स्वीकार नहीं करेगा :

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार में या किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) के अधीन यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी नियोजन पर लागू नहीं होगी ।

2013 का 18

प्राधिकरण की
कार्यवाहियों का
रिक्तियों आदि के
कारण
अविधिमान्य न
होना ।

45छ. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या कोई त्रुटि है;

(ख) प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण की कार्यवाही में ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

प्राधिकरण के
अधिवेशन ।

45ज. (1) प्राधिकरण, ऐसे स्थानों पर और ऐसे समयों पर, अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में कारबाह के संबंध में प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत उसके अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं ।

(2) प्राधिकरण का अध्यक्ष, प्राधिकरण के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारणवश प्राधिकरण का अध्यक्ष, प्राधिकरण के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(3) ऐसे सभी प्रश्न, जो प्राधिकरण के किसी अधिवेशन के समक्ष उत्पन्न होते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के मतों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्षता करने वाले प्राधिकरण के अध्यक्ष या प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को निर्णायिक मत का प्रयोग करने का अधिकार होगा ।

(4) उपधारा (1) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा ।

45झ. प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

प्राधिकरण के कृत्य ।

(i) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के निर्वाचितों का संचालन ;

(ii) निर्वाचिक नामावलियों के तैयार करने से संबंधित मामलों का पर्यवेक्षण, निदेशन और उनका नियंत्रण ; और

(iii) ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किए जाएं ।

45ज. (1) कोई व्यक्ति बोर्ड के सदस्य या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के पदधारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक वह उस सोसाइटी के साधारण निकाय का सक्रिय सदस्य नहीं है ।

बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, “सक्रिय सदस्य” पद से कोई ऐसा सदस्य अभिप्रेत होगा, जो—

(i) सोसाइटी की सेवाओं या उत्पादों के न्यूनतम स्तर का उपभोग कर रहा है; या

(ii) कम से कम तीन लगातार सामान्य अधिवेशनों में उपस्थित हो रहा है ।

(2) बोर्ड का कोई सदस्य या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का पदधारी ऐसा सदस्य या पदधारी नहीं रहेगा, यदि वह उस सोसाइटी के साधारण निकाय का सदस्य नहीं रह जाता है ।

(3) बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा ।

(4) बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्यों के साधारण अधिवेशन में किया जाएगा और बोर्ड के निर्वाचित सदस्य यदि ऐसी सोसाइटी की उपविधियां अनुज्ञात करें तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे ।

(5) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की पदावधि निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष होगी तथा पदाधिकारियों की पदावधि बोर्ड की पदावधि के साथ समाप्त हो जाएगी :

परंतु बोर्ड, बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के एक तिहाई सदस्यों की आकस्मिक रिक्तियों को सदस्यों के उस वर्ग में से नामनिर्देशन द्वारा भर सकेगा जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई है, यदि बोर्ड की पदावधि उसकी मूल पदावधि में से आधे से कम है :

परंतु यह और कि यदि बोर्ड की उसी पदावधि में ऐसी आकस्मिक रिक्तियों की संख्या के निर्वाचित निदेशकों के एक-तिहाई से अधिक होने की दशा में ऐसी रिक्तियों को निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा ।

(6) प्राधिकरण द्वारा निर्वाचन कराने के लिए व्यय बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वहन किया जाएगा ।

(7) केंद्रीय सरकार, बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन के संचालन के लिए शक्तियों का उपबंध करने और प्राधिकरण द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया के लिए नियम बना सकेगी ।

(8) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक, निर्वाचितों का समय के भीतर संचालन करने के लिए प्राधिकरण को विद्यमान बोर्ड की अवधि की समाप्ति से छह मास पूर्व सूचित करेगा ।

(9) ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, जिसके संबंध में निर्वाचन कराया जा रहा है, प्राधिकरण को ऐसी अवसंरचना, कार्मिक, सूचना, दस्तावेज या अन्य सहायता उपलब्ध कराएगी, जिनकी वह अपेक्षा करे।

रिटर्निंग
आफिसर और
अन्य
अधिकारियों की
नियुक्ति।

45ट. (1) प्राधिकरण, बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन संचालित करने के लिए रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति कर सकेगा और ऐसे कृत्यों का, जिनका प्राधिकरण द्वारा निदेश दिया जाए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निर्वहन कर सकेगा।

(2) केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण को ऐसे कर्मचारिवृंद और अधिकारी उपलब्ध कराएगी, जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(3) प्राधिकरण,—

(क) ऐसे संप्रेक्षकों की नियुक्ति कर सकेगा, जो वह निर्वाचनों का पर्यवेक्षण करने और ऐसे कृत्यों, जो विहित किए जाएं, का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे;

(ख) सहायक रिटर्निंग आफिसरों की उतनी संख्या में नियुक्ति कर सकेगा, जो वह रिटर्निंग आफिसर की सहायता करने के लिए आवश्यक समझे।

45ठ. प्राधिकरण सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, बोर्ड को, इसके सदस्यों, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक और अन्य कर्मचारिवृंद को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के लिए आवश्यक हों और बोर्ड, इसके सदस्य, सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक और कर्मचारिवृंद ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे।”।

18. मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(कक) प्राधिकरण के निदेश के अनुसार बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों में से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या सभापति और उप सभापति का निर्वाचन करना :

परंतु निर्वाचन का प्रमाणपत्र बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक द्वारा बोर्ड द्वारा संकल्प पर सहमति होने के पश्चात् जारी किया जाएगा;”;

(ii) खंड (ड) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु ऐसे कर्मचारियों की भर्ती, ऐसी प्रक्रिया के अधीन रहते हुए होगी, जो विहित की जाए।”।

19. मूल अधिनियम की धारा 50 में,—

(क) उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु जहां ऐसा अध्यक्ष या सभापति मुख्य कार्यपालक को बोर्ड की तिमाही के भीतर बैठक आयोजित करने के लिए निदेश देने में असफल रहता है तो ऐसा मुख्य कार्यपालक बोर्ड के उप सभापति या उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की अध्येक्षा के आधार पर बैठक आयोजित करेगा :

परंतु यह और कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य कार्यपालक बोर्ड के कम से कम पचास प्रतिशत सदस्यों की अध्येक्षा के आधार पर बैठक आयोजित कर सकेगा।”।

धारा 50 का
संशोधन।

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएँगी, अर्थात् :—

“(3) सभापति या अध्यक्ष, यदि किसी कारण से बोर्ड की बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं तो उपाध्यक्ष या उप सभापति और दोनों की अनुपस्थिति में बोर्ड के उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से चुना गया बोर्ड का कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के निदेशक बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति इसके निर्वाचित निदेशकों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी।”।

20. मूल अधिनियम की धारा 51 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात् :—

धारा 51 का संशोधन।

“(1अ) कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, ऐसे मुख्य कार्यपालक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करेगी या उसके नियोजन को जारी नहीं रखेगी, जो,—

(क) इक्कीस वर्ष से कम आयु का है या जिसने सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है :

परंतु सत्तर वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति, बोर्ड के तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा उस दशा में नियुक्त किया जा सकेगा, जिस दशा में ऐसे प्रस्ताव के लिए सूचना से उपाबद्ध स्पष्टीकारक विवरण ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए औचित्य को उपर्युक्त करेगा ;

(ख) जो अननुमोचित दिवालिया है या किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ;

(ग) किसी न्यायालय द्वारा किसी भी समय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है और छह मास से अधिक की अवधि के लिए दंडादिष्ट किया गया है।”।

(घ) बहुराज्यीय प्रत्यय सोसाइटियों की दशा में केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा यथा अवधारित ‘ठीक और समुचित’ के मानदंड को पूरा नहीं करता है ; या गैर बहुराज्य प्रत्यय सोसाइटियों की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा शैक्षणिक अर्हताओं और सुसंगत अनुभव के निवंधनों में विहित किए जाने वाले मानदंड को पूरा नहीं करती है।

21. मूल अधिनियम की धारा 52 के खंड (ज) में, “तीस दिन” शब्दों के स्थान पर, “पैंतालीस दिन” शब्द रखे जाएँगे।

धारा 52 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएँगी, अर्थात् :—

धारा 53 का संशोधन।

“(1) बोर्ड, एक कार्यकारी समिति और ऐसी अन्य समितियों या उपसमितियों का गठन कर सकेगा, जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

परंतु बोर्ड,—

(क) उपविधियों के अनुसार एक संपरीक्षा और आचार समिति का गठन करेगा;

(ख) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण संबंधी समिति का गठन करेगा।”।

धारा 63 का
संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर,
निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली सहकारी शिक्षा निधि में शुद्ध लाभ का एक प्रतिशत प्रत्यय वार्षिक रूप से ऐसी रीति में जमा करेगी जो विहित की जाए और ऐसी निधि से प्राप्त आगम भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और ऐसे किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए उपयोग किए जाएंगे ;”।

नई धारा 63क,
धारा 63ख और
धारा 63ग का
अंतःस्थापन।

सहकारी
पुनर्वास,
पुनःसन्निर्माण
और विकास
निधि की
स्थापना।

24. मूल अधिनियम की धारा 63 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

‘63क. (1) केन्द्रीय सरकार धारा 63ख में यथानिर्दिष्ट रूण बहु राजीय सरकारी सोसाइटियों के पुनरुद्धार के लिए और विकास प्रयोजनों के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्गठन और विकास निधि नामक एक निधि का ऐसी रीति में, जो उसके द्वारा अवधारित की जाए, गठन करेगी और ऐसी निधि में ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों द्वारा, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों से लाभ अर्जित कर रही है, एक करोड़ रूपए या ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के शुद्ध लाभ का एक प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हों, वार्षिक रूप से जमा करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक समिति का गठन करेगी, जो ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो वह निधि का प्रशासन करने के लिए ठीक समझे और निधि के संबंध में पृथक् लेखों और अन्य सुसंगत अभिलेखों को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से ऐसे प्ररूप में रखेगी, जो विहित किया जाए।

(3) समिति, उन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए, जिनके लिए ऐसी निधि की स्थापना की गई है, निधि में से धन खर्च करेगी।

रूण
सोसाइटियों का
पुनरुज्जीवन।

63ख. (1) यदि किसी समय केन्द्रीय रजिस्ट्रार की यह राय है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी रूण हो गई है, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी सोसाइटी को रूण सोसाइटी घोषित कर सकेगा।

(2) जहां किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को उपधारा (1) के अधीन रूण सहकारी सोसाइटी घोषित किया जाता है, वहां केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या अभिकरण सोसाइटी के सुधार और पुनर्गठन के लिए एक स्कीम तैयार कर सकेगी/सकेगा और उसे साधारण सभा में अनुमोदन के लिए सोसाइटी को सौंप सकेगी/सकेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, साधारण सभा की सिफारिश पर और उपधारा (2) में निर्दिष्ट सुधार और पुनर्गठन संबंधी स्कीम को प्रभावी रूप देने के लिए, ऐसी सोसाइटी के बोर्ड का ऐसे व्यक्तियों के साथ पुनर्गठन कर सकेगी, जिसके पास सहकरिता, प्रबंध, वित्त, लेखांकन और ऐसी सोसाइटी से संबंधित ऐसे किसी अन्य क्षेत्र में, जिसकी साधारण सभा द्वारा सिफारिश की जाए, अनुभव हो :

परंतु रूण सहकारी बैंक के संबंध में, सुधार या पुनर्गठन संबंधी कोई स्कीम रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से बनाई जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “रूण सहकारी सोसाइटी” से ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, जिसकी किसी वित्तीय वर्ष के अंत में, उसकी समादत्त पूँजी,

मुक्त आरक्षितियों और अधिशेषों के बराबर या उससे अधिक संचयित हानि है और उसने ऐसे वित्तीय वर्ष और ऐसे वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद के रूप में हानियां भी उठाई हैं।

63ग. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा किए गए आवेदन पर, जिसने निरंतर पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए निधि में अभिदाय किया है, जो वह अवसंरचनात्मक अपेक्षा के लिए निधि में से सोसाइटी के लिए ऐसी वित्तीय सहायता मंजूर कर सकेगी, जो वह उचित समझे :

परंतु कुल अपेक्षा का कम से कम पचास प्रतिशत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा वहन किया जाएगा और निधि से वित्तीय सहायता ऐसी अपेक्षा के पचास प्रतिशत से अधिक की नहीं होगी :

(2) धारा 63क की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के उस सीमा तक और ऐसे निवंधनों और शर्तों पर, जो वह आवश्यक समझे, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समीक्षा करेगी और केन्द्रीय सरकार को इसकी सिफारिश करेगी ।।।

25. मूल अधिनियम की धारा 64 में,—

(i) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

बहुराज्य
सहकारी
सोसाइटियों
को विकास के
लिए वित्तीय
सहायता ।

धारा 64 का
संशोधन ।

“(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, सरकारी निगम, सरकारी कंपनियां, प्राधिकरणों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों या सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा सुनिश्चित की गई किसी अन्य प्रतिभूतियों में से किसी में ;”;

(ii) खंड (घ) में “किसी सहायक संस्था या किसी अन्य संस्था” शब्दों से पहले “बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कारबार की उसी श्रेणी में” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ङ) और (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ङ) किसी अन्य अधिसूचित या राष्ट्रीयकृत बैंक में ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति,—

1934 का 2

(i) “अनुसूचित बैंक” का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (ङ) में है ;

1970 का 5
1980 का 40

(ii) “राष्ट्रीयकृत बैंक” से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित तत्स्थानी नए बैंक अभिप्रेत है; या

(च) किसी अन्य रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए ।।।

26. मूल अधिनियम की धारा 67 में, उपधारा (1) के पहले पंरतुक में “दस गुणा” शब्दों के स्थान पर “ऐसे गुणकों से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 67 का
संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 70 में,—

(क) उपधारा (2) में, पंरतुक के स्थान पर, निम्नलिखित पंरतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

‘परंतु ऐसे संपरीक्षक या संपरीक्षा करने वाली फर्म केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल से नियुक्त किए जाएंगे:

परंतु यह और कि पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक के निक्षेपों वाले बहुराज्य सहकारी बैंकों, बहुराज्य प्रत्यय सहकारी सोसाइटियों और पांच सौ करोड़ रुपए से

अधिक की आवर्त वाली बहुराज्य गैर-पत्यय सोसाइटियों की दशा में, संपरीक्षक केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी सोसाइटियों की संपरीक्षा के लिए अनुमोदित संपरीक्षकों के एक पैनल से नियुक्त किया जाएगा।”;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(3क) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त संपरीक्षक ऐसे वितीय वर्ष जिससे ऐसे लेखे संबंधित हैं, के समाप्त होने की तारीख से छह मास के भीतर बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।”;

(ग) उपधारा (7) के खंड (क) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु जहां ऐसी रिक्ति किसी संपरीक्षक के त्याग पत्र से या मृत्यु के कारण कारित हुई है, वहां वह रिक्ति बोर्ड द्वारा, संपरीक्षकों के ऐसे पैनल से जिससे ऐसे संपरीक्षक की नियुक्ति की गई थी, भरी जाएगी।”।

(घ) उपधारा (9) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के तद्दीन, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी :—

“(10) राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी के लेखा की संपरीक्षा रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।”।

नई धारा 70 का
अंतःस्थापन।

समवर्ती
संपरीक्षा।

धारा 73 का
संशोधन।

28. मूल अधिनियम की धारा 70 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“70ख. बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों की दशा में,—

(i) जिनकी वार्षिक आवर्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की गई रकम से अधिक है; या

(ii) जिनका निक्षेप केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअवधारित की गई रकम से अधिक है,

समवर्ती संपरीक्षा केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के एक पैनल से नियुक्त किए गए किसी संपरीक्षक द्वारा की जाएगी।”।

29. मूल अधिनियम की धारा 73 में, उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(6) यथास्थिति, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का वर्ग ऐसी संपरीक्षा और लेखांकन मानकों को अपनाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएँ :

परंतु ऐसे संपरीक्षा और लेखांकन मानक अधिकथित किए जाने तक, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए संपरीक्षा मानकों को लेखा और संपरीक्षा मानक समझा जाएगा :

परंतु यह और कि बहुराज्य सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक द्वारा अधिकथित लेखा और संपरीक्षा मानकों को, यदि कोई हों, अपनाएंगे।”।

धारा 78 का
संशोधन।

30. मूल अधिनियम की धारा 78 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(1क) यदि केन्द्रीय रजिस्ट्रार का उसके पास उपलब्ध या सरकारी अभिकरण द्वारा उसे प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि किसी बहुराज्य

सहकारी सोसाइटी का कारबार किसी कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, तो वह बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को उसके विरुद्ध किए गए अभिकथनों के बारे में जानकारी देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे आदेश में अन्तर्विष्ट सोसाइटी के बोर्ड के पृष्ठांकन के साथ मामलों के संबंध में लिखित में कोई जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगा :

परंतु यदि केन्द्रीय रजिस्ट्रार का सोसाइटी के स्पष्टीकरण से समाधान नहीं होता है तो वह स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत कार्यालय या अभिकरण के माध्यम से सोसाइटी के गठन, कार्यप्रणाली और वित्तीय स्थिति की जांच करेगा ।

(1घ) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय रजिस्ट्रार, चाहे तो स्वप्रेरणा से या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या अभिकरण के माध्यम से, ऐसी अवधि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए में एक बार, किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के गठन, कार्यप्रणाली और वित्तीय स्थिति की जांच करेगा ।”।

31. मूल अधिनियम के अध्याय 9 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

नए अध्याय
9क का
अंतःस्थापन ।

“अध्याय 9क

शिकायतों का समाधान

85क. (1) केन्द्रीय सरकार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों के संबंध में, उनके निक्षेपों, सोसाइटी के कार्यकरण के साम्यापूर्ण फायदों या संबंधित सदस्य के वैयक्तिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी अन्य मुद्दे के संबंध में उसके द्वारा की गई शिकायतों के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता वाले एक या अधिक सहकारी ऑम्बुडसमैन की नियुक्ति ऐसी रीति में कर सकेगी, जो विहित की जाए ।

सहकारी
ऑम्बुडसमैन ।

(2) सहकारी ऑम्बुडसमैन, शिकायत की प्राप्ति पर, शिकायत की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर जांच और अधिनिर्णयन की प्रक्रिया पूर्ण करेगा और जांच के दौरान सोसाइटी को आवश्यक निदेश जारी कर सकेगा और सोसाइटी ऐसे निदेशों के जारीकरण की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी ।

(3) ऑम्बुडसमैन के किसी निदेश द्वारा व्यथित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी केन्द्रीय रजिस्ट्रार के समक्ष एक मास की अवधि के भीतर, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अपील फाइल कर सकेगी जो अपील का पैतालीस दिनों की अवधि के भीतर विनिश्चय करेगा और केन्द्रीय रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम और आवद्धकर होगा:

परंतु केन्द्रीय रजिस्ट्रार एक मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि सोसाइटी समय पर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण द्वारा निवारित हुई थी ।

(4) ऑम्बुडसमैन, सहकारी सोसाइटियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(5) सहकारी ऑम्बुडसमैन, उपधारा (1) के अधीन जांच करते समय, निम्नलिखित के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं,—

(क) व्यक्तियों को समन करने और उनको हाजिर कराने ;

(ख) शपथ पर उनकी परीक्षा करने ;

(ग) लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों के प्रकटीकरण और उन्हें प्रस्तुत करने; और

(घ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।”।

धारा 86 का
संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 86 में,—

(क) उपधारा (1) में “धारा 79” शब्द और अंकों के पश्चात्, “या धारा 108” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) यथास्थिति, सदस्यों की संख्या या सोसाइटियों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या, धारा 6 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट सदस्यों या सोसाइटियों या व्यक्तियों की संख्या से किसी भी समय कम हो गई है :

परंतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को सदस्यों या सोसाइटियों या व्यक्तियों की संख्या को अपेक्षित संख्या में प्रत्यावर्त्तन करने के लिए छह मास का समय दिया जाएगा ;”;

(ii) खंड (ख) में “सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार कृत्य करना बन्द कर दिया है,” शब्दों के स्थान पर, “सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार कृत्य करना बन्द कर दिया है ; या” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) जहां केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकरण तथ्यों के दुर्व्यपदेशन, मिथ्या या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करके, तात्त्विक तथ्यों को छिपाकर या कपट जिसके परिणामस्वरूप सहकारिता की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा से प्राप्त किया गया था ।”।

(iv) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(5) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बहुराज्य सहकारी बैंक के परिसमापन की दशा में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध भी लागू होंगे ।”।

1949 का 10

(v) उपधारा (6) में, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘परंतु परिसमापन के पूर्व, सोसाइटी से बकाया ऋण वाले संस्थागत उधारदाताओं से अनापत्ति, लिखित रूप में अपेक्षित होगी ।

स्पष्टीकरण—इस परंतुक के प्रयोजन के लिए “संस्थागत उधारदाताओं” अभिव्यक्ति के अंतर्गत बैंक, बचत और ऋण संगम, न्यास कंपनी, वीमा कंपनी, भू-संपदा विनिधान न्यास, पेंशन निधि और वैसी ही चीजें भी हैं ।’।

धारा 94 का
संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 94 के आरंभिक पैरा में, “धारा 83 या” शब्दों और अंकों के पश्चात्, “धारा 84 या” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

34. मूल अधिनियम की धारा 98 में, उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 98 का संशोधन।

“(3) केन्द्रीय रजिस्ट्रार को व्यतिक्रमी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के बैंक लेखाओं को कुर्की कर निम्नलिखित शोध्यों की वसूली करने की शक्ति भी होगी—

(क) धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सहकारी शिक्षा निधि ; या

(ख) धारा 63क के अधीन गठित सहकारी पुनर्वास, पुनर्गठन और विकास निधि ; और

(ग) निर्वाचनों के संचालन के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा उपगत व्यय ।”।

35. मूल अधिनियम की धारा 98 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 98क का अंतःस्थापन।

“98क. केन्द्रीय रजिस्ट्रार, किसी पक्षकार से आवेदन की प्राप्ति पर, धारा 94 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करेगा :

परंतु केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या परिसमापक द्वारा जारी किए गए वसूली प्रमाणपत्र के विरुद्ध कोई पुनर्विलोकन का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक आवेदक संबंधित सोसाइटी को वसूलीय शोध्य की रकम का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर देता है :

परंतु यह और कि पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि वह विनिश्चय या आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के पश्चात् किया जाता है :

परंतु यह भी कि केन्द्रीय रजिस्ट्रार, ऐसा कोई आवेदन ऐसी अवधि के पश्चात् तब ग्रहण कर सकेगा, जब आवेदक उसका यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर आवेदन नहीं करने का पर्याप्त कारण था ।”।

36. मूल अधिनियम की धारा 103 में—

धारा 103 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु सभी उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा उक्त बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को उनके उद्देश्यों, सेवाओं और सदस्यों को ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संबंधित राज्यों तक परिरूद्ध करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों में विभाजित या पुनर्गठन करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की दशा में, ऐसी सोसाइटी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नहीं समझी जाएगी :

परंतु यह और कि पहले परंतुक में वर्णित से भिन्न समझी गई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगी और केन्द्रीय रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी ।”।

37. मूल अधिनियम की धारा 104 में,—

धारा 104 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) “मिथ्या विवरणी देगा” शब्दों के पश्चात्, “या विवरणियां फाइल करने में असफल रहेगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) “दो हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) “दस हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, “पांच हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में,—

(i) “धारा 89 के अधीन हकदार किसी व्यक्ति को” शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा 120 के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति को” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) “दो हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) “पांच हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (4) में,—

(i) खंड (ज) में “किसी व्यक्ति किसी दान की प्रस्थापना करेगा या परितोषण की प्रस्थापना करने का वचन देगा” शब्दों के पश्चात् “या ऐसे दान, वचन या परितोषण को प्राप्त करेगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ज) के उपखंड (iii) के पश्चात् होने वाली, लंबी पंक्ति में “या दोनों से दंडनीय होगा” शब्दों के पश्चात् “और तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचनों को लड़ने से विवर्जित भी किया जाएगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ड) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(5) जहां कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी,—

(क) जिससे निरीक्षण, जांच या अन्वेषण के दौरान स्पष्टीकरण देना या कथन करना अपेक्षित है, संपत्ति, आस्तियों या सोसाइटी के क्रियाकलापों से संबंधित किसी दस्तावेज को नष्ट करती है, विद्रुपित करती है या मिथ्या बनाती है या उसे छुपाती है अथवा उससे छेड़छाड़ करती है या अनाधिकृत रूप से उसे हटाती है अथवा उसे नष्ट करवाती है, विद्रुपित करवाती है या मिथ्या बनवाती है या उसे छुपवाती है या उससे छेड़छाड़ करवाती है या अनाधिकृत रूप से उसे हटवाती है ; या

(ख) धारा 64 अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियों के उपबंधों के उल्लंघन में कोई विनिधान करती है ; या

(ग) सोसाइटी की आस्तियों और संपत्ति में अवैध अभिलाभ करती है ; या

(घ) जमाकर्ता को अवैध हानि करती है,

तो बहुराज्य सोसाइटी का निदेशक बोर्ड या उत्तरदायी अधिकारी, ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होंगे, जो एक मास से कम नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम न होगा, किंतु एक लाख रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होंगे ।”।

(6) जहां बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के निदेशक बोर्ड या अधिकारी ऐसी सोसाइटी से संबंधित मामलों का संव्यवहार करते समय कोई विधिविरुद्ध अभिलाभ प्राप्त करते हैं या व्यक्तिगत विधिविरुद्ध अभिलाभ के लिए सोसाइटी

की किसी आस्ति का उपयोग करते हैं, ऐसे निदेशक या संबंधित अधिकारी ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होंगे, जो एक मास से कम नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक हो सकेगी या जुमाने से जो पांच हजार रुपए से कम न होगा, किंतु एक लाख रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होंगे और ऐसे विधिविरुद्ध अभिलाभ के आगम, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, उनसे वसूल और निश्चेपित किए जाएंगे।

38. मूल अधिनियम की धारा 105 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“105क. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त, न कि उसके अल्पीकरण में होंगे ।”।

39. मूल अधिनियम की धारा 106 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“106. (1) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी के सदस्यों को, सोसाइटी के मामलों और प्रबंधन से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए, एक सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति करेगी और ऐसी सूचना सोसाइटी द्वारा इसकी उपविधियों में विनिर्दिष्ट प्रकटन मानदंडों के अधीन आने वाली सूचना तक सीमित होगी ।

(2) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए, ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, आवेदन करेगा ।

(3) सहकारी सूचना अधिकारी, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या तो सूचना प्रदान करेगा या अस्वीकार करने के कारण विनिर्दिष्ट करते हुए उसे अस्वीकार करेगा ।

(4) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य जिसका आवेदन नामंजूर कर दिया गया सहकारी ऑफिसमैन को ऐसी नामंजूरी की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम और बाध्य होगा ।

106क. प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी मुख्य कार्यपालक, नियमों और इसकी उपविधियों की एक प्रति तथा इसके सदस्यों की एक सूची, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत पते पर सभी सुसंगत समयों पर, किसी प्रभार के बिना, निरीक्षण के लिए रखेगी ।”।

40. मूल अधिनियम की धारा 108 की उपधारा (1) के खंड (i) में, “केंद्रीय रजिस्ट्रार” शब्दों के पश्चात्, “या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति जो सहायक आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो या समतुल्य” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

41. मूल अधिनियम की धारा 109 के खंड (क) में, “सहकारी वर्ष” शब्दों के स्थान पर “वित्तीय वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा
105क का
अंतःस्थापन ।

इस अधिनियम
के उपबंधों का
किसी अन्य
विधि के
अल्पीकरण में
न होना ।

धारा 106 के
स्थान पर नई
धारा का
प्रतिस्थापन ।

सहकारी
सूचना
अधिकारी की
नियुक्ति ।

निरीक्षण के
लिए नियमों
और
उपविधियों की
प्रति ।

धारा 108 का
संशोधन ।

धारा 109 का
संशोधन ।

धारा 116 का
संशोधन।

42. मूल अधिनियम की धारा 116 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

“अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति।”;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1क) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची और तीसरी अनुसूची को संशोधित कर सकती है और तत्पश्चात् ऐसी अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी :

परंतु पहली अनुसूची की दशा में, ऐसी अधिसूचना का उपयोग केवल सूची में सहकारी सिद्धांतों को जोड़ने के लिए किया जाएगा।”।

(iii) उपधारा (2) में, “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, “उपधारा (1) और उपधारा (1क)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

धारा 120 का
संशोधन।

43. मूल अधिनियम की धारा 120 में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(क) क्रियाकलापों, जिनमें बोर्ड के ऐसे विनिश्चय जिन पर सर्वसम्मति नहीं बनी थी, के ब्यौरे भी हैं, की वार्षिक रिपोर्ट ;”;

(ii) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(च) ऐसे कर्मचारियों के बारे में प्रकटन जो बोर्ड के सदस्यों के नातेदार हैं ;

(छ) निदेशक बोर्ड द्वारा किसी संबंधित पक्षकार संब्यवहारों की घोषणा;

(ज) इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना।”।

नई धारा
120क और
धारा 120ख
का
अंतःस्थापन।

इलैक्ट्रानिक
रूप से
आवेदनों,
दस्तावेजों का
फाइल किया
जाना और
निरीक्षण आदि
किया जाना।

44. मूल अधिनियम की धारा 120 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“120क. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, ऐसी तारीख से, जो विहित की जाए, यह अपेक्षा कर सकेगी कि—

(क) ऐसे आवेदन, तुलनपत्र, विवरणी या कोई अन्य विशिष्टियां और दस्तावेज, जिनका इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल या परिदत्त किया जाना अपेक्षित हो, इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल अधिप्रमाणित किए जाएंगे ;

(ख) ऐसा दस्तावेज, सूचना, कोई संसूचना या सूचना, जिसका इस अधिनियम के अधीन तामील या परिदान किया जाना अपेक्षित हो, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में तामील या परिदत्त और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित किया जाएगा ;

2000 का 21

(ग) ऐसे आवेदन, तुलनपत्र, विवरणियां, रजिस्टर, उपविधियां या इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल की गई कोई अन्य विशिष्टियां या दस्तावेज और विवरणियां केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में रखी जाएंगी, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत या अधिप्रमाणित की जाएंगी;

(घ) इलैक्ट्रानिक रूप में रखी गई उपविधियों, तुलनपत्रों, विवरणियों या किन्हीं अन्य विशिष्टियों अथवा दस्तावेजों का, जो इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन निरीक्षण के लिए अन्यथा उपलब्ध हों, ऐसा निरीक्षण किसी व्यक्ति द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप के माध्यम से किया जा सकेगा ; और

(ङ) इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय ऐसी फीसों, प्रभारों या अन्य राशियों को इलैक्ट्रानिक रूप के माध्यम से संदत्त किया जाएगा ।

(2) केंद्रीय रजिस्ट्रार,—

- (क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा ;
- (ख) उपविधियों के संशोधन को रजिस्टर करेगा ;
- (ग) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में परिवर्तन को रजिस्टर करेगा ;
- (घ) किसी दस्तावेज को रजिस्टर करेगा ;
- (ङ) किसी प्रमाणपत्र को जारी करेगा ;
- (च) सूचना को जारी करेगा ; और
- (छ) ऐसी संसूचना को प्राप्त करेगा,

जिनका इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या जारी या अभिलिखित या प्राप्त किया जाना अपेक्षित हो अथवा इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन कर्तव्यों का पालन या कृत्यों का निर्वहन या शक्तियों का प्रयोग करेगा अथवा ऐसा कोई कार्य करेगा, जिसको केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में या ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पालन या निर्वहन या प्रयोग किया जाना या करना इस अधिनियम के अधीन निर्देशित किया गया है ।

120ख. इस अधिनियम के उपबंध, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के निगमन, विनियमन और परिसमापन से संबंधित विषयों के संबंध में लागू होंगे :

परंतु बैंककारी कारबार करने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की दशा में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध भी लागू होंगे ।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का लागू होना ।

1949 का 10

1956 का 1
1969 का 54
2013 का 18
2003 का 12

45. मूल अधिनियम की धारा 121 में उपधारा (1) में, “कंपनी अधिनियम, 1956 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “कंपनी अधिनियम, 2013 और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 121 का संशोधन ।

46. मूल अधिनियम की धारा 123 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) “या उसने कोई ऐसा कार्य किया है” से आरंभ होने वाले और “जिसकी कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी”, से अंत होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

धारा 123 का संशोधन ।

“या उसने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके अंतर्गत कपट, मिथ्या दुर्विनियोग और उसी तरह के कार्य शामिल हैं जो सोसाइटी के या उसके सदस्यों के हितों पर

प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है या उसने धारा 122 के अधीन लोक हित में उसे दिए गए किन्हीं निदेशों का अनुपालन करने में लोप किया है या असफल रहा है या बोर्ड के गठन या कृत्य करने में गत्यावरोध आ गया है या सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्वाचनों को संचालित करने में असफल रहा है तो केन्द्रीय सरकार, बोर्ड को अपने आक्षेपों का, यदि कोई हो, कथन करने का अवसर देने के पश्चात् और आक्षेपों पर, यदि प्राप्त हो, विचार करने पर लिखित आदेश द्वारा, बोर्ड को अतिथित या निलंबित कर सकेगी और ऐसे एक या अधिक प्रशासकों को जिनका सोसाइटी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है जिनको ऐसी अवधि के लिए जो छह मास से अनधिक होगी, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।”;

(ख) विद्यामान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि निर्वाचन कराने में असफलता के आधार पर किसी अधिक्रमण या निलंबन के लिए विनिश्चय करते समय, ऐसी कार्रवाई केवल तभी की जाएगी यदि बोर्ड ने धारा 45 के उपबंधों के अनुसार समय-सीमा के भीतर सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को निर्वाचन कराने की अध्यपेक्षा न दी हो या आवश्यक सहायता प्रदान न की हो।”।

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—धारा 122 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट बहुराज्य सहकारी सोसाइटी” पद से कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसमें सरकारी शेयरधारिता है या सरकार द्वारा लिया गया कोई ऋण या दी गई वित्तीय सहायता अथवा कोई प्रतिभूति है।’।

धारा 124 का संशोधन।

47. मूल अधिनियम की धारा 124 में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(कक) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांत ;”;

(ii) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(जक) वह रीति जिसमें बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का बोर्ड धारा 43 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निर्वाचन संचालित करने के लिए सूचना, दस्तावेज, कार्मिक, निधियां या व्ययों या सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा चाही गई कोई अन्य सहायता प्रदान की जाएगी ;”;

(iii) खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(ट) धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की संरचना;

(टक) धारा 45 की उपधारा (3) के खंड (iii) के अधीन प्राधिकरण के सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव ;

(टख) धारा 45 उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्राधिकरण के सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(टग) धारा 45क के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य ;

(टघ) धारा 45व की उपधारा (2) के अधीन जांच की प्रक्रिया ;

(टड) धारा 45ज की उपधारा (1) के अधीन इसकी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्राधिकरण द्वारा पालन किए जाने वाला समय, स्थान और प्रक्रिया;

(टच) धारा 45झ के खंड (3) के अधीन प्राधिकरण के अन्य कृत्य ;

(टछ) धारा 45ज की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन की रीति ;

(टज) धारा 45 (ज) की उपधारा (6) के अधीन प्राधिकरण द्वारा निर्वाचन करने के लिए व्यय वहन करने की रीति ;

(टझ) धारा 45ट की उपधारा (1) और उपधारा (3) के खंड (क) अधीन रिटर्निंग आफिसरों और पर्यवेक्षकों द्वारा कृत्य के निर्वहन की रीति ;

(टज) धारा 45ट की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन प्रयवेक्षकों के अन्य कृत्य ;”;

(iv) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(डक) धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (ड) के परंतुक के अधीन कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रक्रिया ;” ;

(v) खंड (ण) का लोप किया जाएगा ;

(vi) खंड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(थक) धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन निधि के अनुरक्षण की रीति ;”;

(vii) खंड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(धक) धारा 85क की उपधारा (1) के अधीन सहकारी ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति की ओर ऐसे ऑम्बुड्समैन को शिकायत प्रस्तुत करने की रीति ;

(धख) धारा 85क की उपधारा (3) के अधीन ऑम्बुड्समैन के निदेशों के विरुद्ध सोसाइटी द्वारा अपील फाइल करने की रीति ;

(धग) धारा 85क की उपधारा (5) के खंड (घ) के अधीन अन्य मामले” ;”;

(viii) खंड (ब) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(बक) धारा 104 की उपधारा (6) के अधीन विधिविरुद्ध अभिलाभ की वसूली और उनके आगमों के निक्षेपों की रीति ;

(बख) धारा 106 की उपधारा (2) के अधीन सूचना प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी फीस से आवेदन करने की रीति ;”;

(ix) खंड (भ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(भक) धारा 120क की उपधारा (1) के अधीन इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप में आवेदन, दस्तावेज और इसी प्रकार की चीजें फाइल करने से संबंधित मामलों की बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियों की रीति ;

(भख) धारा 120 (क) की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा इलैक्ट्रानिक प्ररूप में उसमें उल्लिखित मामलों की बाबत कार्यों के निर्वहन या शक्तियों के प्रयोग की रीति ,”;

(घ) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(3) धारा 116 के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम तथा जारी की गई कोई अधिसूचना, बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाएं कि धारा 116 के अधीन बनाया गया नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तथा जारी की गई कोई अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो यथास्थिति, वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा ; किंतु धारा 116 के अधीन बनाए गए उस नियम या जारी की गई किसी अधिसूचना के परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।”।

धारा 125 का
संशोधन ।

48. मूल अधिनियम की धारा 125 में उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से अंसगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :—

परंतु ऐसा कोई आदेश, इस धारा के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।”।

49. मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

तीसरी अनुसूची
का
अंतःस्थापन ।

“तीसरी अनुसूची

[धारा 43(1)(ज) और धारा 116(1क) देखिए]

क्रम सं.	अधिनियम का नाम	अधिनियम संख्यांक
(1)	भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 ;	1899 का 2
(2)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 ;	1934 का 2
(3)	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 ;	1944 का 1
(4)	उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 ;	1951 का 65
(5)	खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 ;	1954 का 37
(6)	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ;	1955 का 10
(7)	प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956;	1956 का 42
(8)	धन-कर अधिनियम, 1957 ;	1957 का 27
(9)	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ;	1962 का 52
(10)	इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 ;	1978 का 43
(11)	रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 ;	1986 का 1
(12)	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ;	1992 का 15
(13)	विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 ;	1992 का 22
(14)	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 ;	1999 का 42
(15)	प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ;	2003 का 12
(16)	धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 ;	2003 का 15
(17)	कंपनी अधिनियम, 2013	2013 का 18 I"।

ABBREVIATIONS

AGM	-	Annual General Meeting
BR Act	-	Banking Regulation Act
CARE	-	Credit Analysis & Research
CEA	-	Cooperative Election Authority
CEF	-	Cooperative Education Fund
CIO	-	Co-operative Information Officer
CRAFICARD	-	Committee to Review Arrangements for Institutional Credit for Agriculture and Rural Development
CRCS	-	Central Registrar of Cooperative Societies
CRISIL	-	Credit Rating Information Services of India Limited
CRRDF	-	Cooperative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund
CSR	-	Cooperative Social Responsibility
DEAF	-	Depositor Education and Awareness Fund
DFS	-	Department of Financial Services
DICGC	-	Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
ICAI	-	Institute of Chartered Accountants of India
ICRA	-	Investment Information and Credit Rating Agency of India Limited
IFFCO	-	Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited
JPC	-	Joint Parliamentary Committee
KRIBHKO	-	Krishak Bharati Cooperative Limited
MD/CEO	-	Managing Director/Chief Executive Officer
MSCS	-	Multi State Cooperative Societies
NABARD	-	National Bank for Agriculture and Rural Development
NAFCARD	-	National Cooperative Agriculture & Rural Development Banks Federation Limited
NAFCUB	-	National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies Ltd.
NAFED	-	National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited
NAFSCOB	-	National Federation of State Cooperative Banks
NCCF	-	National Cooperative Consumers Federation of India
NCDC	-	National Cooperative Development Council
NCUI	-	National Cooperative Union of India
NPA	-	Non Performing Assets
ONICRA	-	Onida Individual Credit Rating Agency of India
PSUs	-	Public Sector Undertakings
RBI	-	Reserve Bank of India
RBI-IOS	-	Reserve Bank of India - Integrated Ombudsman Scheme
RCS	-	Registrar of Cooperative societies
RE	-	Regulated Entities
SAF	-	Supervisory Action Framework
SARFAESI Act	-	The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act
SC/ST	-	Scheduled Castes/Scheduled Tribes
UCB	-	Urban Cooperative Banks
WTD	-	Whole Time Director

COMMITTEE ON MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022**Chairperson — Shri Chandra Prakash Joshi****Lok Sabha**

2. Shri Jagdambika Pal
3. Shri Parbatbhai Savabhai Patel
4. Smt. Poonamben Hematbhai Maadam
5. Shri Ramdas Chandrabhanji Tadas
6. Shri Annasaheb Shankar Jolle
7. Dr. Nishikant Dubey
8. Smt. Sunita Duggal
9. Shri Brijendra Singh
10. Smt. Jaskaur Meena
11. Shri Ram Kripal Yadav
12. Dr. Dhal Singh Bisen
13. Shri Suresh Kodikunnil
14. Shri Manish Tewari
15. Smt. Kanimozhi Karunanidhi
16. Shri Kalyan Banerjee
17. Shri Sri Krishna Devarayalu Lavu
18. Shri Hemant Shriram Patil
19. Shri Dulal Chandra Goswami
20. Shri Chandra Sekhar Sahu
21. Shri Girish Chandra

Rajya Sabha

22. Shri Ghanshyam Tiwari
23. Shri Surendra Singh Nagar
24. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik
25. Shri Ram Chander Jangra
26. *Smt. Rajani Ashokrao Patil
27. Shri Sukhendu Sekhar Ray
28. Shri N.R. Elango
29. Shri Vikramjit Singh Sahney
30. Shri Sujeet Kumar
31. Shri S. Niranjan Reddy

* Suspended w.e.f. 10th Feb, 2023 for the remaining part of 259th session vide Rajya Sabha Secretariat circular No. RS.50/2023-T dated 10 Feb, 2023 under Rule 256 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajya Sabha.

SECRETARIAT

- | | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| 1. Shri J.M. Baisakh | ô | Joint Secretary |
| 2. Shri C. Kalyanasundaram | ô | Director |
| 3. Shri Sumesh Kumar | ô | Deputy Secretary |
| 4. Smt. Rachna Saxena | ô | Deputy Secretary |
| 5. Shri Bharat Lal Meena | ô | Deputy Director |
| 6. Smt. Sonia Gupta | ô | Committee Officer |

INTRODUCTION

I, the Chairperson of the Joint Committee on the Multi-State Co-operatives Societies (Amendment) Bill, 2022 to which the Multi-State Co-operatives Societies (Amendment) Bill, 2022' was referred, having been authorized to submit the Report on their behalf, present this Report with the Bill, as reported by the Joint Committee annexed thereto.

2. The Multi-State Co-operatives Societies (Amendment) Bill, 2022 was introduced in Lok Sabha on 7th December, 2022. The Motion for reference of the Bill to a Joint Committee of both the Houses of Parliament was moved in Lok Sabha by Shri Amit Shah, the Minister of Home Affairs and the Minister of Cooperation, (*Vide Appendix-I*) and concurred by Rajya Sabha on 21st December, 2022 (*Vide Appendix-II*).

3. The Joint Committee was given time till last day of the first week of second part of the Budget Session, 2023 of Parliament to present Report to the House.

4. The Joint Committee held 08 sittings. The Committee took the oral evidence of the representatives of the Ministry of Cooperation, Department of Financial Services and Reserve Bank of India on the provisions contained in the Bill. The representatives of the Ministry of Law & Justice were also present during the sittings of the Committee in order to provide clarifications to the points raised by the Members. The Joint Committee heard the views of the national level federations of cooperative societies and cooperative banks including NABARD. The Joint Committee also heard the views of some of the prominent Multi-State Co-operative Societies. Thereafter, the Joint Committee completed Clause by Clause consideration of the Bill. The Bill as reported by the Joint Committee is appended with the Report. Details of the sittings are given in **Appendix-IV**.

5. The Joint Committee heard the views/ suggestions of 12 stakeholders. Sitting-wise list of witnesses who appeared before the Joint Committee for oral evidence is enclosed (*vide Appendix-V*).

6. The Joint Committee, in their 8th sitting held on 13th March 2023 considered and adopted draft report and authorized the Chairperson to present the report on their behalf.

7. The notes of dissent received from Shri N.R. Elango is appended to the Report (*Vide Appendix-VII*).

8. The Joint Committee wish to express their thanks to representatives of the Ministry of Cooperation, Ministry of Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs), Ministry of Finance (Department of Financial services), Reserve Bank of India and NABARD who appeared before the Joint Committee and placed their considered views to the points raised by the Joint Committee during the sittings held in connection with the examination of the Bill. The Joint Committee would like to express their sincere thanks to representatives of national level federations of cooperative societies, cooperative banks and other Multi-State Co-operative Societies who appeared before the Joint Committee and candidly presented their views about the impact of various provisions of Bill in the sphere of Multi-State Co-operative Societies. The Joint Committee would also like to acknowledge sincere and devoted efforts made by the Officers of Lok Sabha Secretariat by facilitating conduct of all sittings of the Joint Committee smoothly and for preparing the draft Report of the Joint Committee.

SHRI CHANDRA PRAKASH JOSHI

CHAIRPERSON,

JOINT COMMITTEE ON THE

MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022

NEW DELHI;

13 March, 2023

22 Phalgun 1944 (SAKA)

REPORT CHAPTER-I

Genesis and features of the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 and its amendment Bill, 2022

1.1 A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise. Cooperatives are based on the values of self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity and solidarity. In the tradition of their founders, cooperative members believe in the ethical values of honesty, openness, social responsibility and caring for others.

Origin and brief history of Cooperative laws in India

1.2 The cooperative movement in India traces its origin to the agriculture and allied sector and was originally evolved as a mechanism for pooling the people's meager resources with a view to providing to them the advantages of the economies of scales. The first attempt to institutionalize cooperatives began with the enactment of the Cooperative Credit Societies Act, 1904 the scope of which was subsequently enlarged by the more comprehensive Cooperative Societies Act of 1912. Under the Government of India Act, 1919, the subject of Cooperation was transferred to the then Provinces which were allowed to enact their own cooperative laws. Under the Government of India Act, 1935, cooperatives remained a provincial subject. Presently, the item "Cooperative Societies" is a State subject under entry 32 of the State List of the Constitution of India. In order to administer the operations of cooperative societies where membership was from more than one province, the Government of India enacted the Multi-Unit Cooperative Societies Act, 1942 which was subsequently replaced by the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984. under entry 44 of the Union List of the Constitution of India.

Multi State Cooperative Societies Act (MSCS Act), 2002

1.3 An Act to consolidate and amend the law relating to co-operative societies, with objects not confined to one State and serving the interests of members in more than one State, to facilitate the voluntary formation and democratic functioning of co-operatives as people's institutions based on self-help and mutual aid and to enable them to promote their economic and social betterment and to provide functional autonomy, was being felt necessary by the various cooperative societies, federations of various cooperative societies as well as by the Government. In this regard, a Committee under the Chairmanship of Choudhary Brahm Perkash was set up. The report of the said Committee suggested a model cooperative law. Based on the report, it was proposed to replace the existing Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 by a proposed legislation, namely, **the Multi State Cooperative Societies Bill, 2000** which was introduced in the Parliament. The bill having been passed by both the Houses of Parliament received the assent of the President on 3rd July 2002 and it came on the Statute Book as The Multi State Cooperative Societies Act 2002 (39 of 2002).

Constitution (Ninety-seventh Amendment) Act, 2011

1.4 Constitution (Ninety Seventh Amendment) Act, 2011 incorporated Part IX B in the Constitution of India. The part deals with the provisions relating to Cooperative Societies. All Central and State Cooperative Acts were to be aligned with this Constitutional Amendment within one year of its commencement i.e. by 15.02.2013. However, Hon'ble High Court of Gujarat struck down Part IX-B of the 97th Constitutional Amendment on 22.04.2013 as it required ratifications of the majority State Legislatures as per the specific provision of Article 368(2) of the Constitution of India. Subsequently, Government of India filed a Civil Appeal against this judgement in the Hon'ble Supreme Court of India which in its majority judgement dated 20.07.2021 pronounced that Part IXB of the Constitution of India is operative only insofar as it concerns Multi State Co-operative Societies both within the various States and in the Union territories of India.

Need for amendment of Multi State Cooperative Societies Act, 2002

1.5 In view of the above developments, Ministry of Cooperation, which is the nodal Ministry dealing with the subject of Cooperation at Central level, has stated that MSCS Act needs to be amended to bring it in consistence with the Constitution (Ninety-Seventh) (Amendment) Act, 2011, to plug loopholes in the existing legislation and to strengthen governance in the Multi State Cooperative Societies, in accordance with the following Cooperative Principles, namely:

Voluntary and Open Membership;
Democratic Member Control;
Member's Economic Participation;
Autonomy and Independence;
Education, Training and Information;
Co-operation among Co-operatives; and
Concern for Community.

1.6 According to the Ministry of Cooperation, need has been felt to amend the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 to address some instances of malfunctioning noticed in some of the Multi State Cooperative Societies. For example, there have been

complaints in some of the Multi State Cooperative Societies about financial embezzlements, delay and disputes regarding holding elections, biased selection of auditors, and favoritism in recruitment, lack of active participation of members, etc. Developments over the years also necessitated required changes in the Act so as to strengthen the cooperative movement in the multi-state cooperative societies. Moreover, there is a need to proactively implement various reforms e.g., Ease of Doing Business by making registration process easier, allowing digital registration, making membership more vibrant and active, providing Information Officer for increasing transparency, appointing Ombudsman for redressal of member grievances, etc.

1.7 Ministry of Cooperation also submitted that provisions for number of directors, their terms, cooption of members on the board, reservation of weaker sections in the board of directors, election authority, supersession and suspension of board on certain grounds, auditing, convening of general body meetings, right to get information and various offences and penalties have already been included in the Constitution for the Multi State Cooperative Societies through the Constitution (Ninety-Seventh Amendment)Act 2011. Hence, these provisions have to be incorporated in the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 by way of suitable amendments. Many of these reforms have already been included in many state laws. Election Authority for conducting Cooperative Elections has already been established in many States. Provisions for active participation of members have also been included in the laws of various States.

1.8 As per the information furnished by the Ministry of Cooperation, there is also a need to create a fund out of contribution made by profitable multi state cooperative societies for revival of sick multi-State cooperative societies. Further, it is necessary to incorporate the constitutional provisions relating to multi-State cooperative societies carrying on banking activity by stating that in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up, multi-State co-operative societies shall be governed by the provisions of the Multi State Cooperative Society Act, provided that the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 shall also apply to a multi-State co-operative society carrying on the business of banking.

Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022

1.9 The Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill 2022 was introduced in Lok Sabha on 7 December, 2022. The Bill aims to amend certain provisions of Multi- State Co-operative Societies Act, 2002. The Minister of Cooperation has stated in the Statement of Objects and Reasons appended with the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022 that the Bill *inter alia* provides for the following, namely:

- (i) to amend section 41 of the Principal Act so as to reform the composition of board of a multi-State co-operative society;
- (ii) to substitute section 45 of the Principal Act so as to establish an Authority to be known as the "Co-operative Election Authority" which shall consist of a Chairperson, a Vice-Chairperson and members not exceeding three to be appointed by the Central Government. The said Authority is proposed to be established with a view to bring electoral reforms in co-operative sector;
- (iii) to insert a new section 63A relating to "establishment of the Co-operative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund" for revival of "sick multi- State co-operative societies";
- (iv) to insert a new section 70A relating to "concurrent audit" for multi-State co-operative societies having an annual turnover or deposit of more than the amount as determined by the Central Government;
- (v) to insert a new Chapter IXA relating to "redressal of complaints" and for this purpose, the Central Government may appoint one or more "Co-operative Ombudsman" with a territorial jurisdiction for inquiring into the complaints made by the members;
- (vi) to amend section 104 of the Principal Act so as to increase the monetary penalties on multi-State co-operative societies for contravention of the provisions of the Act and the rules made there under;
- (vii) to substitute section 106 of the Principal Act relating to "appointment of Co-operative Information Officer" to provide information relating to affairs and management of the multi-State co-operative society to the members of such society; and insert a new section 120A relating to "Filing of applications, documents, returns, statements, statement of accounts in electronic form.

Joint Committee on Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022

1.10 The Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 has been referred by the Parliament to this Joint Committee on Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 for examination and report. Motion in this regard was adopted by Lok Sabha on 20 December, 2022 and the same was concurred by Rajya Sabha on 21 December, 2022. Joint Committee is comprised of 31 Members with 21 Members from Lok Sabha and 10 Members from Rajya Sabha. Shri Chandra Prakash Joshi, MP (Lok Sabha) is the Chairperson of the Committee. The Committee took the oral evidence of the representatives of the Ministry of Cooperation, Department of Financial Services, Reserve Bank of India and Ministry of Law & Justice on the provisions contained in the Bill. The Committee also heard the views of national level federations of Cooperative Societies and cooperative banks. The Committee also heard the views of some of the prominent Multi-State Cooperative Societies. The following Chapter deals with the Clause-by-Clause examination of the Bill by the Committee.

CHAPTER-II

CLAUSE BY CLAUSE EXAMINATION ON THE MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022

Clause No. 1

Short title and commencement

2.1 Clause 1 of the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 states as under:ö

ö1. (1) This Act may be called the Multi State Co-Operative Societies (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.ö

RBI's request for an overarching proviso after Clause(b) of Section 2 of the Principal Act

2.2 During the course of examination of Amendment Bill, the RBI in their submission before Committee has opined that proposed amendments to the MSCS Act will have bearing on some provisions of the Banking Regulation Act. Further, though BR Act is a special law, the possibility of having different interpretations cannot be ruled out. As per them it might not be possible to foresee all possible conflicts that could arise in future and therefore, insertion of an overarching proviso after clause (b) of Section 2 as given below may be inserted:-

öProvided that in case of a co-operative bank, the application of provisions of this Act shall be subject to the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and the Rules, Regulations, Directions or Instructions issued there under by the Reserve Bank from time to time.ö

Comments of Ministry of Cooperation

2.3 The Ministry of Cooperation was asked to furnish its comments on the above suggestion made by RBI. In their written submission, the Ministry furnished the following comments:-

öThe proposed provision 120B is as per Article 243ZI and the third proviso to Article 243 ZL of the Constitution.

During the process of Inter-ministerial consultation, Department of Financial Services (DFS) vide their letter dated 04.10.2022 informed that proposed revised Bill is largely aligned with BR Act and thus, the DFS agrees with and supports the amendment Bill. Further, DFS will make suitable amendments in the BR Act so that its provisions are in consonance with the Constitution. The same was also stated by Secretary (DFS) in the JPC meeting held on 19.01.2023.

As per the prevailing practice, Banking license by RBI is given to entities incorporated under different laws such as Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts under which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for all such entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of MSCS Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up: Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply.ö

Observation/recommendation of the Committee

2.4 The Committee deliberated upon the proposal made by RBI and reply given by the Ministry of Cooperation. The Committee concluded that with insertion of section 120B in the amended Act and the assurance of the Department of Financial Services to make suitable amendments in the Banking Regulation Act, 1949, the concern of RBI will be duly taken care of. Thus, the Committee decided that there is no need to insert an overarching proviso after clause (b) of section 2 of the Principal Act.

Clause No. 2

Provision in the Principal Act

2.5 “Section3: Definitions

In this Act, unless the context otherwise requires,ö

(a) öarea of operationö means the area from which the persons are admitted as members;ö

Amendment Proposed in the Bill

- 2.6 In the Multi-State Co-operative Societies Act,2002 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 3, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:
- (aa) Authority means the Co-operative Election Authority established under sub-section(1) of section 45;

Rationale behind the proposed amendment

- 2.7 In line with the Article 243ZK(2)of the Constitution.

Electoral reforms

Insertion of definition of Coop. Election Authority.

Observation/recommendation of the Committee

- 2.8 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stake holders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the changes proposed under the Clause, which was in line with the article 243ZK(2) of the Constitution.

Provision in the Principal Act

- 2.9 3(d)Central Registrar means the Central Registrar of Cooperative Societies appointed under sub-section (1) of section 4 and includes any officer empowered to exercise the powers of the Central Registrar under sub-section (2) of that section;

2.10 Amendment Proposed in the Bill

- 3(d) to be substituted by the following:

Central Registrar means Central Registrar of Cooperative Societies appointed as per clause(f) of article 243ZH(f) of the constitution read with subsection (1) of section 4 and includes any officer empowered to exercise the powers of the Central Registrar under sub-section(2) of that section.

Rationale behind the proposed amendment

- 2.11 Modification of Definition of Central Registrar to bring it in line with the Article 243ZH(f) of the Constitution.

Clause 2 section 3 (d)

- 2.12 When asked to explain meaning of Central Registrar and the need to amend relevant section, the Secretary, Ministry of Cooperation in evidence deposed:

The Central Registrar is only one. Section 4(1) says that The Government may appoint such other persons. It says that A Central Registrar may appoint a person to be a Central Registrar of Cooperative Societies. This is in line with the Constitution. Now, 4(1) says that ...and may appoint such other persons as it may think fit to assist the Central Registrar. They are not Central Registrar.

This provision in the definition has been taken from the Constitution, where the definition of a Registrar, Article 243zhf, which says that Registrar means the Central Registrar appointed by the Central Government in relation to the Multi-State Cooperative Societies. That is one aspect. The Act that was there earlier, along with the Section that we are reading, says that the Central Government may appoint a person one person to be the Central Registrar of cooperative societies and may appoint such other persons as it may think fit to assist the Central Registrar. The point is, anybody who is appointed to assist the Central Registrar does not become the Central Registrar. Rest comes the fiduciary part of it, other articles which were referred to

- 2.13 When asked to explain contradiction between Central Registrar and inclusion of any Officer empowered to exercise the power of the Central Registrar, the Secretary, Ministry of Cooperation further elaborated as follows:

The Central Government may by notification direct that any powers exercisable, which is part of perhaps any other law that there could be one Registrar of Companies and the Central Government can authorize any other person to exercise certain powers of the Registrar of Companies. Similarly, depending on the load or exigency of work which is part of literally any law, and it says similarly, and there is no contradiction, either with the Constitution or 4(1), 4(2) says that the Central Government may by notification direct that any power exercisable by the Central Registrar, it does not mean that that person becomes the Central Registrar, can exercise the power of the Central Registrar under this Act, and that too it has been circumscribed by saying that other than the power of registration of the multi-State cooperative society, because perhaps that is the primary function, shall in relation to such society there are 1,500 societies there are certain powers with the Registrar which by way of exigencies required to be delegated by the

Central Registrar to some other person and such matters may be specified in the notification that which powers of the notification of the Central Registrar will be exercised by that person so notified, be exercised also by an officer. It doesn't mean that person becomes the Central Registrar...ö

Provision in the Principal Act

2.14 “(f) öcooperative bank ömeans a multi-state cooperative society which under takes banking business;ö

Amendment Proposed in the Bill

2.15 ö(b) after clause(f), the following clause shall be inserted, namely:ö

-(fa) öCo-operative Ombudsman ömeans the Ombudsman appointed by the Central Government under section 85A;ö

Rationale behind the proposed amendment

2.16 öInsertion of definition of Cooperative Ombudsman to be appointed by the Central Government under section 85A.ö

Observation/recommendation of the Committee

2.17 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause, which is in line with the Article 243ZH(f) of the Constitution.

Provision in the Principal Act

2.18 ö(i) öcooperative yearö, in relation to any multi-state cooperative society or class of such societies, means the year ending on the 31st day of March of the year and where the accounts of such society or class of such societies are, with the previous sanction of the Central Registrar, balanced on any other day, they are ending on such day;ö

Amendment Proposed in the Bill

2.19 öIn clause (i), for the words öco-operative yearö, the word öco-operative or financial yearö shall be substituted:ö

Rationale behind the proposed amendment

2.20 öTo cover all cases as some MSCS use word öfinancial yearö and some öco-operative yearöö

Examination by the Committee

2.21 During briefing on the provisions contained in the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, the Committee enquired about the logic behind the definition of Cooperative Year and Financial Year separately, when both end on 31st March. In this regard, the Ministry of Cooperation stated as under in its post briefing replies:

öIn the existing MSCS Act 2002, section 3(i) provides for definition of öco-operative yearö which means the year ending on the 31st day of March of the year and where the accounts of such society or class of such societies are, with the previous sanction of the Central Registrar, balanced on any other day, the year ending on such day.

In the amendment Bill vide clause 2 (section 3(i)), the word öfinancial yearö is being inserted alongside öco-operative yearö to remove any ambiguity and to cover all cases as some MSCS use word öfinancial yearö and some öco-operative yearöö

Suggestions by stakeholders

2.22 NABARD has suggested to use the word öFinancial Yearö in place of öCooperative Yearö or öFinancial Yearö

Observation/recommendation of the Committee

2.23 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation. Since the Cooperative Year and Financial Year denote same period of time i.e. first April of one year to thirty first March of the next year, the Committee have felt that both Cooperative Year and Financial may not be mentioned in the Bill. The Committee, therefore, recommend that the proposed amendment to the Bill may be read as follows:—

“In clause (i), for the words “co-operative year”, the word “financial year” shall be substituted.”

Provision in the Principal Act

2.24 ö(s) önotificationö means a notification published in the Official Gazette;ö

Amendment Proposed in the Bill

2.25 öIn clause (s), after the words öOfficial Gazetteö, the words ö**and the expression ‘notified’ with its cognate meanings and grammatical variations shall be construed accordingly**ö shall be inserted:ö

Rationale behind the proposed amendment

2.26 öDefinition of notification has been expanded to cover all possibilities.ö

Observation/recommendation of the Committee

2.27 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 3**Provision in the Principal Act****2.28 “Section7: Registration**

(2) The application for registration shall be disposed of by the Central Registrar within a period of four months from the date of receipt thereof by him.

(3) Where the Central Registrar refuses to register a multi-state cooperative society, he shall communicate, within a period of four month from the date of receipt of the application for registration, the order of refusal together with the reasons thereof to the applicant or applicants, as the case may be:

Provided that no order or refusal shall be made unless the applicants have been given a reasonable opportunity of being heard:

Provided further that if the application for registration is not disposed of within a period of four months specified in sub-section (2) or the Central Registrar fails to communicate the order of refusal within that period, the application shall be deemed to have been accepted for registration and the Central Registrar shall issue the registration certificate in accordance with the provisions of this Act and the rules made there under.ö

Amendment Proposed in the Bill

2.29 ö(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Central Registrar may register a multi-State co-operative society if the aggregate value of the paid-up capital and provision of reserves along with liquidity, exposure and other prudential norms specified in the bye-laws of the proposed multi-State co-operative society in the business of thrift and credit are in accordance with such guidelines as may be prescribed:

Provided that the multi-State co-operative societies registered before the commencement of the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2022 shall meet such norms within a period of five years from the date of commencement of the said Act:

Provided further that if the liquidity, exposure, prudential and other parameters of the multi-State credit society do not meet such norms within the period mentioned above, the Central Registrar shall have powers to issue such directions as it deems appropriate to such society to take relevant action:

Provided also that in the case of multi-State co-operative bank, the aggregate value of the paid-up capital and provision of reserves along with liquidity norms provided in the bye-laws shall be such as may be laid down by the Reserve Bank from time to time.

(3) The application for registration shall be disposed of by the Central Registrar within a period of three months from the date of receipt of such application by him:

Provided that the Central Registrar may, for rectification of mistakes, if any, in the application, extend the period of three months with such further period, for reasons to be recorded in writing, not exceeding two months on the request of the applicant.

(4) Where the Central Registrar refuses to register a multi-State co-operative society, he shall communicate the order of such refusal stating therein the reasons for such refusal, to the applicant within the period specified in sub-section (3):

Provided that no order of refusal shall be made, unless the applicant has been given an opportunity of being heard:

Provided further that if the application for registration is not disposed of within the period specified in sub-section (3) or the Central Registrar fails to communicate the order of refusal within the said period, the application shall be deemed

to have been accepted for registration and the Central Registrar shall issue the registration certificate in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.^o

Rationale behind the proposed amendment

“Strengthening Governance and Transparency

- 2.30 No existing prudential norms are there for thrift and Credit MSCS leaving scope for malpractices. The amended provision will ensure financial discipline. Already existing credit societies will get 5 years to meet these norms. Multi- State co-operative banks will continue to follow RBI norms.

Ease of doing business

- 2.31 This would expedite registration process and ensure ease of doing business. In case of deficiencies in the registration applications, additional time will be provided for rectification in place of rejecting the application.^o

Examination by the Committee

- 2.32 During briefing on the proposals made in the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, the Committee pointed out that no limit has been prescribed for the MSCS for prudential norms under Section 7(2 & 3), the Ministry of Cooperation in its written reply stated that In the existing Act, there is no provision for prudential norms for credit MSCS, thus leaving scope for malpractices. The amendment in section 7 provides for prudential norms which will be applicable for all MSCS involved in business of credit and thrift. These will be specified in the related rules. The amended provision will ensure financial discipline. Multi- State co-operative banks will continue to follow RBI norms.
- 2.33 During oral evidence of the representatives of Reserve Bank of India (RBI) on the provisions contained in the Bill, the Committee asked about the RBI's views on the proposal made in Clause 3 of the Bill and also the manner in which multi-state cooperative societies or multi-state cooperative banks engaged in thrift and credit regulated at present. In this regard, RBI in its post evidence reply has stated as under:^o

^oAll Multi-State Cooperative Societies are not regulated by Reserve Bank of India. Only the Multi-State Cooperative Societies engaged in banking activities are licensed and regulated by RBI under various provisions of Banking Regulation (BR) Act, 1949. The provisions of Chapter V of the BR Act, 1949 are applicable to a cooperative society carrying on the business of banking, which includes a multi- state cooperative society carrying on the business of banking also. Thus, the present status of regulation of multi-state cooperative societies engaged in the field of banking and thrift is as per the provisions of Chapter V of the BR Act and RBI is bestowed with regulatory powers. Further, all amendments made in Chapter V of the BR Act, 1949, including the amendments made in 2020 are also applicable to a multi-state cooperative society carrying on the business of banking. Subsequent to the BR (Amendment) Act, 2020, the applicability of BR Act was extended to areas like shareholding, management, audit, amalgamation/reconstruction and liquidation (winding up) of cooperative banks, in addition to capital and liquidity related provisions. In the absence of any provision in the proposed amendment in MSCS Act, requiring consequential amendments to other extant governing Acts such as BR Act, 1949, certain contradictions arise from the proposed amendments.

Under the proposed section 7(2) of the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022, the capital and liquidity provisions of MSCS will be governed by the Central Registrar for MSCS, while for Multi-State Cooperative Banks, the same will be as per the norms laid down by RBI. Unlike a cooperative society which collects resources from its members to be put to use for the benefit of those members only, a cooperative bank's main and substantial source of funds are non-member/public deposits. Therefore, in order to protect the interest of depositors, who are not part of the governance of the cooperative bank, ensure sufficiency of capital as a going concern and to ensure that a bank has sufficient liquid assets including cash to meet short-term liabilities, the capital and liquidity related regulations have been rightly emphasized to be the remit of RBI under 3rd proviso to section 7(2).

The BR (Amendment) Act, 2020 was intended to address the issue of ‘dual regulation’ in cooperative banking sector, without sacrificing the principle of proportionality or conformance to cooperative principles. As intended by the BR (Amendment) Act 2020, RBI has adopted a convergent but proportionate and risk-based regulatory approach for cooperative banks so that unfair regulatory arbitrage does not exist as compared to other category of banks as the same can be detrimental not only to the interest of the cooperative sector and their depositors but to the banking system as a whole. Further, experience shows that main reason for failure of several urban cooperative banks (UCBs) in the past have been due to governance or management generated issues which is one of the current focuses of regulation and supervision of UCBs. In view of the above, it is felt that BR Act needs continued primacy over any other law including MSCS Act for banking related activities undertaken by cooperative societies.^o

Suggestions by stakeholders

2.34 In regard to proposal in Clause of the Bill which proposes to substitute sub sections (2) and (3) of Section 7 of the Principal Act on Registration, NAFCUB has suggested that nothing contained in this substitution shall apply to MSCS which are holding license from RBI for doing banking business and the provisions of Banking Regulation Act (BR Act) shall prevail as also the directions of RBI. It has been pointed out to Committee that Multi-State Cooperative Society Banks are facing dual regulation of RBI as well as Ministry of Cooperation and amendments proposed may blur the line of regulation even if the clause contains the compliance towards RBI guidance. Hence, they requested exemption to UCBs from these provisions as BR Act and RBI Act takes care of concerns expressed.

Comments of the Ministry of Cooperation

2.35 Third proviso to proposed Section 7 explicitly mentions that in the case of multi-State co-operative bank, the aggregate value of the paid-up capital and provision of reserves along with liquidity norms provided in the bye-laws shall be such as may be laid down by the Reserve Bank from time to time.

2.36 As per the prevailing practice, Banking license by RBI is given to entities incorporated under different laws such as Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts under which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for all such entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of MSCS Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up: Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply. Therefore, the proposed provisions are as per Constitution and do not require any change.

2.37 When asked to explain rationale of amendment proposed in Clause 3 of the amendment Bill and Section 7 of the principal Act, the representative of Ministry of Cooperation stated as under:—

“We have done this to strengthen the governance and transparency. Para 2(i) is not for multi-state cooperative banks; it is for cooperative societies which are doing credit and other things. For banks, this is the last para which clearly says that. Credit societies are not regulated by RBI. For them, the Registrar will prescribe what should be the liquidity norms. Since hon. Member has raised another point and it will come again and again, I would like to give a summary of it. As per the Constitution, the incorporation, regulation and winding up have been given to the Central Registrar or the Central Government for multi-state cooperative societies. As for the regulation part, first a company is registered, it meets RBI norms and then it may get banking license. Similarly, a cooperative society will get registered, it will have bylaws. There are regulations in this Act that these many Board members should be there, this much qualification of Board members should be there. These are all part of regulations which the cooperative society will have to meet. Once all this is done, the cooperative society may desire to go to RBI and take a banking license. The moment it takes a banking license, the provisions of BR Act shall also apply. It is also clearly stated in section 120B of this Act. Therefore, it is very clear that regulation will always be dual, in the sense that how many directors are there, how the shareholders' meetings take place, how the voting is done, etc. This is part of regulation as far as the DNA of a cooperative society is concerned. If the cooperative society wants to do banking also, then it will have to additional conform to the BR Act. If you recollect, the Finance Secretary had also came here and he said that the Government is also amending the BR Act in line with the Constitution.”

Observation/recommendation of the Committee

2.38 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 4

Provision in the Principal Act

“Section 10: Bye-laws of multi-state cooperative societies:

2.39 (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such bye-laws may provide for all or any of the following matters, namely:

the name, address and area of operation of the society;

Amendment Proposed in the Bill

2.40 (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such bye-laws may provide for all or any of the following matters, namely:

the name, address (**including e-mail address**)^o and area of operation of the multi-State co-operative society;^o

Rationale behind the proposed amendment

“Ease of doing business

2.41 Email address to be part of address for faster and efficient channel of communication with the multi-state coop. societies.^o

Observation/recommendation of the Committee

2.42 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 5

Provision in the Principal Act

2.43 “Section 14: Change of address

Every multi-state cooperative society shall have principal place of business and an address registered in the manner prescribed to which all notices and communications may be sent.^o

Amendment Proposed in the Bill

2.44 “Section 14: Address

Every multi-state cooperative society shall have principal place of business and an address **including e-mail address** registered in the manner prescribed to which all notices and communications may be sent.^o

Rationale behind the proposed amendment

2.45 “Ease of doing business

Email address to be part of address for faster and efficient channel of communication with the multi-state coop. societies.^o

Observation/recommendation of the Committee

2.46 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to insert a “,” after the word address in the proposed amendment. Hence, the proposed amendment will read as under:—

“Every multi-state cooperative society shall have principal place of business and an address, including e-mail address registered in the manner prescribed to which all notices and communications may be sent.”

Clause No. 6

Provision in the Principal Act

2.47 “Section 17: Amalgamation or transfer of assets and liabilities, or division of multi- state cooperative societies

(9) Where a resolution passed by a multi- state cooperative society under this section involves the transfer of any assets and liabilities, the resolution shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be a sufficient conveyance to vest the assets and liabilities in the transferee without any further assurance.^o

Amendment Proposed in the Bill

2.48 ^oAfter sub-section (9), the following sub- section shall be inserted:

(10) Any co-operative society may, by a resolution passed by majority of not less than two-thirds of the members present and voting at a general meeting of such society, decide to merge into an existing multi-State co-operative society:

Provided that such resolution shall be subject to the provisions of the respective State Co-operative Societies Act for the time being in force under which such co-operative society is registered.^o

Rationale behind the proposed amendment

2.49 ^oIn the existing Act, there is a provision for division of MSCS into two or more MSCS and into two or more State Cooperative Societies. Further, there is also provision for conversion of a State coop. society into an MSCS.

Now this proposed provision will provide for merger of a State cooperative into MSCS. However, such merger shall be subject to respective statecoop. laws & with a resolution passed by 2/3rd of the members.^o

Examination by the Committee

2.50 During briefing on the provisions of the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, in regard to the new provision for merger of State Cooperative Society into MSCS, when the Committee suggested that it should have a condition of working in the same line of business, the Ministry of Cooperation submitted in a written reply as under:ö

öIn the Existing MSCS Act, 2002, Section 17 relates to Amalgamation or transfer of assets and liabilities, or division of multi- state cooperative societies into two or more MSCS or State Cooperative Societies. Further, there is an existing provision for conversion of a state cooperative society into an MSCS under section 22 of MSCS Act, 2002.

In the amendment Bill, vide clause 6, a new sub-Section 17(10) is being proposed for inclusion in the existing Section 17 to allow for merger of a State Cooperative Society into an existing MSCS subject to the respective State Cooperative Acts and a resolution by 2/3rd of their members. This will help the existing State Cooperative Societies to improve their viability and achieve economies of scale by merger into MSCS.

In the existing Section 17 and Section 22, no condition of working in the same line of business is provided for amalgamation and division of MSCS or for conversion of State Society into MSCS. The suggestion of Hon'ble MP of placing the restriction of working in the same line of business for allowing merger would need to be further examined, as it might restrict flexibility and diversification.ö

2.51 When it was enquired whether the proposed amendment (in Section 17) is against the federal structure, the Ministry of Cooperation in its written reply commented as below:ö

öNo Sir. In the Existing MSCS Act, 2002, Section 17 relates to Amalgamation or transfer of assets and liabilities, or division of multi- state cooperative societies into two or more MSCS or State Cooperative Societies. Further, there is an existing provision for conversion of a state cooperative society into an MSCS under section 22 of MSCS Act, 2002.

A new sub-Section 17(10) is being proposed for inclusion in the existing Section 17 to allow for merger of a State Cooperative Society into an existing MSCS subject to the respective State Cooperative Acts and a resolution by 2/3rd of their members. This will help the existing State Cooperative Societies to improve their viability and achieve economies of scale by merger into MSCS.

Since the merger is subject to State Cooperative Acts only, it is not in violation of federal structure.ö

2.52 RBI stated in its post evidence replies that the proposed amendments have implications on the regulatory effectiveness of RBI in regard to Multi State Cooperative Banks are concerned and highlighted the below submission as one of the implications:ö

The existing provision in MSCS Act enables amalgamation between two or more MSCS. The proposed insertion of sub-section (10) under Section 17 enables any cooperative society to merge into an existing multi-state cooperative society, provided that such resolution shall be subject to the provisions of the respective State Cooperative Societies Act for the time being in force under which such cooperative society is registered. BR Act, 1949 as amended vide BR(Amendment) Act 2020 provides power to RBI to sanction the voluntary amalgamation between two UCBs under Section 44A in accordance with the procedure specified thereunder and to frame scheme for compulsory amalgamation under Section 45 to be sanctioned by the Central Government. Accordingly, RBI has issued RBI (Amalgamation of Urban Cooperative Banks) Directions, 2020 containing the policy and procedure for amalgamations of UCBs. Section 44A is a code in itself and no further approval under the cooperative law is required for amalgamation. Further, under Section 45 of BR Act, 1949, the Central Government is empowered to sanction a scheme prepared by RBI for compulsory amalgamation or reconstruction for UCBs. However, existing Section 18 of the MSCS Act empowers Central Registrar to prepare scheme of amalgamation or reorganisation of a cooperative bank when an order of moratorium has been made by the Central Government under Section 45(2) of BR Act. Absence of any provision for requirement of prior approval of RBI for amalgamation of a cooperative bank may create conflicting situation. Here also a reference is invited to Section 2(gg) of the DICGC Act 1961.

Suggestion of stakeholders

2.53 NAFCARD have suggested to allow merger of an existing cooperative society into an existing Multi State Cooperative Society having similar objectives and functions.

Observation/recommendation of the Committee

2.54 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 7

Provision in the Principal Act

2.55 “Section 19: Promotion of subsidiary institution

(2) Any subsidiary institution promoted under sub-section (1) shall exist only as long as general body of the multi-state cooperative society deems its existence necessary. Provided that a multi-state cooperative society while promoting such a subsidiary institution, shall not transfer or assign its substantive part of business or activities undertaken in furtherance of its stated objects. Explanation—For the purposes of this section,—

- (a) an institution shall be deemed to be a subsidiary institution if the multi-state cooperative society,—
 - (i) controls the management or board of directors or members of governing body of such institution; or
 - (ii) holds more than half in nominal value of equity shares of such institutions; or
 - (iii) if one or more members of such multi-state cooperative society, hold whether by themselves or together with subsidiary institution or their relatives, as the case may be, the majority of equity shares in this institution;—

Amendment Proposed in the Bill

2.56 —In section 19 of the principal Act, in the Explanation, in clause (a),—

- (i) in sub-clause (ii), the word “or” occurring at the end shall be omitted; sub-clause (iii) shall be omitted.—

Rationale behind the proposed amendment

2.57 Strengthening Governance and Transparency

—This will ensure transparency in the governance of cooperatives and reduce chances of only a few members benefitting from investing in a subsidiary institution where the members or their relatives hold majority of Shares.—

Observation/recommendation of the Committee

2.58 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 8

Provision in the Principal Act

2.59 “Section 22: Conversion of a cooperative society into a multi-state cooperative society

5(c) The Registrar of Cooperative Societies referred to in clause (b) shall thereupon make an order directing that the society had, as from the date of registration by the Central Registrar, ceased to be a society under the law relating to cooperative societies in force in that state.—

Amendment Proposed in the Bill

2.60 —In section 22 of the principal Act, in sub-section (5), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

- (c) the co-operative society shall be deemed to have been de- registered under the law relating to such co-operative society for the time being in force in that State, from the date of the certificate as issued by the Central Registrar and forwarded to such co-operative society, along with a copy of the registered amendment under sub-section (3).—

Rationale behind the proposed amendment

2.61 Ease of doing business

—This will reduce delay and ensure ease of doing business in cooperatives. RCS of the States are, in any case, consulted before conversion is approved as per section 22 of the Act.—

Examination by the Committee

2.62 During briefing on the Bill, the Committee asked about the action taken on a State Society which has committed a fraud in case of deemed de-registration of a State Cooperative Society on conversion into MSCS. In regard to the above, the Ministry of Cooperation in a written reply stated, —In the existing section 22 of the MSCS Act, 2002, Concerned State Registrar of Cooperative societies (RCS) is consulted at the time of conversion into MSCS and if any complaint against the society is found, the concerned RCS should take action against the society.—

Suggestion of stakeholders

2.63 NAFCARD has requested to add an additional clause to Section 22 of the Principal Act regarding conversion of cooperative societies into multi state cooperative societies as 22(6) as under:ö

ö..State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank after conversion into Multi State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank shall continue to follow the provisions in the State Cooperative Act or State Cooperative AgricultureRural Development Bank Act as may be applicable for recovery of loans issued on the security of registered mortgage of land or other properties..ö

Reason:- Such a provision will obviate the likely hurdles in loan recovery due to absence of specific provisions in the principal Act to recover long term mortgage loans.

Observation/recommendation of the Committee

2.64 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 9

Provision in the Principal Act

2.65 Section 26: Nominal or associate members of society

öA multi-state cooperative society may, if provided in its bye-laws, admit a person as nominal or associate member:

Provided that no such nominal or associate member shall be entitled to subscribe the shares of such society or have any interest in the management thereof including right to vote, elect as a director of the board or participate in the general body meetings.ö

Amendment Proposed in the Bill

2.66 öIn section 26 of the principal Act,ö

- (i) in the proviso, the words öbe entitled to subscribe the shares of such society orö shall be omitted;
- (ii) after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely:ö

öProvided further that nominal or associate member can be issued nonvoting shares which may not confer any interest in the management of the multi- State co-operative society including right to vote, to be elected as a director of the board or participate in the general body meetings:

Provided also that in case of multi-State co-operative bank, such shares shall be issued in accordance with the instructions issued by the Reserve Bank from time to time.ö

Rationale behind the proposed amendment

2.67 Enabling raising of funds by Co-operative sector

öThis will ensure enhancement of capital base of MSCS & lead to their growth.RBI has already allowed this for Co-operative banksö

Examination by the Committee

2.68 During briefing on the Bill, the Committee observed that in case of provision of non-voting shares for raising capital the mechanism to control malpractices from raised capital should be there. In regard to the above observation, the Ministry of Cooperation in its written reply submitted as follows:ö

öIn the existing MSCS Act, 2002 under Section 26 there is a bar on issuing shares to the Nominal or Associate members. This condition restricts growth of Capital base of the MSCS.

In the amendment bill, a provision vide clause 9 (Section-26) is being proposed for issuance of non-voting shares to nominal/associate members without voting rights, interest in management and right to be elected.

This will enable MSCS to increase their Capital base. RBI has already permitted the same for cooperatives banks vide its circular dated 08.03.2022. There are other provisions existing in the present Act as well as proposed in the Amendment Bill to prevent financial malpractices by the MSCS.ö

Comments of RBI

2.69 During oral evidence of representatives of RBI on the proposals made in the Bill, the Committee asked for the comments of RBI on the above proposal. RBI in a written reply, furnished the following comments:—

öThe amendment proposes that Nominal or Associate members of a multi-State cooperative society can be issued non-voting shares but shall not have any right in the management thereof i.e., no right to vote, to be elected as a Director of the Board or participate in general body meetings. The amendment further proposes a proviso that öProvided also that in case of multi-state cooperative bank, such shares shall be issued in accordance with the instructions by the Reserve Bank from time to timeö.

It may be mentioned that under Section 12 of the BR Act read with Section 56 (AACs), RBI has power to issue instructions, specify conditions and to approve issuance of such shares by a cooperative bank. RBI has, accordingly, vide circular DOR.CAP.REC.92/09.18.201/2021-22 dated March 8, 2022 issued guidelines to UCBs on öIssue and regulation of share capital and securities - Primary (Urban) Cooperative Banksö, which *inter-alia*, contains guidelines on non-voting shares. RBI has also issued guidelines to UCBs on Issuance of Preference Shares including its terms of issue vide öMaster Circular - Prudential Norms on Capital Adequacy - Primary (Urban) Cooperative Banks (UCBs)ö dated April 1, 2022.

The MSCS (Amendment) Act, 2022 has not proposed any amendment to the BR Act on this aspect. The proposed amendment to Section 26 clearly specifies that in case of multi-state cooperative bank, such shares shall be issued in accordance with the instructions issued by RBI from time to time. Further, the Bill has proposed a new Section 105A which states that the provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of, any other law for the time being in force. Therefore, as far as MSCS undertaking banking activity is concerned, it may need to be amply provided in the Bill that the provisions of BR Act shall be primarily applicable to multi-state UCBs on types of capital instruments.ö

Observation/recommendation of the Committee

- 2.70 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause includingsuggestions made by the stakeholders and the rationale reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.**

Clause No. 10

Provision in the Principal Act

- 2.71 Section 28: Members not to exercise rights till due payment made

öNo member of a multi-state cooperative society shall exercise the rights of a member, unless he has made the payment to the society in respect of membership, or has acquired such interest in the society, as may be specified in the bye-laws.ö

Amendment Proposed in the Bill

- 2.72 öNo member of a multi-state cooperative society shall exercise the rights of a member, unless he has made the payment of all dues to the multi-State co-operative society including the payment in respect of membership or has availed such minimum level of product or services as specified in the bye-laws, or has acquired such interest in the society, as may be specified in the bye-laws.ö

Rationale behind the proposed amendment

- 2.73 öIn line with Article 243ZO(2) of the Constitution.

This will ensure payment of all dues to the society and will define the term ösuch interestö explicitly and promote active membership.ö

Observation/recommendation of the Committee

- 2.74 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.**

Clause No. 11

Provision in the Principal Act

- 2.75 “Section 29: Disqualification for member of a multi-state cooperative society**

No person shall be eligible for being a member of a multi-state cooperative society if ö

(b) he used for two consecutive years the services below the minimum level specified in the bye-laws; or ö

Amendment Proposed in the Bill

- 2.76 öIn section 29 of the principal Act, for clause(b), the following clause shall be substituted, namely:ö
 (b) he fails to use the minimum level of the products or services as specified in the bye-laws for two consecutive years; or.ö

Rationale behind the proposed amendment

- 2.77 This is in line with Article 243ZO(2) of the Constitution.

öThere is a need to promote active membership. Hence word öproductö has been included to disqualify such members who do not use minimum services/products.ö

Examination by the Committee

- 2.78 During briefing by the representatives of the Ministry of Cooperation on the provisions contained in the Bill, a suggestion was made that active membership provision should be changed to attendance in 3 out of 5 general meetings for contesting elections as proposed in section 29 of amendment Bill. In its written reply, the Ministry of Cooperation stated in this regard as under:ö

öThe existing provision of section 29 of the Act relating to disqualification for members provides that no person shall be eligible for being a member of an MSCS if he has not attended three consecutive general meetings of the MSCS and such absence has not been condoned by the members in the general meeting. If a person is disqualified as member, he cannot contest election.

Article 243ZO(2) of the Constitution provides for ensuring active membership by incorporating minimum requirement of attending meeting by the members. Hence, the proposed amendment in Section 45(j) for attending not less than three consecutive general meetings for being eligible for contesting election is as per the existing provision of Section 29. Therefore, if the absence is condoned by the General Body, the member will be eligible to contest in the election.

- 2.79 During briefing when it was further enquired, How can a member be disqualified from election without being disqualified as member, the Ministry of Cooperation stated as below in its written reply:ö

öIn the existing MSCS Act, 2002, Section 29 provides for disqualifications for being a member of the MSCS,

Further, Section 43 of the existing MSCS Act, 2002 separately provides for disqualifications for being a member of the board.

The disqualifications for being a board member are much more elaborate and stricter as compared to disqualifications for being a member of the MSCS as the Board Members are entrusted with the responsibility of overall management of the MSCS.ö

- 2.80 When asked about meaning of öminimum level of the products or servicesöas proposed in Clause 11, Section 29 of Bill, the Secretary, Ministry of Cooperation stated as under during the Clause by Clause examination of the Bill:—

öí Clause 11, Section 29 the principal Act flows out of the Constitution. In addition to products, we are also saying that a minimum level of services also should be taken by the members. It is flowing out of the Article 243ZO(2). I will give you an example. IFFCO has now made a large base of cooperative societies. It will be buying nano fertilizers. It has started producing on its consumer base. In every society the AGM, the Board will decide that everybody should buy at least this much. That is how the products come. And, similarly services. It could be grains, storage, services. It could be products and services both. They should not be the dummy members, putting just capital and neither use products nor use services. Perhaps, that is why in the Constitution, it is clearly written that if you have to be a member, you have to be an active member and for that you have to define the level of products and servicesí ö

Observation/recommendation of the Committee

- 2.81 **The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.**

Clause No. 12

Provision in the Principal Act

2.82 “Section 30: Expulsion of members

(2) No member of the multi-state cooperative society, who has been expelled under sub-section (1), shall be eligible for re-admission as a member of that society, for a period of **one year** from the date of such expulsion.ö

Amendment Proposed in the Bill

2.83 ^o(2) No member of the multi-state cooperative society, who has been expelled under sub-section (1), shall be eligible for re-admission as a member of that society, for a period of **three years** from the date of such expulsion.^o

Rationale behind the proposed amendment

2.84 “Strengthening of Monitoring Mechanism

This has been proposed as re-admission needs to be made more stringent to discourage members from acting against interests of MSCS.^o

Observation/recommendation of the Committee

2.85 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 13

Provision in the Principal Act

2.86 “Section 35: Redemption of shares

(1) Shares held in a multi-state cooperative society by any of the authorities referred to in clauses (c) to (g) of sub-section (1) of section 25 shall be redeemable in accordance with the bye-laws of such multi-state cooperative society and in a case where the byelaws do not contain any provision in this regard, in such manner as may be agreed upon between the multi- state cooperative society and such authority.

(2) The redemption of shares referred to in sub-section (1) shall be on the face value of the shares.^o

Amendment Proposed in the Bill

2.87 ^o35. (1) The shares of the authorities referred to in clauses (c) and (d) of sub-section (1) of section 25, held in multi State co-operative societies,^o66

(a) shall not be redeemed without the prior approval of such authorities; and

(b) may be redeemed in such manner as may be agreed upon between the multi-State co-operative society and such authorities.

(2) The shares held in a multi-State co-operative society by any of the authorities referred to in clauses (e) to (g) of sub-section (1) of section 25, shall be redeemed in accordance with the bye-laws of such multi-State co- operative society and in case, where the bye-laws do not contain any provision, in such manner as may be agreed upon between the multi-State co-operative society and such authorities.

The redemption of shares referred to in sub-sections (1) and (2), shall be on the face value of shares.^o

Rationale behind the proposed amendment

2.88 ^oRequirement of prior approval of government has been included to protect government interest and to prevent any unilateral surrender of government equity.^o

Examination by the Committee

Suggestions from stakeholders

2.89 On the issue of proposed amendment by clause 13 section 35 regarding redemption of share provides for ~~approval of Authority~~, the Committee have received representations from National Cooperative Union of India (NCUI) and National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies Ltd.(NAFCUB) that such provision may act as hindrance to the societies in becoming self sufficient. Further, it has been proposed that instead of this, societies which has obtained fund and non-fund based support from Government shall not be allowed to redeem the share of Government unless such fund or facilities has been returned.

Comments of RBI

2.90 On this issue, the RBI has also submitted that Clause 13 of the Bill (Section 35 of the Principal Act) which stipulates redemption of share capital with prior approval of such authorities and in a manner agreed upon by MSCS and such authorities does not entirely conform to the provisions of Section 12(1) of the BR Act which authorizes Reserve Bank to specify conditions in such cases. This may also affect the extant instructions issued to UCBs on the subject.

2.91 Further, RBI in its post evidence replies stated that certain amendments may have implications on the regulatory effectiveness of RBI in regard to Multi State Cooperative Banks. In regard to redemption of shares, RBI has stated that

the amendment to Section 35 of the MSCS Act, 2002 specifies that the shares held by Government shall not be redeemed without the prior approval of such authorities; and may be redeemed in the manner agreed upon between the MSCS and such authorities. Further, shares held in MSCS by Central Government, State Government, National Cooperative Development Corporation, any Government Corporation and any Government company respectively, shall be redeemable in accordance with the bye-laws of such MSCS, and in case bye-laws do not contain any provision, in such manner as may be agreed upon between the MSCS and such authorities. The terms of withdrawal of same category of share capital should ideally be same for both government and non-government investors or possibly little more stringent for government investors in order to develop confidence in the cooperatives. Section 12(2)(ii) of BR Act specifies that a cooperative bank shall not withdraw or reduce its share capital, except to the extent and subject to such conditions as the Reserve Bank may specify in this behalf. Accordingly, Reserve Bank vide circular on “Issue and regulation of share capital and securities - Primary (Urban) Cooperative Banks” dated March 8, 2022, had specified certain pre-conditions for refund of share capital of cooperative banks to avoid reduction in capital due to redemption of shares by any member, to ensure regulatory compliance and to provide for depositor protection. In view of the above, to the extent of Government shareholding in Multi-State urban cooperative banks, the proposed amendments may have implications on capital position and can potentially interfere at the regulatory stipulations on capital adequacy and conservation.

Comments of Ministry of Cooperation

- 2.92 The proposed provision in section 35 is to protect government interest and to prevent any unilateral surrender of government equity as has happened in some past cases.

Only shares held by State or Central government require permission before redemption. There is no restriction on redemption of ordinary shares which are not held by the Government. Redemption of shares shall be on face value in the line with the cooperative principles.

This provision will not become hindrance to self-sufficiency & future growth of the MSCS. This will protect government's interest.

Regarding the point raised by RBI, the proposed section 120B already clarifies that the provisions of MSCS Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up: Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply.

Observation/recommendation of the Committee

- 2.93 **The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.**

Clause No. 14

Provision in the Principal Act

- 2.94 **“Section 39: Annual general meeting of general body**

(1) The board of every multi-state cooperative society shall, within such period as may be prescribed, and not later than six months after the close of the corresponding year, call the annual general meeting in the manner prescribed for the purpose of:

(o) election of members of the board, if any.;

Amendment Proposed in the Bill

- 2.95 In section 39 of the principal Act, in sub-section (1), after clause (o), the following clause shall be inserted, namely:
- (p) appointment of auditor.;

Rationale behind the proposed amendment

- 2.96 In line with the Article 243ZM(3) of the Constitution. Appointment of auditor is included in the agenda of AGM.;

Examination by the Committee

Suggestions from stakeholders

- 2.97 National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies (NAFCUB) in its power point presentation before the Committee on 20 January, 2023 submitted that the appointment of statutory auditors now needs prior approval of RBI on some stringent guidelines. Thus, this eliminates any malpractice. As a result, the Board should be empowered to appoint statutory or other auditors so as to bring ease of doing business with the approval of RBI. For other MSCS, this may be retained if found essential.

Observation/recommendation of the Committee

2.98 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestion made by the stakeholder and the rationale reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 15

Provision in the Principal Act

2.99 “Section 41: Board of directors

(3) The board shall consist of such number of directors as may be specified in the bye-laws:

Provided that the maximum number of directors in no case shall exceed twenty-one: Provided further that the board may co-opt two directors in addition to twenty-one directors specified in the first proviso:

Provided also that the functional directors in the national cooperative societies shall also be the members of the board and such members shall be excluded for the purpose of counting the total number of directors specified in the first proviso.ö

Amendment Proposed in the Bill

2.100 (3) The board shall consist of such number of directors not exceeding twenty-one, as may be specified by the bye-laws, out of which one Member shall be Scheduled Caste or Scheduled Tribe and two shall be women in the board of multi-state cooperative society consisting of individuals and having members from such class or category of persons:

öProvided that the board may co-opt as Members of the board having experience in the field of banking, management, co-operative management and finance or specialisation in any other field relating to the objects and activities undertaken by such multi-State co-operative society:

Provided further that the number of such co-opted Members shall not exceed two in addition to twenty-one directors specified in this sub-section.

(4) The co-opted directors referred to in sub-section (3) shall not have the right to vote in any election of the office bearers or be eligible to be elected as office bearers of the board.

(5) The functional directors in a multi-State co-operative society shall also be the members of the board and such directors shall be excluded for the purpose of counting the total number of directors specified in sub-section (3).

(6) No director of a multi-State co-operative society shall, as a director, be present in the discussion of, or vote on, any contract or arrangement entered into, or to be entered into, by or on behalf of such society, if he or his relative is directly or indirectly concerned or interested in such contract or arrangement and no relative of any of the sitting directors of the multi-State co-operative society shall be recruited as employee including the Chief Executive of that society.

Explanation.öFor the purposes of this sub-section, the term örelativeö with reference to an individual, includesö

- (a) spouse;
- (b) father (including step father);
- (c) mother (including step mother);
- (d) son (including step son);
- (e) sonös wife;
- (f) daughter (including step daughter);
- (g) daughterös husband;
- (h) fatherös father;
- (i) fatherös mother;
- (j) motherös father;
- (k) motherös mother;
- (l) sonös son;

- (m) son& son&s wife;
- (n) son& daughter;
- (o) son& daughter&s husband;
- (p) daughter& son;
- (q) daughter& son&s wife;
- (r) daughter& daughter;
- (s) daughter& daughter&s husband;
- (t) brother (including step brother);
- (u) brother& wife;
- (v) sister (including step sister);
- (w) sister& husband; and
- (x) Hindu undivided family.

(7) Any director of the board who violates the provision of sub-section (6), shall be disqualified for being a member of the board and deemed to have vacated his office from the date of such meeting of the board as is referred to in the said sub-section and such proceedings shall be deemed to be void.ö

Rationale behind the proposed amendment

2.101 öIn line with the Article 243ZJ(1) of the Constitution.

Reforms in the Composition of Board, Meetings & Membership.

2.102 This would ensure representation of SC/ ST and women in the board of society. The proposed amendment relating to co-opted directors will bring professionalism in cooperatives management.

Strengthening Governance and Transparency

2.103 This will reduce nepotism and malpractices.ö

Examination by the Committee

(i) Representation to SC/ST communities in the Board of MSCS

2.104 During briefing by the representatives of the Ministry of Cooperation on the provisions contained in the Bill, there was a suggestion that the reservation in the Board for SC and ST communities should be on rotation basis. There was also another suggestion that more seats should be reserved for women and minimum one seat each for SC and ST communities. In this regard, Ministry of Cooperation stated in its written reply that in the existing MSCS Act, 2002, there is no provision that provides for reservation of seats for SC/ST and women members in the Board of MSCS. The new provision is being proposed in Section 41(3) to bring the Act in line with Article 243ZJ of the Constitution which provides for reservation for SC/ST/Women. The reservation for SC/ST and women members shall be applicable to MSCS which consists of individuals and have members from such class or category of person. This provision is to ensure representation of weaker section of the society in the Board.

2.105 Further, a suggestion has been received from NAFSCOB that one Member shall be from Other Backward Class in the Board. The Committee have also received suggestion to include one SC and one ST members in place of one member from SC or ST Communities. When asked to submit views on these suggestions, the Ministry of Cooperation in its written reply stated as under:ö

öIn the existing MSCS Act, 2002, there is no provision that provides for reservation of seats for SC or ST and women members in the board of MSCS. The new provision is being proposed in Section 41(3) to bring the Act in line with Article 243ZJ of the Constitution which provides for reservation for one SC or ST and two women members in the board of MSCS.ö

(ii) Coopted Members in the Board

2.106 During briefing on the provisions contained in the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, the Committee suggested that there should be a team of specialist for the MSCS. In this regard, the Ministry of Cooperation stated in its written reply as below:-

öIn the existing MSCS Act, 2002, Section 41 provides for maximum of two co-opted Directors in the board of Directors. However, qualification and experience for such co-opted Directors are not defined in the Act. In the amendment Bill, Sub-Section 41(3) is a new insertion in which the board may co-opt as Members of the board having experience in the field of banking, management, co-operative management and finance or specialisation in any other field relating to the objects and activities undertaken by such MSCS. The new provision proposed in Section 41(3) is in line with Article 243ZJ of the Constitution.ö

- 2.107 NAFCUB in its submission before the Committee has stated that a provision is being made to co-opt members of the board having in the field of banking, management, cooperative management and finance etc. and expressed its view that the provision should also be made to co-opt the members from the field of öTechnologyö as well. In this regard, views of the Ministry of Cooperation was sought. The Ministry in its written reply stated as below:-

“The proposed amendment is in line with Article 243ZJ(3) of the Constitution. The word -specialization in any other fieldö used in the formulation gives sufficient flexibility to co-opt members from the field of technology as well.ö

(iii) Inclusion of MD/CEO within the purview of restriction on recruitment of relatives of a sitting director

- 2.108 During the briefing on the Bill, to the query of the Committee regarding need of inclusion of MD/CEO within the purview of the restrictions as provided under Section 41(6) about restriction on recruitment of relatives of a sitting director as an employee, the Ministry of Cooperation responded as under:—

öí í In the existing MSCS Act, 2002, Section 41 deals with the composition of Board of Directors. There is no bar under this section on recruitment of relatives of a sitting Board member. This leaves scope for nepotism & favouritism in recruitment of employees.

In the amendment bill, clause 15 (Sub-Section 41(6)) which is a new insertion bars the recruitment of relatives of a sitting Director of Board. This amendment is being proposed to prevent nepotism & favouritism in recruitment of employees. This step will increase transparency.

CEO/MD works under the general superintendence, directions and control of the Board as per Section 52 of the MSCS Act, 2002. The suggestion relating to extending the bar on recruitment of relatives to employees of MSCS including MD/CEO would need further examinationí ö

- 2.109 Further, NAFCUB in its submission to the Committee has stated that the definition of the term öRelativeö has been widened as compared to RBI circular dated 05.02.2021 regarding loans and advances to Directors and their relatives. According to it, definition of relative should be kept as per the above RBI circular. When asked to submit views on this suggestion of NAFCUB, the Ministry of Cooperation has submitted as under:-

öThe definition of -relativesö as per RBI circular dated 05.02.2021 mentioned by NAFCUB is specifically regarding loans and advances to Directors and their relatives by the UCBs. However, definition of relative defined under section 41 of the principal Act (clause 15 of the Bill) is in relation to restriction on recruitment of employees and interested party transaction in all MSCS. This wider definition of relatives has been proposed to curb nepotism and favouritism in MSCS.ö

- 2.110 In regard to the proposed amendment, NAFCUB has further submitted to the Committee that many sections refer to terms like öappointment of directorö and Whole time Director (WTD) which are made applicable to cooperative banks where board members are not appointed but elected. Unless the applicability of various provisions of Banking Regulation (Amendment) Act 2020 are reviewed, notwithstanding progressive amendments in MSCS Act, the multi state cooperative banks will continue to suffer. A better solution could be inclusion of a well drafted separate chapter for the multistate cooperative banks on the lines of Section 56(AACS) of BR Act, ensuring that cooperative character is preserved and there are no ambiguities in applicability of provisions of the Constitution, MSCS Act and BR Act. Views/comments of the Ministry of Cooperation were sought on the above suggestion of NAFCUB. In its written reply, the Ministry stated as follows:ö

öÉAs per existing provision of section 45 of MSCS Act, 2002 Board of Directors are elected by the members.

ÉAs per the prevailing practice, Banking license by RBI is given to entities incorporated under different laws such as Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts under which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for all such entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of MSCS Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up: Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply.

This is in line with Article 243ZI and the third proviso to Article 243 ZL of the Constitution. Therefore, there is no need to include a separate chapter.ö

2.111 During the briefing on the Bill, it was suggested that in case of casual vacancies in the board, members should be nominated only. In this regard, the Ministry of Cooperation in its post briefing reply stated as follows:-

öIn the existing MSCS Act, 2002, there is no provision for filling of casual vacancies in the board of an MSCS through nomination.

Filling of casual vacancy through nominations is a new provision i.e. 45(J)(5) in the amendment Bill which is in line with Article 243ZJ (2) of the Constitution. This will prevent the need of frequent elections in case of casual vacancies.

A limit has been kept at 1/3rd of total elected directors for filling casual vacancies by nomination in order to avoid fraudulent practices.ö

Suggestion from stakeholders

2.112 NABARD has suggested for filling up of casual vacancies upto 1/3rd of the total strength of the Board on nomination basis. They have advised to review this and restrict it to 1/4th or 1/5th of the total Board Strength.

2.113 In regard to the proposal that no relative of sitting Director to be recruited as employee, NABARD has stated that no such blanket bar may be (b) Recruitment Process (c) Disclosure regarding existing employees who are relatives of members of board (Sec 120) stipulated as it amounts to denial of opportunity to the relatives of sitting Directors.

Observation/recommendation of the Committee

2.114 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders and the rationale reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 16

Provision in the Principal Act

2.115 “Section 43. Disqualifications for being a member of Board

(1) No member of any multi-state cooperative society or nominee of a member, society or a national cooperative society shall be eligible for being chosen as, or for being, a member of the Board of such multi-state cooperative society or a national cooperative society, or of any other cooperative society to which the multi-state cooperatives society is affiliated, if such member—

(a) has been adjudged by a competent court to be insolvent or of unsound mind;

í í í í í

(h) is a person against whom any amount due under a decree, decision or order is pending recovery under this Act.

43(2) A person shall not be eligible for being elected as member of board of a multi-state cooperative society for a period of five years if the board of such multi-state cooperative society fails—

(a) to conduct elections of the board under section 45; or

(b) í .

(c) to prepare the financial statement and present the same in the annual general meeting.ö

Amendment Proposed in the Bill

2.116 öIn section 43 of the principal Act,öö

(i) in sub-section (1),öö

(a) in clause (a), after the words öto be insolventö, the words öor has been a director of an insolvent companyö shall be inserted;

(b) in clause (h), after the words öunder this Actö, the words öor under any other Act specified in the third Scheduleö shall be inserted;

(c) after clause (n), the following clause shall be inserted, namely:ö

(o) **has been disqualified under sub-section (7) of section 41.:**

(ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:ö (1A) A member who has been a

director of the board of any multi-State co-operative society or co-operative bank, where such board has been superseded, shall not be eligible to be elected as director of the board of another multi-State co-operative society or co-operative bank for a period of five years, from the date of such supersession:

Provided that no member shall be declared ineligible under this sub-section unless an opportunity of being heard has been given to such member by the Central Registrar and declaration for ineligibility shall be made only after ascertaining that the member concerned has been responsible by acts of omission or commission leading to such supersession.;

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:ö

ö(a) to provide information, documents, personnel, funds or expenses or any other assistance as required by the Co-operative Election Authority for conducting elections under this Act in such manner as may be prescribed;ö;

(b) in clause (c), for the words ögeneral meetingö occurring at the end, the words ögeneral meeting; orö shall be substituted;

(c) after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:ö

ö(d) to make contribution to the co-operative education fund referred to in clause (b) of sub-section

(1) of section 63 or the Co-operative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund established under section 63A; or

(e) to file annual return specified in section 120 within the time specified therein; or

(f) to get the audit of the society conducted within six months of the close of the financial year to which such account relate:

Provided that before taking any action under this sub- section, he shall be given an opportunity of being heard by the Central Registrar.ö

Rationale behind the proposed amendment

2.117 “Reforms in the Composition of Board, Meetings & Membership

Additional grounds for disqualification needed to strengthen governance. With the addition of third schedule, Board of Directors would need to pay any outstanding dues under the Acts in the third schedule to avoid disqualification.

This will ensure that directors responsible for supersession of an MSCS earlier are debarred for directorship of another MSCS for five years.

This will ensure discipline in conduct of elections, making contribution to CEF/ CRRDF (proposed), etc.ö

Examination by the Committee

2.118 During briefing on the proposals made in the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, the Committee observed that non filing of annual return should not be one of the reasons for disqualification of a director as it is responsibility of employee or society {Section 43(2)}. In this regard, the Ministry of Cooperation in its post-briefing reply submitted as follows:ö

öIn the existing MSCS Act, 2002 there is no provision for disqualification on account of non-filing of annual return. This leads to poor compliance and many of the MSCS fail to submit their annual returns. This Section 43(2) is a new insertion, as per which a person would not be eligible for being elected as a Board member for 5 years if the Board of such MSCS fails to file annual return. He will be given opportunity of hearing before disqualification. This would ensure better compliance of filing of annual returns by all the MSCS leading to transparency and better monitoring of functioning by the Central Registrar. It is the overall responsibility of Board to run affairs of the MSCS. The Board collectively and Director individually are responsible.ö

2.119 Further during the course of the briefing, it was pointed out that there should be clarity on period of disqualification of board members. In this regard, the Ministry of Cooperation stated as under in its written reply:-

öIn the amendment Bill, the new insertion of section 43(1A) is being introduced as additional grounds for disqualification for being a member of the Board. Under the proposed new insertion as Section 43(1A), the director of an MSCS where such board has been superseded and the member concerned has been ascertained to be responsible for supersession shall not be eligible to be elected as director of the board of another MSCS/ Bank for a period of five years, from the date of such supersession. Opportunity of hearing will be given to the member concerned by CRCS. This will ensure that directors responsible for supersession of an MSCS earlier are debarred from director ship of another MSCS for five years.ö

Suggestions by stakeholders

- 2.120 NCUI in its power point presentation to the Committee has stated that the proposed clause is arbitrary and against the principles of natural justice hence needs to be omitted otherwise the word ‘another’ may be substituted with ‘such’ as the period of five years is reasonable period for punishment. NAFED and NCCF have also suggested that the word ‘another’ may be substituted with the word ‘that’. When asked to submit views on these suggestions, the Ministry of Cooperation submitted in its written reply as follows:–

‘As per proposed clause 16 (section 43(1A)), no members shall be declared ineligible under this sub-section unless an opportunity of being heard has been given to such member by the Central Registrar and declaration for ineligibility shall be made only after ascertaining that the member concerned has been responsible by acts of omission or commission leading to such supersession. Therefore, provision is in accordance with principles of natural justice. Further, once the responsibility of the concerned director for act of omission or commission has been ascertained, debarment from directorship in another MSCS/ banks will help in ensuring that such acts of omission or commission or fraud are not repeated elsewhere by them.’

NAFCUB has also submitted that such an ineligibility should not be there in case the said Director has given dissenting note or has taken effective steps to remove the ambiguity resulting in supersession of the Board. Ministry of Cooperation was asked to submit its views on this suggestion. The Ministry in its written reply stated, ‘The fact that any director has given any dissenting note or taken effective steps would be considered appropriately during the hearing while taking a decision under this section.’

- 2.121 As per Clause 16 (i)(b) of the Bill, (sub section (1) of Section 43 of the Principal Act), in clause (h), after the words ‘under this Act’, the words ‘or under any other Act specified in the third Schedule’ shall be inserted. In this regard, NCUI has stated that this provision is against the spirit of 97th Constitutional (Amendment) Act 2011 and also against the Principles of Cooperatives as the cooperative has a distinct character working for the cause of poor people. Hence, the Cooperative Act cannot have parity with any other Act. Therefore, the proposed additional words ‘or under any other Act specified in the third Schedule’ needs to be deleted. In this regard, Ministry of Cooperation in its written reply submitted as below:-

‘The proposed clause 16 will help in strengthening governance in cooperatives by ensuring greater compliance of law and realization of dues.’

- 2.122 NAFCUB has stated that such ineligibility should not be there in case the said Director has given dissenting note or has taken effective steps to remove the ambiguity resulting in supersession of the Board.

- 2.123 When asked to explain rationale of proposal for exclusion of Director of Insolvent company from holding the post of Director in multi-state cooperative society despite the fact that insolvency laws does not put bar on director of insolvent company from becoming the director in another company, the secretary, Ministry of Cooperation stated as under during the clause by clause examination of the Bill as below:–

‘..Yes, we are talking about that only because unlike in companies, the Cooperative Society that have large number of members, it is not as easy to wind it up or it is not as easy to merge it. So, if a person who has got a bad track-record and if he enters a Cooperative Society, then it is going to be detrimental to the Cooperative sector. Hence, the ineligibility was extended from one year to three years, disqualification, etc. because the Cooperative sector, particularly majority of the cases for which Cooperative sector has got a bad name, we have seen statistically that it happens like this.

- 2.124 Further elaborating on the issue, the secretary, Ministry of Cooperation stated as under:–

‘The word ‘insolvency’ and the word ‘Bankruptcy Code’, these all are applicable to companies, which have got certain immunities or which have got certain privileges. As far as Cooperative structure is concerned, it has got different immunities and different privileges. Therefore, in Cooperative sector we will like to have people who have not had business failures. Otherwise, they will run up with depositors Rs. 80,000 crore or Rs. 20,000 crore. Why do we need such people?..’

Observation/recommendation of the Committee

- 2.125 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 17

Provision in the Principal Act

2.126 “45. Elections of members of board

- (1) The conduct of elections to the board of a multi- state cooperative society shall be the responsibility of the existing board.
- (2) The election of members of board shall be held by secret ballot in the manner as may be prescribed.
- (3) The election of the members of the board shall be held in the general meeting of the members of the multi-state cooperative society.
- (4) The elected members of the board shall, if the bye-laws of such society permit, be eligible for re- election.
- (5) The term of office of the elected members of the board shall be such, not exceeding five years from the date of elections, as may be specified in the bye- laws of a multi-state cooperative society:

Provided that elected members shall continue to hold office till their successors are elected or nominated under the provisions of this Act or the rules or bye-laws and assume charge of their office.

- (6) Where the board fails to conduct election of the members of board, the Central Registrar shall hold the election within a period of ninety days from the date when such election became due.
- (7) No person shall be eligible to be elected as a member of the board of a multi-state cooperative society unless he is a member of the general body of that society.
- (8) The expenses for holding election by the Central Registrar shall be borne by the multi-state cooperative society.
- (9) The Central Government may make rules generally to provide for or to regulate matters in respect of election of members of the board.º

Amendment Proposed in the Bill

2.127 ºFor section 45 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:º

-45. (1) The Central Government shall, by notification, establish an Authority to be known as the Co-operative Election Authority which shall consist of a Chairperson, a Vice-Chairperson and Members not exceeding three to be appointed by the Central Government on the recommendation of the Selection Committee consisting of such persons as may be prescribed.

- (2) The head office of the Authority shall be at such place as may be notified by the Central Government.
- (3) A person shall not be qualified for appointment as a,º
 - i. Chairperson of the Authority unless he held the post of Additional Secretary to the Government of India or equivalent rank;
 - ii. Vice-Chairperson of the Authority unless he held the post of Joint Secretary to the Government of India or equivalent rank; and
 - iii. Member unless he fulfils such qualification and experience as may be prescribed.

(4) The Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority shall hold office for a period of three years from the date on which they enter upon their office or until they attain the age of sixty-five years, whichever is earlier and they shall be eligible for re-appointment:

Provided that in case of appointment of a Government servant as the Chairperson, Vice- Chairperson or a Member, he shall be treated as an ex officio Member and he shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is a Chairperson, Vice-Chairperson or Member.

(5) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson, Vice-Chairperson and Members of the Authority, other than the ex officio Member, shall be such as may be prescribed.

45A. The Chairperson of the Authority shall have powers of general superintendence and directions in the conduct of the affairs of the Authority and he shall, in addition to presiding over the meetings of the Authority, exercise and discharge such other powers and functions as may be prescribed.

45B. (1) The Central Government may, by order, remove from office the Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority, other than ex officio Member, if the Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority, as the case may be, if heº

- (a) has been adjudged as an insolvent;
- (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government involves moral turpitude;
- (c) has been physically or mentally incapable of acting as a Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority;
- (d) has acquired such financial or other interests, as is likely to affect prejudicially his function as a Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority;
- (e) has so abused his position, as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or
- (f) has engaged at any time during his term of office in any other employment.

(2) The Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority shall not be removed from his office except by an order of the Central Government on the ground of his proved misbehaviour or incapacity after the Central Government has, on an inquiry, held in accordance with the procedure prescribed in this behalf by it, come to the conclusion that the Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority ought on any such ground to be removed.

(3) The Central Government may suspend the Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority in respect of whom an inquiry under sub-section (2) is being initiated or pending until the Central Government has passed an order on receipt of the report of the inquiry.

45C. (1) Before appointing any person as Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority, the Central Government shall satisfy itself that the person does not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such Chairperson, Vice-Chairperson or Member.

(2) The Chairperson, Vice-Chairperson or Members of the Authority shall immediately after entering office and every year thereafter, make a declaration as to the extent of their interest, whether direct or indirect and whether financial or otherwise, in any co-operative society.

(3) The declaration so made under sub-section (2) shall be placed in the public domain by the Authority.

45D. The Chairperson, Vice-Chairperson or Members of the Authority, other than ex officio Members, may, by notice in writing of not less than thirty days under their hand addressed to the Central Government, resign their office and on such resignation being accepted by that Government, shall be deemed to have vacated their office:

Provided that the Chairperson, Vice-Chairperson or Member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish his office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as his successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is earlier.

45E. If a casual vacancy occurs in the office of the Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority, whether by reason of his death, resignation or otherwise, such vacancy shall be filled within a period of ninety days by making a fresh appointment in accordance with the provisions of section 45 and the person so appointed shall hold office for the remainder of the term of office for which the Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority, as the case may be, in whose place he is so appointed.

45F. The Chairperson, Vice-Chairperson and Member of the Authority, on ceasing to hold office shall not, for a period of two years, accept any employment (including a consultant or otherwise) in any co-operative society:

Provided that nothing contained in this section shall apply to any employment under the Central Government or in any State Government or any Corporation established by or under any Central or State Act or a Government Company as defined under clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013.

45G. No act or proceeding of the Authority shall be invalid merely by reason of:

- (a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Authority;
- (b) any defect in the appointment of a person as Chairperson or Member of the Authority; or
- (c) any irregularity in the procedure of the Authority not affecting the merits of the case.

45H. (1) The Authority shall meet at such places and times and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings (including the quorum at its meetings), as may be prescribed.

(2) The Chairperson of the Authority shall preside at the meeting of the Authority and if for any reason the Chairperson of the Authority is unable to attend a meeting of the Authority, the Vice-Chairperson of the Authority shall preside at the meeting.

(3) All questions which come up before any meeting of the Authority shall be decided by a majority of votes of the members present and voting and, in the event of an equality of votes, the Chairperson or the Vice-Chairperson of the Authority presiding shall have the right to exercise a second or casting vote.

(4) Save as otherwise provided in sub-section (3), every Member shall have one vote.

45-I. The Authority shall discharge the following functions, namely:

- (i) conduct the elections of the multi-State co-operative society;
- (ii) supervise, direct and control the matters relating to preparation of electoral rolls; and
- (iii) such other functions as may be prescribed.

45J. (1) No person shall be eligible to be elected as a member of the board or office bearer of a multi-State co-operative society, unless he is an active member of the general body of that society.

Explanation. For the purposes of this sub-section, the term "active member" means any member

- (i) availing minimum level of products or services of the society; or attending not less than three consecutive general meetings, as specified in section 29.
- (2) A member of the board or office bearer of a multi-State co-operative society shall cease to be such member or office bearer, if he ceases to be a member of general body of that society.
- (3) The election of members of board shall be held by secret ballot in such manner as maybe prescribed.
- (4) The election of the members of the board shall be held in the general meeting of the members of the multi-State co-operative society and the elected members of the board shall, if the bye-laws of such society permit, be eligible for re-election:

Provided that the board may fill casual vacancies upto one-third of number of elected directors on the board by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of office of the board is less than half of its original term:

Provided further that in case the number of such casual vacancies in the same term of the board exceeds one-third of number of elected directors, such vacancies shall be filled by elections.

- (6) The expenses for holding elections by the Authority shall be borne by the multi-State co-operative society in such manner as may be prescribed.
- (7) The Central Government may make rules to provide for the powers and the procedure to be followed by the Authority for conduct of election of members of the board.
- (8) The Chairperson and the Chief Executive of the multi-State co-operative society shall in form the Authority, six months before the expiry of the term of the existing board, to conduct the elections within time.
- (9) The society in respect of which the election is being held shall provide such infrastructure, personnel, information, documents or other assistance to the Authority as it may require.

45K. (1) The Authority may appoint a Returning Officer to conduct the election of the multi-State co-operative societies and discharge such functions, as directed by the Authority, in such manner as may be prescribed.

- (2) The Central Government shall provide such staff and officers to the Authority as may be necessary for the efficient discharge of functions by the Authority under the Act.
- (3) The Authority may appoint,

 - (a) such observers as it may consider necessary to supervise the elections and discharge such other functions as may be prescribed; and
 - (b) such number of Assistant Returning Officers as it may consider necessary to assist the Returning Officer.

45L. The Authority may, by general or special order, issue such directions to the board, its members, Chief Executive and other staff of the society as maybe necessary for the conduct of free and fair elections and the board, its members, Chief Executive and staff of the society shall comply with such directions.

Rationale behind the proposed amendment

2.128 õEstablishment of a coop. Election authority is in line with the Article 243ZK (2) of the Constitution.

Electoral reform

This reform will ensure impartial, timely & professional conduct of election to Board ofMSCS.

Prescribes qualification for appointment of Coop. Election authority.Terms & conditions of appointment of Coop. Election authority Powers and grounds for removal of Coop. Election authority.

To ensure impartiality of Coop. Election authority.

Provision for resignation and filing of casual vacancies in the Election Authority. Rules of business for CEA in line with Article 243ZO(2) of the Constitution.

Section 29 provides for condonation of absence by the General meeting.

In line with Article243ZO(2) of

The Constitution, Ist proviso to section 45(J)(5) is proposed to avoid the need for frequent elections.

Reforms in the Composition of Board, Meetings & Membership

To facilitate conduct of election.

Examination by the Committee

2.129 During briefing on the provisions contained in the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, it was observed that having Election Authority is contradictory to democratic function and hits at the autonomy of the cooperatives and asked for reasons in regard to constitution of this Authority. In this regard, Ministry of Cooperation in its post briefing reply clarified as below:ô

In the existing MSC Act, 2002 there is no provision regarding constitution of Election Authority. However, as per Section 45 of the existing Act, it is responsibility of the existing board to conduct elections. Article 243ZK (2) of the Constitution provides for establishment of Election Authority and its function. In the amendment bill vide substitution of Section 45 a new provision is being introduced for setting up of a Cooperative Election Authority. The Authority shall be appointed by the Central Government on recommendation of a Selection Committee. As per Section 45 (3) a person shall not be qualified for appointmentas a:ô

- i. Chairperson of the Authority unless he held the post of Additional Secretary tothe Government of India or equivalent rank;
- ii. Vice-Chairperson of the Authority unless he held the post of Joint Secretary to the Government of India or equivalent rank; and
- iii. Member unless he fulfils such qualification and experience as may be prescribed.

Having Election Authority will help in timely conduct of elections in a free and fairmanner and will strengthen democratic functioning of MSCS.

2.130 During briefing, it was enquired whether there is any provision to rectify the action of a person whose appointment in Election Authority has been made illegally. In this regard, Ministry of Cooperation has stated as follows:-

õClause 17 (section 45G) provides that no act or proceeding of the Authority shallbe invalid merely by reason of vacancies, or any defect in appointment of a personas Chairperson or Member of the Authority or any irregularity in the procedure of the Authority not affecting the merits of the case.

This is a standard provision which exists in other Acts also. For example, Section93 of the Electricity Act, 2003 says that no act or proceedings of the Appropriate Commission shall be questioned or shall be invalidated merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the Appropriate Commission.

This standard clause is provided to ensure that valid actions taken by the authorityare not questioned on grounds of defect in constitution of Authority & other procedural matters.ö

Comments of RBI

- 2.131 The RBI in their submission has raised objection regarding provisions in section 41 and 45 regarding Composition of Board of Director and election of members of Board. The RBI has informed that Banking Regulation Act has specified role of RBI in these matters of Co-operative banks. Further, the RBI submitted that proposed amendments to the MSCS Act do not assign any role to RBI/BR Act, in these matters. They have also opined that specific provisos be inserted in the relevant sections, providing that in case of multi-state co-operative banks, the regulations issued by RBI shall apply. When asked to furnish comments on these issues, the Ministry submitted as under:–
- 2.132 Further RBI in its post evidence has stated that Article 243ZJ (2) of the Constitution states that “The term of office of elected members of Board and its office bearers shall be five years from the date of election and the term of office bearers shall be coterminous with the term of the Board.” Accordingly, Section 45J (5) has been proposed in the MSCS (Amendment) Bill to give effect to the aforementioned Constitutional provision. However, as per Section 10A(2A)(i) of BR Act, no Director of a cooperative bank, other than its chairman or whole time director, by whatever name called, shall hold office continuously for a period exceeding eight years. Therefore, Article 243ZJ(2) and Section 45J(2) of MSCS Bill, if made applicable to multi-state urban cooperative banks, would be at variance with provision of BR Act. To address this issue and keep the provisions of BR Act in tune with Constitution of India RBI has recommended to the Government an amendment to Section 10A(2A)(i) of the BR Act in our proposals for the Union Budget 2023-24 to modify the continuous term of 8 years as 10 years for cooperative banks.
- 2.133 In regard to the above submission of RBI, the Secretary, Department of Financial Services stated before the Committee during oral evidence, “It was asked about the tenure that it has been said differently in the BR Act and the Constitution. The proposal to change the BR Act in accordance with constitution and this bill is under consideration in the Ministry. Similarly, the period of supersession of the board, which is of six months and five years, is under consideration in the ministry to replace it with five years as per the constitution. It will be made in accordance with the constitution and we will take immediate action in this.”
- 2.134 RBI has also stated that there are certain provisions in the Bill e.g. Section 41, 45 and 51 which can potentially be interpreted differently to have a board composition or directors/CEO not necessarily conforming to the extant instructions issued by RBI in the matter. They have further observed that few Clauses like Clause 6, 16, 24, 28, 34 and 45 are coming under the domain of RBI regulations as per provisions of BR Act, 1949 which may face the test of unambiguous interpretation in specific situations viewed against certain Amendments in the Bill. In regard to the above contention of RBI, Ministry of Cooperation was asked the manner in which these ambiguities are proposed to be resolved by the nodal Ministry. The furnished the following reply in writing:–
- “Clause 6, 16, 24, 28, 34 and 45 are related to Merger of Cooperative societies, Disqualification for being a member of board, Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund, Concurrent audit, recovery of dues and Supersession respectively.
- Both RBI and DFS were consulted while finalising the bill and appropriate changes were made in the bill on the basis of consultations.
 - During the process of Inter-ministerial consultation, Department of Financial Services (DFS) vide their letter dated 04.10.2022 informed that proposed revised Bill is largely aligned with BR Act and thus, the DFS agrees with and supports the amendment Bill. Further, DFS will make suitable amendments in the BR Act so that its provisions are in consonance with the Constitution. The same was also stated by Secretary (DFS) in the JPC meeting held on 19.01.2023.”

Suggestions by Stakeholders

- 2.135 NAFSCOB has suggested that the proposed amendment to establish cooperative Election Authority to discharge the specified functions under Section 45(1) do not justify the cooperative character. Entire Section 45 is unacceptable as the provisions are against the Cooperative Principles, ethics, values, etc. Existing provision should continue. No need to amend Section 45. When asked to furnish comments on these issues, the Ministry submitted as under:–
- 2.136 When asked to justify that these proposals are not against the cooperative principles, ethics and values; the Ministry submitted as under:–
- “In the amendment bill vide substitution of Section 45, a new provision is being introduced for setting up of a Cooperative Election Authority as per Article 243ZK

(2) of the Constitution. This will ensure timely, regular and transparent conduct of elections and will strengthen governance in the cooperative societies. Therefore, it is not against the cooperative principles, ethics and values.ö

- 2.137 NAFCARD has suggested for amendment to Section 45 of Principal Act relating to establishment of cooperative election authority that proposes clause 45(J)(8) may be changed as öThe Chief Executive of the Multi State Cooperative Society shall inform the authority six months before the expiry of the term of the existing Board, to conduct the election within time.

As per them instead of giving information to the authority jointly by Chairman and Chief Executive, the Chief Executive may give information to the authority for administrative convenience.

NAFCARD has also suggested for addition of an additional clause under Section 45 of Principal Act as 45 (J) (10) after proposed 45 (J)(9) as under:ö

öOn receipt of information from the society as required under Section 45(J)(8), authority shall fix the date of election of Board and office bearers in consultation with the society concerned.ö

According to it, above provision will facilitate the authority to fix a mutually convenient date for the authority and the society to conduct elections within time.

Observation/recommendation of the Committee

- 2.138 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders and the rationale reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.**

Clause No. 18

Provision in the Principal Act

2.139 öSection 49: Powers and functions of board

2.139.1 The board may exercise all such powers as may be necessary or expedient for the purpose of carrying out its functions under this Act.

2.139.2 Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such powers shall include the power-

- (a) to admit members;
- (b) i .to (d)

(e) to make provisions for regulating the appointment of employees of the multi-state cooperative society and the scales of pay, allowances and other conditions of service of, including disciplinary action against such employees.ö

Amendment Proposed in the Bill

- 2.140 In section 49 of the principal Act, in sub-section (2),ö

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:ö

ö(aa) to elect the Chairperson and Vice-Chairperson or President and Vice-President of the multi-State co-operative society from amongst the elected members of the board in accordance with the directions of the Authority:

Provided that the certificate of election shall be issued by the Chief Executive of the multi-State co-operative society after conclusion of resolution by the board;ö;

(ii) in clause (e), the following proviso shall be inserted, namely:ö

öProvided that the recruitment of such employees shall be subject to such procedure as may be prescribed.ö

Rationale behind the proposed amendment

- 2.141 Strengthening Governance and Transparency

This will curb nepotism and increase transparency in recruitment. This will also help in prescribing a standardised recruitment policy.

Examination by the Committee

- 2.142 During briefing on the provisions contained in the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, on a query

of the committee regarding need of Nation-wise recruitment Board in order to bring transparency in recruitment in Coöoperative Societies, the Ministry submitted as under:ô

ð The existing MSCS Act, 2002, does not provide for recruitment procedure for the employees of MSCSs to be prescribed. This leads to arbitrariness & nepotism as each MSCS follows its own procedure.

The proposed provision in section 49 provides for prescription by Government of recruitment procedure to curb nepotism and increase transparency in recruitment. This will also help in having a standardised recruitment policy.

The MSCS are economic entities and are accountable to their members. Formation of recruitment board might adversely affect their autonomous functioning. Hence, provision for only prescribing procedure for recruitment has been includedð

Suggestions by stakeholders

2.143 In regard to the amendment for incorporation of a new para ðaaø under sub-section(2) of 49 of the principal Act to elect chairperson, Vice Chairperson or President and Vice-President of the multi-State cooperative society from amongst the elected members of the board in accordance with the directions of the authority, NCUI has stated that the proposed provision will delay the election of officebearers of the society which is not required as the whole process of election of the board and office bearers of the society is being conducted under the overall supervision of the returning officer, appointed by the election authority hence the existing provision as per the MSCS Act & Rules 2002 may be retained. NAFED has also suggested that the election of office bearers of the Society may be held immediately after the new Board is constituted. Ministry of Cooperation was asked to furnish comments on these issues. In its written response, the Ministry submitted as follows:-

ðThere is no restriction on immediate election of chairperson, Vice Chairperson or President and Vice President of the multi-State cooperative society from amongst the elected members of the board. The entire election process including election of board members will be under superintendence, direction and control of Cooperative election authorityð

2.144 NCUI has also opposed proposed amendment (Clause 18(ii) of the Bill) for insertion in sub-section 2(e) of Section 49 that the recruitment of employees shall be subject to such procedure as may be prescribed. According to NCUI, it may affect independent and autonomous character of the society and demanded that recruitment of employees shall be according to the service rule, duly approved by the Board of such society instead of procedure as may be prescribed by the Govt. NAFCUB also expressed similar opinion NAFED has also suggested that the Clause (e) may be revised as, ðprovided that recruitment of such employees shall be as prescribed in the recruitment rules/service rules of the organizationsð. Attention of Ministry of Cooperation was drawn to the above suggestions and was asked to furnish comments on the same. The Ministry submitted as below:ô

ðThe proposed amendment in Section 49 seeks to insert clause (e) in Section 49

(ii) which states that the recruitment of employees shall be subject to such procedure as may be prescribed. The power of recruitment of employees remains with the board of MSCS. The proposed amendment will help in curbing nepotism and increase transparency in recruitment.ð

2.145 NAFCUB has suggested that this should not be made applicable to UCBs which hold license from RBI and there are directions by RBI u/s 35, 56 of BR Act. B R Act supersedes all other Acts on banking companies. This insertion will create avoidable controversies. Hence, request for non applicability. When asked to furnish comments on these issues, the Ministry of Cooperation submitted as under:-

-As per the prevailing practice, Banking license by RBI is given to entities incorporated under different laws such as Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts under which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for all such entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of MSCS Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up: Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply.ø

Observation/recommendation of the Committee

2.146 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed underthe Clause.

Clause No. 19

Provision in the Principal Act

2.147 Section 50: Meeting of board

- (1) The Chief Executive shall convene the meetings of the board at the instance of the chairperson or president of the multi-state cooperative society.
- (2) i .
- (3) The Chairperson, or if for any reason, he is unable to attend a meeting of the board, any other member of the board chosen by the members of the board present from amongst themselves at the meeting, shall preside at the meeting.

Amendment Proposed in the Bill

2.148 öIn section 50 of the principal Act,öö

(a) in sub-section (1), the following provisos shall be inserted, namely:öö

öProvided that where such Chairperson or President fails to direct the Chief Executive to convene the meeting of the board within the quarter, such Chief Executive shall convene the meeting on the basis of requisition of the Vice-Chairperson or Vice-President or any other Member of the board:

Provided further that notwithstanding anything contained in the first proviso, the Chief Executive may also convene the meeting on the basis of requisition from atleast fifty per cent. of Members of the board;

(b) for sub-section (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:ö

ö(3) The Chairperson or President, if for any reason, is unable to attend a meeting of the board, the Vice-Chairperson or Vice- President and in the absence of both, any other Member of the board chosen by the Members of the board present from amongst themselves at the meeting, shall preside over the meeting.

(4) The quorum for a meeting of the board of directors of a multi-State co-operative society shall be one-third of its total number of elected directors.ö

Rationale behind the proposed amendment

2.149 “Reforms in the Composition of Board, Meetings & Membership

It is seen that sometimes Board meetings get delayed if Chairman/ President is not interested. To prevent this, a proviso is being added under sub- section(1).

No quorum prescribed as on date. This will facilitate inclusive and transparent decision making in the board.ö

Examination by the Committee

2.150 During briefing on the provisions made in the Bill, the Committee observed that Quorum prescribed for board meetings should be at least 50% instead of proposed 1/3rdquorum. In this regard, Ministry of Cooperation has clarified in its post briefing replies as below :-

In the existing MSCS Act, 2002 there is no quorum specified for Board meetings. This leads to scope for decision making by only a few members of the Board.

A need is felt for participation of more members in the decisions of the Board and also to bring uniformity with regard to quorum, for the Board meetings.

The amendment in sub-section (4) is being inserted in Section 50 of the MSCS Act, 2002 to prescribe minimum Quorum for Board meetings. It has been kept at 1/3rd of elected directors as there might be difficulties in conducting meetings if a higher Quorum is prescribed for board meetings of the MSCS.

Suggestions received from stakeholders

2.151 NAFCARD in its submission to the Committee stated that the Members participating in the meeting through video conferencing mode shall also be considered

for the quorum for a meeting of the Board, provided the agenda for the meeting does not include election of office bearers. Such a clause will facilitate better participation and lower cost of participation in terms of expenses and time, particularly for national level societies whose members are located far and wide in various States.

Comments of Ministry of Cooperation

2.152 The Ministry in their replies stated that in clause 19(4) of the amendment Bill, the quorum for a meeting of the board of directors of an MSCS is proposed to be only one- third of total number of elected directors. Participation through physical mode will lead to more interaction and will strengthen democracy in MSCS.

Observation/recommendation of the Committee

- 2.153 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholder and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.**

Clause No. 20

Provision in the Principal Act

- 2.154 Section 51: Chief Executive**

(1) There shall be a Chief Executive, by whatever designation called, of every multi-state cooperative society to be appointed by the board and he shall be a full-time employee of such multi-state cooperative society.

Amendment proposed in the Bill

2.155 In section 51 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:

-(1A) No multi-State co-operative society shall appoint or continue the employment of any person as the Chief Executive who –

(a) is below the age of twenty-one years or has attained the age of seventy years;

Provided that any person above the age of seventy years may be appointed by a special resolution passed by three-fourths of the board members, in which case the explanatory statement annexed to the notice for such motion shall indicate the justification for appointing such person;

(b) is an undischarged insolvent or has any time been adjudged as an insolvent;

(c) has at any time been convicted by a court of an offence and sentenced for a period of more than six months; or

(d) does not meet the criteria for fit and proper, as determined by the Central Registrar in case of multi-State credit societies; or in case of non-credit multi-State societies, does not meet the criteria as the Central Government may prescribe in terms of educational qualifications and relevant experience.

Rationale behind the amendment

- 2.156 Strengthening Governance and Transparency**

Criteria needed for appointment of CEO by the Board. More stringent criteria needed for appointment of CEOs in multi-State credit co-operative societies on the lines of fit & proper criteria by RBI for appointment of CEOs in banks.

Examination by the Committee

- 2.157 During briefing on the provisions contained in the Bill, the Committee enquired the representatives of Ministry of Cooperation whether the age of CEO should be within 21 to 70 years. In this regard, the Ministry of Cooperation submitted in its written reply stated as below:-

Section 51 and Section 52 of the existing Act relate to the Chief Executive Officer and its Power and Functions, respectively. However, age limit for appointing CEO is not defined in the existing Act. Through insertion of new sub-section(1) in Section 51 vide clause 20 of the proposed amendment age limit for CEO has been prescribed. The criteria of age limit is in sync with Section 196(3) of the Companies Act 2013.

Comments of RBI

- 2.158 RBI in their submission before the Committee have stated that the proposed amendment to MSCS Act inserts a new provision under Section 51(1A) which stipulates the age of the Chief Executive to be within 21 and 70 years. Further, a person above the age of 70 years may be appointed by a special resolution. In terms of powers conferred under Sections 10, 10B, 10BB, 35A, 35B, 36AA and 53A (read with Section 56) of the BR Act, 1949 (as amended from time to time), certain directions relating to appointment, re-appointment, termination and removal of Managing Director (MD) and Whole-Time Director (WTD) including Chief Executive Officer have been issued by RBI including the circular dated June 25, 2021. The minimum age to be appointed as the Chief Executive Officer is fixed as 35 years as per the circulars and directions issued by RBI including circular dated June 25, 2021 considering the fact that the Chief Executive Officer is required to have a comprehensive experience and knowledge of banking, finance or administrative function to act as the head of the institution. The maximum age is 70 years and there is no provision to extend the maximum age limit of 70 years under the regulatory guidelines. However, the fit and proper criteria for UCBs have been prescribed by RBI

vide aforementioned circular under para 3.4 (Eligibility) and 3.5 (Propriety Criteria). It would, therefore, be appropriate to add clarity on primacy of applicable regulations issued by RBI under BR Act, 1949 regarding minimum and maximum age of CEO/MD of UCBs, disqualifications and fit and proper criteria for Chairman and MD/CEO multi-state urban cooperative banks.

Observations/ Suggestions received from stakeholders

- 2.159 NAFSCOB in its written submission before the Committee has stated that 21 years CEO is too immature to appreciate and execute the actions and resolutions of the Member driven cooperatives. They have suggested the age to be 35 years.
- 2.160 NABARD has suggested that additional provision may be incorporated under Sec 51 ñ For CEOs of multi-State cooperative Banks, criteria as per provisions of Sec 35 1. (b) and other relevant sections of the Banking Regulation Act, 1949 will apply ñ.
- 2.161 NCUI has suggested that the proposed provision of Fit and proper criteria shall be applicable for multi-state credit societies only as the nature of cooperative business is different from private sector hence fixing the criteria for non credit cooperative societies be invested with the board of such multi state cooperative societies instead of Government of India.

Comments of Ministry of Cooperation

- 2.162 In regard to the above submissions of NCUI and NAFSCOB, Ministry of Cooperation commented as under:
 - ñ The power for appointment of CEO continues to be with the board. The provision for prescription of criteria for appointment of CEO is proposed to strengthen governance in all MSCS. More stringent criteria is needed for appointment of CEOs in multi-State credit cooperative societies on the lines of fit & proper criteria by RBI for appointment of CEOs in banks. For non-credit MSCS, the Central Government may prescribe appropriate criteria for CEO keeping in view the nature of business and requirement of non-credit MSCS.ñ
 - ñ This provision only prescribes minimum and maximum age limit. The board is free to appoint CEO within these age limits depending upon requirements. The proposed age limit is in sync with the age limits prescribed for MD as per Section 196(3) of the Companies Act.
- 2.163 In Response to RBI comments, During the process of Inter-ministerial consultation, Department of Financial Services (DFS) vide their letter dated 04.10.2022 informed that proposed revised Bill is largely aligned with BR Act and thus, the DFS agrees with and supports the amendment Bill. Further, DFS will make suitable amendments in the BR Act so that its provisions are in consonance with the Constitution. The same was also stated by Secretary (DFS) in the JPC meeting held on 19.01.2023.

As per the prevailing practice, Banking license by RBI is given to entities incorporated under different laws such as Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts under which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for all such entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of MSCS Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up: Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply.

Observation/recommendation of the Committee

- 2.164 **The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders and the rationale reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed underthe Clause.**

Clause No. 21

Provision in the Principal Act

2.165 Section 52: Powers and functions of Chief Executive

The Chief Executive shall under the general superintendence, direction and control of the board, exercise the powers and discharge the functions specified below, namely:

- (a) day-to-day management of the business of the multi-state cooperative society;

(b) to (i) ..

(j) present the draft annual report and financial statement for the approval of the board within thirty days of closure of the financial year;

Amendment proposed in the Bill

2.166 In section 52 of the principal Act, in clause (j), for the words "thirty days", the words "forty-five days" shall be substituted.

Rationale behind the amendment

2.167 Some additional time being provided for presenting draft Annual report and financial statements etc.

Observation/recommendation of the Committee

2.168 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 22

Provision in the Principal Act

2.169 53. Committees of Board

(1) The board may, subject to such conditions as may be prescribed, constitute an Executive Committee and other committees or subcommittees as may be considered necessary: Provided that other committees or sub-committees, other than the Executive Committee shall not exceed three.

Amendment in the proposed Bill

2.170 In section 53 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:

(1) The board may constitute an Executive Committee, and such other committees or sub-committees as may be specified in the bye-laws of the multi-State co-operative society:

Provided that the board shall constitute

- (a) an Audit and Ethics Committee;
- (b) a Committee on prevention of sexual harassment at work place.

Rationale for the amendment

2.171 "Strengthening Governance and Transparency"

No existing provision for constitution of committees to ensure ethical practices, and to prevent sexual harassment. Guidance, supervision and mid-course correction through internal committees will ensure better governance in MSCS.

Examination by the Committee

2.172 During the briefing meeting with the Nodal Ministry, it was suggested by a Member to include one more Committee on financial security. To the said suggestion, the Ministry in their written reply stated that the Audit and Ethics Committee can monitor the financial security. Besides, the Board may constitute an executive Committee and other committees and subcommittees as may be considered necessary and number of such committees shall not exceed three.

Suggestions received from stakeholders

2.173 NABARD in its submission has stated that there has been no objection to the amended provisions from stakeholders. However, it has suggested to include "in accordance with byelaws" after "at work place".

Comments of Ministry of Cooperation

2.174 The existing section 53 of the MSCS Act 2002 provides for functioning of the committee in accordance with bye-laws. Therefore, the suggested words "in accordance with byelaws" after "at work place." in clause 22 of the Bill are not required.

Observation/recommendation of the Committee

2.175 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 23

Provision in the Principal Act

2.176 “Section 63: Disposal of net profits

2.176.1 A multi-state cooperative society shall, out of its net profits in any year-

(a) 1 1 ;

(b) credit one per cent, to cooperative education fund maintained, by the National Cooperative Union of India Limited, New Delhi, in the manner as may be prescribed.

Amendment proposed in the Bill

2.177 In section 63 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:

(b) credit annually one per cent of net profit to co-operative education fund to be maintained by the Central Government in such manner as may be prescribed and the proceeds from such fund shall be used for Co-operative Education and Training through the National Co-operative Union of India and any other agency in such manner as may be determined by the Central Government.

Rationale behind the Amendment

2.178 Enabling raising of funds by Cooperative Sector. This will ensure flexibility in usage, better maintenance and compliance.

Examination by the Committee

Suggestions received from stake holders

2.179 NCUI submitted the following suggestions:

- (i) On recommendation of Working Group of Cooperation of Administrative reforms Commission in 1967 and Committee to review CRAFICARD constituted by RBI in 1981, full Section 63 was introduced in MSCS Act 2002 for collection and management of CEF, which was entrusted to NCUI, since inception and maintained and managed by them. None of the MSCS have objected or made adverse observation on maintaining the fund by NCUI whose audit is being done regularly.
- (ii) There is no contribution of GOI to this fund, hence it should remain with NCUI in the spirit of cooperative autonomy, cooperative principles and values of independence and cooperation among cooperatives. Government's role should be as facilitator not as controller.
- (iii) the respective State Governments may take control of such funds which may weaken State cooperative Unions and affect activities of education and training and will cause bureaucratic delays.
- (iv) Proposed amendment may be deleted and existing provision as per MSCS Act may be retained.

2.180 In additional submission, they have stated that NCUI maintains separate Bank account for the Fund including interest on investments which is credited to the account. The budget for activities is approved by CEF Committee every year which are conducted through various National level Cooperative Federations, MSCS, State Cooperative Unions, VAMNCOM, NCCT, NCCE, RICM/ICM for which financial assistance is provided by NCUI. Further, as per M/o Cooperations directions, NCUI is now undertaking key initiatives in line with Ministry's objective such as creation of database, formation of new cooperatives especially in dairy, credit and fisheries, Marketing and branding of products setting up Resource Centre etc. A total budget of 100 crore has been earmarked from CEF for the above and would additionally require regular funds in future also. Hence the existing provision related to collection and management of CEF may continue.

2.181 With regard to utilization of Fund, NCUI submitted that till FY 2021-22, a total sum of Rs. 356.85 crore has been collected out of which Rs 228.145 crores has been utilized after due approvals by CEF Committee from time to time and after carrying out due diligence in maintaining the accounts thereby utilizing about 64 % of the Fund so collected. The amount being reflected as unutilized in the Fund is actually the compound interest accumulated over the years as a result of judicious investing by NCUI being the custodian of CEF. This is a continuous Fund hence accumulated over the years to be used as per requirement of co-operative sector. Moreover due to Covid pandemic and restrictions by Government to curb it, all cooperative education and training was conducted online for 2 years and hence related in accumulation of Fund. The accounts are audited by statutory auditors every year and CAG audit every 3-4 years.

2.182 KRIBHKO have stated that NCUI is managing the fund efficiently and satisfactorily hence existing provision in the Act may continue. Similarly, NAFED have also advocated that existing provision of Section 63 of MSCS Act may continue.

2.183 NAFSCOB have submitted that resources of Cooperatives must be deposited with and used for cooperatives. The Proposal to maintain the Fund by Central Government is not strongly justified. NCUI should be the final authority in maintaining the Fund in all respects.

- 2.184 NABARD have however expressed the view that the provisions stipulated by way of amendment to the Act would help in building the internal resources in the cooperative sector and reduces dependency on budget allocations by government. It's like Cooperative Social Responsibility (CSR)
- 2.185 NAFCUB while deposing before Committee have stated that NCUI is not providing them anything and that some percent should be allocated to national level federations which are imparting education.

Comments/views of RBI

- 2.186 The amendment to Section 63(1)(b) proposes that Cooperative Education Fund would be maintained by the Central Government and would be utilised for cooperative education and training purposes through National Cooperative Union of India. Such mandatory contribution to the Fund may interfere with RBI's supervisory and regulatory restrictions on its expenses imposed under different provisions of BR Act/ Regulations. This may also not be in the best interest of the bank if there are incipient signs of deposit erosion even though it is profitable and not under the Supervisory Action Framework (SAF) of RBI. This is more so as in addition to this fund, additional ₹1 crore or 1% of Net Profit (whichever is less) is required to be contributed for Rehabilitation Fund.

Comments of the Ministry of Cooperation

- 2.187 Above suggestions/views of the stake holders were taken up with the Ministry of Cooperation and its comments were sought. In reply, Ministry of cooperation stated as follows:-

öThe proposed provision will ensure more flexibility in usage, better compliance and utilization of Cooperative Education Fund. Presently, a corpus of approximately Rs.275 Crores is lying unutilized in the Cooperative Education Fund being maintained by NCUI. Since, this contribution is to be collected only from net profit making MSCS and that too only at the rate of 1% as per the existing section 63 of the MSCS Act 2002, this will not be a burden on contributing societies.ö

- 2.188 On RBI's comments Ministry replied that the existing section 63 of the Act already provides for credit of one per cent to cooperative education fund maintained by the National Cooperative Union of India Limited (NCUI). This is an existing provision in terms of contribution. Therefore, the amendment Bill does not impose any extra burden on account of this section.

Observation/recommendation of the Committee

- 2.189 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders and the rationale reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed underthe Clause.**

Clause No. 24

New Insertion 63A to 63C

Amendment in the proposed Bill

- 2.190 öAfter section 63 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:ö

63A. (1) The Central Government shall establish a Fund, to be called the Co-operative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund for revival of sick multi-State co-operative societies as referred to in section 63B and for development purposes in such manner as may be determined by it and there shall be credited to such Fund annually by multi-State co-operative societies which are in profit for the preceding three financial years one crore rupees or one per cent. of the net profits of such multi-State co-operative society, whichever is less.

(2) The Central Government shall, by notification, constitute a Committee, consisting of such members as it may deem fit, to administer the Fund, and maintain separate accounts and other relevant records in relation to the Fund in such form as may be specified by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(3) The Committee shall spend the money out of the Fund for carrying out the objects for which such Fund has been established.

63B. (1) If, at any time, the Central Registrar, is of the opinion that a multi-State co-operative society has become sick, he may, by an order, declare such society as sick co-operative society.

(2) Where a multi-State co-operative society is declared as a sick co-operative society under sub-section (1), the Central Government or any person or agency authorised by it, may prepare a scheme for rehabilitation and reconstruction of the society and hand it over to the society for approval of the general body.

(3) The Central Government may, on the recommendation of the general body and to give effect to the scheme for rehabilitation and reconstruction referred to in sub-section (2), re-organise the board of such society with such persons, having experience in the field of co-operation, management, finance, accountancy and any other area relating to such societies as may be recommended by the general body:

Provided that in respect of a sick multi-State co-operative bank, any scheme for rehabilitation or reconstruction shall be done with the prior approval of the Reserve Bank.

Explanation. For the purposes of this section, the expression "sick co-operative society" means a multi-State co-operative society being a society registered under the provisions of this Act which has at the end of any financial year accumulated losses equal to or exceeding total of its paid-up capital, free reserves and surpluses and has also suffered cash losses in such financial year and the financial year immediately preceding such financial year.

63C. (1) The Central Government may, on an application made by a multi-State co-operative society which has contributed to the Fund for continuous five preceding financial years, grant such financial assistance as it may consider appropriate to the society out of the Fund for infrastructural requirement:

Provided that at least fifty per cent. of the total requirement shall be borne by the multi-State co-operative society and the financial assistance from the Fund shall not exceed more than the fifty per cent. of such requirement.

(3) The Committee constituted under sub-section (2) of section 63A shall examine and recommend to the Central Government for providing the financial assistance to the multi-State co-operative society to such extent and on such terms and conditions as it may consider necessary.

Rationale behind the Amendment

2.191 "Enabling raising of funds by Cooperative sector

This is a new provision to ensure revival and handholding of sick cooperatives who can be made viable through implementation of innovative and profitable business development plans.

Provision of contribution of 50% by the MSCS of the total requirement shall lead to more responsible utilization."

Examination by the Committee

2.192 During briefing on the provisions of the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, the Committee observed that clarity is needed on the management of fund. It was also pointed out that it needs to be specified whether the society should be in profit for 3 consecutive years or otherwise. In this regard, the Ministry in its written comments stated as below:

In the existing MSCS Act, 2002 there is no provision for any Fund for revival or assistance for sick MSCS. The proposed new insertion of Section-63(A) relates to Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund which shall be maintained by Central Government. It will be funded by contribution of 1% of net profit or ₹1 crore whichever is less, by MSCSs in profit for last 3 financial years for revival of sick MSCSs & financial assistance for creation of infrastructure. Central Government will constitute a Committee to administer this Fund. The Central Govt. may, on an application made by an MSCS which has contributed to the Fund for continuous five preceding financial years, grant such financial assistance as it may consider appropriate to the society out of the Fund for infrastructural requirement, provided that 50 % of such requirement shall be met by the MSCS itself.

For the purposes of this section, the expression "sick co-operative society" means a multi-State co-operative society being a society registered under the provisions of this Act which has at the end of any financial year accumulated losses equal to or exceeding total of its paid-up capital, free reserves and surpluses and has also suffered cash losses in such financial year and the financial year immediately preceding such financial year.

The proposed provision is in line with the cooperative principles of "Cooperation among Cooperatives" and "concern for community".

Comments/views of RBI

2.193 The Bill under new Section 63A proposes to establish a fund (Cooperative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund) out of the profits of the MSCS which are making profit since last three years. The yearly contribution to the fund would be ₹1 crore or 1% of the net profit, whichever is less. This fund would be used to revive the sick MSCS, as declared by the Central Registrar. On such declaration, the Central Government would prepare the scheme of rehabilitation or reconstruction of the society and hand it over to the General body for approval. On

recommendation of the general body, the Central Government may reorganise the Board of the Society. However, proviso to Section 63B (3) states that for Multi-State Cooperative Bank, any scheme of rehabilitation or reconstruction shall be done with the prior approval of RBI. As mentioned above, when a cooperative bank is resolved under Section 45 of BR Act, power is with RBI to recommend moratorium to the Central Government and prepare a scheme for reconstruction for approval of the Central Government. Under existing Section 18 of MSCS Act, the power to prepare scheme once moratorium is declared under Section 45 of BR Act is entrusted upon Central Registrar making it inconsistent with Section 45 of BR Act itself.

Besides, RBI has highlighted the following other inconsistencies:

- (a) If a Multi-state UCB is resolved under Section 45 of BR Act, there may be a possibility of both RBI and Central Registrar preparing a scheme for rehabilitation or reconstruction. As Section 45 has been recently made applicable to cooperative banks and is like a non-obstante clause giving primacy to BR Act and Section 105A of MSCS Bill states that the provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of, any other law for the time being in force, it is understood that BR Act would have primacy. This needs ample clarity in the Bill to avoid future interpretational issues.
- (b) If a Multi-state UCB is declared sick by the Central Registrar under Section 63B (1), then Central Government would have to frame scheme for rehabilitation or reconstruction and get it approved by the general body of the society. For Multi-State Cooperative Banks, proviso to Section 63B (3) states that any scheme of rehabilitation or reconstruction shall be done with the prior approval of RBI. Therefore, when a Multi-state UCB is getting resolved, Central Government may have simultaneously two different roles viz. one under Section 63B (1) of MSCS Act to prepare a scheme and another under Section 45 to approve a scheme prepared by RBI. This may give rise to anomalous situations and would be prone to legal challenges.
- (c) The definition of ‘sick’ cooperative society is based on a single metric of profit. However, supervisory action by RBI on a cooperative bank under its Supervisory Action Framework (SAF) is more nuanced and is based on multiple indicators like breach of NPA threshold, profitability and regulatory capital for initiating early action. Keeping in view that cooperative banks handle public deposits, the prompt corrective action undertaken by RBI is multi-dimensional and is not limited to change in the management or infusing funds as prescribed under MSCS (Amendment) Bill, 2022. Accordingly, RBI has held the view that in the interest of bank depositors, it would be necessary to carve out cooperative banks from the general rehabilitation/reconstruction provisions of MSCS Act. It would be appropriate that for expeditious and specialised resolution of UCBs, the amended Act include a provision that any scheme for rehabilitation or reconstruction of a cooperative bank shall be done in accordance with the provisions of the BR Act, 1949 read with Section 56 of the Act ibid and in accordance with the RBI guidelines issued from time to time.

Comments of Ministry of Cooperation

- 2.194 On the above said reservations of RBI, the Ministry replied as under :-

“As per the prevailing practice, Banking license by RBI is given to entities incorporated under different laws such as Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts under which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for all such entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of MSCS Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up: Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply.”

As per proviso to section 63(B)(3) of the proposed amendment Bill, in respect of a sick multi-State co-operative bank, any scheme for rehabilitation or reconstruction shall be done with the prior approval of the Reserve Bank. Therefore, the suggestion by RBI is not accepted.

Suggestions received from stakeholders

- 2.195 While supporting the insertion of Clause 24, stakeholder organization **NABARD** stated that the provisions would help in building the internal resources in the cooperative sector and reduces dependency on budget allocations by government. It’s like Cooperative Social Responsibility (CSR). Similarly, **NCDC** advocated that many cooperative societies that are in financial distress, but may run profitably if provided some monetary relief, will be benefitted with this Fund.
- 2.196 With regard to MSC Banks, **NAFCUB** held the view that contribution of Fund must be managed by Umbrella Organisation recently created and meant for cooperative Banking Sector only. Futuristic view needs to be taken. They also put forth the view that all the societies including those with meager profits will have to contribute to the Fund,

putting unnecessary burden on them, who are already competing with MNCs and other industrial houses and is likely to burden the members of societies. They stated that there are only a few sick cooperative societies and forcing the cooperative societies to credit huge amount to the Fund is not justified. Accordingly they advocated that the Clause 24 and relating provision in Clause 16 must be omitted.

- 2.197 NCUI has stated that this is an additional burden for profit making MSCS and will hamper the requirement of funds for further business development. Secondly, even in respect of companies, no profit earning company is contributing for the revival of sick undertakings. On a parity of reasoning, the profit making cooperatives should not be used as a vehicle for subsidizing the functioning of sick MSCS. Rather such MSCS may be provided all the required policy support, concessions/exemption to overcome the situation. However, such fund may be created by Central Government itself for revival of sick Multi State Cooperative Societies.

Comments of Ministry of Cooperation.

- 2.198 The proposed amendment in the bill is aimed at revival of sick cooperative societies and also to grant financial assistance for infrastructural requirement. This will help in handholding of sick cooperative societies which can be made viable through implementation of innovative and profitable business development plans. The contribution is limited to only 1 percent of net profit or Rs.1 Crore whichever is less, by only those MSCS which are in profit for preceding 3 financial years. Therefore, this will not impose significant burden on such societies. On the contrary, this will help in strengthening cooperative movement in the country in accordance with cooperative principle of co-operation among cooperatives. Regarding Government aid to MSCS, there is already an existing section 61 in the MSCS Act 2002. In the case of companies also, there is a provision for spending under Corporate Social Responsibility.
- 2.199 The Umbrella organization referred to by NAFCUB would only cover Urban cooperative banks (UCBs) whereas this committee and the fund would be for MSCS in all sectors.
- 2.200 With regard to amendment proposed in Clause 63 C pertaining to grant of financial assistance for infrastructural requirement by MSCS, the Ministry responded that the financial assistance for infrastructural requirement is restricted to fifty per cent and to those societies which have contributed to the fund for continuous proceeding five financial years. These restrictions have been put to instill financial discipline and to ensure that societies seeking assistance are viable and also put in the necessary capita.

Further suggestions by Stake holders

- 2.201 As per Clause 24 of the Bill (Proposed Section 63 A(2)), the Central Government shall, by notification, constitute a Committee, consisting of such members as it may deem fit, to administer the Fund, and maintain separate accounts and other relevant records in relation to the Fund in such form as may be specified by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India. In this regard, NAFSCOB has stated that the Committee Composition needs to be spelt out. It has also expressed its opinion that the Bill should in true sense give a feeling that MSC society is not Government owned but Govt. supported. The major objective of amendment of the MSCS Act, 2002 be to ensure democratic, dynamic, viable and autonomous MSCS.

Comments of Ministry of Cooperation

- 2.202 The Ministry further stated that the committee to administer the Fund will be notified by the Central Government which will ensure proper utilization and transparency in administration of the Fund. This proposed amendment would strengthen cooperative movement by helping sick cooperative societies and providing financial assistance for infrastructural requirements of MSCS. For the CEF in the existing Act also, the composition of the committee is not detailed in the Act. Prescribing composition of committee in the Act would not be appropriate as it will restrict flexibility. In case of existing cooperative education fund also, the manner of utilization of fund and composition of committee is not laid down in the Act but is in the rules.
- 2.203 During consideration of Clause by Clause provisions of the amendment Bill by the Committee, on the issue of composition of the proposed Committee in Sec 63 A (2) to be provided in the Bill itself including ex-officio Members for management of Fund, the Secretary informed that they are in consultation with C&AG.

Observation/recommendation of the Committee

- 2.204 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause includingsuggestions made by the stakeholders and the rationale reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 25

Provision in the Principal Act

2.205 Section 64: Investment of funds

A multi-state cooperative society may invest or deposit its funds—

- (a) in any of the securities specified in section 20 of the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882); or
- (d) in the shares, securities or assets of a subsidiary institution or any other institution; or
- (e) with any other bank; or
- (f) in such other mode as may be provided in the bye-laws.

Amendment proposed in the Bill

2.206 In section 64 of the principal Act,—

- (i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—
—(b) in any of the securities issued by the Central Government, State Government, Government Corporations, Government Companies, Authorities, Public Sector Undertakings or any other securities ensured by Government guarantees;—;
- (ii) in clause (d), after the words “any other institution”, the words “in the same line of business as the multi-State co-operative society” shall be inserted;
- (iii) for clauses (e) and (f), the following clauses shall be substituted, namely:—
—(e) with any other scheduled or nationalised bank.

Explanation.—For the purposes of this clause, the expression,—

- (i) “scheduled bank” shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934; and
- (ii) “nationalised bank” means a corresponding new bank constituted under sub-section (1) of section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980; or
- (f) in such other manner as may be determined by the Central Government.—.

Rationale behind the amendment

2.207 “Strengthening Governance and Transparency

Some pre-independence era securities are included in the Indian Trust Act which have to be replaced.

Inclusion of phrase “any other institution” in (d) and “as per bye-laws” in (f) in the existing provisions makes it open-ended and have been misused by some MSCS. Investing in scheduled or nationalized banks in place of “any other bank” would make the investment of MSCS safer.—.

Examination by the Committee

2.208 During the briefing by the representatives of the Ministry of Cooperation on the proposals made in the Bill, the Committee observed that investment of funds (Section 64) in other manner as may be decided by Central Govt. should be clearly defined. In regard to the above observation, the Ministry of Cooperation furnished its written reply as under:-

In the existing MSCS Act, 2002, Section 64 (f) provides that an MSCS may invest or deposit its funds “in such other modes as may be provided in the bye-laws”. This leaves scope for investment into dubious entities & fraudulent investment. In the amendment bill, clause 25 (section 64) is being proposed which will substitute in Section 64(f) the words “in such other mode as may be provided in the bye-laws” with “in such other manner as may be determined by Central Govt.”. This will prevent misuse and fraudulent investments. Since the future emerging instruments/avenues for investments may vary from time to time, flexibility is required for the Central Government to determine the manner in which such investments can be made; keeping the overall interest of Cooperatives in mind.

Suggestions received from stakeholders

2.209 Stakeholder organizations like NCUI have stated that this being a restrictive clause will hamper the diversification and promotion of new ventures and expansion of business, which will resultantly affect the economic growth of the cooperative society. NCUI have stated that investing in specified entities will adversely affect such MSCS which is required to invest

its funds by promotion/creation of JV/SPV in India or abroad. Keeping such enabling provision for JV/SPV will encourage the Government's endeavour to push growth of cooperative sector and economy of India. MSCS may also require JV/SPV to flourish in export/import sector. Hence the words -any other institution- may be retained.

- 2.210 Further, they have expressed the view that the proposed provision in Section 64 (f) erodes the autonomy and independent functioning of MSCS which is not in accordance with the spirit of the 97th Constitutional (Amendment) Act 2011.
- 2.211 On similar lines it has been advocated by **KRIBHCO** that investment of Funds in the same line of business will restrict MSCS in expanding in diversified sectors whereas the Govt's endeavour is to push multifaceted growth of cooperative sector. They have suggested that they should be allowed to invest in any business permitted by its bye-laws.
- 2.212 On amendment in Section 64(f) KRIBHCO stated that the decision on investment or deposit is a commercial decision and best taken by in-house professional experts. The manner and mode of such investments shall be as specified in the bye-laws of MSCS, which in any case are approved and registered by Central Registrar.. Pg2,3 They have also expressed the view that there is contradiction in section 19 and section 64.
- 2.213 With regard to Banks, **NAFSCOB** has stated that Scheduled Cooperative Bank should be explicitly incorporated to avoid complications. The Funds of cooperative societies should not be lodged and/or pumped into Nationalised banks. These resources are infused as capital in Nationalised banks for their losses but not recapitalised to address the accumulated losses of cooperative banks. They have also suggested that -Government Companies, authorities, PSUs or any other securities ensured by Government guarantees- must be deleted.
- 2.214 On similar lines **NABARD** has stated that Board approved investment policy which inter alia drafted as per the regulatory guidelines has to be in place. It needs to be reviewed from time to time.

Comments of Ministry of Cooperation

- 2.215 Above suggestions of the stakeholders were brought to the notice of the Ministry of Cooperation. In its reply, the Ministry has stated, -In the existing section 64(b) of MSCS Act, 2002, some redundant and irrelevant securities such as securities of United Kingdom etc. were included as per Indian Trust Act, a pre-independence era Act. Therefore, this provision needed to be replaced with safe and risk-free investments of Central/ State Government. The amended provisions have taken care of this need. The phrase -any other institution- in 64(d) is open-ended and has been misused by some societies for making dubious investment. The proposed amendment will help in preventing such kinds of investments. The existing provision in 64(e) for investment with any other bank is being replaced by scheduled or nationalised bank to ensure safety of investments of cooperative societies. Existing Section 64 (f) provides that an MSCS may invest or deposit its funds -in such other modes as may be provided in the bye-laws-. This leaves scope for fraudulent investment. It is proposed to replace this with -in such other manner as may be determined by Central Govt.- Since the future emerging instruments/avenues for investments may vary from time to time, flexibility is required for the Central Government to determine the manner in which such investments can be made; keeping the overall interest of Cooperatives in mind. Therefore, changes have been proposed in the interest of safety and security of deposits of the members. The businesses to be carried out by an MSCS are described in the bye-laws and the societies can frame their bye-laws democratically and autonomously to decide their line of business. There is no contradiction as the subsidiary institution as per section 19 has also to be in furtherance of the stated objects of the society which are in the bye-laws.-
- 2.216 On the observation of NAFSCOB, the Ministry has inter alia replied that the existing section 64(a) already permits investment in cooperative bank, State Cooperative bank, cooperative land development bank or Central cooperative bank. The MSCS are free to invest in any of the above.

Observation/recommendation of the Committee

- 2.217 **The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.**

Clause No. 26

Provision in the Principal Act

2.218 Section 67: Restrictions on borrowing

(1) A multi-state cooperative society may receive deposits from its voting members, raise loans and receive grants from external sources to such extent and under such conditions as may be specified in the bye-laws:

Provided that the total amount of deposits and loans received during any financial year shall not exceed **ten times** of the sum of subscribed share capital and accumulated reserves: Provided further that while calculating the total sum of subscribed share capital and accumulated reserves, the accumulated losses shall be deducted.

Amendment proposed in the Bill

2.219 In section 67 of the principal Act, in sub-section (1), in the first proviso, for the words ‘ten times’, the words ‘such multiples as may be determined by the Central Government’ shall be substituted.

Rationale behind the amendment

2.220 “Strengthening of Monitoring Mechanism

This will ensure flexibility in borrowing & deposits.

Examination by the Committee Suggestions received by stake holders

2.221 Stakeholders appearing before the Committee have expressed reservation on the aforesaid provision which inter alia are as follows :

KRIBHCO- The board of MSCS can determine their maximum borrowing limit based on their credit worthiness, borrowing capacity and credit rating . The matter should not be determined by the Central Government. It is suggested that reputed credit rating agencies of India like Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL), Investment Information and Credit Rating Agency of India Limited (ICRA), Credit Analysis & Research (CARE), Onida Individual Credit Rating Agency of India (ONICRA)etc. may assess the credit worthiness of multi-state cooperatives societies for raising offunds. MSCS are competing with companies who do not have such restrictions and borrowing is determined by their board and shareholders. Maximum borrowing should be allowed to be determined by the MSCS only for level playing field

NCUI-To retain the autonomy and independent functioning of the society the existing provision under section 67(1) of MSCS Act 2002 may be retained. Only the Board or society is aware about the financial health, credit worthiness etc. of the Society and determining the same by the Central Government is a concern.

NAFSCOB The proposal is vague and discretionary and not in interest of Cooperatives. The existing provision must continue.

NABARD has however stated that regulatory prescription is essential to avoid over leverage.

Comments of Ministry of Cooperation

2.222 The existing section 67 provides for restriction on borrowings on MSCS wherein the total amount of deposits and loans received during any financial year shall not exceed ten times of the sum of subscribed share capital and accumulated reserves. This limit is being proposed to be changed from ‘ten times’ to ‘such multiple as may be determined by the Central Government’. This will provide flexibility for fixing varying limits depending upon requirement and economic scenario in place of the existing fixed limit of ten times. This would also help in bringing financial discipline.

Observation/recommendation of the Committee

2.223 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders and the rationale reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed underthe Clause.

Clause No. 27

Section 70: Appointment and remuneration of auditors

Provision in the Principal Act

2.224 (2) Every multi-state cooperative society shall, at each annual general meeting, appoint an auditor or auditors to hold office from the conclusion of that meeting until the conclusion of the next annual general meeting and shall, within seven days of the appointment, give intimation thereof to every auditor so appointed.

Provided that such auditor or auditors may be appointed from a panel of auditors approved by the Central Registrar or from a panel of auditors, if any, prepared by the multi- state cooperative society.

Amendment proposed in the Bill

2.225 In section 70 of the principal Act, (a)

(a) in sub-section (2), for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely:

Provided that such auditors or auditing firm shall be appointed from a panel approved by the Central Registrar:

Provided further that in case of multi-State co-operative banks, multi-State creditsocieties with deposits of above five hundred crore rupees and multi-State non- credit societies with turnover of above five hundred crore rupees, the auditor shall be appointed from a panel of auditors approved for audit of such societies by the Central Registrar.ö

Rationale behind the amendment

2.226 öIn line with Article 243ZM(3) of the Constitution

Strengthening Governance and Transparency

The amended provision will bring objectivity in appointment of auditor

Observation/recommendation of the Committee

2.227 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Provision in the Principal Act

2.228 (3) Every auditor appointed under sub-section (1) shall, within thirty days of the receipt from the multi-state cooperative society of the intimation of his appointment, inform the Central Registrar in writing that he has accepted, or refused to accept, the appointment.

Amendment proposed in the Bill

2.229 (b) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:ö

ö(3A) An auditor appointed under sub-section (2) shall submit the audit of accounts report to the multi-State co- operative society, within six months from the date of closing of the financial year, to which such accounts relate.ö;

Rationale behind the amendment

2.230 öIn line with Article 243ZM(4) of the Constitution.ö

Observation/recommendation of the Committee

2.231 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Provision in the Principal Act

2.232 (7) (a) The multi-state cooperative society may fill any causal vacancy in the office of an auditor; but while any such vacancy continues, the remaining auditor or auditors, if any, may act: Provided that where such vacancy is caused by the resignation of an auditor, the vacancy shall only be filled by the multi-state cooperative society in general meeting.

Amendment proposed in the Bill

2.233 (c) in sub-section (7), in clause (a), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:ö

öProvided that where such vacancy is caused by the resignation or death of an auditor, the vacancy shall be filled by the board from the panel of auditors from which such auditor was appointed.ö;

Rationale behind the amendment

2.234 öTo keep in line with the procedure for appointment of Auditors from the panel.ö

Provision in the Principal Act

2.235 (9) The remuneration of the auditors of a multi-state cooperative societyö

in the case of an auditor appointed by the board or the Central Registrar may be fixed by the board or the Central Registrar, as the case may be; and subject to clause (a), shall be fixed by the multi-state cooperative society in general meeting or in such manner as the multi-state cooperative society in general meeting may determine.

Explanation- For the purposes of this sub-section, any sums paid by the multi- state cooperative society in respect of the auditorsöexpenses shall be deemed to be included in the expression öremunerationö.

Amendment proposed in the Bill

2.236 (d) after sub-section (9) and the Explanation thereunder, the following sub-sectionshall be inserted, namely:ö

ö(10) The audit report of the accounts of the national co-operative societies shall be laid before each House of Parliament.ö

Rationale behind the amendment

2.237 öIn line with Article 243ZM(5) of the Constitution. Strengthening Governance and Transparency

To bring more transparency in the operations of National Cooperative Societies listed in schedule 2 of the MSCS Act 2002.ö

Examination by the Committee

2.238 During briefing by the representatives of the Ministry of Cooperation on the provisions of the Bill, the Committee observed that in regard to appointment of Auditors(Section 70) the limit prescribed of Rs. 500 crore should be reduced to 100 crore for the panel of Auditors to be approved by Central Registrar. In this regard, the Ministry stated in writing as follows:ö

öExisting Section 70 of MSCS Act, 2002 provides for appointment of Auditors in every MSCS wherein such auditor or auditors may be appointed from a panel of auditors approved by the Central Registrar or from a panel of auditors, if any, prepared by the MSCS.

This is as per Article 243ZM(3) of the Constitution which provides for appointment of auditor by the MSCS from a panel approved by Government or an authority authorized by the Government.

Hence, clause 27 (section 70) of the amendment bill prescribes for appointment of auditors from a panel approved by Central Registrar for all the MSCS. However, there will be two separate panels of auditors for the MSCS- One panel for MSCS Banks and MSCS societies with deposits/turnover of above Rs 500 crore rupees and other panel for remaining MSCS.ö

Suggestions received from stake holders

2.239 With regard to appointment of auditors **NAFSCOB** suggested that the existing provisions should continue. Auditor may be appointed from a panel of auditors, if any, prepared by the multi-state cooperative society. For UCBs the **NAFCUB** held that appointment of Statutory Auditors now needs prior approval of RBI on some stringent guidelines. Thus this eliminates any malpractice. As a result, the Board should be empowered to appoint statutory or other auditors so as to bring ease of doing business with the approval of RBI. For other MSCS, this may be retained if found essential.

2.240 NAFCARD held the view that the General Body shall not reappoint an auditor or auditing firm after a continuous tenure of three years as auditors of the society without a break of at least one year. The above clause will facilitate fixing a ceiling on number of consecutive years for which an auditor or auditing firm can be appointed.

2.241 NABARD in their Presentation before the Committee held the view that MSC Banks are required to take permission of RBI for appointment of auditors, which has not been provided for in the Bill. They have stated that an additional provision under Sec 70 may be included ö as regards MSC Banks, section 30 of BR Act will be applicable ö

Comments of Ministry of Cooperation

2.242 The proposed provision in section 70 is as per Article 243ZM (3) of the Constitution which provides for appointment of auditor by the MSCS from a panel approved by Government or an authority authorized by the Government. (ii) & (iii) Clause 27 (section 70) of the amendment bill prescribes for appointment of auditors from a panel approved by Central Registrar for all the MSCS. However, there will be two separate panels of auditors for the MSCS- One panel for MSCS Banks and MSCS societies with deposits/turnover of above Rs 500 crore rupees and other panel for remaining MSCS. Separate panel for bigger MSCS is proposed because they would require more experienced auditors and bigger teams.

2.243 The Ministry further stated that the suggestion of NAFCARD will be taken into consideration at the time of formulating standards for auditing.

Observation/recommendation of the Committee

2.244 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 28

New insertion 70A

Amendment proposed in the Bill

2.245 öAfter section 70 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:ö

70A. In case of multi-State co-operative societies,⁶⁶

- (i) having an annual turnover more than the amount as determined by the Central Government; or
- (ii) having deposit of more than the amount as determined by the Central Government, the concurrent audit shall be carried out by an auditor appointed from a panel of auditors approved by the Central Registrar.⁶⁷

Rationale behind the amendment

2.246 “Strengthening Governance and Transparency”

Concurrent audit for bigger MSCS will ensure early detection of fraud or irregularities in the society and accordingly prompt course corrections can be taken.⁶⁸

Examination by the Committee

Comments of RBI

2.247 RBI mentioned that they have not prescribed/ approved any panel of audit firms for undertaking the work of Concurrent Audit in any of its Regulated Entities (REs). RBI guidelines of ⁶⁹Master Circular on Inspection & Audit Systems in Primary Response of Reserve Bank of India, mandate that concurrent audit system is mandatory for all UCBs, irrespective of deposits or turnover criteria, whereas the draft bill states that Multi State Cooperative Societies with more than prescribed amount need to implement concurrent audit system. Hence, there could be conflict between the RBI guidelines on concurrent audit system of UCBs and the relevant clause in the MSCS Bill.

Suggestions by stake holders

- 2.248 NAFCUB in their written submission before the Committee stated that since the Cooperative Banks are covered under the scope of RBI inspection and there are exhaustive guidelines issued by RBI of Audit, RBIA, Statutory Audit it should be exempted by way of specific provision
- 2.249 NCDC put forth the view that robust mechanism will be put in place for effective control to preclude the incidence of serious errors and fraudulent manipulations and protect the interest of members and other stakeholders. Provisions of concurrent audit are also provided for banking Companies as per Banking Regulation Act, 1949 [Section30 (1B)].

Comments of Ministry of Cooperation

2.250 The Ministry apprised the Committee that DFS will make suitable amendments in the BR Act so that its provisions are in consonance with the Constitution. The same was also stated by Secretary (DFS) in the JPC meeting held on 19.01.2023. They also stated that as per the prevailing practice, Banking license by RBI is given to entities incorporated under different laws such as Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts under which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for all such entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120B (new insertion) that the provisions of MSCS Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up: Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply.

However, the concern on concurrent audit for UCBs expressed by RBI will be taken into account while prescribing criteria.

Observation/recommendation of the Committee

2.251 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 29

Provision in the Principal Act

2.252 Section 73: Powers and duties of auditors

(5) Where any of the matters referred to in clauses (a) and (b) of subsection (3) or in clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section (4) is answered in the negative or with a qualification, the auditor⁶⁸s report shall state the reason for the answer.

Amendment proposed in the Bill

2.253 ⁶⁹In section 73 of the principal Act, after sub-section (5), the following sub-section shall be inserted, namely:⁶⁶

⁶⁷(6) the multi-State co-operative society or class of multi-State co-operative societies, as the case may be, shall adopt such standards of auditing and accounting as may be determined by the Central Government:

Provided that until such standards of auditing and accounting are specified, the auditing and accounting standards specified by the Institute of Chartered Accountants of India constituted by sub-section (1) of section 3 of the Chartered Accountants Act, 1949 shall be deemed to be the standards of auditing and accounting:

Provided further that the multi-State co-operative banks shall adopt the standards of accounting and auditing, if any, laid down by the Reserve Bank.^o

Rationale behind the amendment

2.254 ^oIn line with Article 243ZM(2) of the Constitution.

Strengthening Governance and Transparency

There is no existing provision for prescription of standards for auditing & accounting. This will ensure standardisation and uniformity in accounting and auditing and bring in transparency and financial discipline.^o

Examination by the Committee

2.255 During briefing by the representatives of the Ministry of Cooperation on the provisions of the Bill, the Committee observed that auditing standards should be uniform for all MSCS (including MSCS Banks) and that there should be a change in Auditors every three years. In this regard, Ministry of Cooperation has stated in its post briefing reply as follows:-

^oIn the existing MSCS Act, 2002, Section 73 relates to powers and duties of Auditors. The standards for Auditing are not specifically mentioned in the existing Act.

In the amendment bill vide clause (section 73(6)), a provision for determining standards for Auditing is being introduced which is in line with the Article 243ZM(2) of the Constitution. This will ensure standardization and uniformity in accounting and auditing and also bring in transparency and financial discipline. The standards for auditing shall be uniform for all MSCS except co-operative banks which are required to follow standards laid down by RBI. The suggestions made by the Hon^{ble} MP will be examined as per the guidelines of the Institute of Chartered Accountants of India, Indian Companies Act etc..^o

Suggestions by stake holders

2.256 NAFCUB opined that ICAI is the regulator of accounting Standards and creator of it. On no choice basis the standards so prescribed by ICAI should be held mandatory. As a result, this provision is at a tangent to the economic needs of the country and requires deletion.

Comments of Ministry of Cooperation

2.257 In the existing MSCS Act, 2002, Section 73 relates to powers and duties of Auditors. The standards for Auditing are not specifically mentioned in the existing Act. In the amendment bill vide section 73(6), a provision for determining standards for Auditing is being introduced which is in line with the Article 243ZM(2) of the Constitution. This will ensure standardization and uniformity in accounting and auditing and also bring in transparency and financial discipline. The standards for auditing shall be uniform for all MSCS except co-operative banks which are required to follow standards laid down by RBI.

Until such standards of auditing and accounting are specified, the auditing and accounting standards specified by the Institute of Chartered Accountants of India constituted by sub-section (1) of section 3 of the Chartered Accountants Act, 1949 shall be deemed to be the standards of auditing and accounting.

Since, cooperatives are governed by Cooperative principles and do not necessarily function as companies, the standards of auditing if need be, may be tailored accordingly

Observation/recommendation of the Committee

2.258 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 30

Provision in the principal Act

2.259 Section 78: Inquiry by Central Registrar

(1) The Central Registrar may, on a request from a federal cooperative to which a multi-state cooperative society is affiliated or a creditor or not less than one-third of the members of the board or not less than one-fifth of the total number of members of a multi-state cooperative society hold an inquiry or direct some person authorised by him by order in writing in this behalf to

hold an inquiry into the constitution, working and financial condition of a multi-state cooperative society:

Provided that no inquiry under this sub-section shall be held unless a notice of not less than fifteen days has been given to the multistate cooperative society.

Amendment proposed in the Bill

2.260 öIn section 78 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-sections shall be inserted, namely:ö

ö(1A) If the Central Registrar is satisfied on the basis of information available with him or furnished to him by a Government agency, that the business of a multi- State co- operative society is being carried on for a fraudulent or unlawful purpose, he may, after informing the multi-State co-operative society of the allegations made against it, by a written order, call on the multi-State co-operative society to furnish in writing any information or explanation, with the endorsement of the board of the society, on matters contained in such order within the time specified therein:

Provided that if the Central Registrar is not satisfied with the explanation of the society, he shall either himself or through an office or agency authorised by him, conduct inquiry into the constitution, working and financial condition of the society.

(1B) Notwithstanding anything contained in this Act, the Central Registrar shall, either suo moto or through an officer or agency authorised by him, conduct inquiry into the constitution, working and financial condition of any multi-State co-operative society, once in such period as may be determined by the Central Government.ö

Rationale behind the amendment

2.261 **“Strengthening of Monitoring Mechanism**

Present power of inquiry of CRCS are very restrictive. This provision will empower CRCS to inquire if he gets information that business of MSCS is being conducted in a fraudulent manner or for unlawful purposes.ö

Suggestions received from stake holders

2.262 With regard to the above, **NAFSCOB** proposed that Central Registrar should not depend on the information given by Govt agency. Central Registrar should have his own mechanism to take an unbiased decision

Comments of Ministry of Cooperation

2.263 The proposed amendment empowers the Central Registrar to act not only on the basis of information furnished to him by government agency but also on the basis of information available with him.

On query of Committee during Clause by Clause consideration of the Bill regarding kind of a Government agency which will furnish information to the Central Registrar regarding fraudulent business etc, the Secretary, Ministry of Cooperation replied that it could be it could be SEBI; it could be SFIO, Income tax, ED, any of them. It could be any agency.

Observation/recommendation of the Committee

2.264 **The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed underthe Clause.**

Clause No. 31

New insertion 85A

Amendment proposed in the Bill

2.265 öAfter Chapter IX of the principal Act, the following chapter shall be inserted, namely:ö

öCHAPTER IXA REDRESSAL OF COMPLAINTS

85A. (1) The Central Government shall appoint, one or more Co-operative Ombudsman with territorial jurisdiction for inquiring into the complaints made by any member of the multi-State co-operative societies regarding their deposits, equitable benefits of society& functioning or any other issue affecting the individual rights of the concerned member, in such manner, as may be prescribed.

(2) The Co-operative Ombudsman shall, on receipt of a complaint, complete the process of inquiry and adjudicate within a period of three months from the date of receipt of the complaint and may issue necessary directions to the society during the course of inquiry and the society shall be bound to comply with the same within a period of one month from the date of issuance of such directions.

(3) The multi-State co-operative society aggrieved by any directions of the Ombudsman may file an appeal in such manner as may be prescribed, within a period of one month before the Central Registrar who shall decide the appeal within a period of forty-five days and the decision of the Central Registrar shall be final and binding:

Provided that the Central Registrar may entertain the appeal after the expiry of said period of one month, if he is satisfied that the society was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

(4) The Ombudsman shall submit periodic reports to the Central Registrar of Co-operative Societies.

(5) The Co-operative Ombudsman while conducting the inquiry under sub-section(1), shall exercise the same powers as are vested in a civil court under the Codeof Civil Procedure, 1908,⁶⁶

- (a) for summoning and enforcing the attendance of persons;
- (b) examining them on oath;
- (c) discovery and production of books of account and other documents; and
- (d) any other matter which may be prescribed.⁶⁷

Rationale behind the amendment

2.266 ^oStrengthening Governance and Transparency

This newly proposed entity would address grievances of members and ensure financial and operational discipline through timely, expeditious and impartial redressal of complaints of the members.⁶⁸

Examination by the Committee

2.267 During briefing on the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, the Committee enquired about the manner of appointment of Ombudsman and his/her qualifications. Further the Committee observed that Ombudsman (Section 85) name should be changed and should be clearly defined. It should be mandatory for appellate authority to dispose appeals within a fix time period. In regard to the above, the Ministryof Cooperation has stated as follows:⁶⁹

^oIn the existing MSCS Act, 2002 there is no provision for -Ombudsman^o Appointment of Cooperative -Ombudsman^o is a new insertion in the amendment Bill. The definition of the Cooperative -Ombudsman^ois in clause(2)(iii)(fa). The Central Government shall appoint, one or more Co-operative Ombudsman for inquiring into the complaints made by any member of the MSCS. The Co- operative Ombudsman will complete the process of inquiry and adjudicate within a period of three months. The MSCS aggrieved by any directions of the Ombudsman may file an appeal within a period of one month before the Central

Registrar who shall decide the appeal within a period of **forty-five days** and the decision of the Central Registrar shall be final and binding. The manner of appointment by Central Government and qualifications of Co-operative Ombudsman will be detailed in the rules to be prescribed.^o Ombudsman already exists in the Banking Sector.

Comments/Suggestions of RBI

2.268 The Reserve Bank had launched the Integrated Ombudsman Scheme (RB- IOS), 2021 in November 2021. This intends to make the process of redress of grievances easier by enabling the customers of the entities regulated by RBI to register their complaints, with one centralised reference point with the objective to resolve customer grievances in relation to services provided by entities regulated by RBI in an expeditious and cost-effective manner. The RB- IOS, 2021 includes under its ambit, among other entities, scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks and non-scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks with a deposit size of ₹50 crore and above, which includes the MSCBs as well. Complaints against regulated entities of RBI presently not covered under RB-IOS, 2021 shall be handled by the Consumer Education and Protection Cell (CEPC) of Reserve Bank of India. Further, RB-IOS, 2021 endeavors to extend its ambit to all REs of RBI in a phased manner.

19. All complaints involving ^odeficiency in service^o in banking, except those listed in the exclusion list, shall be covered under the RB-IOS, 2021. Complainants can lodge their complaints online 24x7 on the Complaint Management System Portal of RBI. A Centralized Receipt and Processing Centre (CRPC) has been set up at Regional Office, Chandigarh as a single point receipt of complaints from customers of all entities regulated by RBI (for the Offices of RBI-Ombudsman and CEPCs) along with a Contact Center including multi-lingual support. The RB-IOS, 2021 adopts -One Nation One Ombudsman^o approach by making the RBI Ombudsman mechanism jurisdiction neutral.

Thus they apprised that the Integrated Ombudsman Scheme and other mechanism for similar purpose for customers of multi-state cooperative UCBs which have been framed under Sec.35A of B R Act also serve similar purposes. Further RBI has accorded regulatory approval to NAFCUB in June 2019 for formation of UO for UCBsector to provide support to its member UCBs.

Comments of Ministry of Cooperation

2.269 In regard to the above submission of RBI, the Ministry stated that as per the prevailing practice, Banking license by RBI is given to entities incorporated under different laws such as Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts under which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for all such entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of MSCS Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up: Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply.

However, the concern on concurrent audit for UCBs expressed by RBI will be taken into account while prescribing criteria.

Suggestions by stake holders

- 2.270 NCDC held that it would provide an easy, cheap and effective dispute redressal mechanism for the members of cooperative society and improve efficiency in its functioning and also speed up the disposal of the complaints. NAFSCOB recommended that the Criteria for appointment of Ombudsman should be clearly spelt out. They have further suggested that Cooperative Ombudsmen be drawn from cooperatives preferably those retired from National Level MSCS for better understanding of issues and give an unbiased judgement.
- 2.271 For UCBs, NAFCUB argued that since co-operative banks are covered under the purview of Banking Ombudsman Scheme as per RBI guidelines, there is no need for separate "Co-operative Ombudsman". This is more so with UCBS are also part of Integrated Ombudsman scheme of Central Govt./ RBI apart from banking Ombudsman.

Comments of Ministry of Cooperation

- 2.272 The criteria for appointment of Ombudsman under section 85A will be prescribed in the rules and the suggestion of NAFSCOB for drawing out people from Cooperatives preferably those retired from National Level MSCS will be taken into consideration at the time of framing Rules. The suggestion of NAFCUB will be considered at the time of framing rules for appointment of Ombudsman and the manner of addressing grievances by the Ombudsman.
- 2.273 The Ministry further apprised that the board of the MSCS is already responsible for grievance redressal of the members. However, the suggestion for members to approach society first for grievance redressal and thereafter, only aggrieved members to approach Ombudsman will be considered at the time of framing rules.

Observation/recommendation of the Committee

- 2.274 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.**

Clause No. 32

Provision in the Principal Act

2.275 Section 86: Winding up of multi-state cooperative societies

(1) If the Central Registrar, after audit has been conducted under section 70 or special audit has been conducted under section 77 or an inquiry has been held under section 78 or an inspection has been made under section 79, is of opinion that the society ought to be wound up, he may, after giving the society a reasonable opportunity of making its representations by order, direct it to be wound up.

Amendment proposed in the Bill

2.276 In section 86 of the principal Act,

- (a) in sub-section (1), after the words and figures under section 79, the words and figures for section 108 shall be inserted;

Rationale behind the amendment

2.277 Section 108 i.e. proceedings relating to inspection also included as grounds for initiating winding up.

Observation/recommendation of the Committee

- 2.278 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.**

Provision in the Principal Act

- 2.279 (2) The Central Registrar may, of his own motion and after giving the multi-state cooperative society a reasonable opportunity of making its representation, make an order directing the winding up of the multi-state cooperative society,
- (a) where it is a condition of the registration of the society that the society shall consist of at least fifty members and the number of members has been reduced to less than fifty; or

Amendment proposed in the Bill

2.280 ~~(b)~~ in sub-section (2),

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:

~~(a) where the number of members or the number of societies or the number of persons, as the case may be, has at any time reduced below the number of members or societies or persons as specified in sub-section (2) of section 6:~~

Provided that the multi-state society shall be given six months time to restore the number of members or societies or persons to the requisite number;

Rationale behind the amendment

2.281 “Strengthening of Monitoring Mechanism

This will give an opportunity to MSCS to restore the number of requisite members.

Observation/recommendation of the Committee

2.282 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Provision in the Principal Act

- 2.283 (b) where the multi-state cooperative society has not commenced working within a period of six months of the date of its registration or such extended period as the Central Registrar may allow in this behalf or has ceased to function in accordance with **cooperative principles**.

Amendment proposed in the Bill

2.284 ~~(ii)~~ in clause (b), for the words ~~co-operative principles~~, the words ~~co- operative principles~~; or

~~(iii)~~ after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:

~~(c) where the Central Registrar has reasons to believe that the registration was obtained by misrepresentation of facts, submission of false or misleading information, suppression of material facts or fraud thereby compromising the spirit of co-operation.~~

Rationale behind the amendment

2.285 ~~This will ensure weeding out of societies trying to get registered with false information and fraudulent documents.~~

Observation/recommendation of the Committee

2.286 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Provision in the Principal Act

- 2.287 (5) Notwithstanding anything contained in this section, no cooperative bank shall be wound up except with the previous sanction, in writing of the Reserve Bank.

Amendment proposed in the Bill

2.288 ~~(c) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:~~

~~(5) Notwithstanding anything contained in this section, in case of winding up of multi- State co-operative banks, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 shall also apply.~~

Rationale behind the amendment

2.289 ~~To ensure applicability of BR Act also in case of MSCS Banks.~~

Provision in the Principal Act

2.290 (6) Notwithstanding anything contained in this section, the Central Registrar shall make an order for the winding up of a multi-state cooperative society, if the society, by a resolution passed by two-third majority of members present and voting in a general meeting decides for winding up of that society.

Amendment proposed in the Bill

2.291 (d) in sub-section (6), the following shall be inserted, namely:

Provided that prior to winding up, no objection from the institutional lenders, who have outstanding loans from the society, shall be required in writing.

Explanation. For the purposes of this proviso, the expression "institutional lenders" includes banks, savings and loan association, trust company, insurance company, real estate investment trust, pension fund and the like.

Rationale behind the amendment

2.292 To ensure that interest of institutional lenders are protected in case of winding up.

Comments/views of RBI

2.293 In their submission before the Committee, RBI stated that the new provision says that notwithstanding anything contained in this section, in case of winding up of multi- state cooperative banks, the provisions of the BR Act, 1949 shall also apply. This clause does not recognise the requirement of prior approval of RBI. This may affect depositors' interest and financial stability. Further, DICGC coverage is available only to eligible cooperative banks as defined in section 2(gg) of the DICGC Act. Section 2(gg) (i) of the DICGC Act 1961, provides that an order for the winding up, or an order sanctioning a scheme of compromise or arrangement or of amalgamation or reconstruction, of the bank may be made only with the previous sanction in writing of the Reserve Bank. Hence, if the proposed Section 86(5) of MSCS Act, 2002 is implemented, the multi-statecooperative banks may lose the deposit insurance cover provided under DICGC Act.

Examination by the Committee

2.294 As per Clause No. 32, in case of winding up of Cooperative Bank, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 shall also apply. As per the Principal Act no cooperative bank could be wound up except with the previous sanction, in writing of the Reserve Bank. In this regard, Ministry of Cooperation was asked about the rationale for subjecting MSCS Banks to twin regulations when they should specifically be included within the jurisdiction of RBI.

Ministry of Cooperation in its reply stated as follows:-

2.295 As per the prevailing practice, Banking license by RBI is given to entities incorporated under different laws such as Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts under which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for all such entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of MSCS Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up: Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply. This proposed provision is as per Article 243ZI and the third proviso to Article 243 ZL of the Constitution.

2.296 During the process of Inter-ministerial consultation, Department of Financial Services (DFS) vide their letter dated 04.10.2022 informed that proposed revised Bill is largely aligned with BR Act and thus, the DFS agrees with and supports the amendment Bill. Further, DFS will make suitable amendments in the BR Act so that its provisions are in consonance with the Constitution..

Observation/recommendation of the Committee

2.297 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed underthe Clause.

Clause No. 33

Provision in the Principal Act

2.298Section 94: Execution of decisions, etc.

Every decision or order made under section 39 or section 40 or **section 83 or** section 99 or section 101 shall, if not carried out,

Amendment proposed in the Bill

2.299 öIn section 94 of the principal Act, in the opening paragraph, after the words andfigures "section 83 or", the words and figures "section 84 or" shall be inserted.ö

Rationale behind the amendment

2.300 öTo put in place mechanism for implementation of awards of arbitrator.ö

Observation/recommendation of the Committee

2.301 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause includingthe rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 34

Provision in the Principal Act

Section 98: Recovery of sums due to Government

2.302(2) Sums due from a multi-state cooperative society to the Central Government or a State Government and recoverable under subsection (1) may be recovered firstly from the property of the society and secondly from the members, past members or the estates of deceased members, subject to the limit of their liability: Provided that the liability of past members and the estate of deceased members shall in all cases be subject to the provisions of section 37.

Amendment proposed in the Bill

2.303 öIn section 98 of the principal Act, after sub- section (2), the following sub-sectionshall be inserted, namely:ö

"(3) The Central Registrar shall also have the power to recover the following duesby attaching bank accounts of defaulting multi-State co- operative societiesö

- (a) the co-operative education fund referred to in clause (b) of sub-section (1) ofsection 63;
- (b) the Co-operative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fundestablished under section 63A; and
- (c) the expenses incurred by the Co-operative Election Authority for conduct of elections.ö

Rationale behind the amendment

2.304 “Enabling raising of funds by Cooperative Sector

To ensure recovery of dues of CEF, proposed rehabilitation Fund, etc.ö

Examination by the Committee

Comments of RBI

2.305 The proposed amendment to Section 98 gives power to Central Registrar to attach bank accounts of defaulting MSCS for recovery of dues to Cooperative EducationFund, Cooperative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund and expensesincurred by the Cooperative Election Authority. It may be mentioned that as per existingprovisions (Section 94), Central Registrar is deemed to be a Civil Court when exercisingany powers under this Act for the recovery of any amount by attachment or when passingany orders. With the amendment proposed, non-contribution to the said Funds has beenmade an offence making the bank accounts of defaulting MSCS liable for attachment. This may be adversarial in situations such as where there are incipient signs of net worth/ deposit erosion or default in payment of deposit insurance premium or transfer of fundsto Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund) or restrictions on expense have been imposed by RBI. It is therefore suggested that any attachment of bank accounts of Multi-state UCB should only be with prior approval of RBI.

Comments of Ministry of Cooperation

2.306 Contribution to Co-operative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund will be from MSCS which are in profit for the preceding three financial years, limitedto one crore rupees or one per cent. of the net profits of such multi- State co-operative society, whichever is less. Contribution to cooperative education fund (CEF) is already there in the existing section 63 of the Act which provides for credit of one per cent of netprofits to the National Cooperative Union of India Limited (NCUI). Since contribution to the aforementioned funds is a statutory compliance like Income tax/ GST, the compliances and recovery has to be done without any prior approval of any other authority.

Observation/recommendation of the Committee

- 2.307 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed underthe Clause.**

Clause No. 35**New insertion 98A****Amendment proposed in the Bill**

- 2.308 (1) ôAfter section 98 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:ô
"98A. The Central Registrar may, on an application received from any party, review his decision under clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub-section of section 94:
Provided that no application for review shall be entertained against the recovery certificate issued by the Central Registrar or by any person authorised by him in writing in this behalf, unless the applicant deposits with the concerned society, fifty per cent. of the amount of the recoverable dues:
Provided further that no application for review shall be entertained, if made after sixty days of the date of receipt of the decision or order:
Provided also that the Central Registrar may entertain any such application madeafter such period, if the applicant satisfies that he had sufficient cause for not making the application within such period."

Rationale behind the amendment

- 2.309 ôTo provide an avenue for review of decisions for recovery of dues.ô

Observation/recommendation of the Committee

- 2.310 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause includingthe rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.**

Clause No. 36**Provision in the Principal Act****2.311 Section 103: Cooperative societies functioning immediately before reorganisation of states**

- (1) Where, by virtue of the provisions of Part II of the State Reorganisation Act, 1956 (37of 1956) or any other enactment relating to reorganisation of states, any cooperative society which immediately before the day on which the reorganisation takes place, had its objects confined to one state becomes, as from that day, a multi- state cooperative society, it shall be deemed to be a multi- state cooperative society registered under the corresponding provisions of this Act and the bye-laws of such society shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, continue to be in force untilaltered or rescinded.

Amendment proposed in the Bill

- 2.312 In section 103 of the principal Act, in sub-section (1), the following provisos shallbe inserted, namely:ô

"Provided that where all the successor States take necessary steps to divide or reorganise such deemed multi-State co-operative society into State co-operativesocieties in order to confine their objects, services and the members to respective States within a period of three years, such deemed multi-State co-operative society shall cease to be a multi-State co-operative society: Provided further thatthe deemed multi-State co-operative society other than those mentioned in the first proviso shall submit an application for registration and obtain the certificate of registration from the Central Registrar."

Rationale behind the amendment

- 2.313 ôOption for successor States for the re-organisation of deemed MSCs into State societies within a period of 3 years.ô

Suggestions by stake holders

- 2.314 NABARD held the view that the provision is required to enable the continuation of good working Cooperative Societies as MSCS in the successor states. It will avoid unwarranted bifurcation of societies post reorganization of states.

Observation/recommendation of the Committee

2.315 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed underthe Clause.

Clause No. 37**Provision in the Principal Act****2.316 Section 104: Offences and Penalties**

(1) A multi-state cooperative society or an officer or member thereof wilfully making a false return or **furnishing false information**, or any person wilfully or without any reasonable excuse disobeying any summons, requisition or lawful written order issued under the provisions of this Act, or wilfully not furnishing any information required from him by a person authorised in this behalf under the provisions of this Act, shall be punishable with fine which shall not be less than **two thousand rupees** and which may extend to **ten thousand rupees**.

(2) Any employer who, without sufficient cause, fails to pay to a multistate cooperative society the amount deducted by him under section 60 within a period of fourteen days from the date on which such deduction is made shall, without prejudice to any action thatmay be taken against him under any other law for the time being in force, be punishablewith fine which may extend to **five thousand rupees**.

(3) Any officer or custodian who wilfully fails to hand over custody of books, accounts, documents, records, cash, security and other property belonging to a multi-state cooperative society of which he is an officer or custodian, to a person entitled under section 54, or section 70, or section 78, or section 79, or **section 89** shall be punishablewith fine which may extend to **two thousand rupees** and in the case of a continuing breach, with a further fine which may extend to **five thousand rupees** for every day during which the breach is continued after conviction for the first such breach.

(4) Whoever, before, during or after the election of delegates under the proviso to sub-section (1) of section 38 or election of members of the board,ô

í ..

(h) offers any gift or promises to offer any gratification to any person with the object, directly or indirectly, of including-

í ..

(iii) a member for having voted or refrained from voting, shall be punishable withimprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both.

Amendment Proposed in the Bill

2.317 ôIn section 104 of the principal Act,ô

(a) in sub-section (1),ô

(i) after the words "furnishing false information", the words "or failing to file anyreturn or information" shall be inserted;

(ii) for the words "two thousand rupees", the words "five thousand rupees" shallbe substituted;

(iii) for the words "ten thousand rupees", the words "one lakh rupees" shall besubstituted;

(b) in sub-section (2), for the words "five thousand rupees", the words "tenthsousand rupees" shall be substituted;

(c) in sub-section (3),ô

(i) after the word and figures "section 89", the words and figures "or to a personrequired to file return under section 120" shall be inserted;

(ii) for the words "two thousand rupees", the words "five thousand rupees" shallbe substituted;

(iii) for the words "five thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shallbe substituted;

(d) in sub-section (4),ô

(i) in clause (h), after the words "to any person", the words "or receives such gift, promise or gratification" shall be inserted;

- (ii) in the long line, occurring after sub-clause (iii) of clause (h), after the words "or with both", the words "and shall also be debarred from contesting elections for a period of three years" shall be inserted;
- (e) after sub-section (4), the following sub-sections shall be inserted, namely:
- (5) Where a multi-State co-operative society,
- a) which is required to provide an explanation or make a statement during the course of inspection, inquiry or investigation, destroys, mutilates or falsifies, or conceals or tampers or unauthorisedly removes, or causes the destruction, mutilation or falsification or concealment or tampering or unauthorised removal of, any document relating to the property, assets or affairs of the society or makes or causes to make a false entry in any document concerning the society;
 - b) makes any investment in contravention of the provision of section 64 or the bye-laws made under this Act;
 - c) Causes unlawful loss to the assets and property of the society; or
 - d) causes unlawful loss to the depositor, the board of directors or the responsible officers of the multi-State co-operative society shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one month but which may extend to one year or with fine which shall not be less than five thousand rupees but may extend to one lakh rupees or with both.

(6) Where the board of directors or officers of the multi-State co-operative society receive any unlawful gains while transacting matters related to such society or utilise any assets of the society for personal unlawful gains, such directors or officers concerned shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one month but which may extend to one year or with fine which shall not be less than five thousand rupees but may extend to one lakh rupees or with both and the proceeds of such unlawful gains shall be recovered from them and deposited in such manner as may be prescribed. ".

Rationale for Amendment

Strengthening of Monitoring Mechanism

2.318 This will ensure member and Board directors discipline. Fine amount was fixed way back in 2002 and needed a revision. Provision needed to enforce furnishing of returns as many MSCS are not filing timely returns.

Receiving of Gifts, promise or gratification for electoral malpractices included as offence. Debarment to contest elections for 3 years will be a deterrent to committing electoral offences. Provision needed to punish for unlawful loss to society/depositors, unlawful personal gain to self, investment in contravention of Bye-laws/Act.

Examination by the Committee

Suggestions by stakeholders

2.319 NCDC has stated that 20 years have elapsed but no revision of penalty has been made. The proposed change is made in consonance with inflation. This will bring the discipline in the society for filing returns in time.

2.320 During the clause by clause consideration, the Committee raised the concern that we are moving towards decriminalisation then why we are using term penalty rather than fine. In this regard, a representative of the Ministry of Cooperation clarified, öAfter the words furnishing false information, the words are failing to file the returns. These are criminal offences.ö

Observation/recommendation of the Committee

2.321 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestion made by the stakeholder and the rationale reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 38

Provision in the Principal Act

2.322 “Section 105: Cognizance of offences

- (1) No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence under this Act.
- (2) No prosecution for offences under section 104 shall be instituted except on a complaint filed in writing by a member of a multi-state cooperative society or by the Central Registrar in the competent court.ö

Amendment Proposed in the Bill

2.323 After section 105 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:ô

"105A. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force."

Rationale for Amendment

2.324 To clarify applicability of other Acts. The provisions of this Act shall be in additionto, and not in derogation to any other Act. In fact, this is not only for BR Act but for all other Acts.

Observation/recommendation of the Committee

2.325 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause includingthe rationale reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 39

Provision in the Principal Act

2.326 "Section 106 Copies of bye-laws, etc., to be open to inspection

Every multi-state cooperative society shall keep a copy of the rules and its bye- laws and also a list of its members open to inspection free of charge at all reasonable times, at the registered address of the society.ö

Amendment Proposed in the Bill

2.327 For section 106 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:ô

"106. (1) Every multi-State co-operative society shall appoint a Co-operative Information Officer to provide the information relating to affairs and managementof the society to the members of the society and such information shall be confined to the information falling under the disclosure norms specified by the society in its bye-laws.

(2) Any member of multi-State co-operative society shall make an application, accompanying such fee as may be prescribed, to get information specified in sub-section (1).

(3) The Co-operative Information Officer shall, within thirty days from the date of receipt of application, either provide the information or reject the application specifying the reason to do so.

(4) Any member of the multi-State co-operative society whose application has been rejected may prefer an appeal to the Co-operative Ombudsman within a period of one month from the date of such rejection and his decision shall be finaland binding.

106A. Every Chief Executive of multi-State co-operative society shall keep a copy of the rules and its bye-laws and also a list of its members open to inspection free of charge at all reasonable times, at the registered address of the multi-State co-operative society."

Rationale for the proposed amendment

2.328 ôIn line with Article 243ZO(1) of the Constitution.

Strengthening Governance and Transparency: More structured mechanism needed for furnishing information to members. This will bring in transparency in governance and will ensure accountability.ö

Examination by the Committee

Suggestions by stakeholders

2.329 **As per NAFSCOB**, every multi-State cooperative society shall appoint a Co- operative Information Officer (CIO) or designate any officer in the MSCS to officiate as CIO to provide the information relating to affairs and management of the society to the members of the society and such information shall be confined to the information falling under the disclosure norms specified by the society in its bye-laws.

2.330 NAFCUB has suggested that the Right to Information Act, 2005 shall not be applicable to MSCSs provided they do not have equity stake or substantial interest in the society by way of funding or investment by Government of India or for that matter any Government company/organization or any State Government.

2.331 According to **NCDC**, this will bring in the transparency in the working of the society. The access to information will help in making cooperative societies accountableand also useful for other purposes which would serve the overall interests of the members of the society.

Comments of the Ministry

- 2.332 The proposed provision for appointment of 'Information Officer' in MSCS is in line with Article 243ZO(1) of the Constitution. It is upon the MSCS to designate such Information Officer either from its existing employees or employ a separate officer for this purpose. Further, the information officer will provide the information relating to affairs and management of the society to the members of the society and such information shall be confined to the information falling under the disclosure norms specified by the society in its bye-laws. This will improve transparency in the working of cooperatives.

Observation/recommendation of the Committee

- 2.333 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders and the rationale reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.**

Clause No. 40**Provision in the Principal Act****2.334 Section 108: Inspection of books of account, etc., of multi-state cooperative society**

(1) The books of account and other books and papers of every multistate cooperativesociety shall be open to inspection during business hours-

(i) By the **Central Registrar**, or

Amendment Proposed in the Bill

- 2.335 In section 108 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (i), after the words "**Central Registrar**" the words "**or any person authorised by him in this behalf, not below the rank of Assistant Commissioner or equivalent**" shall be inserted.

Rationale for the proposed amendment

- 2.336 To facilitate inspection by office of CRCS.

Examination by the Committee

- 2.337 During the Clause by Clause examination of the Bill, there was an observation about the additional financial burden of that legislation on the stakeholders and it was suggested to do a cost of compliance at some stage. In this regard, the Secretary, the Ministry of Cooperation submitted as under-

It should be in the case of concurrent audit. Where there is a need for a concurrent audit, suppose the Government of India imposes a tax of Rs. 10,000 crore or Rs. 5,000 crore, a multi-state cooperative society with a turnover of more than Rs. 5,000 crore will have to get a concurrent audit done. Concurrent audit is expensive. That's why you have to make efforts after seeing that. But we will have to work out the cost of compliance in the case of concurrent audit.

The Nodal Ministry further clarified that the suggestion to exclude members from inspecting the books of accounts and other books of the MSCS is not accepted as it goes against the principle of transparency.

Suggestions by stakeholders

- 2.338 NAFSCOB has suggested, "by the Central Registrar, or any person authorized by him in this behalf, not below the rank of Assistant Commissioner or equivalent at a national level (Not at the state level)"
- 2.339 In this regard, NAFCUB has stated that this provision fails to maintain secrecy/and disclosure norms as stipulated by RBI for sharing of information. While there is no objection for sharing of any information with any of the regulatory authorities, for members this open provision violates of RBI secrecy and disclosure norms. It has proposed to add to clause (iii) of sub-section 1 of Section 108, "Provided any member of the bank may inspect any of the registers or records during office hours in so far as it relates to his/her own business transactions."
- 2.340 Kendriya Bhandar has suggested that The Section 108(1)(iii) in the Principal Act i.e. MSCS Act 2002 provides similar power to members of a society as are vested in Central Registrar/Central Government and a number of members in existing societies are misusing this provision with vested interest. This is practically not feasible to provide access to every member, if they demands so, to inspect or to have copy of every books and papers of the society. If similar powers as vested in Central Registrar or officer authorized by him/Government, a situation may also arise when a member may like to inspect or ask copy of every book and paper held in any society and if this is allowed even large working/functional society will come to grinding halt.

Therefore, Section 108(1)(iii) may be deleted from the Principal Act. Further, in case, a member submits any credible information/ complaint to Central Registrar, based upon such information, Central Registrar may call for relevant information from the Society and may take such action as may be deemed fit & necessary as per MSCS Act, 2002.

Comments of the Ministry of Cooperation

2.341 As per the existing provision of section 108 of MSCS Act 2002, the books of account and other books and papers of every multi-State cooperative society shall be open to inspection during business hours by the Central Registrar, or by such officer of the Government as may be authorised by the Central Government in this behalf or by the members of the multi-state cooperative society. In the proposed amendment, in addition to Central Registrar, any person authorized by him not below the rank of Assistant Commissioner has been authorized for inspection.

2.342 View of the apprehensions of the Committee with regard to word penalty, the Ministry of Cooperation submitted as under:

It should be in the case of concurrent audit. Where there is a need for a concurrent audit, suppose the Government of India imposes a tax of Rs. 10,000 crore or Rs. 5,000 crore, a multi-state cooperative society with a turnover of more than Rs. 5,000 crore will have to get a concurrent audit done. Concurrent audit is expensive. That's why you have to make efforts after seeing that. But we will have to work out the cost of compliance in the case of concurrent audit.

2.343 The Nodal Ministry further clarified that the suggestion to exclude members from inspecting the books of accounts and other books of the MSCS is not accepted as it goes against the principle of transparency.

Observation/recommendation of the Committee

2.344 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 41

Provision in the Principal Act

2.345 Section 116: Power to amend Second Schedule

(1) If the Central Government is satisfied that any multi-state cooperative society should be designate as a national cooperative society or any national cooperative society specified in the Second Schedule should be omitted from the said Schedule, it may, by notification, amend the said Schedule so as to include therein such multi-state cooperative society or exclude therefrom such national cooperative society, and thereupon the said Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

(2) A copy of every notification under **sub- section (1)** shall be laid before each House of Parliament as soon as may be after it is made.

Amendment Proposed in the Bill

2.346 In section 116 of the principal Act,â

(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:ô

"Power to amend Schedules";

(ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:ô

"(1A) If the Central Government is satisfied that it is necessary or expedient so to do, it may, by notification, amend the First Schedule and the third Schedule and thereupon such Schedules shall be deemed to have been amended accordingly:Provided that in case of the First Schedule, such notification shall be used only for adding to the co-operative principles in the list;

(iii) in sub-section (2), for the word, brackets and figure "sub-section (1)ô, the words, brackets, figures and letter "sub-sections (1) and (1A)ô shall be substituted.ô

Rationale for the proposed amendment

2.347 To include powers to amend the proposed third schedule and facilitate additionof Cooperative principles to the first schedule.

Examination by the Committee**Suggestions by stakeholders**

2.348 As per Clause 41 of the Bill which aims to amend Section 116 of the Bill, if the Central Government is satisfied that it is necessary or expedient so to do, it may, by notification, amend the First Schedule and the third Schedule and there upon such Schedules shall be deemed to have been amended accordingly, In this regard NAFCUB has stated that this schedule includes the cooperative principles agreed upon by the international cooperative alliance and the Government of India is a signatory to it. Therefore, there is no justification to empower the Government to amend the same. Secondly, a provision should be made that all the registered multistate cooperative societies shall be default deemed to be member of their sectoral federations and National/State Level/Union Territory Cooperative Unions. NAFCUB has also suggested that in the third schedule the Acts like the Insolvency Act, SARFAESI Act, Income tax and the Negotiable Instruments Act should also be included.

Comments of the Ministry of Cooperation

2.349 (i) The proposed amendment in section 116 regarding amendment in first schedule containing Cooperative Principles is limited to only adding to the list of Cooperative Principles and any addition will be made keeping in consideration the National/ International obligations.
(ii) Regarding suggestion by NAFCUB that a provision should be made that all the registered multistate cooperative societies shall be deemed by default to be member of their sectoral federations and National/State Level/Union Territory Cooperative Unions. This is not in accordance with cooperative principle of Voluntary membership'. The National federations should make adequate efforts to expand their membership to all cooperatives.
(iii) The list of Acts covered in the third schedule is adequate

Observation/recommendation of the Committee

2.350 **The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stakeholders and the rationale reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.**

Clause No. 42**Provision in the Principal Act****2.351 Section 120: Filing of returns**

Every year within six months of the closure of the accounting year every multi-state cooperative society shall file the following returns with the Central Registrar, namely-

- (a) annual report of the activities
- (b) audited statements of accounts;
- (f) any other information required by the Central Registrar in pursuance of any of the provisions of this Act.

Amendment Proposed in the Bill

2.352 In section 120 of the principal Act,â

- (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:ô
"(a) annual report of the activities including details of board decisions which were not unanimous;";
- (ii) for clause (f), the following clauses shall be substituted, namely:ô
"(f) disclosure regarding employees who are relatives of Members of board;
(g) declaration of any related party transactions by the board of directors; and
(h) any other information required by the Central Registrar in pursuance of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder.".â

Rationale for the proposed amendment**2.353 Strengthening Governance and Transparency**

This will increase transparency and help in keeping a watch over controversial decisions.

- (f) To curb nepotism and increase transparency in recruitment.
- (g) Transparency in the board of MSCS.

Examination by the Committee

2.354 During the briefing on the provisions contained in the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, the Committee asked for the comments of the Ministry of Cooperation on board decisions which are not unanimous and whether the annual report will contain names of the members disagreeing (Section 120). Will there be a dissenting note? Why has the decision not been Unanimous? A Brief note on that could be made mandatory. In this regard, the Ministry of Cooperation in its post briefing reply stated as under:-

“In response to the concern of the committee the nodal ministry stated that in the existing MSCS Act, 2002 there is no provision for reporting board decisions which are not unanimous. Vide substitution of Section 120(i)(a) which is being proposed in the amendment bill, all MSCS will have to submit their Annual report along with the details of such Board decisions which were not unanimous. This will improve transparency in the functioning of the MSCS.”

Observation/recommendation of the Committee

2.355 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 43: Insertion of new sections 120A and 120B.

Provision in the Principal Act

2.356 New insertion

Amendment Proposed in the Bill

2.357 After section 120 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:–

“120A. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, and without prejudice to the provisions of the Information Technology Act, 2000, the Central Government may, from such date as may be notified, require that–

(a) such applications, returns, reports, statement of accounts, or any other particulars or document as may be required to be filed or delivered under this Act or the rules made thereunder, shall be filed in the electronic form and authenticated;

(b) such document, notice, any communication or intimation, as may be required to be served or delivered under this Act, shall be served or delivered in the electronic form and authenticated;

(c) such applications, returns, reports, statement of accounts, registers, bye-laws or any other particulars or documents and returns filed under this Act or the rules made thereunder shall be maintained by the Central Registrar in the electronic form and registered or authenticated, as the case may be;

(d) such inspection of bye-laws, returns, reports, statement of accounts or any other particulars or documents maintained in the electronic form, as is otherwise available for inspection under this Act or the rules made thereunder, may be made by any person through the electronic form; and

(e) such fees, charges or other sums payable under this Act or the rules made thereunder shall be paid through the electronic form,

in such manner as may be prescribed.

(2) The Central Registrar shall–

(a) issue certificate of registration;

(b) register the amendment of bye-laws;

(c) register change of registered office;

(d) register any document;

(e) issue any certificate;

(f) issue notice; and

(g) receive such communication as may be required to be registered or issued or recorded or received, as the case may be, under this Act or the rules made thereunder or perform duties or discharge functions or exercise powers under this

Act or the rules made thereunder or do any act which is by this Act directed to be performed or discharged or exercised or done by the Central Registrar, in the electronic form in such manner as may be prescribed.

120B. The provisions of this Act shall apply to a multi-State co-operative society in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up:

Provided that in case of a multi-State co-operative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 shall also apply.ö

Rationale for the proposed amendment

2.358 120A: Ease of doing business

This is a newly added provision. Paperless / digital office is need of the hour. e- filing of reports/documents will be enabled under the Act. This will also promote ease of doing business. Separately, office of CRCS is being computerized.

120B: In line with Article 243ZI and 243ZL (3rd proviso) of the Constitution and This will clarify jurisdictional issues between BR Act and the present Act.

Examination by the Committee

Comments of RBI

2.359 RBI with respect to the insertion of Section 120B, have stated that this proposed insertion of Section 120B may lead to uncertainty regarding the legal enforceability of guidelines issued by RBI. The Reserve Bank is of the opinion that word öalsoö shall not provide primacy to the provisions of BR Act for multi-state co-operative societies carrying out banking business. It is of the opinion that proposed modified Section 120B addresses the concerns only to a limited extent and it cannot be treated as non-obstante clause giving primacy to the BR Act and providing overriding powers to RBI in case of multi- state cooperative banks. Though by virtue of the non-obstante clause in section 56 of the BR Act, it can be said that in case of any conflict between the provisions in these two Acts, the provisions of the BR Act will prevail, the possibility of further legal issues arising in this regard may not be ruled out in absence of express provision regarding primacy of the BR Act over the MSCS Act. Hence, in order to avoid possible conflict, it is suggested for deletion of the word -alsoö from the proviso to the proposed section 120B or add an overarching provision in Section 2, as suggested.

Comments of the Ministry of Cooperation

2.360 The proposed provision 120B is as per Article 243ZI and the third proviso to Article 243 ZL of the Constitution.

As per the prevailing practice, Banking license by RBI is given to entities incorporated under different laws such as Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts under which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for all such entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of MSCS Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up: Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply.

2.361 When it was further asked, how do they intend to avoid potential dispute and ambiguity about the enforceability of RBI's guidelines under the law, the Ministry of Cooperation stated that during the process of Inter-ministerial consultation, Department of Financial Services (DFS) vide their letter dated 04.10.2022 informed that proposed revised Bill is largely aligned with BR Act and thus, the DFS agrees with and supports the amendment Bill and DFS will make suitable amendments in the BR Act so that its provisions are in consonance with the Constitution. The same was also stated by Secretary (DFS) in the JPC meeting held on 19.01.2023.

2.362 In response to the concern raised regarding dual regulation of the cooperative banks the nodal ministry further clarified thatö

öAs per the prevailing practice, Banking licence by RBI is given to entities incorporated under different laws such as Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts under which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for all such entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of MSCS Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up. However, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply to multi-State Co-operative Banks. This is in line with Article 243ZI and the third proviso to Article 243 ZL of the Constitution.ö

Suggestions by stakeholders

- 2.363 NCDC :It will make process easier and faster for filing the returns and would promote digital governance as well as paperless offices.
- 2.364 According to NABARD, this is in tune with the provisions of State Cooperative Societies Act in various states and BR Act (AACS), 1949.
 section 120A(1)- At all places where authentication is required, ~~by digital signature~~ may be added.
 section 120(j) -Details of frauds/ irregularities observed during the year can be added.
- 2.365 During clause by clause examination of the Bill, the Committee noted that in the case of multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the provision of Banking Regulation Act shall also apply. So, there was an observation that whichever are the higher standards, should be applied. In this regard, the Secretary, the Ministry of Cooperation submitted that RBI regulations will be in addition to the regulations of this Act. But for example RBI cannot, through BR Act, change the DNA structure of any multiple-State cooperative society. Therefore, both will have to be concurrently applied. Both these lines have come out of Article 243ZI and 243ZL specifically written in the Constitution.

Observation/recommendation of the Committee

- 2.366 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.**

Clause No. 44

Provision in the Principal Act

2.367 Section 121: Certain Acts not to apply

- (1) The provisions of **the Companies Act, 1956 (1 of 1956)** and **the Monopolies and Restrictive trade Practices Act, 1969 (54 of 1969)** shall not apply to the multi-state cooperative societies.
- (2) The multi-state Cooperative societies registered or deemed to be registered under the provisions of this Act shall not indulge in monopolistic and restrictive trade practices as defined in the **Monopolies and Restrictive trade Practices Act, 1969 (54 of 1969)**.

Amendment Proposed in the Bill

2.368 In section 121 of the principal Act,~~ö~~

- (i) in sub-section (1), for the words and figures "the Companies Act, 1956" and "the Monopoly and Restrictive trade Practices Act, 1969", the words and figures "the Companies Act, 2013" and "the Competition Act, 2002" shall respectively be substituted;
- (ii) in sub-section (2), for the words and figures ~~ö~~monopolistic and restrictive trade practices as defined in the Monopolies and Restrictive trade Practices Act, 1969~~ö~~, the words and figures ~~ö~~monopoly activities as referred to in the Competition Act, 2002~~ö~~ shall be substituted.

Rationale for the proposed amendment

2.369 These are consequential changes owing to amendment in the respective Acts.

Examination by the Committee

Suggestions by stakeholders

- 2.370 NAFCUB has suggested that in the third schedule the Acts like the Insolvency Act, SARFAESI Act, Income tax and the Negotiable Instruments Act should also be included.

Comments of the Ministry of Cooperation

- 2.371 In view of the suggestion of NAFCUB with regard to insertion of the Insolvency Act, SARFAESI Act, Income tax and the Negotiable Instruments Act in the third schedule, the Ministry of cooperation submitted that the list of Acts covered in the third schedule is adequate.

Observation/recommendation of the Committee

- 2.372 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.**

Clause No. 45**Provision in the Principal Act****2.373 Section 123: Supersession of board of specified multi- state cooperative society**

If in the opinion of the Central Government, the board of any specified multi-state cooperative society is persistently making default or is negligent in the performance of the duties imposed on it by this Act or the rules or the bye- laws or has committed any act which is prejudicial to the interests of the society or its members, or has omitted or failed to comply with any directions given to it under section 122 in public interest or that there is a stalemate in the constitution or functions of the board, the Central Government may, after giving the board an opportunity to state its objections, if any, and considering the objections, if received, by order in writing, remove the board and appoint one or more administrators, who need not be members of the society, to manage the affairs of the society for such period not exceeding six months, as may be specified in the order which period may, at the discretion of the Central Government, be extended from time to time, so, however, that the aggregate period does not exceed one year:

Provided that in the case of a cooperative bank, the provisions of this sub-section shall have effect as if for the words "one year", the words "two years" had been substituted.

Explanation.- For the purposes of sections

122 and 123, "specified multi-state cooperative society" means any multi- state cooperative society in which not less than fifty-one per cent, of the paid-up share capital or of total shares, is held by the Central Government.

Amendment Proposed in the Bill**2.374 In section 123 of the principal Act,â**

(i) in sub-section (1),â

(a) for the portion beginning with "or has committed any act" and ending with "the aggregate period does not exceed one year", the following shall be substituted, namely:â

"or has committed any act including fraud, misappropriation and the like which is prejudicial to the interests of the society or its members, or has omitted or failed to comply with any directions given to it under section 122 in public interest or that there is a stalemate in the constitution or functions of the board or the Co- operative Election Authority has failed to conduct elections in accordance with the provisions of this Act, the Central Government may, after giving the board an opportunity to state its objections, if any, and considering the objections, if received, by order in writing, supersede or suspend the board and appoint one or more administrators, who need not be members of the society, to manage the affairs of the society for such period not exceeding six months, as may be specified in the order:";

(b) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:â

"Provided that while taking a decision for supersession or suspension on grounds of failure to conduct election, such action shall only be taken if the Board had not given requisition to hold election to the Co-operative Election Authority within the time limit or not extended necessary assistance as per the provisions of section 45.â;

(ii) for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:â *Explanation.* For the purposes of section 122 and this section, the expression "specified multi-State co-operative society" means any multi-State co-operative society where there is Government shareholding or loan or financial assistance or any guarantee by the Government.â

Rationale for the proposed amendment**2.375 In line with Article 243ZL(1) of the Constitution.****Strengthening of Monitoring Mechanism**

Action needed in cases of fraud or embezzlement. 97th Constitutional Amendment provides for both supersession & suspension and includes additional ground as failure to conduct elections.

Definition of specified societies to be brought in line as per Article 243ZL(1) of the Constitution.

Examination by the Committee**2.376 During the briefing on the provisions contained in the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, the Committee observed that discussion needed on change in definition of specified Society. In this regard, the Ministry of**

Cooperation has stated in its post-briefing replies as below:ô

ôIn the existing MSCS Act, 2002, explanation given under Section 123 (For the purpose of Section 122 and Section 123) states that ôspecified multi-State co-operative societyö means any multi-State co-operative society in which not less than fifty-one per cent of paid-up share capital, or of the total shares, is held by the Central Government. Action for issue of directions by Central Government u/s 122 and supersession u/s 123 can only be taken in case of specified MSCS which are very few in number. The definition of -specified societiesø has to be changed to bring it in line with Article 243ZL(1) of the Constitution. Accordingly, in the amendment Bill, the definition of Specified society has been extended to include those MSCS where there is Government shareholding or loan or financial assistance or any guarantee by the Government.ö

Suggestions by stakeholders

- 2.377 NAFSCOB has stated that supersession of board of specified multi-state cooperative society (1) Role and responsibility of Central Registrar and Reserve Bank of India may be spelt out in Supersession of board of specified multistate cooperative society
- 2.378 National Cooperative Union of India (NCUI) in its submission has stated that the criteria for supersession of the board of specified multi-State cooperative society is well defined in section 123 sub section (1), (2), (3), (4), (5) & (6). The change of explanation/definition of specified MSCS cannot be a criteria of supersession. Where the Govt. having majority stake in any of the multi-State cooperative society there the govt. may take appropriate action as laid down under section 123 sub section (1), (2), (3), (4), (5) & (6). The existing explanation may continue as the revised explanation gives far reaching power to the government which is against the cooperative principles. Further the guarantee given by the Govt. for its scheme to the society should not be treated as guarantee to the society. The government should play the role of a facilitator only. Hence, the explanation under section 123 of the existing MSCS Act 2002 may be retained.
- 2.379 Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO) in submission has stated asunder:ô

ôThere are seven principles which govern the overall functioning of the Cooperatives. The 4th Cooperative Principle is reproduced below: ô

Autonomy and Independence: Cooperatives are autonomous, self-help organisations controlled by their members. If cooperatives enter into agreement with other organisations including Government or raise capital from external sources, they do so on terms that ensure their democratic control by members and maintenance of cooperative autonomy.

Article 43 B of the Constitution of India also envisages autonomous functioning and independence of cooperative societies and stipulates as follows:ô

“43B. The State shall endeavour to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of co-operative societies.”

In the second proviso of Article 243 ZL (1) (Chapter IX B of the Constitution of India), incorporated by 97th Constitutional Amendment, also emphasizes autonomous functioning and democratic control of the cooperative societies.

In this line, Article 243 ZLI (Part IX B of the Constitution of India), incorporated by 97th Constitutional Amendment states that ôsubject to the provisions of this Part, the Legislature of a State may, make provisions with respect to the incorporation, regulation and winding up of cooperative societies based on the principles of voluntary formation, democratic member control, member economic participation and autonomous functioning.ö

Further, in the second proviso of Article 243 ZL (1) is as follows:

“Provided further that the board of any such cooperative society shall not be superseded or kept under suspension where there is no Government shareholding or loan or financial assistance or any guarantee by the Government”

It is apparent from the above that 97th constitutional amendment has envisaged that in case government does not have any share holding or loan or financial assistance or any guarantee, then it will not supersede the Board of such cooperatives. Even in the case where government has any shareholding or provided any loan or financial assistance or any guarantee, the concept of materiality has to be seen. This was the reason that in case of Multi State Cooperative Act 2002, the shareholding was quantified in the explanation part of section 123 which is as follows:-

ôExplanation.- For the purposes of sections 122 and 123, ôspecified multi-state cooperative societyö means any multi-state cooperative society in which not less than fifty-one per cent, of the paid-up share capital or of total shares, is held by the Central Government.ö

Keeping in view the spirit of Article 43B of Constitution, 97th Constitutional Amendment and 4th Cooperative Principle of Autonomy and Independence, we submit that quantification of Government shareholding as specified in Explanation of Section 122 and 123 of MSCS Act 2002 may be retained.ö

- 2.380 National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) in its submission stated, "While bringing the proposal amendment, quantum and purpose of various elements like government shareholding or loans or financial assistance or any guarantee by the government needs to be specified.ö
- 2.381 NCDC has stated in its comments that the provision has been incorporated to bring in effect Article 243ZL (contained in Part IXB as added by the 97th Amendment, 2012) of the Constitution. This change in the definition of specified co-operative societies would help in better monitoring and control, in case any fraud is committed or serious malpractices are found.
- 2.382 In regard to Clause 45 of the Bill which proposes to amend Section 123 of the Principal Act, NAFSCOB has stated that the role and responsibility of Central Registrar and RBI should be spelt out in supersession of board of a specified multi state cooperative society.

Comments of the Ministry of Cooperation

- 2.383 The proposed definition of specified societies is as per Article 243ZL(1) (2nd proviso) of the Constitution . Further, as per article 243 ZT of Constitution, the provisions of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 that are not consistent with the provisions of Part IXB of the Constitution shall continue to be in force until amended or repealed or expiration of one year from the commencement of the Constitution (Ninety-Seventh) (Amendment) Act, 2011, whichever is less. The present proposal would strengthen governance in MSCS and also help in preventing cases of fraud and mismanagement.
- 2.384 The proposed amendment in section 123 is in line with Article 243ZL(1) of the Constitution. Further, to bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of MSCS Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up:
- Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply.
- Cooperative Societies with objects confined to one State are governed under the respective State Cooperative Societies Act as per Entry 32 of the State List of the Constitution.
 - Multi-State Cooperative Society (MSCS) is defined as per Article 243ZH(d) of the Constitution as a cooperative society that has objects not confined to one State. MSCS are governed under Entry 44 of the Union List-I & part IX B of the Constitution.
 - Multi State Cooperative Societies Act, 1984 was passed in 1984 by the Parliament under the said entry of the Union List.
 - The existing Multi State Cooperative Societies Act, 2002 was enacted by repealing the MSCS Act, 1984.

- 2.385 In response to the concern regarding violation of the Cooperative Principle mentioned in article 243 ZI and article 43 B on directive principles of State policy the nodal ministry clarified that The amendment bill is in consonance with the 97th Constitutional Amendment to plug loopholes in the existing legislation and to strengthen governance in the MSCSs, in accordance with the following Cooperative Principles, namely:ö
- (a) Voluntary and Open Membership;
 - (b) Democratic Member Control;
 - (c) Member's Economic Participation;
 - (d) Autonomy and Independence;
 - (e) Education, Training and Information;
 - (f) Co-operation among Co-operatives; and
 - (g) Concern for Community.

It will strengthen democratic functioning and member participation in the MSCS in accordance with the Cooperative Principles. It will help in addressing some of the instances of malfunctioning noticed in the functioning of MSCS and will also bring reforms related to transparency, active membership, ease of doing business, etc.

As far as concerned about taking away the functional autonomy of MSCS, the ministry stated that the amendment bill is in consonance with the Co-operative principles of voluntary formation, democratic member control, member-economic participation and autonomous functioning. It will lead to more active member participation, transparent and responsive governance and free and fair elections. It does not take away the functional autonomy of MSCS. It will facilitate working of the MSCS by bringing in reforms related to ease of doing business.

Observation/recommendation of the Committee

2.386 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed underthe Clause.

Clause No. 46

Provision in the Principal Act

2.387 Section 124: Power to make rules

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the form to be used, the particulars to be given and the conditions to be complied with in the making of applications under section 6 for the registration of a multi-state cooperative society and the procedure in the matter of such applications;

(3) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Amendment Proposed in the Bill

2.388 In section 124 of the principal Act,ô

(a) in sub-section (2),ô

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:ô

"(aa) the guidelines under sub-section (2) of section 7;";

(ii) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:ô

"(ja) the manner in which the board of a multi-State co- operative society shall provide information, documents, personnel, funds or expenses or any other assistance as sought by the Co-operative Election Authority for conducting elections under clause (a) of sub-section (2) of section 43;";

(iii) for clause (k), the following clauses shall be substituted, namely:ô

"(k) the composition of the Selection Committee for appointment of Chairperson, Vice-Chairperson and Members of the Co-operative Election Authority under sub-section (1) of section 45;

(ka) the qualification and experience for appointment of Member of the Authority under clause (iii) of sub-section (3) of section 45;

(kb) the salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the Chairperson, Vice-Chairperson and Members of the Authority under sub-section (5) of section 45;

(kc) the other powers and functions of Chairperson under section 45A;

(kd) the procedure of inquiry under sub-section (2) of section 45B;

(ke) time, places and the procedure to be observed by the Authority in regard to transaction of business at its meetings under sub-section (1) of section 45H;

(kf) other functions of the Authority under clause (iii) of section 45-I;

(kg) the manner of election of members of board by secret ballot under sub-section (3) of section 45J;

(kh) the manner of bearing the expenses for holding elections by the Authority under sub-section (6) of section 45J;

(ki) the manner of discharge of functions by the Returning Officers and observers under sub-section (1) and clause of sub-section (3) of section 45K;

(kj) other functions of the observers under clause (a) of sub-section (3) of section 45K;ô;

- (iv) after clause (m), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(ma) the procedure for recruitment of employees under proviso to clause (e) of sub- section (2) of section 49;";
- (v) clause (o) shall be omitted;
- (vi) after clause (q), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(qa) the manner of maintenance of fund under clause (b) of sub-section (1) of section 63;";
- (vii) after clause (s), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - "(sa) the manner of appointment of Co-operative Ombudsman and submission of complaints to such Ombudsman under sub-section (1) of section 85A;
 - (sb) the manner of filing an appeal by society against directions of Ombudsman under sub-section (3) of section 85A;
 - (sc) other matters under clause (d) of sub-section (5) of section 85A;";
- (viii) after clause (w), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - "(wa) the manner of recovery and deposit of proceeds of unlawful gains under sub-section (6) of section 104;
 - (wb) the manner to make an application with such fee for the purpose of getting information under sub-section (2) of section 106;";
- (ix) after clause (x), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - "(xa) the manner of powers being exercised by the Central Government in respect of matters relating to filing of applications, documents, inspections and the like in electronic form and fee payable to under sub-section (1) of section 120A;
 - (xb) the manner of discharging the functions or exercising powers with respect to matters mentioned therein by the Central Registrar in electronic form under sub-section (2) of section 120A;"
- (a) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) Every rule made under this section and any notification issued under section 116 shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, whileit is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree that the rules and any notification issued under section 116 should not be made, the rule and any notification issued under section 116 shall thereafter have effect only insuch modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule and any notification issued under section 116.".

Rationale for the proposed amendment

2.389 The power to make rules to include all relevant sections.

For sub-section (3): Provide for laying of notification u/s 116 in Parliament. This provisionis already there. It is only a change of place.

Examination by the Committee

Suggestions by stakeholders

2.390 NAFSCOB has stated that the Central Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act. Except in case the following : (Ja) to (Kj) and (ma),(qa) , (xa),(xb) etc. Any agency vested with too many and unlimited powers may tend to fail in their performance.

2.391 NABARD's Response to Annexure II of draft Cabinet Note dated 05/07/2022

Section 124(2)(aa) The words ~~provision of~~~~after~~~~..paid up capital~~~~and before~~~~reserves alongwith~~ may be deleted.

Observation/recommendation of the Committee

2.392 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 47**Amendment of section 125.****Provision in the Principal Act****2.393 Section 125: Power to remove difficulties**

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty. Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

Amendment Proposed in the Bill

2.394 "(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act as amended by the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2022, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the date of commencement of the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2022.".

Rationale for the proposed amendment

2.395 Standard clauses for removal of difficulties for two years.

Observation/recommendation of the Committee

2.396 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

Clause No. 48**INSERTION OF THIRD SCHEDULE.****Provision in the Principal Act****2.397 New insertion****Amendment Proposed in the Bill**

2.398 After Second Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be inserted, namely:ô

ôTHE THIRD SCHEDULE

[See clause (h) of subösection (1) of section 43]

Sl. No.	Name of the Act	Act Number
1.	the Indian Stamp Act, 1899;	02 of 1899.
2.	the Reserve Bank of India Act, 1934;	02 of 1934.
3.	the Central Excises Act, 1944;	01 of 1944.
4.	the Industries (Development and Regulation) Act, 1951;	65 of 1951.
5.	the Prevention of Food Adulteration Act, 1954;	37 of 1954.
6.	the Essential Commodities Act, 1955;	10 of 1955.
7.	the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956;	42 of 1956.
8.	the Wealth-tax Act, 1957;	27 of 1957.
9.	the Customs Act, 1962;	52 of 1962.
10.	the Prize Chits and Money Circulation Scheme (Banning) Act, 1978;	43 of 1978.
11.	the Sick Industrial Companies (Special provisions) Act, 1985;	01 of 1986.

12.	the Securities and Exchange Board of India Act, 1992;	15 of 1992.
13.	the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992;	22 of 1992.
14.	the Foreign Exchange Management Act, 1999;	42 of 1999.
15.	the Competition Act, 2002;	12 of 2003.
16.	the Prevention of Money Laundering Act, 2002;	15 of 2003.
17.	The Companies Act, 2013.ö.	18 of 2013.

Rationale for the proposed amendment

2.399 Any default in payment of dues for the Acts mentioned in the third schedule will lead to disqualification of the Board of Directors.

Observation/recommendation of the Committee

2.400 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.

SHRI CHANDRA PRAKASH JOSHI

CHAIRPERSON,

JOINT COMMITTEE ON THE

MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022

NEW DELHI;

13 March, 2023

22 Phalgun 1944 (SAKA)

APPENDIX-I**MOTION IN LOK SABHA FOR REFERENCE OF THE BILL TO THE JOINT COMMITTEE**

Tuesday, December, 20, 2022/Agrahayana 29, 1944 (Saka)

Shri Amit Shah moved the following motion:-

That the Bill further to amend the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of the following 21 Members from this House, namely:—

Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022.

1. Shri Chandra Prakash Joshi
2. Shri Jagdambika Pal
3. Shri Parbatbhai Savabhai Patel
4. Smt. Poonamben Hematbhai Maadam
5. Shri Ramdas Chandrabhanji Tadas
6. Shri Annasaheb Shankar Jolle
7. Dr. Nishikant Dubey
8. Smt. Sunita Duggal
9. Shri Brijendra Singh
10. Smt. Jaskaur Meena
11. Shri Ram Kripal Yadav
12. Dr. Dhal Singh Bisen
13. Shri Suresh Kodikunnil
14. Shri Manish Tewari
15. Smt. Kanimozhi Karunanidhi,
16. Shri Kalyan Banerjee
17. Shri Sri Krishna Devarayalu Lavu
18. Shri Hemant Shriram Patil
19. Shri Dulal Chandra Goswami
20. Shri Chandra Sekhar Sahu
21. Shri Girish Chandra

and 10 Members from the Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of Members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first week of second part of the Budget Session, 2023;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make;

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of the Members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee; and

that the Speaker shall appoint one of the Members of the Committee to be its Chairperson.—

The motion regarding reference was adopted.

APPENDIX-II**MOTION IN RAJYA SABHA FOR REFERENCE OF THE BILL TO THE JOINT COMMITTEE**

Monday, December 21, 2022

Message from Rajya Sabha:

That at its sitting held on the 21st December, 2022, Rajya Sabha concurred in the recommendation of Lok Sabha to nominate 10 members from Rajya Sabha to associate with the Joint Committee of the Houses on the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022 and also communicated the names of the following members of Rajya Sabha who have been elected to the said Committee:—

1. Shri Ghanshyam Tiwari
2. Shri Surendra Singh Nagar
3. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik
4. Shri Ram Chander Jangra
5. Smt. Rajani Ashokrao Patil
6. Shri Sukhendu Sekhar Ray
7. Shri N.R. Elango
8. Shri Vikramjit Singh Sahney
9. Shri Surjeet Kumar
10. Shri S. Niranjan Reddy

APPENDIX-III

**LIST OF GOVERNMENT AGENCIES AND EXPERTS/
STAKEHOLDERS/ORGANISATIONS**

WHO SUBMITTED MEMORANDA

Sl. No.	Name of Government Agencies and Experts/Stakeholders/Organisations/Individuals
1.	Reserve Bank of India (RBI)
2.	National Federation of State Cooperative Banks (NAFSCOB)
3.	National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies (NAFCUB)
4.	National Cooperative Union of India (NCUI)
5.	Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO)
6.	Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO)
7.	National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED)
8.	National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)
9.	National Cooperative Agriculture & Rural Development Banks Federation Ltd. (NAFCARD)
10.	National Cooperative Development Corporation (NCDC)
11.	National Cooperative Consumers Federation of India (NCCF)
12.	Kendriya Bhandar
13.	Sahakar Bharati
14.	Sahulat Micro Finance Society
15.	PRS Legislative Research

APPENDIX-IV**DETAILS OF THE SITTINGS OF THE JOINT COMMITTEE ON MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022**

Sitting No.	Date of Sitting	Agenda of the sitting and witnesses appeared.
1	05.01.2023	Briefing by the representatives of the Ministry of Cooperation on Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022. (Present: Ministry of Cooperation, Ministry of Law & Justice-Department of Legal Affairs and Legislative Department)
2	19.01.2023	Oral Evidence of the representatives of Reserve Bank of India and Department of Financial Services, Ministry of Finance on Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022. (Present: Ministry of Cooperation)
3	20.01.2023	To elicit the views of representatives of following organizations on Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022: <ol style="list-style-type: none"> 1. National Federation of State Cooperative Banks (NAFSCOB); and 2. National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies (NAFCUB) (Present: Ministry of Cooperation)
4	20.01.2023	To elicit views of the representatives of following organizations on Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022: <ol style="list-style-type: none"> 1. National Cooperative Union of India (NCUI); 2. Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO); 3. Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO); and 4. National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) (Present: Ministry of Cooperation)
5	13.02.2023	To elicit views of the representatives of following organizations on Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022: <ol style="list-style-type: none"> 1. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) 2. National Cooperative Agriculture & Rural Development Banks Federation Ltd. (NAFCARD) 3. National Cooperative Development Corporation (NCDC) 4. National Cooperative Consumers Federation of India (NCCF) (Present: Ministry of Cooperation, Ministry of Law & Justice-Legislative Department)
6	20.02.2023	Clause by Clause consideration of Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 (Present: Ministry of Cooperation, Ministry of Law & Justice-Legislative Department)
7	27.02.2023	Clause by Clause consideration of Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 (Present: Ministry of Cooperation, Ministry of Law & Justice- Department of Legal Affairs and Legislative Department)
8	13.03.2023	Consideration and adoption of the draft report on Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022.

APPENDIX-V**LIST OF WITNESSES WHO TENDERED ORAL EVIDENCE BEFORE THE COMMITTEE****LIST OF OFFICIAL WITNESSES**

Sl. No.	Name of organizations	Date of oral evidence
1.	Ministry of Cooperation	05.01.2023
2.	Ministry of Law & Justice- Department of Legal Affairs	
3.	Ministry of Law & Justice- Legislative Department	
4.	Reserve Bank of India	19.01.2023
5.	Ministry of Cooperation	
6.	Ministry of Finance-Department of Financial Services	
7.	Ministry of Cooperation	20.01.2023
8.	Ministry of Cooperation	13.02.2023
9.	Ministry of Law & Justice- Legislative Department	
10.	Ministry of Cooperation	20.02.2023
11.	Ministry of Law & Justice- Legislative Department	
12.	Ministry of Cooperation	27.02.2023
13.	Ministry of Law & Justice- Department of Legal Affairs	
14.	Ministry of Law & Justice- Legislative Department	

LIST OF WITNESSES

Sl. No.	Name of organizations	Date of oral evidence
1.	National Federation of State Cooperative Banks (NAFSCOB)	20.01.2023
2.	National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies (NAFCUB)	
3.	National Cooperative Union of India (NCUI)	
4.	Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO)	
5.	Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO)	
6.	National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED)	
7.	National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)-	
8.	National Cooperative Agriculture & Rural Development Banks Federation Ltd. (NAFCARD)	
9	National Cooperative Development Corporation (NCDC)	
10	National Cooperative Consumers Federation of India (NCCF)	

APPENDIX-VI**MINUTES OF THE SITTINGS****Minutes of 1st Sitting of The Joint Committee on the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022**

The 1st sitting of the Joint Committee was held on Thursday, the 5th January, 2023 from 1100 hrs. to 1400 hrs. in Committee Room D, Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT**Shri Chandra Prakash Joshi - Chairperson****LOK SABHA**

2. Shri Parbatbhai Savabhai Patel
3. Smt. Poonamben Hematbhai Maadam
4. Shri Ramdas Chandrabhanji Tadas
5. Shr Annasaheb Shankar Jolle
6. Dr. Nishikant Dubey
7. Smt. Sunita Duggal
8. Shri Brijendra Singh
9. Smt. Jaskaur Meena
10. Shri Ram Kripal Yadav
11. Dr. Dhal Singh Bisen
12. Shri Manish Tewari
13. Shri Kalyan Banerjee
14. Shri Sri Krishna Devarayalu Lavu
15. Shri Hemant Shriram Patil
16. Shri Dulal Chandra Goswami
17. Shri Chandra Sekhar Sahu

RAJYA SABHA

18. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik
19. Shri Ram Chander Jangra
20. Shri N.R. Elango
21. Shri Sujeet Kumar

SECRETARIAT

- | | | |
|----------------------------|---|------------------|
| 1. Shri J.M. Baisakh | - | Joint Secretary |
| 2. Shri C. Kalyanasundaram | - | Director |
| 3. Shri Sumesh Kumar | - | Deputy Secretary |
| 4. Ms. Rachna Saxena | - | Deputy Secretary |

REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF COOPERATION

1. Shri Gyanesh Kumar, Secretary
2. Shri Vijay Kumar, Additional Secretary
3. Shri Kapil Meena, Deputy Secretary
4. Shri Amit Sachdeva, Sr. Technical Assistant

REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF LAW & JUSTICE

5. Dr. Niten Chandra, Secretary, Department of Legal Affairs
 6. Shri R.S. Verma, Additional Secretary, Department of Legal Affairs
 7. Shri K. Biswal, Special Secretary, Legislative Department
 8. Shri R. Sreenivas, Additional Legislative Counsel, Legislative Department
2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members to the first sitting of the Joint Committee. While giving a brief background of the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022, he apprised the Members about the agenda of the sitting.
3. Thereafter, the Chairperson invited the representatives of the Ministry of Cooperation and the Ministry of Law & Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department) to brief the Committee on various aspects related to the Multi- State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022. He then drew the attention of representatives from the Ministries to Direction 55(1) and Direction 58 of the Directions by the Speaker, Lok Sabha concerning the confidentiality of the Committee proceedings.
4. The representatives of the Ministry of Cooperation then made a Power Point presentation to the Committee covering the following aspects :- (i) Brief explanation on Multi-State Cooperative Societies and background of the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022. (ii) Need for the amendments to the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 especially in the context of aligning the Act with Constitutional provisions on cooperative societies (iii) Major Amendments relating to electoral reforms, reforms in composition of Board, Membership and meetings, strengthening governance and transparency, monitoring mechanism and other minor amendments proposed in the Bill.
5. The Members, thereafter, sought clarifications on various amendments being proposed in the Bill. Broadly these related to defining the powers of State and Centre incooperative federalism, improving transparency in fund management and defining standards of audit, regulatory mechanism for cooperative Banks, ground of disqualification in election of Board Members, manner of filling up of the casual vacancy, reservation for women, SC and ST communities, appointment of Members and functions of Cooperative Election Authority, eligibility age of CEO, functional autonomy of cooperatives, management of Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund etc.
6. It was also pointed out by some Members that the Ministry must explain the philosophy behind the amendments and give clause by clause presentation in their nextsitting. The Chairperson then directed the Ministry to provide written replies to all the points raised during the sitting.

The representatives of the Ministries then withdrew

7. The Committee, thereafter, briefly deliberated on future course of examination including date of next sitting and need for oral evidence of representatives of RBI and other stakeholders.

The Committee then adjourned.

A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record

Minutes of 2nd Sitting of the Joint Committee on the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022

The 2nd sitting of the Joint Committee was held on Thursday, the 19th January, 2023 from 1500 hrs. to 1630 hrs. in Committee Room D, Parliament House Annex, New Delhi.

PRESENT

Shri Chandra Prakash Joshi - Chairperson

LOK SABHA

2. Shri Jagdambika Pal
3. Shri Ramdas Chandrabhanji Tadas
4. Shri Annasaheb Shankar Jolle
5. Dr. Nishikant Dubey
6. Shri Brijendra Singh
7. Smt. Jaskaur Meena
8. Shri Ram Kripal Yadav
9. Dr. Dhal Singh Bisen
10. Shri Suresh Kodikunnil
11. Shri Manish Tewari
12. Shri Sri Krishna Devarayalu Lavu
13. Shri Hemant Shriram Patil
14. Shri Dulal Chandra Goswami

RAJYA SABHA

15. Shri Surendra Singh Nagar
16. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik
17. Shri S. Niranjan Reddy

SECRETARIAT

- | | | | |
|----|-------------------------|---|------------------|
| 1. | Shri J.M. Baisakh | - | Joint Secretary |
| 2. | Shri C. Kalyanasundaram | - | Director |
| 3. | Shri Sumesh Kumar | - | Deputy Secretary |
| 4. | Ms. Rachna Saxena | - | Deputy Secretary |
| 5. | Shri Bharat Lal Meena | - | Deputy Director |

REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF COOPERATION

1	Shri Gyanesh Kumar	Secretary
2	Shri Vijay Kumar	Additional Secretary
3	Shri Kapil Meena	Deputy Secretary
4	Shri Kumar Ram Krishna	Deputy Secretary

REPRESENTATIVES OF RESERVE BANK OF INDIA (RBI)

1	Shri Jayant Kumar Dash	Executive Director
2	Shri Joseph Raj	Legal Adviser

REPRESENTATIVES OF DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

1	Shri Vivek Joshi	Secretary
2	Shri M.P. Tangirala	Additional Secretary
3	Shri Parshant Kumar Goyal	Director

2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members to the second sitting of the Joint Committee. Then he briefed the members about the agenda of the sitting and stakeholders called for the oral evidence.

3. Thereafter, the Chairperson invited the representatives of the Ministry of Cooperation, Reserve Bank of India (RBI) and the Ministry of Finance (Department of Financial Services) to brief the Committee on various aspects related to the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022. He also drew the attention of representatives to Direction 55(1) and Direction 58 of the Directions by the Speaker, Lok Sabha concerning the confidentiality of the Committee proceedings.

4. The representative of the Reserve Bank of India (RBI) explained the views of RBI on the amendments proposed in the Bill inter alia covering the following aspects:–

- (i) Applicability of Banking Regulations Act, 1949 to Urban Cooperative Banks
- (ii) Refund of Share Capital
- (iii) Board Composition/Fit and Proper Criteria for Directors
- (iv) Consumer grievance and redressal
- (v) other Clauses which may face the test of unambiguous interpretation in specific situations.

5. The Members, thereafter, sought clarifications on various amendments being proposed in the Bill and the views of RBI and the Department of Financial Services which were briefly replied by the representatives of RBI and the Department of Financial Services. The Chairperson then directed the nodal Ministry, Department of Financial Services and Reserve Bank of India to provide written replies to all the points raised by the Members during the sitting.

The representatives of Nodal Ministry, RBI and Department of Financial Services then withdrew.

The Committee then adjourned.

A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record.

Minutes of 3rd Sitting of the Joint Committee on the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022

The 3rd sitting of the Joint Committee was held on Friday, the 20th January, 2023 from 1100 hrs. to 1300 hrs. in Committee Room No. -1^o EPHA, New Delhi.

PRESENT

Shri Chandra Prakash Joshi - Chairperson

LOK SABHA

2. Shri Ramdas Chandrabhanji Tadas
3. Shri Annasaheb Shankar Jolle
4. Dr. Nishikant Dubey
5. Smt. Sunita Duggal
6. Shri Brijendra Singh
7. Smt. Jaskaur Meena
8. Dr. Dhal Singh Bisen
9. Shri Suresh Kodikunnil
10. Shri Sri Krishna Devarayalu Lavu
11. Shri Dulal Chandra Goswami

RAJYA SABHA

12. Shri Surendra Singh Nagar
13. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik
14. Shri S. Niranjan Reddy

SECRETARIAT

- | | | | |
|----|-------------------------|----|------------------|
| 1. | Shri J.M. Baisakh | - | Joint Secretary |
| 2. | Shri C. Kalyanasundaram | - | Director |
| 3. | Shri Sumesh Kumar | -0 | Deputy Secretary |
| 4. | Ms. Rachna Saxena | - | Deputy Secretary |
| 5. | Shri Bharat Lal Meena | - | Deputy Director |

REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF COOPERATION

1	Shri Gyanesh Kumar	Secretary
2	Shri Vijay Kumar	Additional Secretary
3	Shri Kapil Meena	Deputy Secretary

REPRESENTATIVES OF NATIONAL FEDERATION OF STATE COOPERATIVE BANKS

(NAFSCOB)

1	Shri Konduru Ravinder Rao	Chairman
2	Shri. Bhima Subrahmanyam	Managing Director

REPRESENTATIVES OF NATIONAL FEDERATION OF URBAN COOPERATIVE BANKS AND CREDIT SOCIETIES LTD. (NAFCUB)

1	Sh. Jyotindra Mehta	President
2	Sh. Uday Joshi	Director

3	Sh. O.P. Sharma	Director
4	Sh. Atul Khirwadkar	Expert
5	Sh. Yogesh Sharma	CE I/C

2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members to the third sitting of the Joint Committee. Then he briefed the Members about the agenda of the sitting.

3. Thereafter, the Chairperson invited the representatives of the National Federation of State Cooperative Banks (NAFSCOB), and National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies (NAFCUB) to hear their views on the provisions of the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022. He then drew their attention to Direction 55(1) and Direction 58 of the Directions by the Speaker, Lok Sabha concerning the confidentiality of the Committee proceedings.

4. The representatives from the credit Societies thereafter briefed the Committee on their views on various provisions of the proposed amendments in the Bill which included the Cooperative Election Authority under section 45, disposal of the net profits and restrictions on the borrowing, appointment of Cooperative Ombudsman, supersession of the Board under Section 123, increasing the percentage of priority sector lending etc. The Members, thereafter, sought clarifications on various amendments/suggestions being proposed in the Bill from the representatives of NAFSCOB and NAFCUB. The Chairperson then directed them to provide written replies to all the points raised by the Members during the sitting within a week.

The representatives of the NAFSCOB and NAFCUB then withdrew

5. Then the Committee decided to continue the next meeting, which was scheduled to begin at 1400 hours.

A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record.

Minutes of 4th Sitting of the Joint Committee on the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022

The 4th sitting of the Joint Committee was held on Friday, the 20th January, 2023 from 1300 hrs. to 1400 hrs. in Committee Room No. -1@ EPHA, New Delhi.

PRESENT

Shri Chandra Prakash Joshi - Chairperson

LOK SABHA

2. Shri Ramdas Chandrabhanji Tadas
3. Shri Annasaheb Shankar Jolle
4. Dr. Nishikant Dubey
5. Smt. Sunita Duggal
6. Shri Brijendra Singh
7. Smt. Jaskaur Meena
8. Dr. Dhal Singh Bisen
9. Shri Suresh Kodikunnil
10. Shri Sri Krishna Devarayalu Lavu
11. Shri Dulal Chandra Goswami

RAJYA SABHA

12. Shri Surendra Singh Nagar
13. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik
14. Shri S. Niranjan Reddy

SECRETARIAT

1. Shri J.M. Baisakh - Joint Secretary
2. Shri C. Kalyanasundaram - Director
3. Shri Sumesh Kumar - Deputy Secretary
4. Ms. Rachna Saxena - Deputy Secretary
5. Shri Bharat Lal Meena - Deputy Director

REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF COOPERATION

1	Shri Gyanesh Kumar	Secretary
2	Shri Vijay Kumar	Additional Secretary
3	Shri Kapil Meena	Deputy Secretary

NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA (NCUI)

1	Shri Ved Prakash Setia	Executive Director
2	Shri Ritesh Dey	Director

INDIAN FARMERS FERTILIZER COOPERATIVE LIMITED (IFFCO)

1	Dr. U S Awasthi	Managing Director and CEO
2	Shri Santosh Kumar Shukla	Joint General Manager (Cooperative Development)

KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LIMITED (KRIBHCO)

1	Shri Rajan Chowdhry	Managing Director
---	---------------------	-------------------

2	Shri Sunder Singh Yadav	Director (HR)
3	Shri L.P. Goodwin	DGM(M)

**NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA
LIMITED (NAFED)**

	Shri Rajbir Singh Panwar	Managing Director
--	--------------------------	-------------------

2. At the outset, the Chairperson welcomed all the Members of the Committee and the representatives from National Cooperative Union of India (NCUI); Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO); Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO); and National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) to the sitting of the Committee. He then drew the attention of the witnesses to Direction 55(1) and 58 of the Directions by the Speaker, Lok Sabha, concerning the confidentiality of the Committee proceedings.

3. Then the representatives of NCUI, IFFCO, KRIBHCO and NAFED briefed the Committee about their concerns/views/suggestions on the various provisions of the proposed amendments *inter alia* covering the following aspects:- (i) Disqualification for being a member of the board, (ii) Powers and functions of the board, (iii) Section 63B related to Cooperative Education Fund, (iv) Investment of fund under section 64, (v) Restrictions on borrowings, and (vi) Supersession of Board of specified multi-State cooperative societies.

4. The Members, thereafter, sought clarification on various amendments being proposed in the Bill from the representatives of aforesaid organizations and also put forth their suggestions with respect to the proposed amendments. The Chairperson then directed the representatives of the aforesaid organizations to provide written replies to all the points raised during the sitting within a week.

*The representatives of Cooperative Societies then withdrew
The Committee then adjourned.*

A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record.

MINUTES OF 5TH SITTING OF THE JOINT COMMITTEE ON THE MULTI-STATE COOPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022

The 5th sitting of the Joint Committee was held on Friday, the 13th February, 2023 from 1500 hrs. to 1630 hrs. in Committee Room No. -C^o PHA, New Delhi.

PRESENT

Shri Chandra Prakash Joshi - **Chairperson**

LOK SABHA

2. Shri Jagdambika Pal
3. Shri Parbatbhai Savabhai Patel
4. Shri Ramdas Chandrabhanji Tadas
5. Shri Annasaheb Shankar Jolle
6. Dr. Nishikant Dubey
7. Smt. Sunita Duggal
8. Shri Brijendra Singh
9. Smt. Jaskaur Meena
10. Shri Ram Kripal Yadav
11. Dr. Dhal Singh Bisen
12. Shri Suresh Kodikunnil
13. Shri Manish Tewari
14. Shri Kalyan Banerjee
15. Shri Sri Krishna Devarayalu Lavu
16. Shri Hemant Shriram Patil
17. Shri Dulal Chandra Goswami

RAJYA SABHA

18. Shri Ghanshyam Tiwari
19. Shri Surendra Singh Nagar
20. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik
21. Shri S. Niranjan Reddy

SECRETARIAT

- | | | | |
|----|-------------------------|---|------------------|
| 1. | Shri J.M. Baisakh | - | Joint Secretary |
| 2. | Shri C. Kalyanasundaram | - | Director |
| 3. | Shri Sumesh Kumar | - | Deputy Secretary |
| 4. | Ms. Rachna Saxena | - | Deputy Secretary |
| 5. | Shri Bharat Lal Meena | - | Deputy Director |

REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF COOPERATION

1	Shri Gyanesh Kumar	Secretary
2	Shri Vijay Kumar	Additional Secretary
3	Shri Kapil Meena	Deputy Secretary
4	Shri Jitender Nagar	Deputy Commissioner
5	Smt. Nisha Sagar	Assistant Commissioner
6	Shri Amit Sachdeva	Sr. Technical Assistant

**REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF LAW & JUSTICE (LEGISLATIVE
DEPARTMENT)**

1	Shri K. Biswal	Special Secretary
2	Shri R. Sreenivas	Additional Legislative Counsel

National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)

1	Shri K.S. Raghupathi	Chief General Manager
2	Shri V.K. Pahwa	Deputy General Manager

National Cooperative Agriculture & Rural Development Banks' Federation Ltd (NAFCARD)

1	Shri Dolar Kotecha	Chairman
2	Shri K.K. Ravindran	Managing Director

National Cooperative Development Corporation (NCDC)

	Shri R.K. Mangla	Director (P&C)
--	------------------	----------------

National Cooperative Consumers Federation of India (NCCF)

1	Shri Vishal Singh	Chairman
2	Shri Vineet Mathur	Managing Director

2. At the outset the Chairperson welcomed the Members of the Committee and the representatives from National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), National Cooperative Agriculture & Rural Development Banks Federation Limited (NAFCARD), National Cooperative Development Corporation (NCDC) and National Cooperative Consumers Federation of India (NCCF).

3. The Chairperson then asked the representative to introduce themselves and drew the attention of representatives from the Ministries and the representatives of Google to Directions 55 and 58 of the Directions by the Speaker, Lok Sabha concerning the confidentiality of the Committee proceedings.

4. After the introduction by the witnesses, representatives of NABARD made a presentation before the Committee. Then the representatives from NAFCARD, NCDC and NCCF were asked to brief the Committee about their concerns/views/suggestions on the various provisions of the proposed amendments. In their presentation and oral evidence, they highlighted the key inputs, regarding the Bill, concerning inter alia:

(i) Overlapping of the Banking Regulation (Amendment) Act and provisions of the Bill (ii) Redemption of shares of multi-State cooperative bank under section 35(1) (iii) Qualification, Knowledge etc of the Board of Directors (iv) Disqualification for being a member of the board, (v) Cooperative Election Authority under section 45 (vi) Minimum and Maximum age for the CEO (vii) appointment of an Auditor (viii) Filing of returns under section 120 (ix) Supersession of Board of specified multi-State cooperative societies (x) definition of "cooperative year" (xi) conversion of a cooperative society into multi state cooperative society (xii) fund for sick Co-operative societies (xiii) Power and functions of Board under section 49.

5. During the course of deliberations, the Chairperson and the Members raised several points and sought clarifications from the representatives on various amendments proposed in the bill. The Chairman then directed the representatives to provide written replies to all the points raised during the sitting within a week.

The witnesses then withdrew.

A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record.

The Committee then adjourned.

MINUTES OF 6TH SITTING OF THE JOINT COMMITTEE ON THE MULTI-STATE COOPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022

The 6th sitting of the Joint Committee was held on Monday, the 20th February, 2023 from 1000 hrs. to 1600 hrs. in Committee Room No. -C^o PHA, New Delhi.

PRESENT

Shri Chandra Prakash Joshi - **Chairperson**

LOK SABHA

2. Shri Jagdambika Pal
3. Shri Parbatbhai Savabhai Patel
4. Dr. Nishikant Dubey
5. Smt. Sunita Duggal
6. Shri Brijendra Singh
7. Dr. Dhal Singh Bisen
8. Shri Suresh Kodikunnil
9. Shri Manish Tewari
10. Shri Kalyan Banerjee
11. Shri Sri Krishna Devarayalu Lavu
12. Shri Girish Chandra

RAJYA SABHA

13. Shri Ghanshyam Tiwari
14. Shri Surendra Singh Nagar
15. Shri S. Niranjan Reddy

SECRETARIAT

- | | | |
|----------------------------|---|------------------|
| 1. Shri J.M. Baisakh | - | Joint Secretary |
| 2. Shri C. Kalyanasundaram | - | Director |
| 3. Shri Sumesh Kumar | - | Deputy Secretary |
| 4. Ms. RachnaSaxena | - | Deputy Secretary |
| 5. Shri Bharat Lal Meena | - | Deputy Director |

REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF COOPERATION

1	Shri Gyanesh Kumar	Secretary
2	Shri Vijay Kumar	Additional Secretary
3	Shri Kapil Meena	Deputy Secretary
4	Shri Satya Prakash Kumar	Under Secretary
5	Smt. Nisha Sagar	Assistant Commissioner
6	Shri Amit Sachdeva	Sr. Technical Assistant

REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF LAW & JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

1	Shri K. Biswal	Special Secretary
2	Shri R. Sreenivas	Additional Legislative Counsel

2. At the outset, Chairperson welcomed Members and the representatives of the Ministry of Cooperation and Ministry of Law & Justice (Legislative Department) to the sitting convened for the clause by clause consideration of the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022. Further the Chairperson drew attention of the Committee and officers to Direction 55 and 58 of the *Directions by the Speaker, Lok Sabha* regarding confidentiality of Committee proceedings.

3. After the introduction by the representatives, the Committee took up Clause by Clause examination of the Bill and deliberated on all the Clauses with the representatives of the Ministry of Cooperation and Ministry of Law & Justice (Legislative Department). During the deliberations, they responded to the queries of the Members on the Clauses of the Bill. The Committee had passed the Clauses of the Bill based on the replies/clarifications given by the Ministry of Cooperation including those Clauses on which the Ministry of Cooperation agreed to the suggestions made by the Committee and kept aside six clauses viz. (i) Clause 2 about the Definitions, (ii) Clause 12 regarding Expulsion of members, (iii) Clause 16 which State About The Disqualifications of Members of the Board, (iv) Clause 17 pertaining to Elections of members of board, (v) Clause 18 on Powers and functions of the board and (vi) Clause 20 on appointment of Chief Executive, for further detailed examination during the next sitting.

4. At the end the Chairperson extended vote of thanks to the Members and the representatives of the Ministries.

The Committee then adjourned.

A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record.

MINUTES OF 7TH SITTING OF THE JOINT COMMITTEE ON THE MULTI-STATE COOPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022

The 7th sitting of the Joint Committee was held on Monday, the 27th February, 2023 from 1500 hrs. to 1630 hrs. in Committee Room No. -C₈ PHA, New Delhi.

PRESENT

Shri Chandra Prakash Joshi	-	Chairperson
-----------------------------------	---	--------------------

LOK SABHA

2. Shri Jagdambika Pal
3. Dr. Nishikant Dubey
4. Smt. Sunita Duggal
5. Shri Brijendra Singh
6. Smt. Jaskaur Meena
7. Dr. Dhal Singh Bisen
8. Shri Manish Tewari
9. Smt. Kanimozhi Karunanidhi
10. Shri Sri Krishna Devarayalu Lavu
11. Shri Hemant Shriram Patil
12. Shri Dulal Chandra Goswami
13. Shri Girish Chandra

RAJYA SABHA

14. Shri Ghanshyam Tiwari
15. Shri Surendra Singh Nagar
16. Shri S. Niranjan Reddy

SECRETARIAT

- | | | |
|----------------------------|---|------------------|
| 1. Shri J.M. Baisakh | - | Joint Secretary |
| 2. Shri C. Kalyanasundaram | - | Director |
| 3. Shri Sumesh Kumar | - | Deputy Secretary |
| 4. Ms. Rachna Saxena | - | Deputy Secretary |
| 5. Shri Bharat Lal Meena | - | Deputy Director |

REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF COOPERATION

1	Shri Gyanesh Kumar	Secretary
2	Shri Vijay Kumar	Additional Secretary
3	Shri Kapil Meena	Deputy Secretary
4	Shri Jitender Nagar	Deputy Commissioner
5	Shri Satya Prakash Kumar	Under Secretary
6	Smt. Nisha Sagar	Assistant Commissioner

**REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)**

1	Shri K. Biswal	Special Secretary
2	Shri R. Sreenivas	Additional Legislative Counsel

**REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)**

	Shri R.S. Verma	Additional Secretary
--	-----------------	----------------------

2. At the outset, Chairperson welcomed Members and the representatives of the Ministry of Ministry of Cooperation and Ministry of Law & Justice (Legislative Department) to the sitting convened for the clause by clause consideration of the Multi- State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022. Further the Chairperson drew attention of the Committee and officers to Direction 55 and 58 of the *Directions by the Speaker, Lok Sabha* regarding confidentiality of Committee proceedings.

3. Thereafter, the Committee took up Clause by Clause consideration of the six clauses viz. (i) Clause 2 about the Definitions, (ii) Clause 12 regarding Expulsion of members, (iii) Clause 17 pertaining to Elections of members of board, (iv) Clause 18 on Powers and functions of the board and (v) Clause 20 on appointment of Chief Executive, and (vi) Clause 24 on establishment of a Co-operative rehabilitation, reconstruction and development fund for revival of sick multi-state co-operative societies. In addition, two members also moved their amendments on the bill pertaining to few clauses.

4. The Committee had exhaustive deliberation on these clauses and the representatives of the Ministries responded to the queries of Members and elucidated on proposed amendments. Then the Committee agreed to accept the amendments proposed by the Government under the Clauses and concluded the clause by clause discussion of the Bill. After that the Chairperson extended the vote of thanks to the representatives of the Ministries.

The Committee then adjourned.

A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record.

**MINUTES OF THE JOINT COMMITTEE ON THE MULTI-STATE COOPERATIVE SOCIETIES
(AMENDMENT) BILL, 2022**

The 8th sitting of the Joint Committee was held on Monday, the 13th March, 2023 from 1500 hrs. to 1515 hrs. in Committee Room No. -4g EPHA, New Delhi.

PRESENT

Shri Chandra Prakash Joshi	-	Chairperson
-----------------------------------	---	--------------------

LOK SABHA

2. Shri Parbatbhai Savabhai Patel
3. Dr. Nishikant Dubey
4. Smt. Sunita Duggal
5. Shri Brijendra Singh
6. Smt. Jaskaur Meena
7. Dr. Dhal Singh Bisen
8. Shri Suresh Kodikunnil
9. Shri Manish Tewari
10. Shri Kalyan Banerjee
11. Shri Hemant Shriram Patil
12. Shri Dulal Chandra Goswami
13. Shri Chandra Sekhar Sahu
14. Shri Girish Chandra

RAJYA SABHA

15. Shri Ghanshyam Tiwari
16. Shri Surendra Singh Nagar
17. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik
18. Shri N.R. Elango

SECRETARIAT

- | | | |
|----------------------------|---|------------------|
| 1. Shri J.M. Baisakh | - | Joint Secretary |
| 2. Shri C. Kalyanasundaram | - | Director |
| 3. Shri Sumesh Kumar | - | Deputy Secretary |
| 4. Ms. Rachna Saxena | - | Deputy Secretary |
| 5. Shri Bharat Lal Meena | - | Deputy Director |

2. At the outset, Chairperson welcomed the Members of the Joint Committee to the sitting convened for consideration and adoption of Draft Report of the Committee. The Committee considered the Draft Report and adopted the same. The Committee also authorized the Hon'ble Chairperson to present the Report in Lok Sabha and lay Report on the table of the Rajya Sabha.

3. One of the members wanted to submit a dissent note. In this regard, the Chairperson decided that if any member wants to give any dissent note, he/she may submit the same by evening on the same day *i.e.* 13.03.2023.

4. The Chairperson in his concluding remarks thanked all the members of the Joint Committee for their unstinted support and cooperation which made the Committee to examine and finalize the report on a comprehensive and important legislation in the given time frame. The Chairperson thereafter placed on record the appreciation for the relentless assistance rendered to the Committee by the officers and staff of the Lok Sabha Secretariat.

The Committee then adjourned.

APPENDIX-VII

N. R. ELANGO

MEMBER OF PARLIAMENT

(RAJYA SABHA)

TAMIL NADU

13.03.2023

To

The Chairman,

Joint Committee,

Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022,

Lok Sabha, New Delhi – 110 001

Sir,

SUB: Dissent note to the draft report

REF: mail from LAFEAS – JCMC018/8/2023 – JCMC

Vanakkam,

I express my sincere thanks to you and the members of the committee for having deliberated the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022 at length. Though I could participate only in the few of the meetings of the committee, the deliberations were done in a democratic manner. The manner in which you have conducted the proceedings of the committee reemphasize the need for constituting such committees with respect to all important bills introduced in the parliament.

Though I concur with most of the draft report, I find myself not able to agree with the report on certain clauses. Hence, I propose the following dissent note and request you to place the same on record.

Thank you

N.R.ELANGO

MEMBER OF PARLIAMENT

RAJYA SABHA

IC NO. 4881

NOTE:

1. Dissent note is annexed.
2. I may be permitted to submit the physical copy tomorrow.

**DISSENT NOTE SUBMITTED BY N.R. ELANGO TO THE DRAFT REPORT OF JOINT COMMITTEE OF
MULTI-STATE COOPERATIVE SOCIETIES AMENDMENT BILL 2022**

While introducing the 97th Constitutional Amendment introduced in the year 2012, Part IX B of the constitution, it was observed that, “the state shall promote voluntary formation, *autonomous functioning*, democratic control and professional management of co-operative societies.”

- Whereas the Bill No.215 of 2022, seeks to curtail the same, in different ways, especially to that of MSC Societies, which are exclusively meant for a class of members, such as Employees’ Co-operative Societies.
- Under the Second Schedule of MSCS Act 2002, there are 21 National Co-operative Societies, which were either created under the act or created by an Act of Parliament, in which substantial funding, is made by the Central Government.
- Whereas Employees’ Co-operative Societies, which are formed and managed by the employees, from out of their own funds of contribution, thrift deposits, borrowings etc. with absolutely no funding or subsidy or grant or credit guarantee by the State / Central Government and also the State / Central Government not having any share holding, then such societies, should be excluded from the purview of the following provisions, which are sought to be amended by the above Bill. They are mainly
 - I. Applicability and Jurisdiction of “Co-operative Election Authority”.
 - II. Redressal of complaints under the proposed “Co-operative Ombudsman”.
 - III. Guidelines/Restrictions sought to be introduced, in respect of recruitment of its employees including that of Chief Executive, under Section 49(2)(e) (Powers and Function of the Board).

DISSENT NOTE - I

CLAUSE NO.	PROVISIONS	AMENDMENT SUGGESTED
17	Section 45 (1) to Section 45 (L)	The above provisions relating to Co-operative Election Authority, shall not be applicable in respect of Employees' Co-operative Societies, wherein, there is no funding or shares holding or subsidy or principal/interest relief or waiver by the State/Central Government.

REASONS FOR SUGGESTIONS:

- As per the Principal Act, the election to the successor Board of the Society, is covered under Section 45 of the MSCS Act 2002.
- Whereas in the proposed amendment, the entire Section 45 of the Principal Act, is being substituted from Section 45(1) to Section 45(L) which deals with Co-operative Election Authority.
- When the constitution has provided for ***Autonomous Functioning***, the need for a 'Co-operative Election Authority' and that too, in the case of totally independent financial institutions, such as Employees' Co-operative Societies, is unwarranted and such Employees' Co-operative Societies should be excluded from the proposed amendment to section 45 of the Principal Act.
- Election to the Board of Directors of companies, are done by the Shareholders, themselves in their General Body meeting. In the similar manner, the members of Employees' Co-operative Societies, should also be allowed to have autonomous functioning.
- Furthermore, there are various MSC Societies, with a membership of few thousands, however if the co-operative election authority, is introduced in the manner in which it is proposed to function then it shall cause additional burden on such Co-operative Societies which is totally unwarranted.
- Moreover, if the Central or State Government does not hold any shares or does not grant any subsidy or principal/interest relief or waiver, does not give any credit guarantee, then there is no need to bring in, such Employees' Co-operative Societies, under the ambit of proposed 'Co-operative Election Authority'.
- Already there is a clear mandate, vide Sub-section 6, of Section 45, of the MSCS Act, 2002, where the existing Board fails to conduct Election to its successor Board, then the Central Registrar shall, hold Election, within a period of 90 days from the date, when such Election has become due and also such Board Members shall, incur disqualification, under Clause (a) of Sub-section 2, of Section 43, of the MSCS Act.
- Hence the Co-operative Societies which are not funded by these Governments such as Employees' Co-operative Societies, should be totally excluded from the ambit of proposed amendment to Section 45.

DISSENT NOTE - II

CLAUSE NO.	PROVISIONS	AMENDMENT SUGGESTED
18	Section 49, Sub-section 2 Clause (e)	The above provision relating to powers and function of Board, shall not be applicable in the case of Employees ^o Co-operative Society, where, there is no funding or shareholding or subsidy or principal/interest relief or waiver, by the State /Central Government.

REASONS FOR SUGGESTIONS:

- A proviso to Clause (e) of sub-section 2 of Section 49 of the Principal Act, is proposed to be inserted namely öProvided that the recruitment of such employees shall be subject to such procedure as may be prescribed.ö
- When the State or Central Government does not hold any shares, does not grant any subsidy, does not grant any principal/interest waiver, does not give any credit guarantee, then in such circumstances, the recruitment of required number of personnel, as well as the qualifications of such personnel should be left to the discretion of the employer, namely the Co-operative Society, which functions on its own funds, having due regard to the area of operation, number of branches etc.,
- As such the proviso, which is sought to be introduced by delegated legislation i.e., öas may be prescribedö, is unwarranted and the proposed insertion of proviso to Clause (e) of Sub-Section 2 of Section 49, in respect of powers and function of Board, should be deleted.

DISSENT NOTE - III

CLAUSE NO.	PROVISIONS	AMENDMENT SUGGESTED
31	Section 85A (Sub-section 1 To Sub-section 5)	The above provision relating to Co-operative Ombudsman, shall not be applicable in the case of Employees' Co-operative Society, where, there is no funding or shareholding or subsidy or principal/interest relief or waiver, by the State /Central Government.

REASONS FOR SUGGESTIONS:

- A new chapter under the heading Chapter IXA “Redressal of Complaints” is sought to be inserted in the Principal Act.
- It is stated in the objects of the proposed amendment that “Co-operative Ombudsman”, is being introduced, for “Redressal of Complaints”.
- Whereas, already in terms of Section 84 of the Principal Act, there is a well-defined definition for “Dispute”, and also parties to the “Dispute” such as relating to constitution, management or business of the society, among members, between member and the society, between the board and a member and such “Dispute”, shall be referred for arbitration.
- Such disputes are settled or decided by the arbitrator, appointed by the Central Registrar and the proceedings of such arbitration, are covered under the Arbitration and Conciliation Act 1996. As such any dispute, including financial disputes, are already covered under the Principal Act.
- Further, with the amendment to Arbitration and Conciliation Act, in the year 2015, speedy redressal of the disputes, between the members and the society are already in existence.
- In the Banking Sector, the role of “Ombudsman”, relates only to complaints relating to provision of services to a customer by the bank and in case of Loans and advances, only in so far as they relate to non-observance of RBI orders on interest rates, time limit, and other directions of RBI. It does not cover recovery of dues from a customer by the Bank.
- Furthermore, provision of “Co-operative Ombudsman” will not only confuse and complicate, but will also dilute the existing and effective dispute redressal provisions contained, in Section 84 of the Principal Act.
- As such the “Co-operative Ombudsman”, proposal needs to be rescinded, as it will dilute the provisions of Section 84 of the Principal Act, in respect of Employees' Co-operative Societies.

THE MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022 AS REPORTED BY THE JOINT COMMITTEE

[WORDS AND FIGURES IN BOLD AND UNDERLINED INDICATE THE AMENDMENTS AND (***) MARK INDICATES THE OMISSION SUGGESTED BY THE JOINT COMMITTEE]

BILL NO. 215B OF 2022

**THE MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES
(AMENDMENT) BILL, 2023**

**A
BILL**

further to amend the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002.

BE it enacted by Parliament in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (hereinafter referred to as the principal Act),—

39 of 2002.

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

—(aa) “Authority” means the Co-operative Election Authority established under sub-section (1) of section 45;

(ii) in clause (d), for the words, brackets and figures under sub-section (1) of section 4, the words, brackets, letters and figures as per clause (f) of article 243ZH of the Constitution read with sub-section (1) of section 4 shall be substituted;

(iii) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

—(fa) “Co-operative Ombudsman” means the Ombudsman appointed by the Central Government under section 85A;

(iv) (***) clause (i), (***), shall be omitted;

(v) after clause (k), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(ka) “financial year”, in relation to any multi-State co-operative society or class of such societies, means the year ending on the 31st day of March of the year and where the accounts of such society or class of such societies are, with the previous sanction of the Central Registrar, balanced on any other day, the year ending on such day;’;

(vi) in clause (s), after the words "Official Gazette", the words "and the expression 'notified' with its cognate meanings and grammatical variations shall be construed accordingly" shall be inserted.

Amendment of section 7.

3. In section 7 of the principal Act, for sub-sections (2) and (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Central Registrar may register a multi-State co-operative society if the aggregate value of the paid-up capital and provision of reserves along with liquidity, exposure and other prudential norms specified in the bye-laws of the proposed multi-State co-operative society in the business of thrift and credit are in accordance with such guidelines as may be prescribed:

Provided that the multi-State co-operative societies registered before the commencement of the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023 shall meet such norms within a period of five years from the date of commencement of the said Act:

Provided further that if the liquidity, exposure, prudential and other parameters of the multi-State credit society do not meet such norms within the period mentioned above, the Central Registrar shall have powers to issue such directions as it deems appropriate to such society to take relevant action:

Provided also that in the case of multi-State co-operative bank, the aggregate value of the paid-up capital and provision of reserves along with liquidity norms provided in the bye laws shall be such as may be laid down by the Reserve Bank from time to time.

(3) The application for registration shall be disposed of by the Central Registrar within a period of three months from the date of receipt of such application by him:

Provided that the Central Registrar may, for rectification of mistakes, if any, in the application, extend the period of three months with such further period, for reasons to be recorded in writing, not exceeding two months on the request of the applicant.

(4) Where the Central Registrar refuses to register a multi-State co-operative society, he shall communicate the order of such refusal stating therein the reasons for such refusal, to the applicant within the period specified in sub-section (3):

Provided that no order of refusal shall be made, unless the applicant has been given an opportunity of being heard:

Provided further that if the application for registration is not disposed of within the period specified in sub-section (3) or the Central Registrar fails to communicate the order of refusal within the said period, the application shall be deemed to have been accepted for registration and the Central Registrar shall issue the registration certificate in accordance with the provisions of this Act and the rules made there under.—

Amendment of section 10.

4. In section 10 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (a), for the word “address”, the words and brackets “address, (***), including e-mail address (***),” shall be substituted.

Amendment of section 14.

5. In section 14 of the principal Act-

- (i) for the marginal heading “Change of address”, the marginal heading “Address” shall be substituted;
- (ii) for the word “address”, the words “address, including e-mail address,” shall be substituted.

Amendment of section 17.

6. In section 17 of the principal Act, after sub-section (9), the following sub-section shall be inserted, namely:

“(10) Any co-operative society may, by a resolution passed by majority of not less than two-thirds of the members present and voting at a general meeting of such society, decide to merge into an existing multi-State co-operative society:

Provided that such resolution shall be subject to the provisions of the respective State Co-operative Societies Act for the time being in force under which such co-operative society is registered.”

Amendment of section 19.

7. In section 19 of the principal Act, in the *Explanation*, in clause (a),

- (i) in sub-clause (ii), the word “or” occurring at the end shall be omitted;
- (ii) sub-clause (iii) shall be omitted.

Amendment of section 22.

8. In section 22 of the principal Act, in sub-section (5), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:

“(c) The co-operative society shall be deemed to have been de-registered under the law relating to such co-operative society for the time being in force in that State, from the date of the certificate as issued by the Central Registrar and forwarded to such co-operative society, along with a copy of the registered amendment under sub-section (3).”

Amendment of section 26.

9. In section 26 of the principal Act,

- (i) in the proviso, the words “be entitled to subscribe the shares of such society or” shall be omitted;
- (ii) after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely:

“Provided further that nominal or associate member can be issued non-voting shares which may not confer any interest in the management of the multi-State co-operative society including right to vote, to be elected as a director of the board or participate in the general body meetings:

Provided also that in case of multi-State co-operative bank, such shares shall be issued in accordance with the instructions issued by the Reserve Bank from time to time.ö.

10. In section 28 of the principal Act, for the words öto the society in respect of membership,ö, the words öof all dues to the multi-State co-operative society including the payment in respect of membership or has availed such minimum level of product or services as specified in the bye-laws,ö shall be substituted.

Amendment of section 28.

11. In section 29 of the principal Act, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:

Amendment of section 29.

ö(b) he fails to use the minimum level of the products or services as specified in the bye-laws for two consecutive years; orö.

12. In section 30 of the principal Act, in subösection (2), for the words öone yearö, the words öthree yearsö shall be substituted.

Amendment of section 30.

13. For section 35 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:öö

Substitution of new section for section 35.
Redemption of shares.

ö35(1) The shares of the authorities referred to in clauses (c) and (d) of sub-section (1) of section 25, held in multi-State co-operative societies,öö

(a) shall not be redeemed without the prior approval of such authorities; and

(b) may be redeemed in such manner as may be agreed upon between the multi-State co-operative society and such authorities.

(2) The shares held in a multi-State co-operative society by any of the authorities referred to in clauses (e) to (g) of sub-section (1) of section 25, shall be redeemed in accordance with the bye-laws of such multi-State co-operative society and in case, where the bye-laws do not contain any provision, in such manner as may be agreed upon between the multi-State co-operative society and such authorities.

(3) The redemption of shares referred to in sub-sections (1) and (2), shall be on the face value of shares.ö.

14. In section 39 of the principal Act, in subösection (1), after clause (o), the following clause shall be inserted, namely:

Amendment of section 39.

ö(p) appointment of auditor.ö.

15. In section 41 of the principal Act, for subösection (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:öö

Amendment of section 41.

(3) The board shall consist of such number of directors not exceeding twenty-one, as may be specified by bye-laws, out of which one Member shall be Scheduled Caste or Scheduled Tribe and two shall be women in the board of multi-State co-operative society consisting of individuals and having members from such class or category of persons:

Provided that the board may co-opt as Members of the board having experience in the field of banking, management, co-operative management and finance or specialisation in any other field relating to the objects and activities undertaken by such multi-State co-operative society:

Provided further that the number of such co-opted Members shall not exceed two in addition to twenty-one directors specified in this sub-section.

(4) The co-opted directors referred to in sub-section (3) shall not have the right to vote in any election of the office bearers or be eligible to be elected as office bearers of the board.

(5) The functional directors in a multi-State co-operative society shall also be the members of the board and such directors shall be excluded for the purpose of counting the total number of directors specified in sub-section (3).

(6) No director of a multi-State co-operative society shall, as a director, be present in the discussion of, or vote on, any contract or arrangement entered into, or to be entered into, by or on behalf of such society, if he or his relative is directly or indirectly concerned or interested in such contract or arrangement and no relative of any of the sitting directors of the multi-State co-operative society shall be recruited as employee including the Chief Executive of that society.

Explanation.—For the purposes of this subsection, the term, “relative” with reference to an individual, includes—

- (a) spouse;
- (b) father (including step father);
- (c) mother (including step mother);
- (d) son (including step son);
- (e) son's wife;
- (f) daughter (including step daughter);
- (g) daughter's husband;
- (h) father's father;
- (i) father's mother;
- (j) mother's father;
- (k) mother's mother;
- (l) son's son;
- (m) son's son's wife;
- (n) son's daughter;
- (o) son's daughter's husband;
- (p) daughter's son;
- (q) daughter's son's wife;
- (r) daughter's daughter;
- (s) daughter's daughter's husband;

- (t) brother (including step brother);
- (u) brother's wife;
- (v) sister (including step sister);
- (w) sister's husband; and
- (x) Hindu undivided family.

(7) Any director of the board who violates the provision of sub-section (6), shall be disqualified for being a member of the board and deemed to have vacated his office from the date of such meeting of the board as is referred to in the said sub-section and such proceedings shall be deemed to be void.¶

16. In section 43 of the principal Act,ºº

Amendment of
section 43.

(i) in sub-section (1),ºº

(a) in clause (a), after the words ºto be insolventº, the words ºor has been a director of an insolvent companyº shall be inserted;

(b) in clause (h), after the words ºunder this Actº, the words ºor under any other Act specified in the third Scheduleº shall be inserted;

(c) after clause (n), the following clause shall be inserted, namely: ºº

º(o) has been disqualified under sub-section (7) of section 41.º;
(ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely: ºº

º(1A) A member who has been a director of the board of any multi-State co-operative society or co-operative bank, where such board has been superseded, shall not be eligible to be elected as director of the board of another multi-State co-operative society or co-operative bank for a period of five years, from the date of such supersession:

Provided that no member shall be declared ineligible under this sub-section unless an opportunity of being heard has been given to such member by the Central Registrar and declaration for ineligibility shall be made only after ascertaining that the member concerned has been responsible by acts of omission or commission leading to such supersession.º;

(iii) in sub-section (2),ºº

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: ª

º(a) to provide information, documents, personnel, funds or expenses or any other assistance as required by the Co-operative Election Authority for conducting elections under this Act in such manner as may be prescribed; orº;

(b) in clause (c), for the words “general meeting” occurring at the end, the words “general meeting; or” shall be substituted;

(c) after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:

(d) to make contribution to the co-operative education fund referred to in clause (b) of subsection (1) of section 63 or the Co-operative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund established under section 63A; or

(e) to file annual return specified in section 120 within the time specified therein ; or

(f) to get the audit of the society conducted within six months of the close of the financial year to which such account relate:

Provided that before taking any action under this sub-section, he shall be given an opportunity of being heard by the Central Registrar.

Substitution of new section for section 45.

17. For section 45 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:

Establishment of Co-operative Election Authority.

(1) The Central Government shall, by notification, establish an Authority to be known as the Co-operative Election Authority which shall consist of a Chairperson, a Vice-Chairperson and Members not exceeding three to be appointed by the Central Government on the recommendation of the Selection Committee consisting of such persons as may be prescribed.

(2) The head office of the Authority shall be at such place as may be notified by the Central Government.

(3) A person shall not be qualified for appointment as a,

(i) Chairperson of the Authority unless he held the post of Additional Secretary to the Government of India or equivalent rank;

(ii) Vice-Chairperson of the Authority unless he held the post of Joint Secretary to the Government of India or equivalent rank; and

(iii) Member unless he fulfills such qualification and experience as may be prescribed.

(4) The Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority shall hold office for a period of three years from the date on which they enter upon their office or until they attain the age of sixty-five years, whichever is earlier and they shall be eligible for re-appointment:

Provided that in case of appointment of a Government servant as a Chairperson, Vice-Chairperson or a Member, he shall be treated as an *ex-officio* Member and he shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is a Chairperson, Vice-Chairperson or Member.

(5) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson, Vice-Chairperson and Members of the Authority, other than the *ex-officio* Member, shall be such as may be prescribed.

45A. The Chairperson of the Authority shall have powers of general superintendence and directions in the conduct of the affairs of the Authority and he shall, in addition to presiding over the meetings of the Authority, exercise and discharge such other powers and functions as may be prescribed.

Power of Chairperson.

45B. (1) The Central Government may, by order, remove from office the Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority, other than *ex-officio* Member, if the Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority, as the case may be,⁶

Removal and suspension of Chairperson, Vice-Chairperson and Members.

(a) has been adjudged as an insolvent;

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government involves moral turpitude;

(c) has been physically or mentally incapable of acting as a Chairperson, Vice-Chairpersonor Member of the Authority;

(d) has acquired such financial or other interests, as is likely to affect prejudicially his function as a Chairperson, Vice-Chairpersonor Member of the Authority;

(e) has so abused his position, as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or

(f) has been engaged at any time during his term of office in any other employment.

(2) The Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority shall not be removed from his office except by an order of the Central Government on the ground of his proved misbehaviour or incapacity after the Central Government has, on an inquiry, held in accordance with the procedure prescribed in this behalf by it, come to the conclusion that the Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority ought on any such ground to be removed.

(3) The Central Government may suspend the Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority in respect of whom an inquiry under sub-section (2) is being initiated or pending until the Central Government has passed an order on receipt of the report of the inquiry.

45C. (1) Before appointing any person as Chairperson, Vice-Chairperson or Member, the Central Government shall satisfy itself that the person does not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such Chairperson, Vice-Chairperson or Member.

Disclosure and declaration of interest.

(2) The Chairperson, Vice-Chairperson or Members shall immediately after entering office and every year thereafter, make a declaration as to the extent of their interest, whether direct or indirect and whether financial or otherwise, in any co-operative society.

(3) The declaration so made under sub-section (2) shall be placed in the public domain by the Authority.

Resignation of Members.

45D. The Chairperson, Vice-Chairperson or Members, other than *ex-officio* Members, may, by notice in writing of not less than thirty days under their hand addressed to the Central Government, resign their office and on such resignation being accepted by that Government, shall be deemed to have vacated their office:

Provided that the Chairperson, Vice-Chairperson or Member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish his office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as his successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is the earliest.

Filling of casual vacancy.

45E. If a casual vacancy occurs in the office of the Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority, whether by reason of his death, resignation or otherwise, such vacancy shall be filled within a period of ninety days by making a fresh appointment in accordance with the provisions of section 45 and the person so appointed shall hold office for the remainder of the term of office for which the Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority, as the case may be, in whose place he is so appointed.

Restriction of re-employment.

45F. The Chairperson, Vice-Chairperson and Member of the Authority, on ceasing to hold office shall not, for a period of two years, accept any employment (including as consultant or otherwise) in any co-operative society:

Provided that nothing contained in this section shall apply to any employment under the Central Government or in any State Government or any Corporation established by or under any Central or State Act or a Government Company as defined under clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013.

18 of 2013.

Vacancies etc. not to invalidate proceedings of Authority.

45G. No act or proceeding of the Authority shall be invalid merely by reason of—

(a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Authority;

(b) any defect in the appointment of a person as Chairperson or Member of the Authority; or

(c) any irregularity in the procedure of the Authority not affecting the merits of the case.

Meetings of Authority.

45H. (1) The Authority shall meet at such places and times and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings (including the quorum at its meetings), as may be prescribed.

(2) The Chairperson of the Authority shall preside at the meeting of the Authority and if for any reason the Chairperson of the

Authority is unable to attend a meeting of the Authority, the Vice-Chairperson of the Authority shall preside at the meeting.

(3) All questions which come up before any meeting of the Authority shall be decided by a majority of votes of the members present and voting and, in the event of an equality of votes, the Chairperson or the Vice-Chairperson of the Authority presiding shall have the right to exercise a second or casting vote.

(4) Save as otherwise provided in sub-section (1), every Member shall have one vote.

45-I. The Authority shall discharge the following functions, namely:

Functions of Authority.

(i) conduct the elections of the multi-State co-operative society;

(ii) supervise, direct and control the matters relating to preparation of electoral rolls; and

(iii) such other functions as may be prescribed.

45J. (1) No person shall be eligible to be elected as a member of the board or office bearer of a multi-State co-operative society, unless he is an active member of the general body of that society.

Elections of Members of board.

Explanation. For the purposes of this subsection, the term "active member" means any member

(i) availing minimum level of products or services of the society; or

(ii) attending not less than three consecutive general meetings,

as specified in section 29.

(2) A member of the board or office bearer of a multi-State co-operative society shall cease to be such member or office bearer, if he ceases to be a member of general body of that society.

(3) The election of members of board shall be held by secret ballot in such manner as may be prescribed.

(4) The election of the members of the board shall be held in the general meeting of the members of the multi-State co-operative society and the elected members of the board shall, if the bye-laws of such society permit, be eligible for re-election.

(5) The term of office of elected members of the board and its office bearers shall be five years from the date of election and the term of office bearers shall be co-terminus with the term of the board:

Provided that the board may fill casual vacancies upto one-third of number of elected directors on the board by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of office of the board is less than half of its original term:

Provided further that in case the number of such casual vacancies in the same term of the board exceeds one-third of number of elected directors, such vacancies shall be filled by elections.

(6) The expenses for holding elections by the Authority shall be borne by the multi-State co-operative society in such manner as may be prescribed.

(7) The Central Government may make rules to provide for the powers and the procedure to be followed by the Authority for conduct of election of members of the board.

(8) The Chairperson and the Chief Executive of the multi-State co-operative society shall inform the Authority, six months before the expiry of the term of the existing board, to conduct the elections within time.

(9) The **multi-State co-operative** society in respect of which the election is being held shall provide such infrastructure, personnel, information, documents or other assistance to the Authority as it may require.

Appointment of
Returning
Officer and
other officers.

45K. (1) The Authority may appoint a Returning Officer to conduct the election of the multi-State co-operative societies and discharge such functions, as directed by the Authority, in such manner as may be prescribed.

(2) The Central Government shall provide such staff and officers to the Authority as may be necessary for the efficient discharge of functions by the Authority under the Act.

(3) The Authority may appoint,

(a) such observers as it may consider necessary to supervise the elections and discharge such other functions as may be prescribed; and

(b) such number of Assistant Returning Officers as it may consider necessary to assist the Returning Officer.

Power to issue
directions.

45L. The Authority may, by general or special order, issue such directions to the board, its members, Chief Executive and other staff of the **multi-State co-operative** society as may be necessary for the conduct of free and fair elections and the board, its members, Chief Executive and staff of the society shall comply with such directions.^o

Amendment of
section 49.

18. In section 49 of the principal Act, in sub-section (2),^o

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:^o

o(aa) to elect the Chairperson and Vice-Chairperson or President and Vice-President of the multi-State co-operative society from amongst the elected members of the board in accordance with the directions of the Authority:

Provided that the certificate of election shall be issued by the Chief Executive of the multi-State co-operative society after conclusion of resolution by the board;

(ii) in clause (e), the following proviso shall be inserted, namely:—

—Provided that the recruitment of such employees shall be subject to such procedure as may be prescribed.—

19. In section 50 of the principal Act,—

Amendment of
section 50.

(a) in sub-section (1), the following provisos shall be inserted, namely:—

—Provided that where such Chairperson or President fails to direct the Chief Executive to convene the meeting of the board within the quarter, such Chief Executive shall convene the meeting on the basis of requisition of the Vice-Chairperson or Vice-President or any other Member of the board:

Provided further that notwithstanding anything contained in the first proviso, the Chief Executive may also convene the meeting on the basis of requisition from at least fifty per cent. of Members of the board;

(b) for sub-section (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

(3) The Chairperson or President, if for any reason, is unable to attend a meeting of the board, the Vice Chairperson or Vice President and in the absence of both, any other Member of the board chosen by the Members of the board present from amongst themselves at the meeting, shall preside over the meeting.

(4) The quorum for a meeting of the board of directors of a multi-State co-operative society shall be one-third of its total number of elected directors.—

20. In section 51 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

Amendment of
section 51.

(1A) No multi-State co-operative society shall appoint or continue the employment of any person as the Chief Executive who—

(a) is below the age of twenty-one years or has attained the age of seventy years;

Provided that any person above the age of seventy years may be appointed by a special resolution passed by three-fourth of the board members, in which case the explanatory statement annexed to the notice for such motion shall indicate the justification for appointing such person;

(b) is an undischarged insolvent or has any time been adjudged as an insolvent;

(c) has at any time been convicted by a court of an offence and sentenced for a period of more than six months; or

(d) does not meet the criteria for ~~fit and proper~~, as determined by the Central Registrar in case of multi-State credit societies or in case of non-credit multi-State societies, does not meet the criteria as Central Government may prescribe in terms of education qualifications and relevant experience.

Amendment of section 52. **21.** In section 52 of the principal Act, in clause (j), for the words ~~thirty days~~, the words ~~forty-five days~~ shall be substituted.

Amendment of section 53. **22.** In section 53 of the principal Act, for subsection (1), the following subsection shall be substituted, namely: ~~oo~~

~~(1)~~ The board may constitute an Executive Committee, and such other committees or sub-committees as may be specified in the bye-laws of the multi-State co-operative society:

Provided that the board shall constitute~~oo~~

(a) an Audit and Ethics Committee;

(b) a Committee on prevention of sexual harassment at work place.~~oo~~

Amendment of section 63. **23.** In section 63 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:~~oo~~

~~(b)~~ credit annually one per cent. of net profit to co-operative education fund to be maintained by the Central Government in such manner as may be prescribed and the proceeds from such fund shall be used for co-operative education and training through the National Co-operative Union of India and any other agency in such manner as may be determined by the Central Government;~~oo~~.

Insertion of new sections 63A, 63B and 63C. **24.** After section 63 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:~~oo~~

~~63A.~~ (1) The Central Government shall establish a Fund, to be called the Co-operative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund for revival of sick multi-State co-operative societies as referred to in section 63B and for development purposes in such manner as may be determined by it and there shall be credited to such Fund annually by multi-State co-operative societies which are in profit for the preceding three financial years one crore rupees or one per cent. of the net profits of such multi-State co-operative society, whichever is less.

(2) The Central Government shall, by notification, constitute a Committee, consisting of such members as it may deem fit, to administer the Fund, and maintain separate accounts and other relevant records in relation to the Fund in such form as may be specified by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(3) The Committee shall spend the money out of the Fund for carrying out the objects for which such Fund has been established.

63B. (1) If, at any time, the Central Registrar, is of the opinion that a multi-State co-operative society has become sick, he may, by an order, declare such society as sick co-operative society.

Rehabilitation and reconstruction of sick societies.

(2) Where a multi-State co-operative society is declared as a sick co-operative society under sub-section (1), the Central Government or any person or agency authorised by it, may prepare a scheme for rehabilitation and reconstruction of the society and hand it over to the society for approval of the general body.

(3) The Central Government may, on the recommendation of the general body and to give effect to the scheme for rehabilitation and reconstruction referred to in sub-section (2), re-organise the board of such society with such persons, having experience in the field of co-operation, management, finance, accountancy and any other area relating to such societies as may be recommended by the general body:

Provided that in respect of a sick multi-State co-operative bank, any scheme for rehabilitation or reconstruction shall be done with the prior approval of the Reserve Bank.

Explanation. For the purposes of this section, the expression “sick co-operative society” means a multi-State co-operative society being a society registered under the provisions of this Act which has at the end of any financial year accumulated losses equal to or exceeding total of its paid up capital, free reserves and surpluses and has also suffered cash losses in such financial year and the financial year immediately preceding such financial year.

63C. (1) The Central Government may, on an application made by a multi-State co-operative society which has contributed to the Fund for continuous five preceding financial years, grant such financial assistance as it may consider appropriate to the society out of the Fund for infrastructural requirement:

Financial assistance to multi-State co-operative societies for development.

Provided that at least fifty per cent. of the total requirement shall be borne by the multi-State co-operative society and the financial assistance from the Fund shall not exceed more than the fifty per cent. of such requirement.

(2) The Committee constituted under sub-section (2) of section 63A shall examine and recommend to the Central Government for providing the financial assistance to the multi-State co-operative society to such extent and on such terms and conditions as it may consider necessary.

25. In section 64 of the principal Act,

Amendment of section 64.

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: (b)

(b) in any of the securities issued by the Central Government, State Government, Government Corporations, Government Companies, Authorities, Public Sector Undertakings or any other securities ensured by Government guarantees;

- (ii) in clause (d), after the words “any other institution”, the words “in the same line of business as the multi-State co-operative society” shall be inserted;
- (iii) for clauses (e) and (f), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(e) with any other scheduled or nationalised bank.

Explanation. For the purposes of this clause, the expression,-

(i) “scheduled bank” shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934; and

2 of 1934.

(ii) “nationalised bank” means a corresponding new bank constituted under sub-section (1) of section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980; or

5 of 1970.

40 of 1980.

(f) in such other manner as may be determined by the Central Government.

Amendment of section 67.

26. In section 67 of the principal Act, in sub-section (1), in the first proviso, for the words “ten times”, the words “such multiples as may be determined by the Central Government” shall be substituted.

Amendment of section 70.

27. In section 70 of the principal Act,

(a) in sub-section (2), for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

“Provided that such auditors or auditing firm shall be appointed from a panel approved by the Central Registrar:

Provided further that in case of multi-State co-operative banks, multi-State credit societies with deposits of above five hundred crore rupees and multi-State non-credit societies with turnover of above five hundred crore rupees, the auditor shall be appointed from a panel of auditors approved for audit of such societies by the Central Registrar.

(b) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:

“(3A) An auditor appointed under sub-section (2) shall submit the audit of accounts report to the multi-State co-operative society, within six months from the date of closing of the financial year, to which such accounts relate.”;

(c) in sub-section (7), in clause (a), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:

“Provided that where such vacancy is caused by the resignation or death of an auditor, the vacancy shall be filled by the board from the panel of auditors from which such auditor was appointed.”;

(d) after sub-section (9) and the *Explanation* thereunder, the following sub-section shall be inserted, namely:

ð(10) The audit report of the accounts of the national co-operative societies shall be laid before each House of Parliament.ö.

28. After section 70 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:ö

ð70A. In case of multi-State co-operative societies,öö

Insertion of new section 70A.

Concurrent Audit.

(i) having an annual turnover more than the amount as determined by the Central Government; or

(ii) having deposit of more than the amount as determined by the Central Government,

the concurrent audit shall be carried out by an auditor appointed from a panel of auditors approved by the Central Registrar.

29. In section 73 of the principal Act, after subösection (5), the following sub-section shall be inserted, namely:öö

Amendment of section 73.

ð(6) the multiöState coöoperative society or class of multiöState coöoperative societies, as the case may be, shall adopt such standards of auditing and accounting as may be determined by the Central Government:

Provided that until such standards of auditing and accounting are specified, the auditing and accounting standards specified by the Institute of Chartered Accountants of India constituted by subö section (1) of section 3 of the Chartered Accountants Act, 1949 shall be deemed to be the standards of auditing and accounting:

Provided further that the multi-State coöoperative banks shall adopt the standards of accounting and auditing, if any, laid down by the Reserve Bank.ö.

30. In section 78 of the principal Act, after subösection (1), the following subösections shall be inserted, namely:öö

Amendment of section 78.

ð(1A) If the Central Registrar is satisfied on the basis of information available with him or furnished to him by a Government agency, that the business of a multiöState coöoperative society is being carried on for a fraudulent or unlawful purpose, he may, after informing the multiöState coöoperative society of the allegations made against it, by a written order, call on the multiöState coö operative society to furnish in writing any information or explanation, with the endorsement of the board of the society, on matters contained in such order within the time specified therein:

Provided that if the Central Registrar is not satisfied with the explanation of the society, he shall either himself or through an office or agency authorized by him, conduct inquiry into the constitution, working and financial condition of the society.

(1B) Notwithstanding anything contained in this Act, the Central Registrar shall, either *suo moto* or through an officer or agency authorised by him, conduct inquiry into the constitution, working and financial condition of any multi-State co-operative society, once in such period as may be determined by the Central Government.ö.

Insertion of new Chapter IXA.

31. After Chapter IX of the principal Act, the following Chapter shall be inserted, namely:

oChapter IXA
Redressal of Complaints

Co-operative Ombudsman.

85A. (1) The Central Government shall appoint, one or more Co-operative Ombudsman with territorial jurisdiction for inquiring into the complaints made by any member of the multi-State co-operative societies regarding their deposits, equitable benefits of society's functioning or any other issue affecting the individual rights of the concerned member, in such manner, as may be prescribed.

(2) The Co-operative Ombudsman shall, on receipt of a complaint, complete the process of inquiry and adjudicate within a period of three months from the date of receipt of the complaint and may issue necessary directions to the society during the course of inquiry and the society shall be bound to comply with the same within a period of one month from the date of issuance of such directions.

(3) The multi-State co-operative society aggrieved by any directions of the Ombudsman may file an appeal in such manner as may be prescribed, within a period of one month before the Central Registrar who shall decide the appeal within a period of forty-five days and the decision of the Central Registrar shall be final and binding:

Provided that the Central Registrar may entertain the appeal after the expiry of said period of one month, if he is satisfied that the society was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

(4) The Ombudsman shall submit periodic reports to the Central Registrar of Co-operative Societies.

(5) The Co-operative Ombudsman while conducting the inquiry under sub-section (1), shall exercise the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, o

05 of 1908.

(a) for summoning and enforcing the attendance of persons;

(b) examining them on oath;

(c) discovery and production of books of account and other documents; and

(d) any other matter which may be prescribed. o

Amendment of section 86.

32. In section 86 of the principal Act, o

(a) in sub-section (1), after the words and figures o under section 79o, the words and figures o for section 108o shall be inserted;

(b) in sub-section (2), o

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

—(a) where the number of members or the number of societies or the number of persons, as the case may be, has at any time reduced below the number of members or societies or persons as specified in sub-section (2) of section 6:

Provided that the multi-State co-operative society shall be given six months' time to restore the number of members or societies or persons to the requisite number;—;

(ii) in clause (b), for the words “co-operative principles”, the words “co-operative principles; or” shall be substituted;

(iii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

—(c) where the Central Registrar has reasons to believe that the registration was obtained by misrepresentation of facts, submission of false or misleading information, suppression of material facts or fraud thereby compromising the spirit of cooperation.—.

(iv) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:—

—(5) Notwithstanding anything contained in this section, in case of winding up of multi-State co-operative banks, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 shall also apply.—.

10 of 1949

(iv) in sub-section (6), the following proviso shall be inserted, namely:—

Provided that prior to winding up, no objection from the institutional lenders, who have outstanding loans from the society, shall be required in writing.

Explanation.—For the purposes of this proviso, the expression “institutional lenders” includes banks, savings and loan association, trust company, insurance company, real estate investment trust, pension fund and the like.—

33. In section 94 of the principal Act, in the opening paragraph, after the words and figures “section 83 or”, the words and figures “section 84 or” shall be inserted.

Amendment of section 94.

34. In section 98 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

Amendment of section 98.

—(3) The Central Registrar shall also have the power to recover the following dues by attaching bank accounts of defaulting multi-State co-operative societies—

(a) the co-operative education fund referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 63;

(b) the Co-operative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund established under section 63A; and

(c) the expenses incurred by the Co-operative Election Authority for conduct of elections.

Insertion of new section 98A. **35.** After section 98 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Review of decision. **98A.** The Central Registrar may, on an application received from any party, review his decision under clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub-section (1) of section 94:

Provided that no application for review shall be entertained against the recovery certificate issued by the Central Registrar or by any person authorised by him in writing in this behalf, unless the applicant deposits with the concerned society, fifty per cent. of the amount of the recoverable dues:

Provided further that no application for review shall be entertained, if made after sixty days of the date of receipt of the decision or order:

Provided also that the Central Registrar may entertain any such application made after such period, if the applicant satisfies that he had sufficient cause for not making the application within such period.—

Amendment of section 103. **36.** In section 103 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), the following provisos shall be inserted, namely:—

Provided that where all the successor States take necessary steps to divide or reorganise such deemed multi-State co-operative society into State co-operative societies in order to confine their objects, services and the members to respective States within a period of three years, such deemed multi-State co-operative society shall cease to be a multi-State co-operative society:

Provided further that the deemed multi-State co-operative society other than those mentioned in the first proviso shall submit an application for registration and obtain the certificate of registration from the Central Registrar.—

Amendment of section 104. **37.** In section 104 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) after the words “furnishing false information”, the words “or failing to file any return or information” shall be inserted;

(ii) for the words “two thousand rupees”, the words “five thousand rupees” shall be substituted;

(iii) for the words “ten thousand rupees”, the words “one lakh rupees” shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words “five thousand rupees”, the words “ten thousand rupees” shall be substituted;

(c) in sub-section (3),—

(i) after the word and figures ösection 89ö, the words and figures öor to a person required to file return under section 120ö shall be inserted;

(ii) for the words ötwo thousand rupeesö, the words öfive thousand rupeesö shall be substituted;

(iii) for the words, öfive thousand rupeesö, the words öten thousand rupeesö shall be substituted;

(d) in sub-section (4),

(i) in clause (h), after the words öto any personö, the words öor receives such gift, promise or gratificationö shall be inserted;

(ii) in the long line, occurring after sub-clause (iii) of clause (h), after the words öor with bothö, the words öand shall also be debarred from contesting elections for a period of three yearsö shall be inserted;

(e) after subösection (4), the following sub-section shall be inserted, namely :ö

ö(5) Where a multi-State co-operative society,

(a) which is required to provide an explanation or make a statement during the course of inspection, inquiry or investigation, destroys, mutilates or falsifies, or conceals or tampers or unauthorisedly removes, or causes the destruction, mutilation or falsification or concealment or tampering or unauthorised removal of, any document relating to the property, assets or affairs of the society or makes or causes to make a false entry in any document concerning the society;

(b) makes any investment in contravention of the provision of section 64 or the bye-laws made under this Act;

(c) causes unlawful loss to the assets and property of the society; or

(d) causes unlawful loss to the depositor,

the board of directors or the responsible officers of the multi-State co-operative society shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one month but which may extend to one year or with fine which shall not be less than five thousand rupees but may extend to one lakh rupees or with both.

(6) Where the board of directors or officers of the multi-State co-operative society receive any unlawful gains while transacting matters related to such society or utilise any assets of the society for personal unlawful gains, such directors or officers concerned shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one month but which may extend to one year or with fine which shall not be less than five thousand rupees but may extend to one lakh rupees or with both and the proceeds of such unlawful gains shall be recovered from them and deposited in such manner as may be prescribed.ö

Insertion of new section 105A.

38. After section 105 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Provisions of this Act not in derogation of any other law.

—105A. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.—

Substitution of new sections for section 106.

39. For section 106 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:—

Appointment of Co-operative Information Officer.

—106. (1) Every multi-State co-operative society shall appoint a Co-operative Information Officer to provide the information relating to affairs and management of the society to the members of the society and such information shall be confined to the information falling under the disclosure norms specified by the society in its bye-laws.

(2) Any member of multi-State co-operative society shall make an application, accompanying such fee as may be prescribed, to get information specified in sub-section (1).

(3) The Co-operative Information Officer shall, within thirty days from the date of receipt of application, either provide the information or reject the application specifying the reason to do so.

(4) Any member of the multi-State co-operative society whose application has been rejected may prefer an appeal to the Co-operative Ombudsman within a period of one month from the date of such rejection and his decision shall be final and binding.

Copy of rules and bye-laws etc. for inspection.

106A. Every Chief Executive of multi-State co-operative society shall keep a copy of the rules and its bye-laws and also a list of its members, open to inspection free of charge at all reasonable times, at the registered address of the multi-State co-operative society.—

Amendment of section 108.

40. In section 108 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (i), after the words “Central Registrar” the words, “or any person authorised by him in this behalf, not below the rank of Assistant Commissioner or equivalent” shall be inserted.

Amendment of section 109.

41. In section 109 of the principal Act, in clause (a), for the words “co-operative year”, the words “financial year” shall be substituted.

Amendment of section 116.

42. In section 116 of the principal Act,—

(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

—Power to amend Schedules;

(ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

—(1A) If the Central Government is satisfied that it is necessary or expedient so to do, it may, by notification, amend the

First Schedule and Third Schedule and thereupon such Schedules shall be deemed to have been amended accordingly:

Provided that in case of First Schedule, such notification shall be used only for adding to the co-operative principles in the list.;

- (iii) in sub-section (2), for the word, brackets and figure ñsub-section (1)ñ the words, brackets, figures and letter ñsub-sections (1) and (1A)ñ shall be substituted.

43. In section 120 of the principal Act,â

Amendment of section 120.

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:â

ñ(a) annual report of the activities including details of board decisions which were not unanimous;ñ,

(ii) for clause (f), the following clauses shall be substituted, namely:â

ñ(f) disclosure regarding employees who are relatives of Members of board;

(g) declaration of any related party transactions by the board of directors; and

(h) any other information required by the Central Registrar in pursuance of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder.ñ.

44. After section 120 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:óó

Insertion of new sections 120A and 120B.

ñ120A. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, and without prejudice to the provisions of the Information Technology Act, 2000, the Central Government may, from such date as may be notified, require thatóó

Filing of applications, documents, inspections, etc. in electronic form.

(a) such applications, returns, reports, statement of accounts, or any other particulars or document as may be required to be filed or delivered under this Act or the rules made thereunder, shall be filed in the electronic form and authenticated;

(b) such document, notice, any communication or intimation, as may be required to be served or delivered under this Act, shall be served or delivered in the electronic form and authenticated;

(c) such applications, returns, reports, statement of accounts, registers, byeólaws or any other particulars or documents and returns filed under this Act or the rules made thereunder shall be maintained by the Central Registrar in the electronic form and registered or authenticated, as the case may be;

(d) such inspection of the byeólaws, returns, reports, statement of accounts or any other particulars or documents maintained in the

21 of 2000.

electronic form, as is otherwise available for inspection under this Act or the rules made thereunder, may be made by any person through the electronic form; and

(e) such fees, charges or other sums payable under this Act or the rules made thereunder shall be paid through the electronic form,

in such manner as may be prescribed.

(2) The Central Registrar shall—

- (a) issue certificate of registration;
- (b) register the amendment of bye-laws;
- (c) register change of registered office;
- (d) register any document;
- (e) issue any certificate;
- (f) issue notice; and

(g) receive such communication as may be required to be registered or issued or recorded or received, as the case may be,

under this Act or the rules made thereunder or perform duties or discharge functions or exercise powers under this Act or the rules made thereunder or do any act which is by this Act directed to be performed or discharged or exercised or done by the Central Registrar, in the electronic form in such manner as may be prescribed.

Application of
Banking
Regulation Act,
1949.

120B. The provisions of this Act shall apply to a multi-State co-operative society in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up:

Provided that in case of a multi-State co-operative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 shall also apply.

10 of 1949.

Amendment of
section 121.

45. In section 121 of the principal Act, in sub-section (1), for the words and figures “the Companies Act, 1956” and “the Monopoly and Restrictive trade Practices Act, 1969”, the words and figures “the Companies Act, 2013” and “the Competition Act, 2002” shall respectively be substituted.

01 of 1956.

54 of 1969.

18 of 2013.

12 of 2003.

Amendment of
section 123.

46. In section 123 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1),—

(a) for the portion beginning with “or has committed any act” and ending with “the aggregate period does not exceed one year”, the following shall be substituted, namely:—

“or has committed any act including fraud, misappropriation and the like which is prejudicial to the interests of the society or its members, or has omitted or failed to comply with any directions given to it under section 122 in public interest or that there is a stalemate in the constitution or functions of the board or the Co-operative Election Authority has failed to conduct elections in accordance with the provisions of this Act, the Central Government may, after giving the board an opportunity to state its objections, if any, and considering the

objections, if received, by order in writing, supersede or suspend the board and appoint one or more administrators, who need not be members of the society, to manage the affairs of the society for such period not exceeding six months, as may be specified in the order:;

(b) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:ó

Provided that while taking a decision for supersession or suspension on grounds of failure to conduct election, such action shall only be taken if the Board had not given requisition to hold election to the Co-operative Election Authority within the time limit or not extended necessary assistance as per the provisions of section 45.

(ii) for the *Explanation*, the following *Explanation* shall be substituted, namely:óó

ó*Explanation*.óóFor the purposes of section 122 and this section, the expression óspecified multi-State co-operative societyó means any multi-State co-operative society where there is Government shareholding or loan or financial assistance or any guarantee by the Government.ó.

47. In section 124 of the principal Act,óó

Amendment of
section 124.

(a) in sub-section (2),óó

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:óó

ó(aa) the guidelines under sub-section (2) of section 7;ó;

(ii) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:óó

ó(ja) the manner in which the board of a multi-State co-operative society shall provide information, documents, personnel, funds or expenses or any other assistance as sought by the Co-operative Election Authority for conducting elections under clause (a) of sub-section (2) of section 43;ó;

(iii) for clause (k), the following clauses shall be substituted, namely:

ó(k) the composition of the Selection Committee for appointment of Chairperson, Vice-Chairperson and Members of the Co-operative Election Authority under sub-section (1) of section 45;

(ka) the qualification and experience for appointment of Member of the Authority under clause (iii) of sub-section (3) of section 45;

(kb) the salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the Chairperson, Vice-Chairperson and Members of the Authority under sub-section (5) of section 45;

(kc) the other powers and functions of Chairperson under section 45A;

(kd) the procedure of inquiry under sub-section (2) of section 45B;

(ke) time, places and the procedure to be observed by the Authority in regard to transaction of business at its meetings under sub-section (1) of section 45H;

(kf) other functions of the Authority under clause (iii) of section 45-I;

(kg) the manner of election of members of board by secret ballot under sub-section (3) of section 45J;

(kh) the manner of bearing the expenses for holding elections by the Authority under sub-section (6) of section 45J;

(ki) the manner of discharge of functions by the Returning Officers and observers under sub-section (1) and clause (a) of sub-section (3) of section 45K;ö;

(kj) other functions of the observers under clause (a) of sub-section (3) of section 45K;

(iv) after clause (m), the following clause shall be inserted, namely:ö

ö(ma) the procedure for recruitment of employees under proviso to clause (e) of sub-section (2) of section 49 ö;

(v) clause (o) shall be omitted;

(vi) after clause (q), the following clause shall be inserted, namely:

ö(qa) the manner of maintenance of fund under clause (b) of sub-section (1) of section 63.

(vii) after clause (s), the following clauses shall be inserted, namely:

(sa) the manner of appointment of Co-operative Ombudsman and submission of complaints to such Ombudsman under sub-section (1) of section 85A;

(sb) the manner of filing an appeal by society against directions of Ombudsman under sub-section (3) of section 85A;

(sc) other matters under clause (d) of sub-section (5) of section 85Aö;

(viii) after clause (w), the following clauses shall be inserted, namely:ö

(wa) the manner of recovery and deposit of proceeds of unlawful gains under sub-section (6) of section 104;

(wb) the manner to make an application with such fee for the purpose of getting information under sub-section (2) of section 106;ö;

(ix) after clause (x), the following clause shall be inserted, namely:

ö(xa) the manner of powers being exercised by the Central Government in respect of matters relating to filing of applications, documents, inspections and the like in electronic form under sub-section (1) of section 120A;

(xb) the manner of discharging the functions or exercising powers with respect to matters mentioned therein by the Central Registrar in electronic form under sub-section (2) of section 120A;

(b) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:öö

ö(3) Every rule made under this section and any notification issued under section 116 shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree that the rules and any notification issued under section 116 should not be made, the rule and any notification issued under section 116 shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule and any notification issued under section 116.ö.

48. In section 125 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:öö

Amendment of
section 125.

(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act as amended by the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the date of commencement of the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023.

Insertion of
Third Schedule.

49. After Second Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be inserted, namely:

THE THIRD SCHEDULE
 [See clause (h) of subsection (1) of section 43]

Sl. No.	Name of the Act	Act Number
1.	The Indian Stamp Act, 1899;	02 of 1899.
2.	The Reserve Bank of India Act, 1934;	02 of 1934.
3.	The Central Excises Act, 1944;	01 of 1944.
4.	The Industries (Development and Regulation) Act, 1951;	65 of 1951.
5.	The Prevention of Food Adulteration Act, 1954;	37 of 1954.
6.	The Essential Commodities Act, 1955;	10 of 1955.
7.	The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956;	42 of 1956.
8.	The Wealth-tax Act, 1957;	27 of 1957.
9.	The Customs Act, 1962;	52 of 1962.
10.	The Prize Chits and Money Circulation Scheme (Banning) Act, 1978;	43 of 1978.
11.	The Sick Industrial Companies (Special provisions) Act, 1985;	01 of 1986.
12.	The Securities and Exchange Board of India Act, 1992;	15 of 1992.
13.	The Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992;	22 of 1992.
14.	The Foreign Exchange Management Act, 1999;	42 of 1999.
15.	The Competition Act, 2002;	12 of 2003.
16.	The Prevention of Money Laundering Act, 2002;	15 of 2003.
17.	The Companies Act, 2013	18 of 2013. ^o